



वर्ष - 03 अंक - 10 ISSN-2993-4648

शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh

A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly
international E-Journal Impact factor-03

अप्रैल - जून - 2025

<https://shodhutkarsh.com>

अतिथि संपादक - डॉ. अंजली. एस



शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh



A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly international E- Research Journal
वर्ष-03 अंक - 10 अप्रैल - जून -2025

सलाहकार मण्डल (Advisory Board)

Shri Jai Prakash Pandey

Director-Department of Education And Literacy, Ministry Of Education, Govt.Of India.

Prof. Prabha Shankar Shukla

Vice Chancellor North Eastern Hill University (NEHU) Shillong

डॉ. कन्हैया त्रिपाठी पूर्व (OSD), महामहिम राष्ट्रपति 'भारत'

प्रो. दिनेश कुशवाह, रीवा (म.प्र.)

प्रो. राजेश कुमार गर्ग प्रयागराज (उ.प्र.)

प्रो. अनुराग मिश्रा द्वारका, नई दिल्ली

प्रो. कै. एस. नेताम सीधी (म.प्र.)

डॉ. एम.जी. एच. जैदी पन्त नगर (उत्तराखण्ड)

डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' बठिंडा (पंजाब)

डॉ. संगीता मसीह शहडोल (म.प्र.)

डॉ. अंजनी कुमार श्रीवास्तव मोतिहारी विहार

डॉ. अनिल कुमार दीक्षित, भोपाल (म.प्र.)

श्री संकर्षण मिश्रा ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

प्रो. एम.यू. सिद्दीकी सिंगरौली (म.प्र.)

डॉ. बी.पी. बडोला (हिमाचल प्रदेश)

डॉ. अजय चौधरी, नागपुर (महाराष्ट्र)

श्री प्रदीप कुमार- मूल्यांकक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली

डॉ. रेणु सिन्हा, रांची- (झारखंड)

डॉ. निशा मुरलीधरन, वडपलनी- चेन्नई

डॉ. अंजलि एस. एर्नाकुलम, (केरल)

श्री पांडुरंग एस. जाधव बेंगलुरु, (कर्नाटक)

संपादक मंडल

प्रधान संपादक - डॉ. एन. पी. प्रजापति सह **संपादक** - प्रो. यूसी बोल्वीकिन तारास शेव्चेको कीव (युक्रेन), प्रो. सिराजुद्दीन नूर्मतोव (उज़्बेकिस्तान गणराज्य) प्रो. रीनु रानी मिश्रा (उत्तराखंड), डॉ. संतोष कुमार सोनकर अमरकंटक (म.प्र.) प्रो. मोहन लाल 'आर्य' निदेशक एवं डीन IFTM (U.P.) डॉ. बालेन्द्र सिंह यादव, उंचाहार-रायबरेली (उ.प्र.) डॉ. उमाकांत सिंह सिंगरौली (म.प्र.) कैप्टन डॉ. बाबासाहेब माने पुणे (महाराष्ट्र)

लेख भेजने के लिए :- Mail-ID-shodh utkarsh@gmail.com नोट:- पत्रिका में प्रकाशित लेख / शोध आदि में विवाद की स्थिति में लेखक / शोधार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे. पत्रिका के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखें:-

Website:- <http://www.shodhutkarsh.com>

प्रकाशक :-

Radha publications

Mail id-radhapub@gmail.com फोन -087505 51515, 9350551515 Website:-<https://radhapublications.com>

पता :-4231, 1, Ansari Rd, Delhi Gate, Daryaganj, New Delhi, Delhi, 110002

दलित उत्कर्ष
समिति द्वारा
प्रकाशित

संपादकीय..

1.Vikasit Bharath Sankalp Yatra: Good Governance Initiative for Reaching the Unreached - Dr.K.Balaraju	01 2-6
2.National Integration: Social and Ethical Issues in India- Dr.Sarita‘TriKoti’&Dr.Mohan Lal ‘Arya’	6-8 8-9
3.लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य का स्वरूप - प्रो. कविता त्यागी	10-13
4.Revisiting the Past: The Intersection of Indian Knowledge Systems and Nationalism - Gokul Chandra Fulara¹, Prof. Reenu Rani Mishra² & Hanumant Oli³	14-17
5.अंडमान निकोबार की जनजातियाँ और उनकी संस्कृति - डॉ. महेन्द्र कुमार वर्मा	17-19
6.सामाजिक-आर्थिक विकास पर इंदिरा आवास योजना की भूमिका का अध्ययन - मुकेश वर्मा & डॉ.रीनू रानी मिश्रा	20-21
7.Geology and GeologicalPerspective in Ancient India:A Multidimensional Approach- T.N.Mishra& Srurabh Shubham	22-24
8.दलित साहित्य में दलित चिन्तन का उभरता स्वर - शिल्पा भाटिया & डॉ.मलकीयत सिंह	25
9.The Importance of World Book Day - Saurabh Shubham	26-28
10.संजीव कृत ‘फांस’ उपन्यास में अभिव्यक्त पर्यावरण - डॉ.रत्नेश कुमार यादव & शिवम	28-31
11.जनजातीय विकास की रणनीतियाँ (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में) - डॉ. संजीव कुमार पाण्डेय	31-32
12. हिन्दी की आधुनिक कविता में राम - डॉ. पी.एम.आर. जयन्ती	33-34
13. ‘आज की सीता’- एक अध्ययन - डॉ. मिनी ए. आर.	34-41
14. कृषि उपार्जन एवं नवाचारी जनसंचार साधनों का पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में सशक्तीकरण (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) - डॉ. महानन्द द्विवेदी & श्रद्धा शुक्ला	42-44
15.अतियथार्थवादी कहानी: एक सामाजिक दृष्टिकोण - डॉ. श्रीमाया सी	44-49
16.Consumer Behavior Trends in Online Fashion Retail: A Study of Gen Z Shoppers in India. - Shweta Saini	50-57
17.Empowerment and Challenges of Women Tea Workers in Panitola Block with Specific Reference to their Social Status. - Sangita Hazarika, Dr. Baloy Bhattacharjee & Dr. Sachchidanand Sharan Das	57-58
18.शब्दों का खाकरोब कहानी में आर्थिक समस्याएँ - उमा बणिचुल	58-60
19.समकालीन स्त्री के बदलते मायने - डॉ. सीमा चन्द्रन	61-63
20.Physico-Chemical Study of Water in Singrauli District, Madhya Pradesh - Dr.Vishwanath Singh Kushram	64-65
21.समकालीन कथा साहित्य में वंचित समाज का विमर्श - श्रीमती बेलावती सिंह & डॉ.परमानन्द तिवारी	66-69
22.Gender Dynamics in the Diaspora from Western UP: Women's Experiences in Migration to the US and Europe - Akash Bhati	70-71
23.सारा जोसेफ का ‘ओथप्पु’ और मृदुला गर्ग का ‘कठगुलाब’ : एक तुलनात्मक अध्ययन- डॉ. के. भार्गवन	72-76
24.Exploring the Role of Stress Management Programs in Enhancing Teacher Satisfaction at the Secondary Level in West Bengal- Alauddin Middya	77-78
25.मालती जोशी की कहानियों में सामाजिक यथार्थ- अनीता कुमारी	79-80
26.हिन्दी कथा साहित्य में भारतीय ग्यान परंपरा - डा. सुधामणि.एस.	



जेठ की दुपहरी में खिले हुए अमलताश के फूल

संपादकीय ...

युद्धाय कृतनिश्चयः.....

सत्य, अहिंसा, त्याग एवं सेवा भारत के आदर्श हैं। विश्व के सामने इन्हीं मूल्यों के तहत हम सिर उठाकर खड़े हुए हैं। संपूर्ण धरती को अपना परिवार मानने की शिक्षा इस धरती ने अपनी संतानों को दी थी। सबके सुख, शान्ति, निरामयता और कल्याण की कामना की थी। यहाँ जो भी आए, उनके उद्देश्यों को परखे बिना हमने सबको आत्मसात कर लिया था। उनमें से बहुतों ने दूध में शक्कर के समान इस संस्कृति को बहुरंगी फूलों की माला बना दी। जब भी कोई आपदा आ जाए, देश का आत्म चैतन्य जाग उठता है। कभी वह भक्ति के रूप में रहा तो कभी प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में। हमारी सीमाओं को लाँघकर आतंकवाद हमारे ऊपर बरस पड़े तो मुहतोड़ जवाब भी दिए गए। हर बार जनता भाषा-प्रांत-धर्म-जाति-संप्रदाय-रंग जैसे भेदों को भूलकर भारत माता की रक्षा के लिए एकजुट हो गई है।

अधर्म का संहार एवं धर्म तथा मानवता की स्थापना प्रत्येक संस्कृति का दायित्व है। निरीह जनता पर होनेवाले अत्याचार प्रत्येक देश के स्वाभिमान पर लगनेवाली चोट है। इसीलिए भारत ने अपनी शक्ति दिखा दी। पड़ोसी देश जो आतंकवाद के ठेकेदार है, उन्हें अंतिम चेतावनी देनी ही थी। चेतावनी ऐसी थी कि फिर आततायी सिर ऊपर न उठाए। सत्य, अहिंसा आदि महान आदर्श हैं, किन्तु विपक्षी इन्हें मानने के लिए अगर तैयार नहीं है तो शक्ति लगानी पड़ेगी। अधर्म के संहार के लिए शक्ति का प्रयोग कोई अपराध नहीं। इसीलिए भारत ने पूरे विश्व को यह सन्देश दिया कि हम अहिंसा एवं शांति के पक्षधर हैं। परन्तु हमारी शान्ति और एकता को भंग करनेवाली किसी भी गतिविधि को क्षमा नहीं करेंगे।

साहित्यकारों का भी यही दायित्व है कि वे सभी भिन्नताओं के ऊपर उठकर अनेकता एवं बहुस्वरता को बनाए रखते हुए देश की अखंडता, गरिमा और विकास के लिए साहित्य सृजन करें। सृजनात्मकता हमारी महान परंपराओं और विरासतों से ऊर्जा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। संपूर्ण विश्व का नियंत्रण हम नहीं चाहते, दूसरों की संपत्ति या धरती को हड़पना नहीं चाहते, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। पर यदि कोई हमारे ऊपर प्रहार करें तो आत्मरक्षा स्वाभाविक हो जाती है।

हमारे देश में प्राचीन काल से शक्ति की उपासना होती आ रही है। उसमें शिथिलता एवं एकात्मकता में दरार ही हमारी गुलामी का कारण बनी थी। यदि इन दो महत्वपूर्ण मानकों पर हमारा समाज खरा उतरता है तो जगत की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी, भले ही हमारे शत्रु कितनी उठापटक कर लें। इस महान गौरवशाली, कल्याणकारी राष्ट्र-शक्ति का जागरण ही हमारा जीवन लक्ष्य हो। उसके लिए शत्रु संहार की आवश्यकता आ पड़े तो पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए वर्तमान समय के रचनाकारों का दायित्व है लड़ना, अपनी कलम से लड़ना। एक नई मानवता के गठन का दृढ़ संकल्प लेते हुए लेखनी को तलवार बनाना होगा।

दिनांक -30/06/2025

डॉ. अंजली. एसविभागाध्यक्षा एवं सहायक आचार्या
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग एवं शोध केन्द्र
महाराजा कॉलेज, एरणाकुलम, केरल

Vikasit Bharath Sankalp Yatra: Good Governance Initiative for Reaching the Unreached

Dr.K.Balaraju

Associate Professor

Wardha Samajkarya Sansthan MGAHV, Maharashtra

Abstract

Vikasit Bharat Sankalp Yatra captivated crores of people across the country, within a two-month time period from 15th November 2023 to 17th January 2024, more than 15 crore citizens participated in this initiative. This programme was initiated to reach the unreached beneficiaries who could not receive benefits from the government's flagship schemes and to ensure benefits to all the eligible citizens across the country with Jan-Bhagidaari (people's participation). This research paper's main objective is to analyse the strategic steps and methodologies adopted for the success of Vikasit Bharat Sankalp Yatra and its role in effective delivery of the government flagship schemes.

(Key Words: *Vikasit Bharat Sankalp Yatra, Jan-Bhagidaari, Flagship Schemes and Effective Delivery*)

Introduction -India is now the fourth-largest economy in the world, by surpassing Japan India reached this significant achievement and the government of India is focusing on improving the quality of life of every citizen in the country through its initiatives at various levels, with the transformative agenda of Vikasit Bharat different ministries of government of India implementing development and welfare schemes for the betterment of target groups in their respective ministries, huge amount of funds also allocated and spending at grassroot level. We can also see considerable progress in several sectors. By spending more on digital infrastructure, India is moving towards the top place in the digitalised economy. At the same time, with improved health care sector infrastructure and initiatives like health tech startups and telemedicine, health care services are now more accessible than earlier. sustainable practices in farming and the utilisation of the latest technology in the agriculture sector, there is an increase in food grain production recently minister for agriculture and farmers welfare government of India announced that, for 2024-25 India's food grain production has increased to 1663.91 lakh tonnes which is more than 106 lakh tonnes from the previous year 2023-24. Apart from infrastructure development in different priority sectors, the government of India is also implementing various flagship programmes like PMAY (Rural and Urban), PMJAY, Mudra Yojana, Atal Pension Yojana, Jal Jeevan Mission, and PM Kisan Samman Nidhi, etc., for the welfare of the needy population with different social backgrounds.

In spite of considerable progress in target areas, several challenges have also been observed at various levels in achieving the goal of Vikasit Bharat. Due to low awareness, insufficient human resources, less availability of trained manpower, procedural gaps, inadequate infrastructure and other irregularities affecting the effective implementation of the government of India's flagship programmes, in some cases state governments are not performing as expected level due to various reasons including political and coordination problems with central government, which could badly results on the lives of the most eligible beneficiaries of the flagship programmes, they are not able to avail the benefits of the flagship welfare schemes which can help them to overcome from their poverty and lead better quality of life. To overcome these challenges, there is a need to evolve systematic tools and flagship programmes implementing strategies which can reach each and every beneficiary without fail. By identifying this important gap, the Government of India launched a strategic programme, Vikasit Bharat Sankalp Yatra, across the country to attain saturation of flagship schemes.

The objective of this paper is to analyse the strategic tool Vikasit Bharath Sankalp Yatra for reaching unreached beneficiaries of the government of India's flagship programmes, and its impact on eligible beneficiaries. Secondary data is collected from various sources like government ministries' official websites and reports published by government agencies, NGOs and other sources.

Vikasit Bharath Sankalp Yarta-The present government of India's flagship schemes can be categorised as welfare schemes, financial inclusion programmes, healthcare services, infrastructure development, rural development, education and skill development, etc. The success of any flagship programme or welfare scheme depends on ensuring the benefits to all beneficiaries without any procedural gaps or other difficulties. In this view, it is clear that merely announcing and allocating crores of rupees to flagship programmes is not enough for the successful implementation of any scheme or flagship programme. In recent days, people are not just restricting themselves to participation in voting and electing the government for a particular term; they are observing the performance of the government and its

related organisations, and people are expecting more transparency and accountability from the government in a given time. To perform better and effective delivery of welfare and development schemes the government is also not limited to announcing the programmes and allocating the funds; apart from these two important steps, government organisations and implementing agencies are trying to find out effective implementation strategies for ensuring the benefits of the schemes to all eligible target population, for this important task, government adopting special initiatives.

The Government of India is adopting various governance strategies for effective governance, concerned departments and ministries are employing appropriate technologies, e-governance, community engagement, and even encouraging community participation to ensure welfare and development schemes benefit all eligible citizens. Vikasit Bharath Sankalp Yatra is one of the unique initiatives by the government of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to ensure the flagship programmes' benefits to each and every eligible beneficiary across the country.

Vikasit Bharat Sankalp Yatra as a Good Governance Initiative - According to the UN, governance refers to the activities of all political and administrative authorities to govern their country. Good governance includes important elements like participation, responsiveness, effectiveness, quality of services provided, transparency, inclusivity and accountability; even feedback from all stakeholders is also very important for good governance (UCLG ASPAC, 2021) With these good governance elements, any government or institution can deliver effective and efficient services to its citizens or stakeholders. As one of the good governance initiatives of the government of India, Vikasit Bharat Sankalp Yatra was flagged off by the Prime Minister of India, Narendra Modi, in Jharkhand on 15th November, 2023. VBSY aims at attaining saturation of the

government of India's flagship programmes and ensuring benefits of the flagship schemes to every eligible beneficiary. It was planned to cover 2.60 lakh gram panchayats and 4,000-plus urban local bodies across the country through IEC (Information, Education and Communication) vans and camps of various development and welfare schemes (PIB, Viksit Bharat Sankalp Yatra: Transformation in Action, 2023)

Ensuring Awareness and Delivering Spot Services - Vikasit Bharat Sankalp Yatra's one of the main objectives is to ensure awareness of the benefits of the flagship programmes, to fulfil this objective, a mass campaign was conducted at various levels throughout the country by involving state governments and Union Territories, and generated awareness on flagship schemes by targeting all eligible beneficiaries in rural, urban and tribal areas in the country. IEC (Information, Education and Communication) vans were used across the country to spread information about the flagship schemes during the yatra, and audio-visuals, booklets, brochures and pamphlets were distributed to the public.

During this process, lakhs of new applications are received from the citizens for basic amenities, like housing, sanitation, health care facilities, drinking water and LPG Connections, etc., by the citizens for availing the benefits of the government's flagship programmes. By involving the concerned department officials, on-spot services are also being provided to the citizens across the country. Health Camps are being organised. TB screening was carried out in the health camps, in tribal areas, screening was done for the detection of Sickle Cell Disease (SCD), and other health screenings like Hypertension and Diabetes were also conducted and suspected cases were referred to higher centres.

Table 1: Citizens' Participation in "Vikasit Bharat Sankalp Yatra"

S. No.	Name of the State	Progress Uploaded / GPs Covered	People Attended	Total Number of Men Attended	Total Number of Women Attended	Meri Kahaani Meri Zubaani Beneficiaries
1	A&N Islands	66	10,812	4,576	6,220	418
2	Andhra Pradesh	8,383	29,59,847	14,55,372	14,93,667	40,648
3	Arunachal Pradesh	1,015	1,11,782	59,210	52,156	17,948
4	Assam	2,173	26,76,773	10,60,651	16,14,079	38,112
5	Bihar	5,419	24,52,734	13,58,912	10,86,541	29,916
6	Chhattisgarh	4,267	32,09,722	14,79,365	17,01,791	1,15,719
7	Goa	181	29,334	11,882	17,363	291
8	Gujarat	12,833	50,87,709	28,78,934	21,93,906	72,624
9	Haryana	4,457	31,29,151	18,20,340	13,03,054	47,118
10	Himachal Pradesh	3,534	2,86,277	1,24,238	1,58,716	7,881
11	Jammu& Kashmir	4,197	29,06,671	16,71,234	12,28,461	87,557
12	Jharkhand	2,665	9,75,990	4,51,697	5,20,364	19,515
13	Karnataka	3,546	9,13,663	5,01,786	4,08,995	4,831
14	Kerala	657	1,77,596	1,00,085	77,386	3,478
15	Ladakh	184	29,206	13,211	15,940	789
16	Lakshadweep	10	14,437	7,801	6,612	13
17	Madhya Pradesh	10,967	80,18,219	44,43,693	35,34,465	1,55,380
18	Maharashtra	17,621	90,83,751	51,24,211	38,93,198	1,15,268
19	Meghalaya	1,108	78,798	29,401	48,965	2,768
20	Mizoram	112	8,764	4,338	4,422	459
21	Nagaland	377	31,067	15,349	15,702	1,815
22	Odisha	5,275	17,94,800	7,63,246	10,26,928	11,592
23	Puducherry	72	36,219	13,032	22,615	14,935
24	Punjab	6,792	11,97,520	6,00,065	5,95,203	18,941
25	Rajasthan	5,773	74,65,509	39,90,904	34,33,415	3,36,300
26	Tamil NADU	4,900	8,63,684	3,56,580	5,06,910	9,065
27	Telangana	4,522	6,07,486	3,29,118	2,77,451	5,377
28	Dnh & Dnd	38	34,820	15,783	19,032	286
29	Tripura	781	5,70,942	2,50,127	3,19,595	53,554
30	Uttar Pradesh	39,895	2,77,83,894	1,53,04,019	1,24,01,227	2,39,237
31	Uttarakhand	7,423	16,39,569	7,73,431	8,61,063	19,112
TOTAL		1,59,243	8,41,86,746	4,50,12,591	3,88,45,442	14,70,947

(Source: [Press Release: Press Information Bureau, Ministry of Women and Child Development](#))

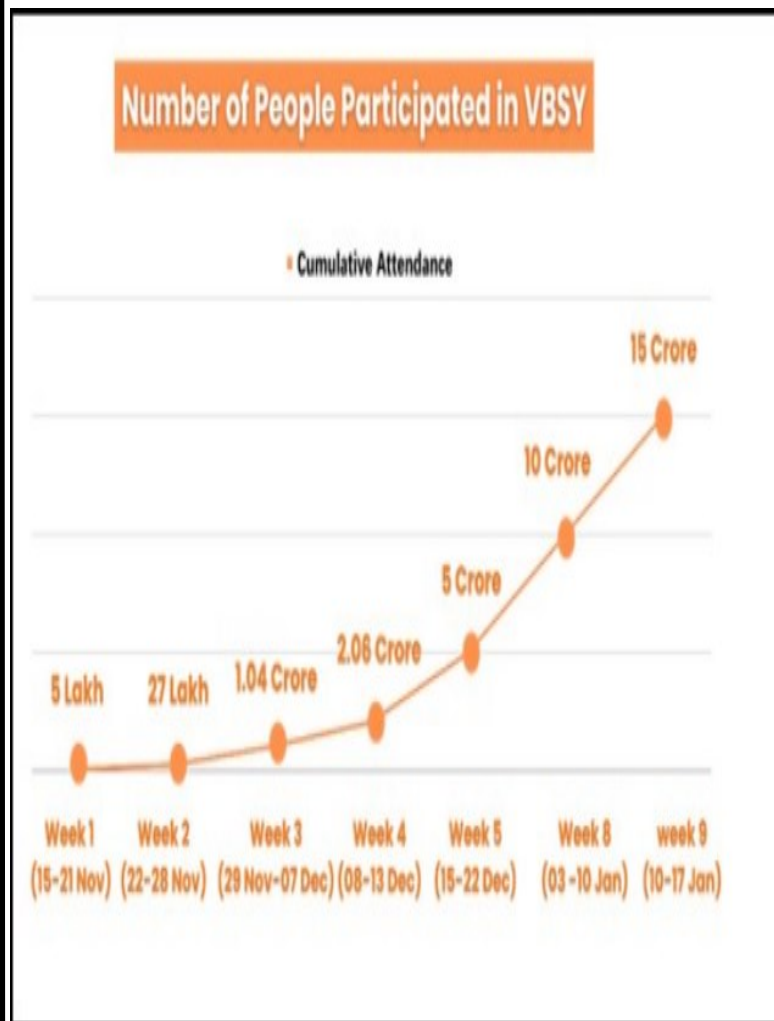
Meri Kahani Meri Zubani-Sharing best practices and success stories can inspire and motivate people who could not participate in the process of development or have not availed the benefits from the available welfare schemes. It also helps individuals and communities to replicate the shared success stories for the improvement of the quality of life in their personal lives. Meri Kahani Meri Zubani was one of the activities performed during the Vikasit Bharat Sankalp Yatra, where a platform is provided to beneficiaries to share their success stories by participating or availing the benefits of the government's flagship schemes. With this activity, lakhs of citizens were encouraged to access the flagship schemes. As per Viksit Bharat Dashboard, 14.70 lakh beneficiaries from around 60 schemes of various Ministries have narrated their experiences under "Meri Kahani Meri Zubani (MKMZ)," (PIB, Vikasit Bharat Sankalp Yatra "Meri Kahani Meri Zubani", 2024)

Pledge to Create a Developed India -In Vikasit Bharat Sankalp Yatra programmes, the government of India appealed to citizens to take a pledge as "Hamara Sankalp Vikasit Bharat" Lakhs of volunteers and citizens took the Vikasit Bharat pledge as per my government website, more than 8.5 lakhs citizens took pledge and uploaded their details digitally, even received pledge taken digital certificates, this kind of initiation promoted voluntary nature to serve the country and be committed towards nation's growth and development especially young generation in India.

Feedback from Primary Stakeholders -Quality of provided services can be rightly assessed with the feedback from the users, in "Vikasit Bharat Sankalp Yatra", with the "Jan-Bhaagidaari" (people's participation) enabled the government mechanism to get feedback on implemented government flagship programmes, during this VBSY different ministries and concerned departments were collected information from the beneficiaries on their departmental welfare programmes, this kind of feedback can be utilized to fulfill the gaps in planning and implementing development and welfare schemes in future, even officials from related departments can make modifications in existing schemes as per beneficiaries requirement wherever it is possible.

Impact of Vikasit Bharat Sankalp Yatra -The objective of Vikasit Bharat Sankalp Yatra was to reach such people who are still deprived of the government schemes, said Prime Minister Narendra Modi. Calling VBSY a great medium of the last mile delivery, the Prime Minister informed that during the Yatra, more

than 4 crore health check-ups were performed, 2.5 crore TB screenings and 50 lakh sickle cell anaemia screenings were done. 50 lakh Ayushman cards, 33 lakh new PM Kisan beneficiaries, 25 lakh new Kisan Credit Cards, 25 lakh free gas connections and 10 lakh new SVANidhi applications were achieved during the course of the yatra so far. (PM India, 2025)



(Source: [Press Release: Press Information Bureau Ministry of Information & Broadcasting](#))

Conclusion

Vikasit Bharat Sankalp Yatra was a successful initiative by the government of India with the objective of reaching the unreached eligible beneficiaries' of welfare schemes. Through its effective planning and implementation strategies the central government, with the active involvement of state governments and UTs, collectively generated awareness among citizens on government's flagship schemes, identified unreached areas and eligible beneficiaries who deprived to get benefit from the available schemes and received applications for different welfare schemes from the citizens at the same time VBSY initiative provided many spot services to beneficiaries.,

To ensure health services to the citizens, more than four crore people's health screening was done in health camps, and more than 2 crore Ayushman Bharat health cards were issued to eligible citizens (Iqbal, 2024). Initiatives like sharing success stories by the beneficiaries in VBSY programmes, collecting feedback from the citizens on implemented welfare programmes, will be helpful to both citizens and the government functionaries for better planning and implementation of welfare programmes. Pledge taking for developed India and the Prime Minister's direct interaction with beneficiaries generated confidence among the unreached needy people.

References:

1. Iqbal, N. R. (2024). Delhi: PIB Ministry of Information & Broadcasting. Retrieved June 4, 2024, from <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1996884#:~:text=In%20just%20two%20months%2C%20the,a%20thriving%20and%20inclusive%20India.>
2. PIB. (2023). Viksit Bharat Sankalp Yatra: Transformation in Action. Delhi: PIB Ministry of Information and Broadcasting.
3. PIB. (2024). Vikasit Bharat Sankalp Yatra "Meri Kahani Meri Zubani". Ministry of Women and Child Development. PIB Government of India. Retrieved June 05, 2025, from <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1993797>
4. PM India. (2025). Retrieved from https://www.pmindia.gov.in/en/https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-interacts-with-the-beneficiaries-of-viksit-bharat-sankalp_yatra/#:~:text=%E2%80%9CThe%20main%20objective%20of%20Vikas,by%20everyone%E2%80%9D%20Said%20PM%20Modi.
5. UCLG ASPAC. (2021, November 18). Retrieved from United Cities and Local Governments Asia-Pacific : <https://uclg-aspac.org>

National Integration: Social and Ethical Issues in India

Dr. Sarita 'Trikoti'

Assistant Professor

Department of Sociology & Social Work

Dr. Mohan Lal 'Arya'

Professor

Department of Education

School of Education and Humanities

IFTM University, Moradabad (U.P.)

E-mail id: drmlarya2012@gmail.com

Abstract:

National integration in India refers to the unification of its diverse population, encompassing various religions, cultures, regions, and languages, into a single cohesive nation. This process is challenged by several social and ethical issues that disrupt the country's peace and unity. These include religious and communal divisions, caste-based discrimination, regionalism, linguistic diversity, economic disparity, gender inequality, and political corruption. Each of these issues perpetuates divisions and undermines the principles of equality and justice necessary for national cohesion. Addressing these challenges is crucial for achieving true national integration, which requires fostering a sense of shared identity, respect for diversity, and inclusive policies. For India to realize its vision of a united nation, it is essential to confront these issues collectively, ensuring that every individual, irrespective of their background, enjoys equal dignity, opportunity, and respect. Only by tackling these complex social and ethical issues can India move toward a more integrated and harmonious future.

Key Words: National Integration, Caste-Based Discrimination, Regionalism, Ethical Issues.

Introduction:

National integration in India refers to the process of uniting people from various diverse backgrounds, regions, cultures, and religions into a single, cohesive nation. India is often referred to as a "subcontinent" because of its rich diversity, which

spans not just geographical boundaries but also social, economic, and cultural differences. As a result, achieving national integration remains one of the most significant challenges the country faces. However, this challenge comes with several social and ethical issues that, if not addressed, can disrupt the peace and unity of the nation. The idea of national integration is critical to the survival of a unified India, especially in a country with a long history of regionalism, communalism, caste divisions, and linguistic differences. In this article, we will explore some of the social and ethical issues related to national integration in India and their implications.

1. Religious and Communal Divisions:

India is home to various religions, including Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, and others. The diversity of faiths has been a source of cultural richness but has also given rise to communal tensions. The ethical issue here arises when religious groups foster animosity towards one another. The rise of religious intolerance, hate speech, and religious-based violence threatens the fabric of unity in the country. Instances such as the Babri Masjid demolition in 1992, communal riots in Gujarat in 2002, and ongoing tensions in Kashmir have posed serious questions about religious coexistence and the ethical responsibility of citizens and leaders in fostering harmony. National integration cannot succeed unless individuals and communities make a conscious effort to rise above religious differences and uphold the secular fabric of the nation.

2. Caste System and Social Inequality:

The caste system, though constitutionally abolished, continues to be an enduring social issue in India. Discrimination on the basis of caste leads to social exclusion and economic disparity. The lower castes, particularly the Dalits, face severe social discrimination, which impedes their ability to achieve social and economic mobility. The ethical issue here revolves around the practice of untouchability, violence against lower-caste communities, and unequal access to education and employment. Despite legal protections and affirmative action policies, caste-based discrimination still exists, causing division and undermining national unity. National integration will be achieved only when these deep-rooted social inequalities are addressed, and every citizen is afforded equal dignity and respect, irrespective of their caste.

3. Regionalism and Linguistic Diversity:

India's vast geographical expanse results in significant regional diversity. Each state has its own unique culture, language, and traditions, leading to a sense of regional pride and identity. While regionalism is natural, it can sometimes morph into chauvinism or secessionism, as

seen in movements for statehood or independence in places like Punjab, Tamil Nadu, and Jammu and Kashmir. The linguistic issue is another layer of complexity. The imposition of Hindi as the national language, while aimed at unifying the country, has sparked protests in states like Tamil Nadu, where people feel that their regional language and culture are being threatened. National integration can only take place if regional identities are respected, and the government fosters policies that celebrate India's linguistic and cultural diversity, rather than imposing one culture or language over others.

4. Economic Disparity and Social Stratification:

India has made impressive strides in economic development, but wealth distribution remains highly unequal. The urban-rural divide, income inequality, and unequal access to resources such as healthcare, education, and infrastructure continue to exist. The ethical issue here is the disparity between the rich and the poor, leading to a sense of alienation and resentment in marginalized communities. Economic disparity has significant social consequences. People from underdeveloped regions, such as tribal areas, often feel neglected and excluded from the benefits of economic growth. For national integration to be meaningful, there needs to be a concerted effort to address the social stratification and ensure that the benefits of development reach all sections of society.

5. Gender Inequality:

While India has made notable progress in women's rights, gender inequality continues to be a significant social issue. The deeply entrenched patriarchal culture often leads to discrimination against women in various spheres, including education, employment, and decision-making. Violence against women, such as sexual assault, dowry-related violence, and female foeticide, remains a persistent problem. The ethical issue in this context is the denial of basic rights and opportunities to women based on their gender. The lack of gender equality creates divisions in society and undermines the idea of a just and inclusive national integration. It is essential to promote gender equality as part of the process of national integration, ensuring that women have equal access to opportunities and are treated with dignity and respect.

6. Political Corruption and Ethical Governance:

Corruption in India is a pervasive problem that hampers national integration by eroding trust in institutions and hindering the equitable distribution of resources. Ethical governance is essential for creating a just society, where every citizen has access to equal opportunities. Political

leaders, when motivated by self-interest or personal gain, often make decisions that benefit a particular group or region at the expense of others, deepening divisions. The fight against corruption and the promotion of ethical governance are vital in building a united nation. Transparent and accountable institutions that serve the interests of the entire nation, rather than specific political or economic elites, are essential for fostering national integration.

Conclusion

National integration in India is a complex process that requires addressing several social and ethical issues that continue to divide the nation. While India's diversity is its strength, it also poses challenges to the creation of a harmonious society. To achieve true national integration, it is essential to overcome religious intolerance, caste-based discrimination, regionalism, gender inequality, economic disparity, and political corruption. Citizens, political leaders, and civil society must come together to create an inclusive environment where every individual, regardless of their background, feels a sense of belonging and equality. Only then can India achieve its vision of a united and integrated nation where diversity is celebrated, and unity is the guiding principle.

References:

1. Andersen, S C, and H S Nielsen (2019), "Learning from Performance Information", Journal of Public Administration Research and Theory.
2. Bjorklund, A and K Salvanes (2011), "Education and Family Background: Mechanisms and Policies", in E Hanushek, S Machin and L Woessmann (eds), Handbook of the Economics of Education, Vol. 3.
3. Burgess, S and E Greaves (2013), "Test Scores, Subjective Assessment, and Stereotyping of Ethnic Minorities", Journal of Labor Economics 31 (3): 535-576
4. Chipata Day Secondary School (2020). Performance analysis report for 2019 school certificate examinations. Chipata, Zambia.
5. Creswell, J. W. (2017). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th edition.

लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य का स्वरूप

प्रो. कविता त्यागी

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
मेरठ कॉलेज, मेरठ

ईमेल-tkavita953@gmail.com

सारांश-लोक जीवन की गरिमा को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है। वैदिक विधि निषेधों के समानान्तर लोक व्यवहार की धारा निरन्तर प्रवाहित होती रही। यद्यपि लोक शब्द का प्रयोग जिन अर्थों में प्राचीन काल से हुआ है, लोक साहित्य में समग्रतः उन्हीं अर्थों में नहीं प्रयुक्त है। आजकल लोक शब्द जन जीवन तथा लोक व्यवहार की ओर अवश्य संकेत करता है। इसलिए 'सहितस्य भावः साहित्यम् हितेन सह सहितम् सः साहित्यम् की व्याख्या के अनुसार साहित्य में हित का भाव स्वतः निहित है। इसलिए लोक साहित्य का महत्व शिष्ट साहित्य की अपेक्षा कहीं अधिक है, क्योंकि लोक साहित्य की रचना लोक के हित के लिए है जबकि शिष्ट साहित्य अधिकतर स्वान्तः सुखाएँ और परोक्ष रूप से लोक हिताएँ होती हैं।

मुख्य शब्द-अन्तरंग, समग्रतः सर्वकालिक, प्रसुप्त, प्रांजल, नैसर्गिक, अवसाद, साधारणीकृत, स्फुटित, देदीप्यमान, उपजीवी

जीवन से सम्बन्धित अनेक बातें शिष्ट साहित्य में छूट जाती हैं किन्तु लोक साहित्य में जन-जीवन का अन्तरंग और पूर्ण चित्र चित्रित होता है। लोक साहित्य सर्वकालिक, सर्वदेशीय और सर्व जनीन होता है। इसमें मानव मात्र का चिरन्तन और चिर प्रसुप्त भावनाएँ समाहित रहती हैं। लोक साहित्य में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक का समस्त मानव समुदाय अपनी भावनाओं, कामनाओं, इच्छाओं और अभिलाषाओं को प्रतिफलित होते देखता है। जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जो इससे अछूता रह जाए। सभी को अपनी सीमा में समेट लेता है।

लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हुए ताराकान्त मिश्र कहते हैं 'लोक साहित्य समस्त जनता का साहित्य होता है किन्तु शिष्ट साहित्य शिक्षित एवं संस्कृत व्यक्तियों का साहित्य है। लोक साहित्य के प्रणेता अज्ञात होते हैं, शिष्ट साहित्य के रचियता ज्ञाता। लोक साहित्य मौखिक और परम्परागत होते हैं परन्तु शिष्ट साहित्य की भाषा प्रायः ललित प्रांजल और परिष्कृत होती है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के सम्बन्ध में लिखा है कि- 'लोक साहित्य मानव समाज के उन लोगों का साहित्य है जो आधुनिक सभ्यता, संस्कृति एवं नागरिक संस्कारों से दूर अपनी आदिम अवस्था से आबद्ध सहज अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं। इस साहित्य में समस्त भाव धारा विरामहीन एवं अन्तहीन रूप में प्रवाहित होती रहती है। परम्परा इस साहित्य का आधार है और जनभाषा इसकी अभिव्यंजना का माध्यम। श्रुति एवं स्मृति के द्वारा यह जन जीवन में संचित और सुरक्षित रहता है। यह जनता के नैसर्गिक उदगारों की सहज, स्वाभाविक तथा मौखिक अभिव्यक्ति का साहित्य है जिसमें उसकी सम्पूर्ण आशा, आकांक्षा, उल्लास, अवसाद, चिन्तन-मनन तथा धारणाओं को वाणी मिलती है।' इसमें कोई भी दिखावटीपन नहीं रहता है बल्कि स्वतः स्वरूप में रहता है। लोक साहित्य के प्रधान गुण, स्वाभाविकता, स्वच्छन्दता और सरलता के विषय में डॉ. कृष्ण चन्द्र शर्मा ने कहा है- 'लोक साहित्य वह साहित्य है जो जंगल में खिलने वाले फूल की तरह स्वाभाविक, आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों की भांति स्वच्छन्द गंगा की निर्मल

धारा के समान सरल एवं पवित्र था। उस साहित्य का जो अंग आज अवशिष्ट तथा सुरक्षित रह गया है वह लोक साहित्य है।³ लोक साहित्य जीवन का सहज और अकृत्रिम रूप है। डॉ. सन्तराम अनिल के कथनानुसार- "लोक साहित्य में अभ्यास और अध्ययन की अपेक्षा नहीं होती, जिसमें कर्ता का व्यक्तित्व साधारणीकृत हो जाता है और जिसमें आदि मानस के कुछ न कुछ अवशेष विद्यमान हो जाता है और जिसमें आदि मानस के कुछ न कुछ अवशेष विद्यमान हो और जिसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती चला जाए लोक साहित्य कहलाता है।"⁴ इस और कुन्दनलाल उप्रेती ने लिखा है 'लोक साहित्य श्रुति या परम्परा पर आधारित होता है जबकि शिष्ट साहित्य श्रुति या परम्परा पर आधारित नहीं होता है, अर्थात् लोक साहित्य मौखिक और शिष्ट साहित्य लिपि बद्ध होता है। डॉ. दीनदयाल गुप्त ने कहा है- 'शिष्ट साहित्य में भाव और विचारों का प्रकाशन कलात्मक ढंग से भाषा और कथन शैली के परिष्कार के साथ होता है, परन्तु लोक साहित्य में वह बिना किसी सजावट के स्वतः स्फुटित होता है। डॉ. रामनरेश त्रिपाठी ने भी मत दिया है- 'शिष्ट साहित्य में अलंकारों पर बहुत बल दिया जाता है परन्तु लोक साहित्य में अलंकारों के प्रति कोई आग्रह नहीं है। यह तो वन्य कुसुम की भांति बिना संवारे ही अपने प्राकृतिक सौन्दर्य से देदीप्यमान रहता है।'⁵ यही उसकी मूल विशेषता को प्रदर्शित के साथ भव्यता को प्रकट करता है।

पाश्चात्य विद्वान फ्रैंक सिजविक ने लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के सम्बन्ध में लिखा है 'लोक साहित्य में रचियता का व्यक्तित्व नहीं मिलता है परन्तु शिष्ट साहित्य में कलाकार का व्यक्तित्व झलकता है। इस ओर रूसी विद्वान सोकोलोव के विचार देखिए- 'लोक साहित्य अतीत की गूँज भी है और वर्तमान की सशक्त आवाज भी। बाटकिन ने भी कहा है 'लिपिबद्ध साहित्य लोक साहित्य नहीं है। लोक साहित्य में अन्तर्भूत मानव भावनाएं दीर्घकाल से मौलिक धरातल पर विचरण करती हुई चली आ रही है। लोक की मौलिक भावाभिव्यक्ति को लोक साहित्य की आवश्यक तत्व माना है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य सर्वथा एक दूसरे से भिन्न हैं। लोक साहित्य की कतिपय विशेषताएं उसे शिष्ट साहित्य से पृथक कर उसके स्वरूप व पृथक अस्तित्व का निर्धारण करती हैं। लोक साहित्य में शिष्ट समाज द्वारा ग्राह्य विचारों और भावों की गौणता तथा परम्परागत एवं मौखिक रूप में आदान-प्रदान होने वाले विचारों की प्रमुखता होती है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में भेद होते हुए भी इनमें उपजीव्य और उपजीवी का अटूट सम्बन्ध है। लोक साहित्य शिष्ट साहित्य का पोषक होने के नाते उपजीव्य और शिष्ट साहित्य पोष्य होने के नाते उपजीवी है। इस सम्बन्ध में डॉ. श्रीराम शर्मा का कहना है 'लोक साहित्य को शिष्ट साहित्य का जनक कहने में इसलिए संकोच नहीं होना चाहिए कि शिष्ट और शास्त्रीय मर्यादाओं में बंधे साहित्य के लिए उत्स भूमि कहीं प्राप्त थी तो लोक साहित्य में लोक कथाओं से प्रेरणा प्राप्त कर शिष्ट साहित्यिक कहानी नामक विधा का उद्भव एवं विकास हुआ है। लोकगीतों की विकास समान स्थिति ही शिष्ट गीतियों के रूप में दिखलाई देती है।'⁶ अतः लोक कथाओं से प्रेरणा शिष्ट साहित्य लेकर निरन्तर गतिमान रहता है।

लोक साहित्य में परम्परा एवं रीतिरिवाजों की ऋणी तथा इन दोनों की उपकारिणी लोक कल्पना प्रधान होती है। लोक साहित्य मौखिक परम्परा से चला आता है जबकि शिष्ट साहित्य निश्चित रूप से लिखित होता है। लोक साहित्य अब न केवल मौखिक बल्कि लिखित रूप में प्राप्त होता है जबकि शिष्ट साहित्य निश्चित रूप से लिखित होता है। इसका बराबर प्रकाशन बराबर होता रहता है। जनपदीय जनों द्वारा लोक साहित्य की भाषा स्वतन्त्र जीवित लोकभाषा होती है जबकि शिष्ट

साहित्य की भांति शास्त्रीय सिद्धान्तों का अंकुश उसमें नहीं होता है। लोक साहित्य के रचियता का नाम अंकित नहीं होता जबकि शिष्ट साहित्य की रचियता का नाम आवश्यक रूप से ज्ञात होता है। आधुनिक युग में रचित लोक साहित्य में लोक कवि के नाम की छाप लगाई जाती है। लोक साहित्य तर्कहीन एवं कल्पना प्रधान होने के साथ -साथ लोक का लोक द्वारा लोक के लिए होता है। लोक साहित्य में लोक की अभिव्यक्ति होती है किन्तु शिष्ट साहित्य में एक वर्ग या व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है।

निष्कर्ष-

लोक साहित्य शिष्ट साहित्य से अधिक व्यापक, स्वाभाविक तथा लोकप्रिय होता है। प्राचीन काल से यह सजीव, सरस एवं प्रवाहपूर्ण लोक साहित्य यांत्रिक शिष्ट साहित्य के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता रहा है। इसलिए लोक साहित्य किसी प्रकार के नियमों के बन्धनों से मुक्त विस्तृत परिधि वाली स्वच्छन्द गति से प्रवाहमान एक धारा है। शिष्ट साहित्य उसके चुने हुए कुछ भावों को लेकर सजा-संवरा नहर है जिसे स्वतन्त्र रूप से नहीं बहने दिया जाता है।

सन्दर्भ सूची

1. आदेश बाला, अमृतलाल नागर के उपन्यासों में लोकतत्व, पृ. 15
2. ताराकान्त मिश्र, डॉ. सुरेश चन्द्र त्यागी, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, पृ. 38
3. डॉ0 कृष्ण चन्द्र शर्मा, लोक साहित्य की रूपरेखा, पृ. 1
4. डॉ. सन्तराम अनिल, कन्नौजी लोक साहित्य, पृ. 25
5. डॉ. रामनरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, पृ. 69
6. डॉ. श्रीराम शर्मा, लोक साहित्य सिद्धान्त और प्रयोग, पृ. 247

Revisiting the Past: The Intersection of Indian Knowledge Systems and Nationalism

Gokul Chandra Fulara¹

(Assistant Professor – Guest faculty, Department of Political Science, Faculty of Social Science, HNB Garhwal University.

Prof. Reenu Rani Mishra²

Professor, Department of Economics, MB Govt. PG College Haldwani, Uttarakhand, India

Hanumant Oli³

Research scholar, Department of Economics, MB Govt. PG College Haldwani, Uttarakhand, India

ABSTRACT-The research paper explores the relationship between India's indigenous knowledge systems (IKS) and the development of nationalism. The study begins by examining the cultural unity in pre-colonial India through shared religious texts, philosophical systems, and social structures. It then delves into the disruption caused by British colonialism, which marginalized IKS and led to a deep intellectual and cultural rift. However, this very marginalization sparked a revival of interest in IKS during the late 19th and early 20th centuries, as nationalists such as Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi turned to India's spiritual and intellectual heritage to resist colonial domination and promote national unity. Methodologically, the research utilizes historical analysis, tracing the role of IKS in shaping key nationalist ideologies, from the spiritual nationalism of Sri Aurobindo to Deendayal Upadhyaya's Integral Humanism. It also examines the role of IKS in contemporary nationalist discourses, particularly through the lens of India's educational policies and soft power strategies. Major results show that IKS has been central in both fostering a sense of cultural pride and contributing to national unity, despite ongoing challenges posed by globalization, caste and class dynamics, and the politicization of traditional knowledge. The paper concludes by arguing that while IKS has historically played a crucial role in the development of Indian nationalism, its future relevance depends on balancing tradition with modernity and ensuring inclusivity. This research contributes to a deeper understanding of how traditional knowledge systems can be leveraged to address contemporary national and global challenges.

Keywords: Nationalism, Marginalization, Colonial domination, Integral Humanism.

Introduction- Indian Knowledge Systems (IKS) encompass a wide array of disciplines, including philosophy, medicine, astronomy, linguistics, mathematics, and spirituality, that have formed the bedrock of India's cultural and intellectual heritage. Rooted in texts like the Vedas, Upanishads, and epics such as the Mahabharata and Ramayana, IKS represent a sophisticated and holistic worldview that thrived for centuries, shaping not only

cultural identity of the Indian subcontinent but also influencing civilizations across the globe. From the philosophical treatises of ancient India to practical applications like Ayurveda and yoga, these systems embodied a blend of empirical observation, intellectual rigor, and spiritual insight.

In pre-colonial India, IKS served as a unifying cultural framework despite regional diversities. Centers of learning such as Nalanda and Takshashila symbolized India's intellectual prowess, attracting scholars from far and wide. The shared ethos embedded in these systems created a sense of cultural unity and continuity. However, this flourishing knowledge tradition suffered significant setbacks with the advent of British colonial rule. Colonial policies systematically marginalized IKS, deeming them outdated and unscientific, while privileging Western systems of knowledge and education. The infamous Macaulay Minute of 1835 epitomized this shift, as it sought to create a class of Indians steeped in Western education and alienated from their cultural roots. The colonial project not only disrupted traditional educational and intellectual structures but also created an epistemological divide, where indigenous knowledge was dismissed as superstition and relegated to obscurity.

Paradoxically, the colonial marginalization of IKS became a catalyst for its revival. The late 19th and early 20th centuries witnessed a resurgence of interest in India's indigenous knowledge systems, spearheaded by nationalist leaders and thinkers. Figures like Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, and Deendayal Upadhyaya turned to India's rich intellectual and spiritual traditions as a source of cultural pride and as a tool to resist colonial domination. Swami Vivekananda's emphasis on Vedantic philosophy and spirituality at the global stage, Gandhi's integration of traditional practices into his vision of Swaraj (self-rule), and Aurobindo's spiritual nationalism underscored the relevance of IKS in uniting the nation. This revival was not merely a nostalgic return to the past but a strategic reclamation of cultural identity to foster national unity and self-confidence.

The interplay between IKS and nationalism continues to shape contemporary India. The integration of IKS into modern education policies, such as the National Education Policy (NEP) 2020, and the global recognition of practices like yoga and Ayurveda highlight its enduring relevance. However, this resurgence is not without challenges. The politicization of IKS, the need for scientific validation, and the pressures of globalization pose significant hurdles.

This paper seeks to explore the historical and contemporary dimensions of IKS within the framework of Indian nationalism. By examining the disruptions caused by colonialism, the revival during the nationalist movement, and its current role in India's cultural and political discourses, the research aims to underscore the importance of balancing tradition with modernity. Understanding the intersection of IKS and nationalism offers valuable insights into how traditional knowledge can contribute to addressing contemporary challenges in a globalized world.

Pre-Colonial Unity through IKS- Pre-colonial India witnessed a remarkable cultural coherence, nurtured by Indian Knowledge Systems (IKS), which provided a shared intellectual and spiritual framework across the subcontinent. This unity emerged through interconnected religious, philosophical, and social structures, creating a sense of belonging among diverse communities while respecting regional variations.

Religious and Philosophical Foundations- The foundation of this cultural coherence lay in shared religious texts and philosophical doctrines. Canonical texts like the Vedas and Upanishads offered profound insights into metaphysics, ethics, and cosmology, while epics such as the Mahabharata and Ramayana shaped collective moral and cultural values. Philosophical traditions like Vedanta, Nyaya, and Samkhya emphasized logic, epistemology, and ethics, contributing to a rich intellectual tradition that transcended regional boundaries.

These systems were not merely academic pursuits but provided frameworks for governance, education, and daily life. The integration of spiritual inquiry with practical wisdom fostered a common intellectual ethos that united the subcontinent.

Social Integration- Beyond philosophy, practical systems like Ayurveda played a unifying role in healthcare, while traditional education through Gurukulas perpetuated cultural values. Institutions such as Nalanda and Takshashila stood as global centers of learning, attracting scholars from diverse regions and cultures. These institutions symbolized India's intellectual wealth and served as hubs for the transmission of knowledge across

generations and geographies. While these structures promoted unity, they also accommodated diversity, allowing regional practices and interpretations to flourish within a broader cultural framework. This inclusivity was the hallmark of pre-colonial Indian society, exemplifying a dynamic balance between unity and diversity.

Disruption by Colonialism- The advent of British colonialism profoundly disrupted Indian Knowledge Systems (IKS), systematically undermining their relevance and credibility. Through targeted policies and practices, the colonial administration marginalized traditional knowledge and created an intellectual and cultural divide that persists to this day.

Educational Policies- The Macaulay Minute of 1835 marked a decisive shift in India's education system. It advocated for the introduction of English education to create a class of "English-educated Indians" who would act as intermediaries between the British rulers and the local population. This policy sidelined traditional educational institutions like Gurukulas and Madrasas, replacing them with schools that taught Western subjects and disregarded Indian texts, sciences, and philosophies. This alienated Indians from their intellectual heritage.

Economic Exploitation- Under British rule, the economic patronage that sustained IKS was systematically dismantled. Traditional crafts, arts, and scientific practices were devalued in favor of British imports, leading to the decline of indigenous industries and knowledge systems. This economic disruption weakened the institutional frameworks that preserved and transmitted IKS.

Epistemological Marginalization- Colonial ideologies dismissed IKS as "unscientific" and irrational, contrasting them with the supposed superiority of Western science and rationality. This narrative devalued India's intellectual heritage, eroding its legitimacy and creating a divide between tradition and modernity. The cumulative impact was a profound intellectual and cultural rift, relegating IKS to the margins of society and severing India's connection with its knowledge traditions.

Revival during Nationalist Movements- The colonial marginalization of Indian Knowledge Systems (IKS) paradoxically ignited their revival during the late 19th and early 20th centuries. This period saw nationalist leaders harness IKS to counter colonial narratives of inferiority and to foster cultural pride, unity, and resistance.

Spiritual Nationalism and Swami Vivekananda- Swami Vivekananda was a pivotal figure in the revival of IKS, particularly through his articulation of spiritual nationalism. His speeches at the Parliament of the

World's Religions in Chicago (1893) presented India's spiritual and philosophical traditions, emphasizing Vedanta's universal relevance. Vivekananda countered colonial stereotypes of India as backward by showcasing its intellectual and spiritual depth. He called for a resurgence of Indian values, urging Indians to rediscover their self-respect and cultural pride. His vision not only inspired the nationalist movement but also laid the foundation for India's global identity as a land of spiritual wisdom.

Gandhian Thought-Mahatma Gandhi integrated IKS into his philosophy of Swaraj (self-rule). He championed traditional practices like spinning khadi and emphasized self-reliance through indigenous industries, viewing them as both economic and moral resistance to colonial exploitation. Gandhi's approach demonstrated how IKS could be harnessed for practical and ethical resistance.

Sri Aurobindo's Vision-Sri Aurobindo framed nationalism as a spiritual awakening. Drawing from Vedic philosophy, he argued that India's destiny lay in advancing global human consciousness. His writings connected IKS to India's mission of guiding humanity toward higher ideals of freedom and spirituality.

Integral Humanism-Deendayal Upadhyaya's philosophy of Integral Humanism merged traditional knowledge with modern needs. He proposed a holistic model of development grounded in India's cultural ethos, offering a vision for nation-building rooted in inclusivity and tradition.

These leaders revived IKS not only as symbols of resistance but as unifying elements, fostering cultural pride and shaping a shared national identity amidst diversity.

IKS in Contemporary Nationalist Discourses-Indian Knowledge Systems (IKS) continue to play a pivotal role in shaping contemporary nationalist discourses, reflecting their enduring relevance in modern India's socio-political and cultural identity. From educational reforms to global diplomacy, the legacy of IKS remains an integral part of the nation-building process.

Educational Integration-The National Education Policy (NEP) 2020 marks a significant effort to integrate IKS into mainstream education. By emphasizing the inclusion of traditional knowledge in curricula, the NEP aims to bridge the gap between India's ancient intellectual heritage and modern educational practices. This initiative seeks to nurture cultural pride while fostering critical thinking and innovation through interdisciplinary approaches that combine traditional wisdom with contemporary sciences.

Soft Power Strategies-IKS forms the backbone of India's cultural diplomacy, enhancing its global image. Practices like yoga, Ayurveda, and meditation have gained widespread recognition, with initiatives like International Yoga Day showcasing India's soft power on the world stage.

These traditions project India as a leader in holistic wellness and spirituality, reinforcing its cultural and philosophical contributions to the global community.

Economic and Environmental Relevance-IKS offers valuable insights into sustainable development. Traditional agricultural practices, water conservation techniques, and ecological wisdom rooted in ancient texts present viable solutions to contemporary challenges like climate change and resource depletion. Reviving and modernizing these practices can contribute to India's economic and environmental resilience.

Challenges-Despite these successes, challenges persist. Historical caste and class inequalities restrict access to IKS, and the politicization of traditional knowledge risks alienating sections of society. Additionally, some aspects of IKS require validation through rigorous scientific methodologies to gain broader acceptance and applicability in modern contexts.

Addressing these challenges is essential for ensuring that IKS continues to enrich India's cultural identity while contributing to sustainable national and global development.

Challenges to Indian Knowledge Systems (IKS)-While the revival of Indian Knowledge Systems (IKS) has brought renewed recognition, several challenges hinder their full potential in contemporary contexts.

Globalization-The pervasive influence of global cultural and economic models poses a significant threat to the continuity of IKS. Western scientific paradigms and lifestyles often overshadow traditional Indian practices, leading to their marginalization. Additionally, global consumerism dilutes the value of indigenous practices by commodifying them, as seen with yoga being reduced to fitness trends rather than its holistic philosophy.

Social Inequalities-Historically, access to certain aspects of IKS was restricted by caste and class hierarchies. For instance, knowledge of the Vedas and other sacred texts was confined to specific groups. To make IKS inclusive in modern times, these historical barriers must be re-evaluated and dismantled. Inclusive dissemination and democratization of traditional knowledge are essential for its broader relevance.

Politicization-The use of IKS for ideological or political purposes risks alienating sections of society. When traditional knowledge systems are co-opted for partisan agendas, their rich diversity and inclusivity are undermined, potentially polarizing communities rather than uniting them.

Scientific Rigor-While IKS have proven benefits, some aspects require validation through contemporary

scientific methodologies. Bridging the gap between traditional knowledge and modern science is critical for global acceptance and credibility, ensuring that IKS remain relevant and impactful in addressing modern challenges.

Addressing these challenges requires a balanced approach that respects tradition while adapting to modern needs.

Conclusion- The intersection of Indian Knowledge Systems (IKS) and nationalism highlights the profound role of traditional knowledge in shaping cultural identity, fostering pride, and uniting the nation. Historically, IKS served as both a tool of resistance and a foundation for articulating a distinct Indian identity during the colonial struggle. Leaders like Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, and Sri Aurobindo drew from India's intellectual and spiritual traditions to counter colonial narratives of inferiority and to inspire a collective sense of purpose and unity. These systems not only underscored India's civilizational continuity but also became symbols of resilience and renewal.

In contemporary times, the relevance of IKS extends beyond history. Their integration into national policies, such as the National Education Policy (NEP) 2020, and their prominence in global diplomacy through initiatives like International Yoga Day, demonstrate their enduring significance. By showcasing the value of indigenous knowledge in areas like sustainability, holistic health, and ethics, IKS continue to enrich India's soft power and contribute to global discourses.

However, the future of IKS depends on addressing critical challenges. Balancing tradition with modernity is essential to ensure their relevance in an increasingly globalized world. Inclusivity must replace historical caste and class restrictions to democratize access to this knowledge. Moreover, bridging the gap between traditional wisdom and modern scientific validation will enhance their credibility and application in diverse fields.

By revisiting the past and reinterpreting it for the present, this paper emphasizes the potential of IKS to address contemporary national challenges while contributing to global discussions on sustainability, ethics, and cultural diversity. India's traditional knowledge systems, rooted in timeless values yet adaptable to change, offer a framework for achieving not just national progress but also global harmony and understanding.

References -

1. Aurobindo, Sri. *The Renaissance in India and Other Essays on Indian Culture*. Sri Aurobindo Ashram, 1997.
2. Balasubramanian, R. *Indian Philosophy: Past and Future*. Indian Council of Philosophical Research, 1998.
3. Bharati, Dayananda. *The Role of Swami Vivekananda in Indian Nationalism*. Vedanta Press, 2011.

4. Chattopadhyay, Kunal. *Science, Society, and Indian Knowledge Systems*. Orient Blackswan, 2010.
5. Das, Gurcharan. *India Unbound: The Social and Economic Revolution from Independence to the Global Information Age*. Penguin Books, 2002.
6. Gandhi, M.K. *Hind Swaraj or Indian Home Rule*. Navajivan Publishing House, 1938.
7. Ghose, Sisir Kumar. *The Renaissance in India: A Historical and Philosophical Perspective*. Sahitya Akademi, 2008.
8. Kumar, Deepak. *Science and the Raj: A Study of British India*. Oxford University Press, 2006.
9. Mukherjee, Rudrangshu. *The Great Speeches of Modern India*. Random House India, 2011.
10. Narayan, Laxmi. *Integral Humanism and Indian Nationalism*. Concept Publishing Company, 2005.
11. Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy: Volumes 1 and 2*. Oxford University Press, 1951.
12. Rao, T.S. Satyanarayana. *Vedantic Nationalism: Swami Vivekananda's Perspective*. Bharatiya Vidya Bhavan, 1980.
13. Sen, Amartya. *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity*. Farrar, Straus and Giroux, 2005.
14. Sharma, Arvind. *Modern Hindu Thought: The Essential Texts*. Oxford University Press, 2002.
15. Upadhyaya, Deendayal. *Integral Humanism*. Bharatiya Janata Party Publication, 1965.

अंडमान निकोबार की जनजातियाँ और उनकी संस्कृति

डॉ. महेन्द्र कुमार वर्मा

अतिथि प्रवक्ता, हिन्दी विभाग

जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय

श्रीविजयापुरम, अंडमान निकोबार

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण-पूर्व में स्थित एक समुद्री भूभाग है, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के मध्य विस्तृत है। जहाँ निकोबार द्वीप समूह अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या और आधुनिक संपर्कों से जुड़ा हुआ है, वहीं अंडमान द्वीपों में कुछ ऐसी प्राचीन जनजातियाँ निवास करती हैं, जो आज भी अपनी परंपरागत जीवनशैली को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता से दूर जीवन यापन करती हैं। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की प्राकृतिक सुंदरता और जैवविविधता जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही समृद्ध है यहाँ की जनजातीय संस्कृति। विशेष रूप से अंडमान द्वीपसमूह में निवास करने वाली जनजातियाँ अत्यंत प्राचीन, विशिष्ट एवं अनूठी हैं। ये जनजातियाँ आज भी अपने पारंपरिक जीवन के साथ प्रकृति के अत्यधिक निकट रह रही हैं। इनकी जीवनशैली, संस्कृति, भाषा और सामाजिक संरचना भारत की जनजातीय विरासत का एक अमूल्य अंग है। अंडमान की जनजातियाँ मानव सभ्यता की आदिम शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसा अनुमान है कि ये जनजातियाँ लगभग 60,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से प्रवाहित होकर यहाँ पहुँचीं और तब से ही इस भूभाग में निवास कर रही हैं।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में इन जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत असंवेदनशील रहा। विशेषकर ग्रेट अंडमानी जनजाति को जबरन बाहर लाकर उपनिवेशों में काम कराया गया, जिससे उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई। अंडमान में निम्नलिखित पाँच प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं- ग्रेट अंडमानी जनजाति, ओंगी जनजाति, जारवा जनजाति, सेन्टिनली जनजाति, शोम्पेन जनजाति और निकोबारी जनजातियाँ।

'ग्रेट अंडमानी जनजाति' अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है। यह जनजाति कभी अंडमान द्वीपों में फैली हुई कई उपजनजातियों का समूह थी, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत सीमित रह गई है। वर्तमान में यह जनजाति मुख्यतः पोर्ट ब्लेयर के पास स्थित स्ट्रेट द्वीप (Strait Island) में निवास करती है। जो पारंपरिक रूप से ग्रेट अंडमानी लोग जंगलों में अस्थायी झोपड़ियाँ बनाते थे जिन्हें 'चौला' कहा जाता था। झोपड़ियाँ बांस, लकड़ी और पत्तों से बनाई जाती थीं। ये मौसम के अनुसार अस्थायी या स्थायी हो सकती थीं। अब ये लोग सरकार द्वारा बनाए गए पक्के मकानों में रहते हैं, विशेष रूप से स्ट्रेट द्वीप पर। पारंपरिक रूप से पुरुष और महिलाएँ बहुत ही सीमित वस्त्र पहनते थे, जैसे पुरुष कमर में पेड़ की छाल या पत्तों से बना वस्त्र पहनते थे और महिलाएँ कमर से नीचे तक ढकती थीं। आधुनिक समय में सरकार की पहल के बाद अब ये लोग सामान्य कपड़े पहनते हैं। इनके पारंपरिक आहार में शिकार, मछली, जंगल के फल, जड़ें और शहद प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनको कछुए, सूर, मछली, केकड़ा, नारियल, और विभिन्न प्रकार के कंद-मूल खाना ही मुख्य रूप से पसंद था किन्तु अब ये चावल, दाल और अन्य सरकारी आपूर्ति पर भी निर्भर हैं। भाषाई आधार पर देखा जाये तो ग्रेट अंडमानी जनजाति की कई भाषाएँ थीं, जैसे जेरु, बो,

आदि, लेकिन अब इनमें से अधिकांश विलुप्त हो चुकी हैं। अब ये लोग मिश्रित 'ग्रेट अंडमानी हिंदी' बोलते हैं जो उनकी पारंपरिक भाषाओं और हिंदी का मिश्रण है। इनका धार्मिक कर्म प्रकृति पूजा था यह लोग प्रकृति-पूजक होते थे। पेड़, जानवर, सूरज, चाँद आदि को देवता मानते थे और आत्मा, पूर्वजों एवं प्राकृतिक शक्तियों में आस्था रखते थे। किन्तु अब कुछ लोग ईसाई और हिन्दू धर्म को मानने लगे हैं लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक आस्था अब भी इनमें शेष है। त्यौहार और उत्सव की बात करें तो शिकार की सफलता, वर्षा और फसल के समय छोटे स्तर पर उत्सव मनाते थे। लेकिन अब दीवाली, होली आदि भी इनके त्यौहारों में शामिल हैं किन्तु सीमित रूप में। संगीत और नृत्य इनकी संस्कृति का अहम हिस्सा था।

ये लकड़ी के वाद्य यंत्र बजाते थे। इनके पारंपरिक गीतों में प्रकृति, शिकार, युद्ध और प्रेम की बातें होती थीं। इनको अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना, टैटू गुदवाना और प्राकृतिक रंगों से सज्जा करना पसंद था। किन्तु अब यह परंपरा लगभग समाप्त हो रही है। 19वीं सदी में ब्रिटिशों के आगमन के बाद इनकी संख्या में भारी गिरावट आ गई। इसके अलावा रोग, विस्थापन और सांस्कृतिक परिवर्तन भी इनकी जनसंख्या में गिरावट की मुख्य वजह रही है। अब इनकी संख्या बहुत कम रह गई है और इसी वजह से भारत सरकार इन्हें विशेष सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और आवास प्रदान कर रही है। 'ओंगी जनजाति' भी यहाँ की एक प्रमुख जनजाति के रूप में गिनी जाती है। यह जनजाति अंडमान के 'लिटिल अंडमान' द्वीप पर निवास करती है और भारत की उन कुछ आदिवासी जातियों में शामिल है जिनका जीवन आज भी प्रकृति से गहरे जुड़ा हुआ है। आधुनिक सभ्यता के प्रभावों के बावजूद ओंगी जनजाति ने अपने पारंपरिक रहन-सहन और सांस्कृतिक जीवन को काफी हद तक संरक्षित रखा है। ओंगी जनजाति के लोग लिटिल अंडमान के जंगलों और तटवर्ती क्षेत्रों में लकड़ी, ताड़ के पत्तों और बाँस से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। इन झोपड़ियों को स्थानीय भाषा में 'बाहै' कहा जाता है। ये गोल या अर्धगोलाकार आकार की होती हैं और इनका निर्माण जलवायु तथा मौसम को ध्यान में रखकर किया जाता है। ओंगी लोग पारंपरिक रूप से बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष कमर में कपड़ा या छाल लपेटते हैं, जबकि महिलाएँ शरीर को ताड़ या केले के पत्तों से ढकती हैं। शरीर पर गोदना (टैटू) और प्राकृतिक रंगों से सज्जा करना इनकी पारंपरिक पहचान है। वे बालों में फूल, पत्तियाँ और सीपियाँ सजाते हैं। ओंगी जनजाति मुख्यतः शिकारी और खाद्य-संग्राहक जीवनशैली का पालन करते हैं। इनका आहार जंगल से प्राप्त कंद-मूल, फल, शहद, केकड़े, मछली, कछुए आदि पर आधारित होता है। वे समुद्री तटों से मछली पकड़ते हैं और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। अब सरकारी सहायता से उन्हें चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री भी प्राप्त होती है। ओंगी जनजाति की अपनी अलग भाषा है जिसे ओंगी भाषा कहा जाता है। यह अंडमानी भाषा-परिवार से संबंधित है और अत्यंत सीमित लोगों

द्वारा बोली जाती है। अब बहुत से ओंगी लोग अंडमानी हिंदी भी समझने लगे हैं, परंतु उनकी मातृभाषा विलुप्ति के कगार पर है। ओंगी समाज सामूहिकता और सहयोग पर आधारित है। पुरुष शिकार करते हैं जबकि महिलाएँ भोजन संग्रह और बच्चों की देखभाल करती हैं। विवाह प्रथा सरल है और समाज में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव या संपत्ति का संचय नहीं होता। समाज में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। ओंगी लोग प्रकृति-पूजक हैं। उनका विश्वास है कि पेड़-पौधे, जानवर, आकाश, जल आदि सभी में आत्माएँ निवास करती हैं। वे किसी विशेष देवता की पूजा नहीं करते, परंतु प्राकृतिक शक्तियों के प्रति आदरभाव रखते हैं। मृतकों की आत्मा को भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। ओंगी जनजाति विशेष अवसरों पर पारंपरिक गीतों और नृत्यों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट करते हैं। जैसे शिकार में सफलता, बच्चों का जन्म या प्रकृति के साथ सामंजस्य के अवसर पर सामूहिक नृत्य होता है।

यह नृत्य गोल घेरे में होता है, जिसमें पुरुष और महिलाएँ एक साथ भाग लेते हैं। ओंगी जनजाति की कला उनके दैनिक जीवन और परिवेश से जुड़ी होती है। वे प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर शरीर पर चित्र बनाते हैं और मिट्टी, लकड़ी तथा सीपियों से अलंकृत वस्तुएँ बनाते हैं। ये कलाकृतियाँ न केवल सजावट के लिए होती हैं बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी होती हैं। ओंगी जनजाति की जनसंख्या तेजी से घट रही है। जहाँ एक समय इनकी संख्या सैकड़ों में थी, अब यह घटकर लगभग 100 से भी कम रह गई है। जिसकी मुख्य वजह बीमारियाँ, बाहरी प्रभाव और जीवनशैली में आए अचानक परिवर्तनों को माना जा सकता है। भारत सरकार ने इन्हें विशेष संरक्षित जनजाति की श्रेणी में रखा है और इनके लिए 'दुगोंग क्रीक' में एक सुरक्षित बस्ती बनाई है। सरकार द्वारा इन्हें भोजन, दवा, शिक्षा, और आवास की सुविधाएँ दी जाती हैं, किंतु इसके बावजूद उनकी सांस्कृतिक पहचान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

'जारवा जनजाति' अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है, जो मुख्यतः दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के घने वनों में निवास करती है। यह जनजाति भारत की सबसे प्राचीन और पथक समुदायों में से एक मानी जाती है। जिसकी जनसंख्या बहुत सीमित है और जो आधुनिक सभ्यता से काफी हद तक कटी हुई जीवनशैली अपनाए हुए है। जारवा लोग स्थायी मकानों में नहीं रहते। ये झोपड़ियाँ या अस्थायी आश्रय बनाते हैं, जिन्हें ये 'चाड़ा' कहते हैं। बांस, पत्ते और लकड़ी का प्रयोग कर जंगल के भीतर या समुद्र किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनका खान-पान पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। ये शिकारी और संग्रहकर्ता होते हैं। इनका मुख्य भोजन- जंगली फल, शहद, मछली, सूअर, कछुआ, और अन्य जंगली जानवर साथ ही समुद्री शंख, केकड़े और कंद-मूल इनके मुख्य भोजन में सम्मिलित है। जारवा पुरुष पारंपरिक धनुष-बाण से शिकार करते हैं, जबकि महिलाएँ मछली पकड़ने और भोजन संग्रह में मदद करती हैं। जारवा जनजाति वस्त्र बहुत कम पहनते हैं। पुरुष और महिलाएँ कमर के नीचे पेड़ की छाल या पत्तों का उपयोग करते हैं। आभूषणों में ये लोग सीपियों, हड्डियों और लकड़ी से बने हार, कंगन, और बोजबंद पहनते हैं। ये लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति से अनभिज्ञ होते हैं। बीमारियों का इलाज जड़ी-बटियों और पारंपरिक तरीकों से करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहरी संक्रमण है, जिनसे इनका शरीर प्रतिरोध नहीं कर पाता। जारवा जनजाति की अपनी मौखिक भाषा है जिसे 'जारवा भाषा' कहा जाता है। यह किसी अन्य भाषा से संबद्ध नहीं मानी जाती और अत्यंत दुर्लभ है। इसका कोई लिखित रूप नहीं है। इनकी संस्कृति में लोकगीत और नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। उत्सवों, शिकार के बाद, या खुशी के अवसरों पर सामूहिक नृत्य करते हैं। शरीर की थापों और मौखिक ध्वनियों से संगीत रचते हैं।

जारवा समाज सामूहिक और सहयोगात्मक होता है। ये लोग छोटे समूहों में रहते हैं और सभी कार्य सामूहिक रूप से करते हैं। कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, लेकिन बुजुर्गों को सम्मान प्राप्त होता है। इनकी विवाह पद्धति सरल होती है। विवाह सामुदायिक सहमति से होता है। बहुपत्नी विवाह या बाल विवाह जैसी कुप्रथाएँ इनमें नहीं पाई जाती। जारवा जनजाति लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटे रहे, लेकिन हाल के दशकों में अंडमान टंक रोड के कारण इनके क्षेत्र में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इससे इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे- संक्रमण और बीमारियाँ, भूमि और संसाधनों पर अतिक्रमण और सांस्कृतिक क्षरण का खतरा इत्यादि। भारत सरकार ने इन्हें "अनुसूचित जनजाति" घोषित किया है और इनके संरक्षण के लिए "जारवा रिजर्व" क्षेत्र घोषित किया गया है, जहाँ आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ताकि इनकी जनसंख्या को सुरक्षित किया जा सके। जारवा जनजाति एक 'संकटग्रस्त समुदाय' है। इनकी जीवनशैली और संस्कृति को बचाने के लिए सरकार ने कई नीतियाँ बनाई हैं, जैसे- बाहरी संपर्क को न्यूनतम करना, स्वास्थ्य सेवाएँ पहुंचाना लेकिन संपर्क सीमित रखना, अनधिकृत पर्यटन पर रोक तथा उनकी संस्कृति और आत्मनिर्भरता को सम्मान देना आदि।

'सेंटीनेली' जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली एक अत्यंत रहस्यमय और विश्व की सबसे अलग-थलग रहने वाली जनजातियों में से एक है। ये जनजाति 'नॉर्थ सेंटिनल द्वीप' पर निवास करती है, और आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह से कटे हुए जीवन की मिसाल प्रस्तुत करती है। इनके बारे में जानकारी अत्यंत सीमित है, क्योंकि ये बाहरी संपर्क को सख्ती से अस्वीकार करते हैं और अपने क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान द्वीपसमूह का हिस्सा है। यह लगभग 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और घने जंगलों से आच्छादित है। सेंटिनेली जनजाति को 'नेओलिथिक' युग का प्रतिनिधि माना जाता है, जिसका अर्थ है कि ये अभी भी पत्थर युग की जीवन शैली अपनाए हुए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग लगभग 60,000 वर्षों से इस द्वीप पर निवास कर रहे हैं। 'सेंटीनेली' जनजाति लकड़ी, पत्तों और शाखाओं से बनी झोपड़ियों में निवास करती है। इनकी बस्तियाँ जंगलों के भीतर स्थित होती हैं और समुद्र तट से कुछ दूरी पर होती हैं। सेंटिनेली जनजाति का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। वे शिकारी-संग्राहक होते हैं और कृषि नहीं करते। इनका मुख्य भोजन जंगली फल, कंद, शहद, मछलियाँ, सूअर, और कछुए आदि हैं। ये तीर-कमान से शिकार करते हैं और समुद्र में मछली पकड़ते हैं। इनके औजार मुख्यतः पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने होते हैं। तीर-कमान, भाला, और काटने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये लोग वस्त्र नहीं पहनते या बहुत ही सीमित मात्रा में प्राकृतिक साधनों से अपने शरीर को ढकते हैं। शरीर पर आभूषण नहीं होते, परंतु कभी-कभी इनके शरीर पर बांस या लकड़ी से बने गेहने या अन्य चिह्न पहने जाते हैं। सेंटिनेली समाज की संरचना पर कोई पक्की जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु अनुमानतः इनका समाज कबीलाई और सामूहिक जीवन पर आधारित होता है। वे छोटे-छोटे समूहों में रहते हैं। समूह का नेतृत्व संभवतः सबसे अनुभवी या बुजुर्ग सदस्य करता है। विवाह संबंधों और लैंगिक भूमिकाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, परंतु सामान्यतया पुरुष शिकार और सुरक्षा का कार्य करते हैं और महिलाएँ भोजन एकत्रित करने तथा बच्चों की देखभाल में लगी होती हैं। सेंटिनेली जनजाति की संस्कृति उनके पारंपरिक रहन-सहन, विश्वासों और

व्यवहार से प्रकट होती है। हालांकि सीधा संपर्क न होने के कारण इसकी जानकारी सीमित है। सेंटनेली जनजाति की अपनी अलग भाषा है, जिसे अब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। यह अंडमानी भाषाओं से भी भिन्न है। इनके धार्मिक विश्वास रहस्यमय हैं, लेकिन संभवतः ये प्रकृति पूजा करते हैं। सूर्य, समुद्र, पेड़-पौधों को पूजनीय मानते होंगे। कोई प्रत्यक्ष धार्मिक अनुष्ठान नहीं देखा गया है, लेकिन उनके व्यवहारों में सामूहिकता और किसी अनुशासन का पालन स्पष्ट दिखाई देता है। चित्रकला या शिल्पकला के प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु उनके तीर-कमान और अन्य उपकरणों में सुंदरता और उपयोगिता का सम्मिलन देखने को मिलता है। सेंटनेली जनजाति बाहरी संपर्क को पूरी तरह नकारती रही है। 1970 और 1990 के दशकों में भारतीय प्रशासन ने संपर्क की कोशिश की, जिसमें कभी-कभार वे बाहर आए, लेकिन ज्यादातर मौकों पर उन्होंने आक्रामकता दिखाई। 2006 में जब दो मछुआरे गलती से उनके द्वीप के पास चले गए, तो उन्हें मार दिया गया। 2018 में अमेरिकी मिशनरी जॉन एलेन चौ की हत्या ने फिर इस जनजाति को वैश्विक ध्यान में ला दिया। भारत सरकार ने इस जनजाति की सुरक्षा और उनके जीवन के संरक्षण हेतु नॉर्थ सेंटनेल द्वीप को 'प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र' घोषित कर रखा है। वहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। भारतीय संविधान के तहत सेंटनेली जनजाति को संरक्षित जनजाति घोषित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप (आदिवासी संरक्षण) विनियम, 1956 के तहत इन्हें कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। भारत सरकार का दृष्टिकोण 'नो-कॉन्टैक्ट' पर आधारित है, जिससे उनकी जीवनशैली में बाहरी हस्तक्षेप न हो। इन्हें अपने पारंपरिक क्षेत्र में स्वतंत्रता से रहने का अधिकार प्राप्त है। इनकी संस्कृति और परंपरा को नष्ट होने से बचाने के लिए वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सतर्कता बरती जा रही है।

'शोम्पेन जनजाति' एक अत्यंत अल्पज्ञात, सीमित जनसंख्या वाली और मुख्यधारा से पूर्णतः अलग-थलग रहने वाली आदिम जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः ग्रेट निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। शोम्पेन जनजाति को भारत सरकार ने **'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह'** के रूप में वर्गीकृत किया है। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप **ग्रेट निकोबार** में निवास करती है। इनका निवास क्षेत्र मुख्यतः **इन्द्रा पॉइंट** से लेकर **गालाथिया नदी** तक फैला हुआ है। इनकी कुल जनसंख्या अत्यंत सीमित है और यह लगभग 250-300 के आसपास है (आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार)। यह जनजाति सघन वन क्षेत्रों में रहती है और बाहरी दुनिया से संपर्क रखने से कतराती है। शोम्पेन लोग स्थायी बस्तियों में नहीं रहते। वे **अर्ध-घुमंतू जीवन** जीते हैं। ये लोग जंगलों के भीतर बांस, लकड़ी और पत्तों से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। वर्षा ऋतु में वे ऊँचे और सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी झोपड़ियाँ बनाते हैं। शोम्पेन जनजाति मुख्यतः शिकार, मछली पकड़ने, कंद-मूल और फल पर निर्भर रहती है। वे धनुष-बाण और भाले का उपयोग कर सूअर, पक्षियों और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। उनका भोजन पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। वे धान या गेहूँ नहीं उगाते, किंतु कुछ क्षेत्रों में उन्होंने सीमित कृषि करना शुरू किया है जैसे केला, नारियल, हल्दी आदि की खेती। शोम्पेन लोगों के वस्त्र अत्यंत सीमित होते हैं। महिलाएँ आमतौर पर पेड़ों की छाल, घास या सूती कपड़ों से बनी स्कर्ट पहनती हैं जबकि पुरुष कमर में कपड़ा या छाल लपेटते हैं। शरीर पर गहनों के स्थान पर वे कंकड़, सीप, हड्डियों और लकड़ी से बने सजावटी तत्व पहनते हैं। शरीर पर टैट बनवाने की भी परंपरा पाई जाती है। शोम्पेन जनजाति की अपनी विशिष्ट भाषा है, जिसे "शोम्पेन भाषा" कहा जाता है। यह भाषा म्यांमार की कुछ जनजातीय भाषाओं से मिलती-जुलती है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। इनकी भाषा

कोई लिपि नहीं है और यह मौखिक परंपरा पर आधारित है। भाषा के संरक्षण को लेकर सरकार और भाषाविदों द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। शोम्पेन समाज आदिम सामूहिकता पर आधारित है। इनमें कबीलाई संरचना पाई जाती है। उनका समाज पुरुष प्रधान होता है और पारंपरिक मुखिया प्रणाली चलन में है। विवाह संबंधों में बहुपति प्रथा (polyandry) या बहुपत्नी प्रथा (polygyny) के भी संकेत कुछ अध्ययनों में मिलते हैं। परिवारों में सहयोग की भावना बहुत प्रबल होती है। एक-दूसरे के बच्चों का पालन-पोषण सामूहिक रूप से किया जाता है। शोम्पेन लोग प्राकृतिक शक्तियों में गहन विश्वास रखते हैं। वे वृक्ष, नदी, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को पूजनीय मानते हैं। कोई संगठित धर्म नहीं है, लेकिन उनकी मान्यताएँ एनिमिज्म (Animism) पर आधारित हैं। ये आत्मा, भूत-प्रेत, और वनदेवताओं में विश्वास रखते हैं और बीमारियों का इलाज झाड़ू-फूँक या परंपरागत जड़ी-बटियों से करते हैं। शोम्पेन समाज में पारंपरिक **नृत्य और लोकगीत** की परंपरा है। उत्सवों में सामूहिक नृत्य किया जाता है। वे पेड़ों की लकड़ी और जानवरों की खाल से बने वाद्ययंत्रों का उपयोग करते हैं। शोम्पेन जनजाति वर्षा, शिकार या फसल की प्राप्ति के अवसर पर छोटे स्तर पर **अनुष्ठान और उत्सव** मनाते हैं। ये उत्सव पूरे समुदाय को एक सत्र में बाँधते हैं। शोम्पेन जनजाति आज **विलुप्ति के संकट** से जूझ रही है। उनकी परंपरागत जीवनशैली को बाहरी संपर्क, पर्यटन, सड़क निर्माण, बीमारियाँ, सांस्कृतिक क्षरण, विकास परियोजनाओं से विस्थापन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय बदलावों ने प्रभावित किया है। हालांकि सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र अधिनियम, विकास प्रतिबंध, और आरोग्य सेवाओं के कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनकी सफलता सीमित रही है क्योंकि शोम्पेन समुदाय बाहरी हस्तक्षेप को सहजता से स्वीकार नहीं करता। भारत सरकार ने शोम्पेन जनजाति के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे- शोम्पेन हब क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना, संपर्क रहित विकास नीति अपनाना, स्वास्थ्य सेवाओं की मोबाइल इकाइयों का संचालन, जनसंख्या और स्वास्थ्य का नियमित सर्वेक्षण इत्यादि। परंतु इन प्रयासों में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और स्थानीय सहभागिता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। **'निकोबारी जनजाति'** के लोग निकोबार द्वीप समूह में बसी हुई हैं और इनकी जीवनशैली, संस्कृति, रीति-रिवाज, और सामाजिक संरचना इन्हें विशिष्ट बनाती है। भारत सरकार द्वारा इन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। निकोबारी जनजाति की संस्कृति प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक सहयोग और पारंपरिक आस्थाओं पर आधारित है। इनकी संस्कृति भारतीय आदिवासी जीवन का एक प्राचीन और जीवंत रूप प्रस्तुत करती है। निकोबारी जनजातियाँ मुख्यतः नारकोंडम, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, कैमोर्टा, कोंडुल और चौरा द्वीपों में निवास करती हैं। इनमें सबसे अधिक आबादी कार निकोबार द्वीप में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निकोबार द्वीपों की कुल जनसंख्या में निकोबारी जनजातियों की संख्या लगभग 30,000 के आसपास थी। निकोबारी लोग पारंपरिक झोपड़ीनुमा घरों में रहते हैं जिन्हें "मचानों" पर बनाया जाता है। ये घर बांस, लकड़ी और पत्तों से बने होते हैं तथा ज़मीन से कुछ ऊँचाई पर बने होते हैं ताकि वर्षा जल और कीटों से सुरक्षा मिल सके। घर गोल या अष्टकोणीय आकार में होते हैं और छत पाम या नारियल की पत्तियों से बनी होती है। इनका मुख्य भोजन नारियल, केला, मछली, सूअर और समुद्री जीव-जंतु होते हैं। चावल इनकी भोजन व्यवस्था में बाद में शामिल हुआ। भोजन सामूहिक रूप से तैयार किया जाता है और अधिकांशतः उबालकर या आग में भूनकर खाया जाता

है। पुरुष प्रायः लुंगी या धोती पहनते हैं, जबकि महिलाएँ लंबी स्कर्ट और ब्लाउज पहनती हैं। आधुनिकता के प्रभाव से अब कुछ लोग पश्चिमी परिधान भी पहनने लगे हैं, लेकिन पारंपरिक परिधान आज भी उत्सवों व अनुष्ठानों में पहने जाते हैं। निकोबारी समाज में **मुखिया प्रणाली** प्रचलित है। गाँव के मुखिया को “Captain” कहा जाता है और यह प्रशासनिक एवं सामाजिक मामलों का नेतृत्व करता है। उनके सामाजिक जीवन में **विवाह, जन्म, मृत्यु और त्यौहार** सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। निकोबारी जनजातियों की धार्मिक आस्थाएँ प्राचीन प्रकृतिपूजक विश्वासों पर आधारित रही हैं। हालांकि वर्तमान में ईसाई धर्म (मुख्यतः कैथोलिक) का प्रभाव बहुत व्यापक है। ये लोग मुख्यतः आत्मा और पुनर्जन्म, समुद्र, जंगल, सूर्य और चंद्रमा की पूजा, **टोना-टोटका और भूत-प्रेत** की अवधारणा पर यकीन रखते हैं। 20वीं शताब्दी में मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ और आज अधिकांश निकोबारी जनजाति ईसाई धर्म मानती है। चर्च इनकी सामाजिक संरचना का एक हिस्सा बन चुका है। इनका सबसे प्रमुख त्यौहार “**पिग फेस्ट**” (सूअर उत्सव) है। यह एक पारंपरिक त्यौहार है जिसमें समुदाय के लोग मिलकर सूअर का पालन करते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। यह उत्सव समूह की एकता और सहयोग का प्रतीक है। अन्य उत्सवों में ईसाई धर्म के त्यौहार जैसे क्रिसमस और ईस्टर भी पूरे उल्लास से मनाए जाते हैं। निकोबारी जनजाति के लोग बांस और लकड़ी से वस्तुएँ बनाते हैं। उनके हस्तशिल्प में नाव बनाना, टोकरी बुनाई और हथियार निर्माण की कला देखने को मिलती है। महिलाएँ पारंपरिक बुनाई में पारंगत होती हैं और चटाइयाँ, टोकरियाँ और झोले बनाती हैं। हाल के वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से निकोबारी समाज में परिवर्तन आया है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएँ विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। हालांकि, 2004 की सुनामी के बाद इस जनजाति को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिससे इनकी सामाजिक और आर्थिक संरचना प्रभावित हुई। सरकार द्वारा पुनर्वास कार्यक्रमों से सुधार आया है। निकोबारी लोग निकोबारी भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें कई स्थानीय उपभाषाएँ हैं। भारत सरकार द्वारा निकोबारी जनजातियों के लिए विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं जैसे- जनजातीय विकास परियोजनाएँ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण हेतु शोध एवं प्रलेखन कार्यक्रम।

अंडमान की जनजातियाँ मानव जाति की आदिम जीवनशैली और संस्कृति की जीवित मिसाल हैं। इनका अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर भी जीवन जिया जा सकता है। इन जनजातियों का संरक्षण केवल मानवविज्ञान की दृष्टि से नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी है। हमें इनके जीवन में हस्तक्षेप के बजाय, इनके अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए संरक्षण करना चाहिए।

नोट:- यह आलेख साक्षात्कार और अंतरजाल से मिली जानकारी पर आधारित है।

सामाजिक-आर्थिक विकास पर इंदिरा आवास योजना की भूमिका का अध्ययन

मुकेश वर्मा¹

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग
एम०बी० जी० पी०जी० कालेज
हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

डॉ० रीन रानी मिश्रा²

प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
एम०बी० जी० पी०जी०
कालेजहल्द्वानी, नैनीताल,
उत्तराखण्ड।

सारांश-

वर्तमान समय में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलायी जा रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र “सामाजिक-आर्थिक स्थिति विकास पर इंदिरा आवास योजना की भूमिका का अध्ययन” को समस्या के रूप में लिया गया है, जिसके लिये वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया एवं शोध न्यादर्श के रूप में 100 लाभार्थियों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया। शोध कार्य से सम्बंधित आकड़ों के संकलन के लिये स्व:निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति विकास पर इंदिरा आवास योजना के माध्यम से आवास प्राप्त होने के पश्चात् उनकी सामाजिक-आर्थिक विकास में काफी सुधार हुआ है।

प्रमुख शब्द:- इंदिरा आवास योजना, सामाजिक-आर्थिक विकास।

प्रस्तावना

प्रकृति के प्रांगण में आवास या घर मनुष्य की महत्वपूर्ण अहम आवश्यकताओं में से एक है। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि “आवास के बिना मनुष्य का भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकास नहीं हो सकता है।” इस प्रकार आवास, मानव के विकास और स्थायित्व का अभिन्न अंग है। मानव के लिए आवास या घर एक बुनियादी आवश्यकता है। एक सामान्य नागरिक, जिसके पास अपना आवास या घर है अर्थात् उसके पास सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक दर्जा प्राप्त होता है। बिना आवास या घर के आदमी के लिए एक मकान उसके अस्तित्व में आमूल-चूक परिवर्तन लाता है, उसे एक पहचान दिलाता है, जिससे वह अपने आस-पास के सामाजिक परिवेश के साथ जुड़ जाता है।

समाज में रहने वाले अनेक न्यूनतम-आय-वर्ग के लोगों के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के सन्दर्भ में आर्थिक विकास का अर्थ है उनके विकास क्रम को आत्म-पोषित बनाना, भूख और निर्धनता से छुटकारा दिलाना तथा रहने के लिए एक आवास या घर उपलब्ध कराना। परिवार के सिर पर एक छत का होना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आवास न सिर्फ रहने के लिए बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से मनुष्य के सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य के अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक-दूसरे के पूरक रूप में देखा जाता है। निजी क्षेत्र में संगठित उद्योग, लघु उद्योग, कृषि, व्यापार और गृह निर्माण तथा संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं। विकास के राष्ट्रीय प्रयास में व्यक्तिगत कोशिश और निजी पहल को आवश्यक और वांछित माना जाता है और इसके साथ ही साथ अधिकतम स्वैच्छिक सहयोग को भी अनिवार्य समझा जाता है। देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी दोहन, उत्पादन, वृद्धि और समाज के हित में सभी के लिए

रोजगार के अवसर पैदा करके लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा घोषित लक्ष्य के अनुसरण करने के निमित्त मार्च, 1950 के एक संकल्प के जरिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग देश के उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तय करने के लिए योजनाएँ बनाने का दायित्व सौंपा गया था।

अध्ययन के उद्देश्य-

- इंदिरा आवास योजना समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ-

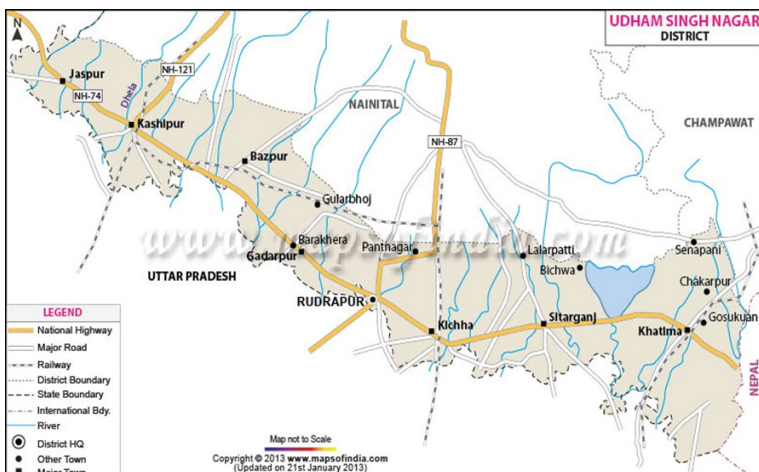
- इंदिरा आवास योजना समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करती है।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर समान प्रभाव पडा।

शोध विधि-

किसी भी शोध कार्य को करने के लिये किसी न किसी शोध विधि का प्रयोग किया जाता है। बिना शोध विधि का प्रयोग किये किसी भी शोध अध्ययन को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोध विधि के रूप में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का न्यादर्श-

लोकतांत्रिक व्यवस्था में गांव सबसे छोटी इकाई है। इस इकाई के माध्यम से ही ग्राम स्तर की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ग्राम पंचायतों की उपादेयता इसलिये भी है कि इसका ग्रामीणों के साथ सीधा सम्बन्ध होता है तथा रोजगार उपलब्ध कराने में यह इकाई लाभार्थियों का चयन कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ती है। प्रस्तुत शोधपत्र मे ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के 100 लाभार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में दैव निर्देशन $\frac{1}{4}$ Random Sampling $\frac{1}{2}$ विधि द्वारा किया गया है।



तालिका संख्या-1

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण

आवास आवंटन का वर्ष	चयनित लाभार्थी				कुल योग
	महिला	महिलाओं का प्रतिशत	पुरुष	पुरुषों का प्रतिशत	
2021-22	20	71.43	8	28.57	28
2022-23	27	79.41	7	20.59	34
2023-24	24	63.16	14	36.84	38
कुल योग	71	71.00	29	29.00	100

उपरोक्त तालिका 1 में प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध अध्ययन क्षेत्र ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के कुल चयनित 100 लाभार्थियों में से कुल 28 चयनित लाभार्थियों के आवास वर्ष 2021-22 में निर्मित किये गये है, जिसमें से 20 अर्थात 71.43 प्रतिशत आवासों का आवंटन परिवार की महिला मुखिया के नाम है तथा 7 अर्थात 20.59 प्रतिशत आवास परिवार के पुरुष के नाम आवंटित किये गये है। वर्ष 2022-23 में कुल 37 लाभार्थियों के आवास इस आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये हैं, जिनमें 27 अर्थात 79.41 प्रतिशत आवासों की मुखिया महिला सदस्य है तथा शेष 7 अर्थात 20.59 प्रतिशत आवास के मुखिया पुरुष सदस्य है। वर्ष 2023-24 में कुल 38 लाभार्थियों को चयनित करके आवासों के निर्माण का कार्य किया गया, जिनमें 24 अर्थात 63.16 प्रतिशत आवास महिला सदस्यों के नाम है तथा 14 अर्थात 36.84 प्रतिशत आवास पुरुष सदस्यों के नाम पर आवंटित किये गये है। इस प्रकार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के द्वारा चयनित विकासखण्डों में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिये मे इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के नाम आवास आवंटित होने के पश्चात् उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis) Ho- “इंदिरा आवास योजना समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करती है।” सत्य सिद्ध होती है और वैकल्पिक परिकल्पना (Alternative Hypothesis) Ha- “इंदिरा आवास योजना समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत आधार नहीं प्रदान करती है।” असत्य सिद्ध होती है।

तालिका-2

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जातिवार आंवटित किये गये आवासों का विश्लेषण

चयनित लाभार्थियों की जाति	चयनित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत	सचयी प्रतिशत
सामान्य	12	12.00	12.00
अनुसूचित जाति	41	41.00	53.00
अनुसूचित जन जाति	17	17.00	70.00
अन्य पिछड़ी वर्ग	21	21.00	91.00
अल्प संख्यक वर्ग	9	9.00	100.00
कुल चयनित लाभार्थियों की संख्या	100	100.00	

उपरोक्त तालिका संख्या 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शोध अध्ययन क्षेत्र ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के कुल चयनित 100 लाभार्थियों में से कुल 12 अर्थात् 12.00 प्रतिशत आवास सामान्य जाति वर्ग के, 41 अर्थात् 41.00 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति वर्ग के, 17 अर्थात् 17.00 प्रतिशत आवास अनुसूचित जन जाति वर्ग के, 21 अर्थात् 21.00 प्रतिशत आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के तथा 9 अर्थात् 9.00 प्रतिशत आवास अल्प संख्यक वर्ग के लाभार्थियों के लिये निर्मित किये गये। इस प्रकार पाया गया कि इंदिरा आवास योजना में सबसे अधिक आवास अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिये बनाये गये है। इस प्रकार यहाँ हमारी शून्य परिकल्पना की मान्यता गलत सिद्ध होती है अर्थात् हम अपनी वैकल्पिक परिकल्पना के साथ जायेंगे जो सत्य सिद्ध होती है कि इंदिरा आवास योजना में सभी वर्गों को समान रूप से आवास आंवटित नहीं किये गये है, क्योंकि इस योजना में सबसे अधिक आवास अनुसूचित वर्ग के लोगों को आंवटित किये गये है, इसके साथ ही इंदिरा आवास योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यह योजना समाज में पिछड़े तथा निर्धन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिये चलायी गयी है तथा यहां यह योजना की सफलता को प्रदर्शित करता है। इंदिरा आवास योजना के माध्यम से समाज में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सबसे अधिक प्राथमिकता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात हुआ कि इंदिरा आवास योजना में सबसे अधिक आवास अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिये आंवटित किये गये है तथा अन्य जाति वर्गों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की अपेक्षा कम संख्या में आवासों का आंवटन किया गया है। इस प्रकार यहाँ शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis) Ho “इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों को समान रूप से आवास आंवटित किये गये है।” गलत सिद्ध होती है और वैकल्पिक परिकल्पना (Alternative Hypothesis) Ha- “इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों को समान रूप से आवास आंवटित नहीं किये गये है।” सत्य सिद्ध होती है कि इंदिरा आवास योजना में सभी वर्गों को समान रूप से आवास आंवटित नहीं किये गये है, क्योंकि इस योजना में सबसे अधिक आवास अनुसूचित वर्ग के लोगों को आंवटित किये गये है तथा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह योजना समाज

पिछड़े तथा गरीब व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लाने के लिये चलाई गयी जा रही है। इंदिरा आवास योजना के द्वारा समाज में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ है जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उनके रहन-सहन में भी परिवर्तन में भी काफी सुधार देखा गया है, जो कि इंदिरा आवास योजना की सफलता को दर्शाती है।

शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष— प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी के द्वारा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के सर्वेक्षण के लिये ऊधमसिंह नगर जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के कुल 100 लाभार्थियों का चुनाव यादृच्छिक न्यादर्शन विधि के द्वारा किया गया। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित है-

शोध अध्ययन हेतु चयनित ऊधमसिंह नगर जनपद के गदरपुर में वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2023-24 के दौरान सबसे अधिक आवासों का निर्माण वर्ष 2022-23 में किया गया है। कुल चयनित 100 लाभार्थियों में से कुल 27 लाभार्थियों के आवास वर्ष 2022-23 में बनाये गये है, अर्थात् कहाँ जा सकता है कि समय के साथ-साथ लोगों में इंदिरा आवास योजना के प्रति जागरूकता भी लगातार बढ़ती जा रही है। कुल चयनित 100 लाभार्थियों के निर्मित आवासों में से 41 आवास अनुसूचित जाति के लोगों के है अर्थात् इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सबसे अधिक लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार द्वारा भी इस इंदिरा आवास योजना के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक आवास आंवटित किये जा रहें है। प्रत्येक वर्ष होने वाली जनसंख्या वृद्धि से आवासों की होने वाली कमी को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

ऊधम सिंह जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के कुल चयनित 100 लाभार्थियों में से 71 महिला लाभार्थी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इंदिरा आवास योजना में महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है तथा इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

प्रायः व्यक्तियों में केन्द्र तथा राज्य सरकार के द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी पायी जाती है, परन्तु फिर भी इंदिरा आवास योजना के बारे में व्यक्तियों में जागरूकता को अधिक देखा गया है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, एस०के० (1990), हमेन राइट टू हाउसिंग प्रोसेस, कुरुक्षेत्र, मई-जून, पृष्ठ सं०-131
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन, (1998), द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, जेनेवा, पृष्ठ सं०-127।
3. भारत सरकार योजना आयोग, (1999-2000). पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ सं० 178।
4. त्रिपाठी नन्दन केसरी एवं कुमार आलोक, 'उत्तराखण्ड एक समग्र अध्ययन', बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, जुलाई 2013-14, पृष्ठ सं० 4-20।
5. त्रिपाठी नन्दन केसरी एवं कुमार आलोक, 'उत्तराखण्ड एक समग्र अध्ययन', बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, जुलाई 2013-14, पृष्ठ सं० 208।
6. अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तराखण्ड, 'सांख्यिकी पत्रिका- पत्रिका-2020-21, जनपद ऊधमसिंह नगर', पृष्ठ संख्या 92।
7. एक्सपर्ट्स, दिशा (2020), द मेगा ईयर बुक 2018, दिशा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृष्ठ सं० 132।

Geology and Geological Perspective in Ancient India: A Multidimensional Approach

T.N. MISHRA¹

Ex-Director, Mines and Geology
Government of Bihar India

SAURABH SHUBHAM²

Research Scholar
University of Hyderabad India

Abstract- This paper explores the geological know-how embedded within the highbrow, economic, non secular, and medical traditions of historic India. Through a multidimensional lens, the observe investigates the remedy of geological phenomena throughout historic texts which include the Arthashastra, Brhat Samhita, Vastu Shastra, and Puranas, at the same time as additionally thinking about archaeological, metallurgical, hydrological, and agronomic practices. Contrary to the belief that geological sciences advanced completely within the cutting-edge era, the proof offered herein shows that historic India possessed a complicated and holistic method to earth sciences, integrating empirical remark with metaphysical and ecological frameworks. This research contributes to the wider discourse on indigenous medical know-how structures and their relevance to cutting-edge environmental and geoscientific inquiry.

1. Introduction

Geology, as a proper medical discipline, is regularly considered as a manufactured from the Enlightenment era. However, historic civilizations, which include India, advanced deep empirical and philosophical insights into geological processes. This paper provides a multidisciplinary evaluation of geological views in historic India, analyzing how geological know-how turned into conceptualized, recorded, and applied.

2. Philosophical and Cosmological Frameworks

The Panchamahabhuta Theory- Indian philosophy articulated the universe thru the panchamahabhuta doctrine: earth (prithvi), water (ap), hearthplace (tejas), air (vayu), and space (akasha). The Vaisheshika Sutras, attributed to Kanada (circa 2d century BCE), classify earth because the substratum of odour and solidity, suggesting an essential category of geological materials.

Cosmological Myths and Geodynamics- Mythological texts which include the Vishnu Purana and Bhagavata Purana describe the Earth as composed of islands (dvipa), mountains, and oceans, conceptualizing a geospatial shape prompted with the aid of using geological remark. These resourceful geographies regularly reflected actual geological know-how embedded inside symbolic narratives.

Textual Evidence of Geological Observations

The Arthashastra and Resource Geology

Kautilya's Arthashastra (c. third century BCE) gives realistic commands for finding ores, figuring out geological symptoms and symptoms like rock color, mineral efflorescence, and spring water properties. It classifies land with the aid of using productiveness and aid potential, highlighting an early survey methodology.

Varahamihira's Brhat Samhita

In the Brhat Samhita (sixth century CE), Varahamihira information geological phenomena, which include earthquakes, groundwater, and minerals. His category of earthquakes primarily based totally on causative elements and observational symptoms and symptoms—which include animal conduct and atmospheric changes—displays a scientific empirical tradition.

3. Vastu Shastra and Geotechnical Engineering

Vastu Shastra texts just like the Manasara endorse soil checking out through colour, texture, and odour, prescribing suitability for foundations. The integration of soil technology and structure shows early focus of geotechnical principles.

4. Mineralogy, Mining, and Metallurgy

Gemology in Ancient Texts

Texts which include the Garuda Purana and Ratnapariksha classify minerals and gems with the aid of using color, luster, hardness, and origin. Techniques just like the scratch check and visible inspection had been used to assess gem quality.

Archaeological Mining Evidence- Mining sites which include Khetri (Rajasthan) and Zawar (Udaipur) display large-scale historic mining. The latter consists of proof of zinc distillation strategies from the first millennium

CE.

Metallurgical Knowledge

Wootz metal manufacturing in Tamilakam and the corrosion-resistant Delhi Iron Pillar exemplify superior fabric technology. Knowledge of ore processing and alloy composition implies a complicated know-how of geology and chemistry.

5. Hydrology and Geological Substrates

Traditional Water Systems

Ancient water management—which include stepwells, tanks, and aqueducts—demonstrates geological literacy. Structures had been constructed on impermeable rock or designed to engage optimally with geological strata.

Indigenous Hydrogeology

The Brhat Samhita describes strategies to discover groundwater thru plant life indicators, soil moisture, and animal conduct. These practices correlate with cutting-edge hydrogeological strategies.

6. Agricultural Geoscience and Pedology

Soil Classification in Ancient Agriculture

Agricultural texts like Krishi-Parashara and Vrksayurveda categorize soil into types—syama (black), rakta (red), pandu (yellow), and kapila (brown)—primarily based totally on texture and fertility.

Geological Awareness in Farming Practices

Geological capabilities prompted agricultural layouts: terracing in hill areas, bunding in dry zones, and soil amendments in riverine areas. Such integration of agronomy and geology shows systemic environmental adaptation.

7. Seismology and Volcanology

Early Earthquake Theories

Varahamihira categorizes earthquakes as originating from divine, terrestrial, or climatic causes. Though pre-medical, those classifications mirror eager environmental remark.

Volcanism and Cultural Memory

Texts point out subterranean hearthplace and agni-kundas (hearthplace pits), likely echoing recollections of volcanism or geothermal activity, mainly in areas close to the Deccan Traps.

8. Sacred Geography and Geological Determinism

Sacred Sites and Unique Formations

Many pilgrimage facilities are placed close to precise geological formations: Amarnath's ice stalagmite, Gaya's basalt formations, and Badrinath's warm springs. These places sacralize geological phenomena.¹⁵

Stone Selection in Temple Architecture

Temple production hired region-unique stones: granite (South India), basalt (Maharashtra), sandstone (Madhya Pradesh). Choices had been knowledgeable with the aid of using structural integrity, aesthetic value, and availability.

9. Environmental Ethics and Earth Stewardship

Earth as Divinity

The Atharvaveda personifies Earth as a nurturing mother, and the Mahabharata extols Bhumi Devi. This ethical-theological framework promoted conservation and reverence for the land.

Rainwater Harvesting

In ancient India, people used advanced techniques to collect rainwater sustainably. They built stepwells, tanks, ponds, and reservoirs such as baolis, johads, and kunds to gather and save rainwater. These old-fashioned methods showed smart thinking about the environment, made sure there was water all year long, and encouraged communities to work together to take care of natural resources in different areas altogether.

Geoconservation by Ritual Practices

Sacred groves (devrai), water bodies, and woodland patches had been preserved thru non secular taboo and neighborhood mythologies. Often placed close to ecologically or geologically touchy areas, those practices supported casual conservation.

Comparative Perspectives and Contemporary Relevance-

India's historic geological idea compares with Chinese flood manipulate theories and Greek mineralogy. Its forte lies in holistic integration—linking aid use, cosmology, and ethics. This included version gives insights for sustainable geoscientific tactics today.

Conclusion

Ancient India verified a deep, multidimensional know-how of geology. Through its texts, technologies, non secular practices, and structure, geology turned into woven into the cultural and highbrow fabric. Revisiting those views complements our appreciation of indigenous technology and gives treasured options to cutting-edge extractivist paradigms.

SELECT BIBLIOGRAPHY

1. Atharvaveda, Book 12, Hymn 1.
2. Madhav Gadgil and V.D. Vartak, "Sacred Groves of India: A Plea for Continued Conservation," *Journal of the Bombay Natural History Society* 72, no. 2 (1975).
3. Diana Eck, *India: A Sacred Geography* (New York: Harmony Books, 2012)
4. Piccardi, Luigi, and W. Bruce Masse, eds. *Myth and Geology*. London: Geological Society, 2007.
5. A. K. Bag, ed., *Science and Technology in Ancient India* (New Delhi: Indian National Science Academy, 1985).
6. D.D. Kosambi, *An Introduction to the Study of Indian History* (Mumbai: Popular Prakashan, 1956).
7. Varahamihira, *Brhat Samhita*, Chapter 54
8. Kautilya, *Arthashastra*, trans. R. Shamasastri (Bangalore: Government Press, 1915)
9. Debiprasad Chattopadhyaya, *Science and Society in Ancient India* (Calcutta: Research India Publications, 1977).
10. Ludo Rocher, *The Puranas* (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1986).

दलित साहित्य में दलित चिन्तन का उभरता स्वर

शिल्पा भाटिया

शोधार्थी, हिंदी विभाग
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

डॉ. मलकीयत सिंह

सह-आचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

शोध-सार :- साहित्य मानवीय चित्तवृत्तियों, सरोकारों और मनोभावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। साहित्य तब भी था जब लिखित भाषा का विकास नहीं हुआ था। मानव ने मौखिक परम्परा से ही अपनी अनुभूतियों को विविध माध्यमों से वाणी प्रदान की। आज लिपि के विकास के कारण विश्व की प्रत्येक भाषा में साहित्य रचना हो रही है। जिससे विभिन्न मानवीय सरोकारों के प्रति चिन्तन हो रहा है। आज साहित्य मात्र क्षणिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र नहीं रहा अपितु इसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी सार्थक पहल हुई है जिसमें हाशिये पर जीवन व्यतीत कर रहे दलित वर्ग एवं स्त्री विमर्श प्रमुख है। वर्षों से समाज में एक ऐसा वर्ग है, जो सदियों से लगातार शोषण और अपमान का शिकार हो रहा है। इस शोषित, अपमानित और घृणित वर्ग को दलित नाम दिया। आज के समय में दलित विमर्श अत्यंत सक्रिय विषय बना है। समाज और साहित्य में इस विमर्श को एक अलग पहचान मिली है। इसके लिए कई संगठन बन चुके हैं, जो आंदोलनों का रूप ले रहे हैं। सम्भवतः जिसका असर समाज, साहित्य और राजनीति पर भी पड़ रहा है। दलित विमर्श की आवश्यकता क्यों रही होगी, क्यों इतने विमर्शों में दलित विमर्श साहित्य के रूप में उभर कर सामने आया? इन सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयत्न किया गया है। दमन वर्ग के आधार पर ही नहीं हुआ है, बल्कि स्त्री, मजदूर, रंग आदि को भी आधार बनाकर शोषण किया गया।

बीज-शब्द:- दलित, शोषित, उत्पीड़न, वर्ण, दमन, आन्दोलन, समाज, जाति, हक, विमर्श, स्त्री, मजदूर और किसान आदि।

विषय-वस्तु:- दलित वे हैं जिनका दमन हुआ है, जो शोषित हैं या फिर जिनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा हो। कोई भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार जन्म या मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म के लिए, परिवार, जाति, समाज और देश को नहीं चुन सकता है। व्यक्ति का जहाँ जन्म होता है। उसी परिवार और समाज की संस्कृति और व्यवहार से सीखता है, और उसका आत्मसात करता है। जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था का सहारा लेकर कुछ लोग निम्न वर्ग के लोगों का दमन और शोषण सदियों से करते आ रहे हैं। जिस कारण आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के व्यवहार को आत्मसात करते हुए, निम्न वर्ग का शोषण करना अपना अधिकार समझते हैं। निम्न वर्ग की मानसिकता भी शोषण सहते – सहते यही हो चुकी है कि शोषित होना उनका भाग्य है। इसी पर चिन्तन करते हुए बहुत से आन्दोलन हुए। जिसमें ज्योतिराव गोविंदराव फुले, डॉ अम्बेडकर, पेरियार के, राम कृष्ण पिल्लई और सी.वी.रमन पिल्लई आदि का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। चिन्तन का सम्बन्ध दृष्टि से है। किसी भी विषय को समझने का प्रयास चिन्तन है। दलित साहित्य जिजीविषा और आत्मसमान का साहित्य है। दलित साहित्य में दलितों ने अपनी पीड़ा को एक वाणी का रूप देने

प्रयास किया है और अपने जीवन संघर्ष और यथार्थ को सामने लाने का प्रयास किया है। यह अन्य विषयों की तरह 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के लिए नहीं अपितु जीवन जीने के लिए किये जाने वाले संघर्ष और आन्दोलन पर आधारित साहित्य है। दलित विमर्श के केंद्र बिन्दु में वे सभी सवाल आते हैं, जो भेदभाव से सम्बन्धित हैं चाहे भेदभाव जातिगत हो, रंग के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर ही क्यों न हो दलित विमर्श के अंतर्गत आते हैं। ये जातिगत भेद श्रम के आधार पर ही नहीं श्रमिकों में भी भेद करते हैं।

दलित शब्द उन सभी के लिए उपयुक्त है, जिनका दमन हो रहा है। वे सभी दलित हैं, फिर वो स्त्री हो, मजदूर हो, किसी दफ्तर का कर्मचारी हो या फिर कोई पंचम वर्ण का हो। लेकिन साहित्य में बहुत से विमर्शों को मुद्दा बनाया है जिसमें दलित विमर्श भी एक है। जो किसी जाति वर्ग पर आधारित है। जाति को समाज ने कितना महत्वपूर्ण माना है, यह मोहनदास नैमिशराय की आत्मकथा 'अपने-अपने पिंजरे' में बताया है। "आदमी जब पैदा होता है, उसकी जाति लिखाई जाती है और मरने पर भी। यही जाति पहले सरकारी रजिस्टर में ही होती है या लोगों के दिलों में। "यह पंक्तियाँ हमें समाज की मानसिकता को दर्शाती हैं कि जाति के आधार पर ही समाज में किसी व्यक्ति के लिए सम्मान होता है। व्यक्ति का चरित्र और गुण महत्व नहीं रखते, बल्कि जाति सर्वोपरि है। इसी जातिवाद की भावना को आधार बनाकर जो अन्याय और शोषण समाज में हो रहा है। उसके विरोध में साहित्य तथा आंदोलनों का सहारा लिया गया। डॉ अम्बेडकर ने दलितों के आत्मसमान और उनके हक को दिलाने के लिए अनेक प्रयास किये। लेकिन उनका मानना था, कि जब तक खुद लोगों को एहसास नहीं होगा कि उनके साथ गलत हो रहा है और उनके अन्दर आत्मसमान की भावना जागृत नहीं होगी। तब तक उनके द्वारा किये गये प्रयासों का कोई अर्थ नहीं है। डॉ बी.आर.अम्बेडकर का मानना था कि शोषण को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है और साथ ही अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय पर आवाज उठा सकते हैं।

निम्न वर्ग के लोग अस्पृश्यता और लगातार शोषित होने के कारण समाज के सामने अपनी जाति का सच छुपाता है। एक बेटा अपने दोस्तों के सामने अपने पिता से नजरे नहीं मिलाता। क्योंकि उसको लगता है कि पिता को सर पर बोझा ढोते देख या मजदूरी करते देख, उसकी जाति का सच सामने आ जाएगा, जिससे समाज और मित्रों की दृष्टि में घृणा का पात्र बनेगा।

ओमप्रकाश वाल्मीकि कि जूठन खंड दो में इसी मानसिकता को दिखाया है, कि किस प्रकार कंपनी में लोगों से जाति छुपा के कार्य किया जा रहा है। अपने समाज को भी छोड़ दिया गया है ताकि दफ्तर और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। "यदि मेरे से बात करने से

आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो कृपया आगे से हम नहीं मिलेंगे लेकिन साथ ही वाल्मीकि जी ने निम्न वर्ग को उनकी शक्ति का एहसास भी करवाया है, "जाति को लेकर समाज में जो स्थिति है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। जितना डरोगे लोग उतना तुम्हें डराएँगे। एक बार मन से डर निकाल दो, फिर देखो तुमसे डरने लगेंगे।"²

यह समाज का कड़वा सच है। जहाँ किसी की कमजोरी देखेंगे, उसकी कमजोरी का फायदा उठा कर शोषण करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ हम अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू करते हैं हमारी शक्ति का एहसास शाषित वर्ग को भी हो जाता है। समाज में जितना अपराधी शाषित वर्ग है उतना ही अपराध का हिस्सेदार शाषित वर्ग भी है। क्योंकि वो अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। हमने खुद शाषित वर्ग को हक दिया शाषण करने का अपना आत्मसमान खुद उनके सामने गिरवी रख दिया। उच्च वर्ग का छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग, निम्न वर्ग के लोग उनके सामने सर झुकाते हैं। इस गुलामी का चित्रण हम सुखवीर सिंह द्वारा रचित कविता बयान बाहर कविता के माध्यम से समझ सकते हैं -

जब कोई दो कोड़ी /दस बीघे या चार हवेली
का मालिक रास्ते से गुजरे

तो खुदबखुद फुर्ती से/ किनारे हट कर
बाअदब बामुलाहिजा होशियार के लहजे में
सलाम बजानी है।

खुद चाहे कीचड़ में/ कांटो में/ खड़े रहें एक पाँव
पर अलग हटकर

जाति कि श्रेष्ठता में अकड़े हुए

नीच से नीच व्यक्ति के लिए भी राह बनानी है।³

उच्च वर्ग का चपरासी भी निम्न वर्ग के उच्च अधिकारी को खुद से तुच्छ समझता है। व्यक्ति और समाज का मूल्यांकन जातिगत आधार पर किया जाता है, ना कि उसके गुणों के आधार पर। देखा जाए तो मूल वैदिक काल में आर्य, ब्राह्मण और वैश्यों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। "ऋग्वेद काल में शूद्र तिरस्कृत नहीं थे। वास्तव में ऋग्वेद में तीन ही वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्या।"⁴ उपनिषद काल में धीरे-धीरे चौथे वर्ण की तथा बाद के काल खंडों में अछूत वर्ग की निर्मिति की गयी है। हिन्दू धर्म के अनुसार वेदों में वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जाँघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से उत्पन्न होने के कारण शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर माना जाता है, और उपर के सभी वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म माना गया। साथ ही इन्हें घृणित भी माना गया, लेकिन हिन्दू धर्म कि व्यवस्थाओं का अनुसरण किया जाए तो किसी भी पूजनीय देवता और पुरुष के सम्मान के लिए उसके पाँव में नतमस्तक होते हैं। तो फिर उन्ही पाँव से उत्पन्न शूद्र अस्पृश्य कैसे हो सकते हैं? "सनातन धर्म कि चिन्ता में मूलतः मानव है। और वह जिस भी स्थिति में है, और जैसा भी काम करता है, वहीं पर अपना आत्मिक विकास करता करे, इसकी व्यवस्था करता है। जो धर्म 'कर्मेषु कोशलं योगा : 'कहता हो। फिर कर्म के आधार पर वह किसी प्रकार की उंच- नीच व्यवस्था नहीं दे सकता।"⁵ वैसे तो 'मनुस्मृति' को भी वर्ण व्यवस्था का आधार माना जाता है। लेकिन वास्तव में मनु ने तो जो समाज में परिचलित था, उसी को लिखित रूप में सामने रखा। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, और इनका जन्म ईसा पू. 500 से 600 माना जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 3000 वर्षों से पूर्व दलितों का शोषण होता आ रहा है। और जातिवाद की हद तो तब होती है, जहाँ जातियों में भी उप जाति है। जो लगातार शोषित होते हैं। शोषण जाति वर्ग के आधार पर ही

नहीं होता है, वल्कि किसानों का पूरा मेहनताना नहीं देना, दफतरो में अपने से छोटे पद पर आसीन अधिकारियों का शोषण, महिलाओं का शोषण और महिलाओं को तो दोहरा शोषण सहना पड़ता है। जिसमे मानसिक, शारीरिक, घरेलू शोषण, कार्यालयों में और साथ ही निम्न वर्ग के होने पर भी शोषण सहन करना पड़ता है। स्त्रियों के शोषण के सम्बंध में मोहनदास नैमिशराय ने 'अपने - अपने पिंजरे' में बताया कि किस प्रकार नूर मोहम्मद एक कसाई है, जिसकी नजर में औरत क्या है "जानवर और औरत में कोई फर्क न था। एक को काटते थे दूसरे को पीटते थे।"⁶ औरत समाज में हमेशा शोषित होती आई है, चाहे किसी भी वर्ग की क्यों ना हो। ये बात अलग है कि उनके दमन/ शोषण का तरीका अलग - अलग हो सकता है। उच्च वर्ग का शोषण चारदीवारी के भीतर होता है और निम्न वर्ग की स्त्री का समाज के सामने कभी मजदूरी करते तो कभी मैला उठाते हुए और कभी अपने परिवार के द्वारा तो कभी उच्च वर्ग के द्वारा। रजनी तिलक अपनी कविता में लिखते हैं-

"एक सताई जाती है स्त्री होने के कारण,

दूसरी सताई जाती है स्त्री और दलित होने पर

एक तडपती है सम्मान के लिए,

दूसरी तिरस्कृत है भूख और अपमान से।"⁷

आजादी के 78 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। स्त्री की स्थिति में भी काफी बदलाव आया है, लेकिन आज भी समाज की मानसिकता औरत को गुलाम बना कर रखना है। दफतर जायेगी तो सहकर्मियों कि नजरों में खटकती है, घर पर नौकरी के नाम पर आजादी तो है। लेकिन जाने से पहले घर के सारे काम करने के बाद दफतर जायेगी और घर आ कर सारा काम करेगी। आज भी लड़की अपने घर और बाहर सुरक्षित महसूस नहीं करती, रात तो की वो दिन म भी अकेले कहीं जाने में सुरक्षित नहीं है। औरत की असली आजादी तब मानी जायेगी जब उसको रात में घर से अकेले निकलते समय ये न सोचना पड़े कि वो किसी की गंदी नजरों का शिकार ना हो जाए। स्त्री की आजादी का अर्थ असल मायनों में तब है, जब समाज स्त्री को उसके शरीर नहीं अपितु उसकी प्रतिभा और श्रम का मूल्य देना सीखेगा। जब स्त्री को स्त्री या खिलौना न समझ कर उसको मनुष्य के रूप में स्वीकृत करेगा। शोषण अभी भी होता है, लेकिन शोषण का तरीका बदल चुका है। आज निम्न वर्ग के लोग जागरूक हो गये हैं शिक्षा ग्रहण करके उच्च पदों पर आसीन हैं। लेकिन उच्च वर्ग की मानसिकता वही है। इस पर दयानंद बटोही लिखते हैं- "अब दान में अंगूठा मांगने का साहस कोई नहीं करता/ प्रेक्टिकल में फ़ैल करता है।"⁸

डॉ आम्बेडकर जी हमेशा से निम्न वर्ग पर हो रहे अन्यायों के विरुद्ध थे, वे हमेशा से उनको समानता, आत्मसमान तथा उनका हक उन्हें दिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पढ़े लिखे दलित समुदाय के लोगों को दलितों पर हो रहे अन्याय और हक के लिए लिखने को प्रेरित किया। जिसके परिणामस्वरूप बहुत से दलित आन्दोलन भी हुए। वे चाहते थे कि इन लोगों पर हो रहे अन्याय का एहसास इनको हो जिससे कि अपने हक के लिए और अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय पर आवाज़ उठाना सीखे। "कोई भी वर्ग कितना भी कमजोर क्यों न हो अगर उसे अन्याय कि सुरंग से गुजरना पड़ता है तो अन्याय और उत्पीड़न की वेदना या पीड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल तक स्थान्तरित होती रहती है। उनके अपने मिथ बन जाते हैं भले ही शासक वर्ग उनका नोटिस न ले। परन्तु कभी न कभी वह बिन्दु आता है। जब वह उत्पीड़न विस्फोट में बदलकर लावे की शकल ले लेता है।"⁹ शाषित वर्ग को भी समझना होगा साथ चलकर तथा एक दूसरे का सम्मान करके ही जीवन को सहज और विकास के पथ पर ले जाया जा सकता है।

अगर निम्न वर्ग काम करना छोड़ दे तो समाज और देश अस्त – व्यस्त हो जाएगा I हर किसी का कार्य सम्माननीय है, एक – दूसरे के कर्म के बिना समाज अपूर्ण है I जिस प्रकार एक तरफ से सेकी गयी रोटी खाने योग्य नहीं होती I ठीक उसी तरह से समाज किसी एक वर्ग के सहारे उन्नत नहीं हो सकता, समाज के सभी वर्गों को साथ मिलाकर चलने से ही एक विकसित समाज को बनाया जा सकता है I हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता 'ठाकुर का कुआँ' की पंक्तियों से समझ सकते हैं कि दलित समाज किस तरह मेहनत करने के बाद भी अपना हक नहीं पाता I

**“बैल ठाकुर का
हल ठाकुर का
हल कि मूठ पर हथेली अपनी
फसल ठाकुर की। ”¹⁰**

आज भी किसानों कि स्थिति यही है I किसान खेतों में मेहनत करता है, बीज और खाद के लिए ऋण तक लेता है I साथ ही इतने समय तक उस फसल कि देखभाल करता है I उसके बाद या तो उसको मौसम से हारना पड़ता है या फिर साहूकारों से जो उनकी फसल का मूल्य बहुत कम देते हैं I जिस कर्ण ऋण की रकम भी किसान वापिस नहीं कर पाता और आत्महत्या तक कर लेते हैं, ये भी शोषण का रूप है I आज भी मजदूरों के साथ शोषण होता है, जिस वस्तु का मूल्य बाजार में 500 रुपये है, उसी वस्तु को बनाने वाले मजदूर को उसका मूल्य 50 रुपये या इससे भी कम दिया जाता है I

निष्कर्ष:- भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का बीज बहुत पुराना है I जाति के आधार पर अस्पृश्यता, शोषण और ऊँच – नीच का जहर समाज में बहुत गहराई तक घुल चुका है I जिसको खत्म करने में समय तो लगेगा, क्योंकि जातिवाद का अहंकार उच्च वर्ण में इस तरह समा चुका है जिस प्रकार शरीर में आत्मा I ज़ाहिर सी बात है अगर कोई सदियों से सबसे ऊँचे पायदान पर रहकर शासन कर रहा हो और अचानक उसके शासन के अधिकार ले लिए जाये तो यह उसके लिए असहनीय होगा I लेकिन अब समय बदल चुका है, शिक्षा के माध्यम से निम्न वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है I समाज और राष्ट्र का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब सभी वर्ग मिलजुल कर कार्य करे और सभी को सम्मान और उनके हक प्राप्त हों I अब शाषित वर्ग को भी समझना होगा अगर सफाई बाला अपना कार्य छोड़ दे, किसान फसल उगाना, मजदूर मजदूरी करना और मैला ढोने वाले अपना कार्य छोड़ दें I तो समाज की स्थिति क्या होगी ? क्या उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बिना अपने जीवन कि कल्पना कर सकता है ? इसलिए हर किसी के कार्य का सम्मान करना चाहिए I किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए

संदर्भ सूची:-

1. ओम प्रकाश वाल्मीकि, 'जूठन दूसरा खंड' राधाकृष्ण प्रकाशन, पृष्ठ -19
2. वही पृष्ठ
3. (सम्पादक) डॉ एन.सिंह, 'दर्द के दस्तावेज' आनन्द साहित्य सदन, अलीगढ़, प्रथम संस्करण 1992 पृष्ठ -40
4. रामधारी सिंह दिनकर, 'संस्कृति के चार अध्याय' लोकभारती प्रकाशन 2011, पृष्ठ-52
5. डॉ एन.सिंह, 'दलित चिंतन अनुभव और विचार' वाणी प्रकाशन 2015, पृष्ठ-15
6. मोहनदास नैमिशराय, 'अपने-अपने पिंजरे (भाग-1)' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली पृष्ठ -21
7. रजनी तिलक, 'दलित निर्वाचित कविताएँ' इतिहासबोध प्रकाशन, संस्करण 2006, पृष्ठ-144
8. डॉ. एन.सिंह, 'दर्द के दस्तावेज' आनन्द साहित्य सदन अलीगढ़, प्रथम संस्करण 1992, पृष्ठ-111
9. गिरिराज किशोर, 'दलित विमर्श :सन्दर्भ गांधी' प्रथम संस्करण 2003, पृष्ठ-18
10. सर्वेश कुमार मोर्य, 'यथार्थवाद और हिंदी दलित साहित्य' स्वराज प्रकाशन 2012, पृष्ठ 162

The Importance of World Book Day

Saurabh Shubham

Research Scholar
University of Hyderabad

World Book Day, celebrated globally on April 23rd, is a tribute to the strength of books and the crucial role they play within the cultural, intellectual, and emotional development of human beings and societies. Initiated with the resource of the use of UNESCO in 1995, this annual event marks the deaths of literary giants William Shakespeare and Miguel de Cervantes, and has thinking about end up a symbolic occasion that brings people of each age together in appreciation of literature.

At its core, World Book Day serves as a powerful reminder of the transformative strength of reading. Books are more than discovered terms on paper—they may be vessels of knowledge, imagination, empathy, and history. They allow readers to excursion via time and during continents, stumble upon new cultures, project assumptions, and deepen their understanding of themselves and others. In an increasingly extra digital and rapid paced world, the act of slowing proper all of the manner right all the way down to observe an ebook becomes now not best an intellectual workout but a deeply human one.

One of the number one desires of World Book Day is to promote reading among children and more youthful adults. By fostering a love for books at an early age, the day encourages lifelong reading and curiosity. Schools, libraries, and businesses spherical the arena host activities which consist of storytelling sessions, book fairs, reading competitions, and writer visits. These sports activities help to ignite imagination and inspire university college students to find out literature beyond their prescribed curricula. Many countries even distribute free or subsidized books to children, particularly those from underprivileged backgrounds, assisting to bridge educational gaps and promote literacy equity.

World Book Day moreover champions freedom of expression and the protection of intellectual freedom. Books have historically been automobiles for modern ideas, social critique, and political resistance. In many regions, authors and publishers keep to face censorship and persecution. World Book Day stands in concord with the

ones voices, underscoring the right of every individual to observe, write, and submit freely.

Moreover, the day highlights the global nature of literature. In an interconnected world, literature has the unique cap potential to assemble bridges amongst cultures. Translated works allow readers to access tales and perspectives from all corners of the globe, fostering mutual understanding and respect. Celebrating World Book Day during linguistic and cultural barriers underscores our shared humanity and the famous appeal of storytelling.

In conclusion, World Book Day is more than a celebration of books—it's miles a celebration of human creativity, resilience, and connection. It emphasizes the irreplaceable role of books in education, cultural preservation, and personal growth. In honoring this day, we reaffirm our collective determination to literacy, free expression, and the iconic price of the written word. Whether in print or digital shape, in poetry or prose, books live the most powerful device we very own to enlighten minds, uplift businesses, and shape a better future

संजीव कृत 'फांस' उपन्यास में अभिव्यक्त पर्यावरण

डॉ.रत्नेश कुमार यादव

सह आचार्य

हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राया-सुचानी, (बागला) जिला, साम्बा
जम्मू एवं कश्मीर -181143 ई-मेल- ratnesh.hnd@cuajammu.ac.in, दूरभाष - 9560046944

शिवम

शोध-छात्र

हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राया-सुचानी, (बागला) जिला, साम्बा
जम्मू एवं कश्मीर -181143

शोध सार : पर्यावरण समूचे विश्व को स्वयं के आवरण में संजोये हुए है। समस्त चराचर इसमें व्याप्त है। इसलिए जब पर्यावरण का दोहन होने लगा तो इसका प्रभाव लगभग पूरे विश्व में देखा जाने लगा। अंटार्कटिका जो मानव-विहीन क्षेत्र है, वह भी इसके चपेट में आ गया। वहां के महासागरीय ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जिससे ज्ञात होता है कि वहां का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। आज पर्यावरण के असंतुलन से मौसम तथा जलवायु में तेजी से परिवर्तन होता जा रहा है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में मार्च के महीने में फूलने वाला 'बुरांश' तथा इसी महीने पकने वाला 'काफल' नामक फल इस वर्ष असमय ही जनवरी में तैयार हो गये। इसके अतिरिक्त आज प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत की अनेक प्रजातियाँ या तो संकटापन्न स्थिति में हैं या लुप्तप्रायः मान ली गयी हैं। ये हमारे पर्यावरण असंतुलन का स्पष्ट संकेत दे रहा है। जिसकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, अन्यथा सम्पूर्ण पृथ्वी के जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

बीज शब्द : पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य-श्रृंखला, वायुमंडल, ग्लेशियर, महासागर।

मूल आलेख : पर्यावरण की अवधारणा बहुत ही विस्तृत है। यह शब्द परि+आवरण के योग से बना है, जिसका अर्थ है हमारे आस-पास का ऐसा आवरण जिसने पृथ्वी को चारों ओर से ढका हुआ है। इसके अंतर्गत वे सभी तत्त्व आते हैं, जो धरती को जीवन योग्य बनाते हैं। पर्यावरण की इस विस्तृत परिधि के केंद्र में प्रकृति है, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, के साथ ही सभी जैविक और अजैविक तत्त्व शामिल होते हैं। प्रकृति का मानव से अत्यंत पुरातन संबंध है। मनुष्य के अस्तित्व में आने के बाद वह सर्वप्रथम प्रकृति से ही साक्षात्कार करता है, वही उसकी आश्रयदाता बनती है। उसी के वृक्षों के फल तथा कंद-मूल उसका भोजन बनते हैं तथा उसी की कन्दराएँ तथा गुफाएँ उसका निवास बनते हैं। इसी कारण प्रकृति को 'मनुष्य की माता' भी कहा गया है। प्रकृति का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्त्व रहा है। ऋषि-मुनि अपनी साधना हेतु ऐसे स्थान के खोज में रहते थे जहाँ उन्हें एकांत के साथ ही शान्ति का अनुभव भी हो जिसके लिए वह प्रकृति का आश्रय उत्तम समझते थे। अतः वे अपने निवास-स्थान के रूप में नदियों के सुरम्य तटों को तथा उनके किनारे अवस्थित वनों को बनाते थे। जिस कारण वेदों, उपनिषदों, आरण्यकों आदि में वनों के महत्त्व के साथ ही मानव स्वास्थ्य हेतु पर्यावरण को महत्त्व दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने निबंध 'कूटज' में इस धरती के प्रति मातृ प्रेम दर्शाते हुए कहते हैं - "यह धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ।"

इसलिए मैं सदैव इसका सम्मान करता हूँ और मेरी धरती माता के प्रति नतमस्तक हूँ।" जब तक मनुष्य में प्रकृति के प्रति भावनात्मक संबंध रहा, वह अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत करता रहा परन्तु जब मनुष्य प्रकृति का दोहन अपने लालच तथा स्वार्थ सिद्धि हेतु करने लगा, पर्यावरण का हास होने लगा। पर्यावरण का यह हास मनुष्य के अलावा जीव-जंतुओं, वनस्पति जगत तथा जलीय जीव-जंतुओं, सभी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आज निरंतर वनों के कटाव ने न सिर्फ वायु की गुणवत्ता को प्रभावित किया है अपितु भूमि के अपरदन में भी अपना योगदान दिया है। जंगलों के काटे जाने से वन्य जीवों का आश्रय छिन रहा है साथ ही वायुमंडल में कार्बनडाई ऑक्साइड की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी आ रही है क्योंकि वृक्ष ही कार्बनडाई ऑक्साइड को अवशोषित करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन तथा मीथेन गैस की निरंतर वृद्धि होने के कारण आज सम्पूर्ण विश्व 'ग्लोबल वार्मिंग' की चपेट में आ चुका है। जिसके परिणामस्वरूप ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसके कारण ही जलीय पारिस्थितिकी भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। जंगलों के निरंतर कम होने के कारण मौसम में लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है। कभी सर्दी का समय संकुचित हो रहा है, कभी मई के महीने में पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है, तो कभी दिसंबर के महीने में भारी बारिश। जिसके कारण कई बार अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है तो कहीं असमय सूखे की मार झेलनी पड़ती है। इससे कभी नदियों का स्तर बहुत कम होता जा रहा है तो कभी भयंकर बाढ़ से सामना हो रहा है। आज मनुष्य की स्थिति बहुत शोचनीय हो गयी है। उसके पास न शुद्ध पीने का जल है न सांस लेने के लिए शुद्ध वायु। ओजोन परत में बना हुआ होल लगातार बढ़ा हो रहा है। जिससे बचाव हेतु पर्यावरण में सुधार लाना आवश्यक है।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भारत में बीसवीं सदी के अंतिम दशक से देखने की मिलती है। इस सदी में भारत में अनेक कारखाने लगे, वैज्ञानिक प्रगति हुई तथा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग बढ़ा। निरंतर जनसंख्या की वृद्धि, जंगलों का दोहन और औद्योगीकरण के फैलते प्रदूषण ने समस्त प्राणी जाति को खतरे में डाल दिया है। हरीश अग्रवाल जी पर्यावरण-प्रदूषण के मानव जीवन पर पड़ते प्रभावों को इंगित करते हुए कहते हैं - "जब से ओजोन पट्टी के हास के बारे में पता चला है और अविलम्ब खतरे की घंटी बजी है, तब से विश्व की

सरकारें हरकत में आ गई हैं। लोगों के सामने त्वचा कैंसर, फसलों की हानि, मोतिया बिंद बढ़ने जैसे खतरे मंडराने लगे हैं।² आज हिंदी साहित्य के लेखक पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या से समाज को जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे न सिर्फ इस समस्या के कुप्रभावों को दर्शाते हुए समाज को सचेत कर रहे हैं अपितु इस समस्या के बचाव के संभावित प्रयासों की ओर भी जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज कविता, निबंध, नाटक, कहानी के अलावा उपन्यास विधा में भी पर्यावरण के प्रति चेतना को प्रसारित करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। नासिरा शर्मा के उपन्यास 'कुड़याँजान' में जल संकट का विस्तार से वर्णन किया गया है तो महुआ माझी के उपन्यास 'मरंग गोडा नीलकंठ हुआ' में 'मरंग गोडा' क्षेत्र में स्थित यूरैनियम से निकलने वाली रेडिएशन के भयंकर प्रभावों का वर्णन किया गया है तो भगवती शरण मिश्र के उपन्यास 'लक्ष्मण-रेखा' के माध्यम से उपन्यासकार कहते हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है। उस सीमा का उल्लंघन हमें विनाश की ओर ले जाता है और यही बात पर्यावरण के सन्दर्भ में भी है। यदि प्रकृति के द्वारा दिए जा रहे खतरे के संकेतों के बाद भी मनुष्य सचेत नहीं हुआ तो उसका विनाश निश्चित है। इसी परम्परा में उपन्यासकार संजीव का उपन्यास 'फांस' भी आता है, जिसका मुख्य विषय तो सम्पूर्ण भारत में किसानों के ऋण में दबे होने पर की जाने वाली आत्महत्याएं तथा तत्कालीन सरकार की किसानों के लिए लागू नीतियों का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास का केंद्र महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत के 'यवतमाल' क्षेत्र को बनाया गया है। जिसमें पहले तो किसानों को देशी किस्म के बीज बोने की अपेक्षा विदेशी उन्नत किस्म के बीजों की खेती करने का प्रलोभन देकर कर्ज दिया जाता है परन्तु सूखे की मार तथा अतिवृष्टि के कारण भोले-भाले किसान ऋण के बोझ तले दब जाते हैं। इस सब से उबर कर भी जब किसान अपनी बची-खुची फसल लेकर फसल मंडी में जाते हैं, तो उसे दलाल मामूली कीमत पर खरीदकर किसानों का शोषण करते हैं। इस तबाही में किसानों का आत्मबल गिरता गया और अंत में वे आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार विकास के नाम पर आदिवासियों से उनका सब कुछ छीन लिया गया। वह जंगल में तो रहते हैं परन्तु बिना सरकार की अनुमति के पेड़ों के फलों, फूलों तथा पत्तियों पर उनका कोई अधिकार नहीं है।

'फांस' उपन्यास का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसमें किसानों की बर्बादी के साथ ही पर्यावरण की अनेक समस्याओं को भी चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इन समस्याओं के समाधान को दर्शाने का भी लेखक ने यथासंभव प्रयास किया है। इस क्षेत्र के किसानों को अधिक पैदावार करने के लिए उन्नत किस्म के विदेशी बीज दिए जाते हैं। उन बीजों के उचित पोषण के लिए रासायनिक उर्वरक देना पड़ता है। जो किसानों की आर्थिक समस्याओं को बढ़ाने के साथ ही प्रकृति प्रदत्त खाद्य-श्रृंखला तथा पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करने का प्रयास करता है। इस उपन्यास की पात्र 'कलावती' के माध्यम से उपन्यासकार इस समस्या से हमें अवगत करवाते हैं – "मैं यहाँ दो बार पहले भी आ चुकी हूँ। मैंने उस सूखे नाले के पास झुण्ड की झुण्ड तितलियाँ देखी हैं, पीली-पीली और दूसरे रंगों की भी....। इस बार जब से आई हूँ, गौर कर रही हूँ कि अब उतनी तितलियाँ नहीं दिखतीं। वहाँ एक मधुमक्खी पालन का छोटा-सा प्रोजेक्ट है। वह भी विषाक्त हो रहा होगा।"³ यह रसायन भूमि से मिलकर जहाँ मिट्टी को दूषित करते हैं वहीं भू-जल को भी खराब करते हैं, जिसके मानव-जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ रहे हैं – "पानी में आर्सेनिक है या अत्यधिक कीटनाशक और खाद घुलकर उसे विषाक्त बना रहा है?...सरपंच लिख-लिखकर हार गये, होम्योपैथिक के डॉक्टरों

का एक एन. जी. ओ. कैंप लगा-लगाकर हार गया। रोग के कारणों का पता न चल सका...।"⁴ यह विदेशी उन्नत बीज अपने साथ अनेक परजीवियों तथा विषैले पौधों की अनेक किस्मों को भी साथ में लाया। जिसने हमारे अनेक औषधीय पौधों की किस्मों के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया। परिणामस्वरूप आज जहाँ उन देशी औषधीय पौधों का अस्तित्व खतरे में है वहीं वे विदेशी पौधे ही सर्वत्र फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपन्यासकार इस समस्या को दर्शाते हुए कहते हैं – "मिलीबग नामक कीड़ा बी. टी. के आने के पहले भारत में नहीं देखा गया था। बी. टी. मिलीबग ले आया...वैसे ही जैसे पी एल 480 नाम के अमेरिकन गेहूँ के साथ आया था जहरीला पौधा पर्थेनियम जो अब भारतीय हो गया है, नाम – 'गाजर घास'।"⁵

हरित क्रांति का उद्देश्य हमारे देश को अनाज के पैदावार की दृष्टि में समृद्ध करना था ताकि उसे अन्य देशों से अनाज खरीदना न पड़े। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए कम समय तथा कम जमीन से, अधिकतम लाभ लेने का प्रयास किया गया। जिसके लिए मिश्रित फसलों को उगाना शुरू किया गया जैसे मक्का के साथ उरद तथा गेहूँ के साथ मटर एवं सरसों इत्यादि। इनके पर्याप्त पोषण के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक प्रयोग में लाये जाने लगे। जिसके कारण पैदावार में तो आशातीत लाभ हुआ लेकिन इसके दूरगामी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। इसका वर्णन उपन्यास में इस प्रकार से देखा जा सकता है – "सबसे पहले प्रचलित केमिकल कीटनाशकों के साथ दिक्कत यह है कि वे मिट्टी, पानी बीज में मिलकर हमारे संहारक सिद्ध हो रहे हैं। पंजाब और गुजरात के कितने ही किसान कैंसर और दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं।"⁶

कृषि उत्पादन में विज्ञान नित-नये प्रयोग कर रहा है, जिसका लाभ किसानों को सीधे रूप में हो रहा है। दो भिन्न गुणों के बीजों का आपस में परागण करवा के एक नई किस्म का निर्माण किया जाता है। जैसे कम फलन वाले रोग प्रतिरोधक बीज का परागण अधिक फलन परन्तु बीमारियों से प्रभावित बीज से करना। ताकि एक ऐसा संकर किस्म प्राप्त हो जो रोग प्रतिरोधक भी हो और अधिक पैदावार भी दे। इसका लक्ष्य किसानों के नुकसान को कम करना होता है। इसी के कारण भारत अनाज उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर भी बना। परन्तु इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं। ऐसा बीज हर बुवाई में नया खरीदना पड़ता है, तथा कई बार फसलों की अनुवांशिकी भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप हमारे पारिस्थितिक तंत्र भी इससे अछूता नहीं रह पाता है – "एक पर्चे में एक वैज्ञानिक ने मटर के बीज में बीन के जीन डालकर उन्हें लम्बी फलियाँ बनाने के प्रयोग की चर्चा की थी। जिसके प्रयोग का परिणाम यह हुआ कि पूरी फली ही जहरीली हो गयीजेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के साथ दिक्कत यह है कि हमें अक्सर पता नहीं होता कि कौन-सा भस्मासुर बना रहे हैं... कौन-सा जीन हमें बाँझ या नपुंसक बनाएगा और कौन-सा कैंसर, पार्किंसन, अल्जाइमर्स का रोगी।"⁷

नदियाँ किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का आधार होती हैं क्योंकि जहाँ एक ओर वे कृषि योग्य भूमि को जल उपलब्ध करवाती हैं तो वहीं दूसरी ओर वे प्राकृतिक सुन्दरता से भी सभी का मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। जिसके कारण देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जल की सहायता से सबसे सस्ती विद्युत बनती है। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण बढ़ती विद्युत मांग की आपूर्ति हेतु अधिक से अधिक पनविद्युत परियोजनाएं बनाये जाने लगीं। जिन्हें हमारे पहले प्रधानमंत्री ने "आधुनिक भारत का मंदिर" कह कर संबोधित भी किया था। परन्तु नदियों पर बाँध बन जाने से जल-भराव प्रभावित क्षेत्र की प्राकृतिक

संपदा, वन्यजीवों इत्यादि को भरी नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही उस सम्पूर्ण क्षेत्र की खाद्य-श्रृंखला भी बुरी तरह से प्रभावित हुई – “ इस 1970 में मध्यप्रदेश में एक डैम बनाकर पन-बिजली बनाकर सरकार ने हमारा भला करना चाहा। हमने देखा इससे तो डूब और कटाव में हमारा आधार जंगल ही तहस-नहस हो जाएगा।”⁸

वर्तमान समय में पर्यावरण एक अत्यंत चिंता का विषय है इसे गौरैया पक्षी के माध्यम से समझा जा सकता है। गौरैया जिसे ‘घरेलू चिड़िया’ के नाम से भी जाना जाता है, मनुष्य से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी, क्योंकि इसका निवास मानव घरों के झरोखों में होता था। परन्तु आज वह बहुत कम घरों के आसपास दिखाई देती है। जिसका मुख्य कारण मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगें मानी जाती हैं। आज मनुष्य इन्टरनेट का तीव्र से तीव्रतम रूप का उपयोग करना चाहता है परन्तु इस दौड़ में रहकर वह प्रकृति से कितना दूर होता जा रहा है। इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है – “ धुएँ के केहर के अलावा खेती के प्रयोग में आने वाले कीटनाशक, मोबाइल टावर के रेडिएशन भी मधु मक्खियों और मित्र पक्षियों के संहारक हैं।”⁹

इस उपन्यास की यह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेखक द्वारा समस्याओं के चित्रण के साथ ही समाधान को भी भलीभांति दर्शाया है। जल-संकट इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ अनिश्चित सूखा पड़ता है और बिन मौसम भारी बारिश। लेखक ने इस बिन मौसम की वर्षा के पानी को छोटे-छोटे बाँधों के माध्यम से संरक्षित करने को कहा है। जिसके लिए वह अहमदनगर जिले के ‘हिवरे बाजार’ गाँव का उदाहरण देते हुए कहते हैं – “ विदर्भ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पानी.....गाँव के बाहर हर पहाड़ी ढलान पर बारिश के पानी को रोका गया। छोटे-बड़े स्टॉप डैम बना के। घर-घर में सॉक पिट बने। 10 लाख पौधे रोपे, परिणाम – भू-जल स्तर 100 फीट से ऊपर उठाकर 20 से 40 फीट पर आ गया।”¹⁰ लेखक कहते हैं कि जहाँ उर्वरक तथा कीटनाशक खरीदने के लिए किसान को कर्ज लेना पड़ता है वहीं वह उर्वरक और कीटनाशक हमारे पर्यावरण को भी दूषित करते हैं इसलिए हमें इनके विकल्प में ऐसे जैविक उत्पादों का उपयोग कृषि में करना चाहिए। जिससे खेती के साथ-साथ पर्यावरण में भी लाभ हो – “ कृषि वैज्ञानिक मल्टीनेशनल कीटनाशक कम्पनियों की अपनी नौकरी छोड़-छोड़कर आये हैं। ये गाँव-गाँव जाकर शेतकरी लोगों को जैविक तरीके से कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं..... हम सिर्फ कीटनाशक ही नहीं, खाद भी बनाते हैं।”¹¹

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि ‘फांस’ उपन्यास में पर्यावरण पर सूक्ष्मता से विवेचन किया गया है। इस उपन्यास के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास तभी संभव है, जब हम विकास के हर पहलू का अध्ययन करके उसे तभी अपनाने का प्रयास करें जब वह पर्यावरण की दृष्टि से भी हितकर हो।

सन्दर्भ सूची :

1. द्विवेदी, हजारी प्रसाद. कुटज, पृ. सं. 32. राजकमल प्रकाशन।
2. अग्रवाल, हरीश. ‘ओजोन हॉल की हकीकत’. जनसत्ता. 26 अगस्त, 2007
3. संजीव. फांस.पृ. सं. 169. वाणी प्रकाशन
4. संजीव. फांस.पृ. सं. 213. वाणी प्रकाशन
5. संजीव. फांस.पृ. सं. 189-190. वाणी प्रकाशन
6. संजीव. फांस.पृ. सं. 190. वाणी प्रकाशन
7. संजीव. फांस.पृ. सं. 202. वाणी प्रकाशन
8. संजीव. फांस.पृ. सं. 239. वाणी प्रकाशन
9. संजीव. फांस.पृ. सं. 189. वाणी प्रकाशन
10. संजीव. फांस.पृ. सं. 194. वाणी प्रकाशन
11. संजीव. फांस.पृ. सं. 191. वाणी प्रकाशन

जनजातीय विकास की रणनीतियाँ (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में)

डॉ. संजीव कुमार पाण्डेय
प्राचार्य

संस्कार विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला-
अनूपपुर (म.प्र.)

शोध सारांश:-

भारत सरकार के योजनाबद्ध प्रयासों ने देश में अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों के समग्र विकास को गति दी है। इस रणनीति ने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को पहचान करने के अलावा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहल कदमियों के जरिए इनके निवारण का रास्ता भी तैयार किया है। सरकार ने इन सामाजिक और आर्थिक पहलकदमियों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया है। लेकिन साथ ही, खासतौर से अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी भागीदारी पर एक आधारित एक ऐसी स्वशासन प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की सख्त जरूरत महसूस की गई है जिसमें यह समुदाय अपने संसाधनों का प्रबंधन खुद कर सके। इस तरह की भागीदारी पर आधारित और जनजाति प्रबंधित विकास प्रक्रिया से अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण संभव होगा। शैक्षिक अवसरचना में इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धी दुनिया में किस तरह आधुनिक और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के जरिए अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की दक्षता और ज्ञान को बढ़ाया जाए।

मुख्य शब्द:-जनजातीय, विकास, रणनीतियाँ, शैक्षिक, अवसरचना, सामाजिक, आर्थिक, भागीदारी आदि।

प्रस्तावना:-

भारत में विभिन्न पंचवर्षीय और सालाना योजनाओं में जनजातियों के विकास पर जोर दिया गया है। लेकिन देश की अनुसूचित जनजातियों के विकास के मार्ग में चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। इसका मुख्य कारण इस समुदाय की पारम्परिक जीवनशैली, दरदराज के इलाकों में बसावट, बिखरी हुई आबादी और निरंतर विस्थापन है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6 प्रतिशत यानी 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की आबादी का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में वृद्धि देखी गई है। देश की जनसंख्या में उनका हिस्सा 1961 में 6.9 प्रतिशत था जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया। लेकिन विकास के विभिन्न पैमानों पर देश के अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति कम रही है। हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इस आलेख में हम इन प्रावधानों के साथ ही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकारी रणनीतियों, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे।

सांविधानिक प्रावधान - भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजातियों की विशेष जरूरतों को समझते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ खास प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के अलावा इन समुदाय को शोषण

से बचाना भी है। नागरिकों के मौलिक अधिकार उनका समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, संविधान में निरूपित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिसमें नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

विकास योजनाएँ और कार्यक्रम - नीति निर्माताओं और योजनाकारों ने पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) की शुरुआत से ही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पहली योजना में वंचित तबकों की जरूरतों को पर्याप्त और समुचित ढंग से पूरा करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाने से संबंधित सिद्धांत निर्धारित किए गए। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए प्रभावी और सघन अभियान चलाने के मकसद से विशेष प्रावधान भी किए गए।

सरकार ने पहली योजना के अंत में देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस और समेकित विकास योजनाओं की जरूरत को महसूस किया। परिणामस्वरूप दूसरी योजना (1956-61) के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों को चार समूहों में बांटा गया जो इस प्रकार थे- 1. संचार, 2. शिक्षा और संस्कृति, 3. जनजातीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा 4. स्वास्थ्य, आवासन और जल आपूर्ति। आर्थिक विकास पर जोर देते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि समाज में असमानता घटे। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों की योजना बनाते समय उनकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखा गया। ये कार्यक्रम इस समुदाय की संस्कृति और परम्पराओं के प्रति सम्मान और समझ पर आधारित थे। पहली योजना में जनजातीय कल्याण के लिए जो कार्यक्रम तैयार किए गए थे, उन्हें 1961 तक प्रभावी स्वरूप मिल गया। दूसरी योजना के इस आखिरी वर्ष में सरकार ने 43 विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंडों की स्थापना की। इन्हें बाद में जनजातीय विकास खंड (टीडीबी) का नाम दिया गया। अनुसूचित जनजातियों को अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए दूसरी योजना में शामिल योजनाओं और नीतियों को तीसरी योजना (1961-66) में भी जारी रखा गया।

जनजातीय वर्ग के कल्याण और इन्हें समर्थ बनाने की संवेदनशील पहल पर वित्त वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिये 40 हजार 804 करोड़ रुपये का बजट पारित किया है। जनजातियों के समग्र विकास के लिये पारित यह बजट वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 3,856 करोड़ रुपये (करीब 23.4 प्रतिशत) अधिक है। जनजातीय बंधुओं और इनकी पुरा संस्कृति के संरक्षण और समयानुकूल विकास के लिये सरकार द्वारा अनेक नवाचारी कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से ही जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी, युवा, खिलाड़ी और कलाकार अब विकास की एक नई राह पर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में विशेष रूप से पिछड़े एवं कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिये भी मध्यप्रदेश सरकार अत्यंत संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया एवं सहरिया निवास करती हैं। पीएम जन-मन में इन विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में बहुउद्देशीय केन्द्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण से जुड़े कार्य कराये जा रहे हैं। सरकार ने जारी साल के बजट में इन कामों के लिये 1,607 करोड़ रुपये दिये हैं। जनजातीय कार्य विभाग की शौर्य संकल्प योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिये अलग से

गठित की जायेगी। साथ ही इस समूह के इच्छुक युवाओं को पुलिस, सेना एवं होमगार्ड में भर्ती कराने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के युवाओं को रोजगार एवं सेवा से जोड़ने के लिये पीवीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश दिये हैं। प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति पीवीटीजी समूह में आती हैं। इसी प्रकार आर्म्ड फोर्स में भर्ती के लिये प्रशिक्षण योजना में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के युवाओं को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती कराने के लिये इन्हें प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पीवीटीजी आहार अनुदान योजना में इन जनजातीय परिवारों की महिला मुखिया को 1,500 रुपये प्रतिमाह पोषण आहार अनुदान राशि दी जाती है। इसके लिये सरकार ने बजट 2024-25 में 450 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिये मध्यप्रदेश सरकार 2024-25 में 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। पीवीटीजी क्षेत्रों में 217 नये आंगनवाड़ी भवन बनाये जा रहे हैं। इसके लिये बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिये राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित कराने के लिये फ्री-कोचिंग दी जायेगी। इसके लिये सरकार प्रदेश के सभी जनजातीय विकासखंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। इस अकादमी के जरिये जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई, नीट, क्लेट और यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की बड़ी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग देकर इन्हें परीक्षाओं में सफल होने के गुर सिखाए जायेंगे। शासन से स्वीकृति मिलते ही रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी प्रारंभ कर दी जायेगी।

वर्तमान में जनजातीय विद्यार्थियों को 'आकांक्षा योजना' के अंतर्गत जेईई, नीट, क्लेट की तैयारी के लिये भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में कोचिंग दी जा रही है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराने के लिये निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को कोचिंग दी जा रही है। अब सभी ट्राइबल ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग का लाभ देने के लिये योजना की संशोधित डीपीआर तैयार कर ली गई है।

जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की ठोस चिंता करते हुए सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिये 667 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन का छात्रवृत्ति के लिये 500 करोड़ रुपये प्रावधान किया है। निरुशुल्क कोचिंग के साथ सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को टैबलेट भी देगी। टैबलेट के लिये डेटा प्लान भी सरकार निरुशुल्क उपलब्ध करायेगी। योजना के लिये सरकार ने बजट में 10.42 करोड़ रुपये आरक्षित किये हैं। तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये कार्यरत हैं पृथक-पृथक विकास प्राधिकरण जनजातीय कार्य विभाग में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संचालक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के विकास के लिए योजना बनाने एवं इनका क्रियान्वयन के लिये एजेंसी भी कार्यरत है। इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिये योजना बनाने एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिये प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया पीवीटीजी के लिये पृथक-पृथक विकास

प्राधिकरणों सहित कुल 11 प्राधिकरण कार्यरत हैं। पेसा एक्ट में मध्य प्रदेश में पेसा नियम, नवम्बर 2022 से लागू हैं। यह नियम प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकासखंडों की 5 हजार 133 ग्राम पंचायतों के अधीन 11 हजार 596 गावों में लागू है। इन नियमों में प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजातीय वर्ग के हितों के लिये अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। पेसा से जनजातीय वर्ग अपनी क्षेत्रीय परम्पराओं, अपनी संस्कृति और जरूरतों के मुताबिक फैसले लेकर विकास की राह में आगे बढ़ सकेगा। पेसा नियमों के क्रियान्वयन से जनजातीय समुदाय के एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हो रहा है।

कक्षा पहली से आठवीं तक प्री-मेट्रिक राज्य छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2023-24 में 17 लाख 36 हजार 14 विद्यार्थियों को 56 करोड़ 59 लाख रुपये छात्रवृत्ति दी गई। कक्षा 9वीं और 10वीं केन्द्र प्रवर्तित प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2023-24 में 1 लाख 51 हजार 292 विद्यार्थियों को 52 करोड़ 15 लाख रुपये छात्रवृत्ति दी गई। कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय में पढ़ रहे कुल 2 लाख 33 हजार 91 विद्यार्थियों को 356 करोड़ 95 लाख रुपये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति वितरित की गई।

अजजा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में वित्त वर्ष 2023-24 में 10 होनहार विद्यार्थियों को 2 करोड़ 89 लाख रुपये की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति राशि दी गई। आवास किराया सहायता योजना में वित्त वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा एक लाख 44 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 109 करोड़ 52 लाख रुपये की किराया प्रतिपूर्ति भुगतान की गई। सिविल सेवा परीक्षा के लिये निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग योजना में वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ 13 लाख रुपये व्यय कर 97 विद्यार्थियों को कोचिंग कराई गई। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में 2023-24 में एक करोड़ से 497 अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना में 2023-24 में 18 लाख रुपये से 580 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया।

योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आंकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के सर्वे नतीजों पर आधारित तेंदुलकर पद्धति को अपनाया था। इन अनुमानों के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या गाँवों में 45.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 24.1 प्रतिशत थी।

एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य स्थिति (मूल: सहायक) में श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 41.8 प्रतिशत और 2019-20 में 47.1 प्रतिशत थी। सभी वर्गों के लिए यह दर 2017-18 में 36.9 प्रतिशत और 2019-20 में 40.1 प्रतिशत थी।

इसी तरह, एनएसएसओ और पीएलएफएस 2019-20 से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर 2017-18 में 4.3 प्रतिशत से घट कर 2019-20 में 3.4 प्रतिशत रह गई।

2011 की जनगणना के अनुसार सभी आयु वर्गों को मिला कर साक्षरता की दर कुल आबादी में 73 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों में 59 प्रतिशत थी। युवा वर्ग की बात करें तो कुल आबादी और अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता का दर का अंतर 11.1 प्रतिशत था। यह अंतर युवकों में 7.1 प्रतिशत और युवतियों में 14.7 प्रतिशत का था। कुल आबादी और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के बीच साक्षरता दर का यह फासला काफी बड़ा था। निःसन्देह, सरकार के साक्षरता अभियानों का लाभ देश के सभी नागरिकों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। विद्यालय परित्याग दर शैक्षिक विकास के अभाव और शिक्षा के एक खास स्तर तक पहुंचने में किसी सामाजिक समूह की

अक्षमता का महत्वपूर्ण संकेतक है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में विद्यालय परित्याग दर में कमी आ रही है। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में साक्षरता की कमी, औपचारिक शिक्षा के परित्याग और दाखिले के कम अनुपात जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। स्कूलों में उनकी शिक्षा निःशुल्क किए जाने के साथ ही उन्हें पुस्तकें और वर्दियाँ मुफ्त दी जा रही हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए खासतौर से आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इनमें इस समुदाय के छात्रों के भोजन और आवास का खर्च सरकार वहन करती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना और नवोदय विद्यालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में साक्षरता का प्रसार है। दरदराज के गाँवों के निवासी और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण तीसरी योजना के दौरान ही शुरू कर दिया गया था। वर्ष 1989-90 में अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की एक अलग योजना शुरू की गई। जनजातीय उप-योजना के क्षेत्रों में 1990-91 से आदिवासी विद्यालयों की स्थापना शुरू की गई। सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मकसद से संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कोष के एक अंश का उपयोग करने का फैसला किया। इस धन का इस्तेमाल 20 राज्यों में छठी से बारहवीं तक कक्षाओं के लिए 288 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना पर किया जाना था। वर्ष 1997-98 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उच्चतर और पेशेवर शिक्षा के पाठ्यक्रमों तथा सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की उच्चस्तरीय नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा पाने के लायक बनाना था। संशोधित कार्यक्रम को 12 सितंबर, 2019 को शुरू किए जाने के समय तक 200 ईएमआरएस काम करने लगे थे।

सरकार ने संशोधित योजना के तहत ईएमआरएस की स्थापना के लिए देश में 452 प्रखंडों की पहचान की है। ये प्रखंड इन विद्यालयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा जनजातीय आबादी और कम-से-कम 20,000 आदिवासियों के निवास की शर्तें पूरी करते हैं। इन प्रखंडों में स्थापित किए जाने वाले ईएमआरएस पुरानी योजना के तहत मंजूर 288 विद्यालयों के अतिरिक्त होंगे। सरकार ने 740 ईएमआरएस खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा शहर में देश भर में 378 ईएमआरएस चल रहे हैं। इनमें से 205 विद्यालयों का संचालन पिछले पांच वर्षों (2017-22) के दौरान शुरू हुआ है।

साक्षरता और शिक्षा में प्रगति के साथ ही उद्यमिता के माहौल और कौशल विकास की पहलकदमियों की भी दरकार है ताकि अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित व्यक्तियों को अपने निवास स्थान के नजदीक ही समुचित रोजगार मिल सके। कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल इंडिया मिशन के तहत इस दिशा में कई योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के जरिए अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में जनजातीय समुदाय समेत समाज के सभी तबकों के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए दीर्घकालिक कौशल उपलब्ध कराया जाता है। इन सभी योजनाओं में अनुसूचित जनजाति घटक के माध्यम से

आदिवासियों के लिए कोषों के उपयोग का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। संसाधनों की कोई कमी नहीं होने के बावजूद अनुसूचित जनजातियों के रोजगार के योग्य युवाओं को उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप विभिन्न पेशों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष - मध्य प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकारों की योजनाओं और कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर हमेशा जोर दिया गया है। लेकिन राज्यों में इस दिशा में हुई प्रगति में काफी असमानता है। आँकड़ों से जाहिर है कि अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजातियाँ आर्थिक तौर पर ज्यादा पिछड़ी हैं। अनुसूचित जनजातियों की गरीबी रेखा से नीचे की ज्यादातर आबादी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की है। उनके पास उत्पादक संपत्तियाँ बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं हैं।

सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की पहचान करते हुए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलकदमियों के जरिए उनके समाधान के तौर-तरीके तैयार किए हैं। जनजातियों की भागीदारी पर आधारित स्वशासन की एक ऐसी प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है जिसमें इस समुदाय के सदस्य संसाधनों का खुद प्रबंध कर अपनी नियति स्वयं निर्धारित करें। इससे जनजातियों का उनकी भागीदारी और उनके प्रबंधन वाली विकास प्रक्रिया में सशक्तीकरण होगा। उचित स्थानों पर प्राइमरी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों जैसी शैक्षिक अवसरंचना के निर्माण का कदम सराहनीय है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की योग्यता और ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए छोटे वनोपजों और कम उत्पादकता वाली कृषि पर निर्भर करता है। लिहाजा, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने तथा जनजातीय उत्पादों को संवहनीय ढंग से बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। आखिरी महत्वपूर्ण बात यह कि अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय सहयोग, तालमेल और एकजुटता की आवश्यकता है।

संदर्भ स्रोत:-

1. जनसम्पर्क विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी वर्ष 2025
2. जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश वर्ष 2015
3. गौतम मरकाम, जनजातियों की समस्याएं एवं निदान, (आलेख) 2025
<https://www.allgk.in/cg-gk-cgpsc-and-vyapam-gk/>
4. रावर्ट चैम्बर्स(1988) पुटिंग द पीपुल फर्स्ट, रूरल डेवलपमेंट लागमैन
5. ब्रार जे एस (1983) पोलिटिक्स इकोनामी आफ रूरल डेवलपमेंट, एलाइड पब्लिकेशन नई दिल्ली
6. दक टी एम (1982) सोशल इनइक्वालिटी एण्ड रूरल डेवलपमेंट नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
7. अजीत दाण्डा (1984)स्टडीज ऑन रूरल डेवलपमेंट एक्सपेरियेन्स एण्ड इश्यूज इंटर इंडिया पब्लिकेशन
8. गिलवर्ट इटन (1985) मीटिंग विथ पीजेन्ट्स रूरल डेवलपमेंट इन एशिया सेज नई दिल्ली
9. एस.सी.जैन(1985) रूरल डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूशंस एण्ड स्टेजि, रावत पब्लिकेशंस
10. इन्दु माथुर (1982) चेंज इन रूरल सोसाइटी

हिन्दी की आधुनिक कविता में राम

डॉ. पी.एम.आर. जयन्ती

प्राध्यापक, हिंदी विभाग

एस.के.आर. एवं एस.के.आर. राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय (स्वायत्त) कडप्पा (आंध्र प्रदेश)

मनुष्य जाति को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने में युग युगांतर से राम के चरित्र ने मार्गदर्शक की भूमिका अदा की है। राम के चरित्र में समग्र भारतीय संस्कृति मूर्तिमान हो उठी है। उनके व्यक्तित्व को आधार बनाकर विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेक कवियों ने श्रेष्ठ साहित्य की रचना की है और उसमें लोकमंगल की साधना की है। आधुनिक काव्य में भी विभिन्न भारतीय भाषाओं सहित हिन्दीभाषा में राम के चरित्र पर आधारित ऐसे अनेक काव्यों की रचना हुई है जिनमें रचनाकारों ने परिवर्तित युगीन परिवेश के अनुसार परंपरागत कथा को नए अर्थों से संपन्न किया है। ऐसे काव्यों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के वैदेही वनवास, मैथिलीशरण गुप्त के साकेत और पंचवटी, बालकृष्ण शर्मा नवीन के उर्मिला, बलदेव प्रसाद मिश्र के कौशल किशोर, साकेत संत और राम राज्य, सुमित्रानंदन पंत के पुरुषोत्तम राम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राम की शक्तिपूजा, श्री नरेश मेंहता के सशय की एकरात, प्रवाद पर्व और शबरी, भारतभूषण के राम की जल समाधि, लक्ष्मीकांत वमी के चित्रकूट चरित्र, डॉ जगदीश गुप्त के शंबुक, डॉ. महेंद्र कार्तिकेय के प्रेभ या तमु परात्पर एवं महेशचंद्र शुक्ल के छंद रामायण जैसे कई छोटे- बड़े -काव्य उल्लेखनीय हैं। इनमें "वैदेही वनवास" और "साकेत" की पृष्ठभूमि इस अर्थ में लगभग एक समान है कि कवियों में अपने युग की परिस्थितियों एवं आंदोलनों के प्रभाव ग्रहण करते हुए रामकथा के पात्रों के चरित्र में नवयुग के लिए आवश्यक आदर्शों की उद्भावना की। इन दोनों काव्यों में राम को एक ऐसे महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान कर दिया। साकेत के राम का आदर्श है -

"निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी

हम हो समष्टि के लिए व्याष्टि बलिदानी ।"

इसी प्रकार वैदेही वनवास के राम जनता-जनार्दन के प्रति निःस्वार्थ भाव से समर्पित दिखाई देते हैं।

" गौरव क्या है?

जन भार वहन करना ही

सुख क्या है

बढ़कर दुःख सहन करना ही ."

गुप्त जी ने अपने काव्य पंचवटी में सूर्यनखा प्रसंग को आधार बनाया है। इसमें एक ओर तो तत्कालीनसमस्याओं पर कवि ने पाठक ध्यान केंद्रित किया है तथा दूसरी ओर सीता और लक्ष्मण के चरित्रों में राष्ट्रीय परिवर्तन के अनुरूप आधुनिकता का समावेश किया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने काव्य 'उर्मिला' में राम को एक ऐसे क्रांति धर्मी मनुष्य के रूप में चित्रित किया है जो युगप्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस काव्य की भूमिका में कवि ने इसके वैशिष्ट्य को रेखांकित करते हुए कहा है "मेरी इस उर्मिला में पाठकों को रामायण की कथा नहीं मिलेगी। रामायणी कथा से मेरा अर्थ है - क्रम से राम लक्ष्मण, जन्म से लगातार रावण विजय और फिर अयोध्या आगमन तक की घटनाओं का वर्णन. ये घटनाएँ भारत वर्ष में इतनी अधिक

सुपरिचित हैं कि इनका वर्णन करना मैंने उचित नहीं समझा इस ग्रन्थ को मैंने विशेषकर मनः स्तर पर होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का दर्पण बनाने का बनाने का प्रयास किया है।

रामायणीय घटनाओं का राम, सीता, सुमित्रा और विशेषकर लक्षण और उर्मिला के मनो पर क्या प्रभाव पड़ा वे इन घटनाओं के प्रति किस प्रकार प्रतिकृत हुए आदि का वर्णन ही इस ग्रंथ का विषय बन गया है।" इस काव्य की विशेषता कवि के इस दृष्टिकोण में निहित है कि-

**“नर को नारायण कर देना
यही राम की लीला है।”**

बलदेव प्रसाद मिश्र ने अपने राम काव्यों में तुलसी के राम को नवीन युग परिवेश में ढालकर प्रस्तुत किया है। उनके काव्य “कौशल किशोर में राम को आर्य संस्कृति के उद्धार करता के रूप में चित्रित किया गया है। उनके चरित्र में योग समृद्धि सम्पत्ति, राज्य त्याग और प्रवृत्ति, निवृत्ति जैसे विरोधी भावों का सामंजस्य दिखाई देता है।

**“भोग योग समृद्धि-संपत्ति राज-त्याग समान,
या प्रवृत्ति-निवृत्ति वह ऐक्य शोभावान ।”**

इसी प्रकार साकेत संत में कवि ने राम को एक ऐसे स्वप्न दृष्टा महानायक के रूप में प्रस्तुत किया है जो समस्त भारतवर्ष का एक सूत्र में पिरोकर अनार्यों से म भी सहयोग लेते हुए आर्य संस्कृति का विकास करसके

**“कि जिससे विकसे आर्यावर्त
तुम्हारा भारत बने अभंग।”**

अपने तीसरे राम काव्य राम राज्य भी बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने राम के चरित्र में पूर्ण मनुष्यत्व के साथ-साथ प्रत्यक्ष विष्णु भाव का भी समावेश किया है और मनुष्यता के लिए महा सत्य और आराध्य बताया है -

**“मनुष्य ही महासत्य मनुष्य मन के लिए
वही परम आराध्य वही प्रत्यक्ष विष्णु।”**

इस काव्य की भूमिका में कवि ने काव्य रचना के युग सापेक्ष उद्देश्य की ओर पाठकों का ध्यान खींचते हुए लिखा है कि-‘कथा का उद्देश्य केवल कथा नहीं किन्तु राष्ट्रीय एकीकरण और सुराज्य स्थापना से सम्बंधित राम के प्रयत्नों पर अपनी मति के अनुसार प्रकाश डालना है।

पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की लम्बी कविता राम की शक्तिपूजा का इस युग में राम काव्यों के बीच अद्वितीय स्थान है। निराला जी ने राम को एक संघर्षशील मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आदि कवि बाल्मीकि से लेकर आधुनिक युग के कवियों तक ने राम के प्रति अनेक प्रकार के दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं। परन्तु निराला जी के राम का व्यक्तित्व उन सबसे पृथक और विशिष्ट है निराला के काव्य में राम अपनी अपराजेयता के प्रति दिव्य आश्रुति से भरपूर चित्रित नहीं किये गए हैं बल्कि कवि ने उन्हें पराजय के भय से चिन्तित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। जीवन भर विरोध झेलने और साधानहीनता की स्थिति में भटकाने वाले मध्यवृत्त व्यक्ति तथा स्वयं कवि का व्यक्तित्व राम के माध्यम से अभिव्यजित हुआ है-

धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध

धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध।

प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाने वाले पं. सुमित्रानन्दन पंत ने अपने महाकाव्य पुरुषोत्तम राम में राम को विष्व चेतना के प्रतीक के रूप में रूपायित किया है। जिनका अवतार ही मनुष्य के हृदय में नवयुग के निर्माण करने के लिए हुआ है। राम के चरित्र की इस नवीन परिकल्पना की प्रक्रिया के संबंध में डॉ. ब्रह्म शंकर पुरुषोत्तम व्यास यह स्थापना है पंत जी ने काव्य में एक ओर तो कोरे आध्यात्म भाव का खण्डन किया है।

दूसरी ओर मार्क्सवाद और गाँधीवाद की भी। उनका कथन है कि- “भू-नर के सृजन के लिए उसने अद्वैत और मार्क्सवाद, गाँधीवाद अध्यात्मवाद, और भौतिकवाद का समन्वय किया। पन्त जी के इस काव्य का नायक राम अखिल विश्व में मानवीय साम्राज्य स्थापित करने में संघर्षरत दिखाई देते हैं.-

**“अभी जूझना मुझको निर्मम वर्तमान से.
मानवीय साम्राज्य विश्व में स्थापित करने।”**

श्री नरेश मेहता ने ‘संशय की एक रात’ में राम को प्रज्ञा का प्रतीक पुरुष बनाया है। इस काव्य में कवि ने राम को एक साथ दृष्टा और सृष्टा की तरह प्रस्तुत किया है। इस काव्य के राम सामने प्रस्तुत युद्ध की पूर्व बेला में कभी समुद्र तट पर उदास मन से टहलते हैं, कभी चिंताग्रस्त होकर बैठ जाते हैं और कभी ज्वार का जल उन्हें भिगो जाता है। शांति स्थापित करने के लिए भेजे गए दूत के असफल होने और शांति वार्ता के अनेक बार टूट जाने पर भी राम युद्ध को टालना चाहते हैं। आधुनिक काल के कवि ने दो विश्व युद्धों के रूप में जिस विभीषिका का साक्षात्कार किया है उसी के कारण उसने राम के चरित्र में यह समकालीन द्वंद्व उपस्थित किया है।

**“ मैं केवल युद्ध को बचाना चाहता हूँ बन्धु,
मानव में जो श्रेष्ठ विराजा है
उसको ही**

हाँ उसको ही जगाना चाहता हूँ.”

नरेश जी अपने एक एनी काव्य ‘प्रवाद पर्व’ में सीता निर्वासन की कथा को मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रस्तुत किया है। इस काव्य में राम की अनाशक्ति की भावना की व्याख्या की गई है। लोकहित को ध्यान में रखते हुए राम एक साधारण अनाम व्यक्ति के सन्देह को ध्यान में रखते हुए अपनी देवी तुल्य तेजस्वी चरित्र वाली पत्नी का त्याग तो अवश्य करते हैं परन्तु मन से उन्हें कभी त्याग नहीं पाते, तथा अपने इस कार्य के लिए सीता से क्षमा याचना भी करते हैं।

इसी प्रकार कवि ने अपने शबरी नामक खंड काव्य में शबरी के माध्यम से एक निम्न वर्ग की स्त्री की आध्यात्मिक संघर्ष की गाथा का वर्णन करते हुए राम के समाज सुधारक और करान्ति द्रष्टा स्वरूप को प्रस्तुत किया है। डॉ. जगदीश गुप्त ने अपने काव्य शम्बूक में शूद्र ऋषि कहे गए शम्बूक को भूमि पुत्र की संज्ञा प्रदान की है।

निष्कर्ष :- राम कथा पर आधारित हिंदी भाषा के आधुनिक काव्यों की यह चर्चा तब तक अधूरी रहेगी जब तक महेश चन्द्र शुक्ल कृत ‘छंद रामायण’ का उल्लेख न किया जाय। ब्रज भाषा में रचित छन्द रामायण में राम को पुरुषोत्तम, आदर्श और मर्यादाशील रूप में चित्रित किया गया है।

‘आज की सीता’ - एक अध्ययन

डॉ. मिनी ए. आर.

सहायक प्राध्यापक
हिंदी विभाग पय्यनूर कॉलेज

‘आज की सीता’ नाम ही इस बात की ओर संकेत करता है कि यह कविता रामायण की पारंपरिक सीता से अलग एक आधुनिक और सजग स्त्री की छवि प्रस्तुत करती है। आज के समय में जब स्त्री अधिकार, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और बराबरी की बातें समाज के हर कोने में उठ रही हैं, तब ‘आज की सीता’ जैसी कविता अत्यन्त प्रासंगिक हो जाती है। आज की सीता वह स्त्री है, जो केवल पति या परिवार के आदेशों पर नहीं, चलती, बल्कि स्वयं सोचती और निर्णय लेती हैं। वह वनवास या अग्निपरीक्षा जैसे अन्यायपूर्ण व्यवहार को सहन नहीं करती, बल्कि सवाल उठाती हैं। वह नौकरी करती है, अपने फैसले खुद लेते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। वह घर, समाज नौकरी, रिश्तों-हर क्षेत्र में अपनी पहचान और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। आज की सीता नारी अस्मिता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह केवल पौराणिक चरित्र की पुनर्व्याख्या नहीं, बल्कि समकालीन भारतीय नारी के आत्मबोध की आवाज़ है।

भारतीय नारी संवेदनशीलता शक्ति, सहनशीलता, समर्पण और संघर्ष की प्रतीक मानी जाती हैं। वह भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों की आधार शिला रही है। वह केवल एक परिवार की धुरी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की भी निर्माता है। उसकी भूमिका बहुआयामी है। कभी वह माँ के रूप में ममता की मूर्ति बन जाती है, तो कभी लक्ष्मी के रूप में समृद्धि का स्रोत बनती हैं। आज की भारतीय नारी पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक विचारों के बीच संतुलन बनाकर चल रही हैं।

प्राचीन भारत में नारियों को उच्च सम्मान प्राप्त था, वे विद्वता, ज्ञान और धार्मिक कर्मों में भाग लेती थीं। गार्गी, मैत्रेयी, सीता और अनसूया जैसी नारियाँ नारी शक्ति की प्रतीक मानी जाती थीं। लेकिन मध्यकाल में समाज में अनेक कुरीतियाँ आ गईं जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा, जिनसे नारी की स्थिति कमजोर हो गयी। ब्रिटिश काल में जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार हुआ, भारतीय समाज में सुधार की लहर उठी। राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने में योगदान दिया। महिलाओं ने भी इस दौर में स्वतंत्रता में भारत लिया। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गाँधी जैसी नारियों ने साहस, नेतृत्व और बलिदान का परिचय दिया।

स्वतंत्र भारत में भारतीय नारी ने नए युग में प्रवेश किया। शिक्षा और अधिकारों के विस्तार के साथ अब यह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्जा करा रही है। वह डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री, सैनिक, खिलाड़ी, राजनीतिज्ञ और उद्यमी तक बनी है। कल्पना चावला, किरण बेदी, पी.टी.उषा, मिताली राज और निर्मला सीतारामन जैसी नारियाँ इसकी मिसाल हैं। फिर भी समाज में नारी के समक्ष कई चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं। जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग भेद, असमान वेतन और यौन शोषण। इन समस्याओं के बावजूद भारतीय नारी अपने आत्मविश्वास और संघर्षशीलता के बल पर आगे बढ़ रही है। वह अब अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी है। और अपने अधिकारों के लिए सजग हो चुकी है।

भारतीय नारी अब अबला नहीं रही, वह सबला है। वह अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए समाज को भी नई दिशा दे रही है। वह आज न केवल अपने परिवार का बल्कि देश के प्रगति का भी महत्वपूर्ण आधार बन

चुकी है। उसका संघर्ष, त्याग और समर्पण प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय नारी परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है। वह प्रेम, करुणा, शक्ति, संघर्ष और बुद्धिमता की प्रतिमूर्ति है। यदि समाज उसे बराबरी का स्थान दे, तो वह न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे राष्ट्र को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है। पौराणिक काल में सीता एक आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित है। रामायण के अनुसार, सीता राजा जनक की पुत्री थी और धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें भूमिपुत्री भी कहा जाता है। उनका विवाह भगवान राम से हुआ जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। सीता का जीवन त्याग, सहनशीलता, नारी मर्यादा और आदर्शों का प्रतीक रहा। वनवास काल में उन्होंने पति धर्म निभाते हुए राम के साथ वनागमन किया। रावण द्वारा हरण किए जाने के बाद भी उन्होंने मर्यादा और संयम का पालन किया और लंका में रहते हुए अपने सतीत्व की रक्षा की। युद्ध के बाद जब राम ने उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाया, तब उन्होंने अग्निपरीक्षा दी। बाद में जब समाज ने पुनः उनकी शुद्धता पर प्रश्न उठाए तो उन्होंने राम की आज्ञा का पालन करते हुए गर्भावस्था में ही वनवास स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने लव और कुश का जन्म दिया। सीता का संपूर्ण जीवन नारी धर्म, धैर्य, तपस्या और गरिमा का प्रतीक है। वे भारतीय स्त्रीत्व की उस परंपरा की प्रतीक हैं। जिसमें त्याग और सहनशीलता सर्वोच्च मूल्य माने जाते हैं।

आज की सीता परंपरागत सीता से भिन्न है। वह अब केवल त्याग, सहनशीलता और चुप्पी की मूर्ति नहीं, बल्कि जागरूक, आत्मनिर्भर और सवाल पूछनेवाली नारी है। उसने समाज द्वारा थोपी गई चुप्पी को तोड़ दिया है, और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो गयी है। आज की सीता पढ़ी-लिखी है। अपने निर्णय स्वयं लेती हैं और परिवार व समाज दोनों में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का साहस रखती है। वह नौकरी करती है, अपनी बात खुलकर कहती हैं और अगर अन्याय होता है तो विरोध करती है। वह अब अग्नि परीक्षा नहीं देती, बल्कि प्रश्न करती है, क्यों केवल स्त्री को ही परीक्षा देनी पड़ती है? वह अब राम की आज्ञा से ब्रन नहीं जाती, बल्कि अपना रास्ता खुद चुनती हैं। वह अब बेटे की माँ होकर भी बेटी को बराबरी का हक देना जानती हैं। आज की सीता वह स्त्री है, जो परंपराओं को सम्मान देते हुए भी अपनी अस्मिता और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करती। वह अब अबला नहीं, सबला है। संवेदनशील भी, संघर्षशील भी। आज की सीता संघर्ष की नहीं, समाधान की प्रतीक बन चुकी है।

शिखाकुमारी उपाध्याय की एक प्रमुख कविता है- ‘आज की सीता’ जो नारी अस्मिता, आत्मसम्मान और सामाजिक अन्याय के विरोध में एक साहसी स्वर प्रदान करती है। यह कविता प्राचीन काल की सीता की तुलना आज की स्त्री से करती है और यह दिखाती है कि कैसे आधुनिक स्त्री अब मौन नहीं है, वह अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करती है। यह रचना स्त्री सशक्तीकरण की एक प्रेरणादायी व्यवस्था है। यहाँ कवयित्री एक नारी की साहसी स्वर उभरकर सामने आता है। वह राम से कहती है कि अबल वह वही सीता नहीं रही, जो मर्यादा के नाम पर चुपचाप अन्याय सह लें। आज की स्त्री अब हर अन्याय के खिलाफ सवाल बनकर खड़ी होती है और जवाब भी खुद

लेती हैं। यहाँ कवयित्री यह बताती है कि अब की स्त्री, आँसुओं में बह जानेवाली जानकी नहीं है। वह बार-बार अग्निपरीक्षा नहीं देगी और न ही अपने चरित्र के प्रमाण प्रस्तुत करेगी। यह स्पष्ट संकेत है कि आज की नारी अपने अस्तित्व और चरित्र को लेकर अपराधबोध से मुक्त है, और अपने आत्म सम्मान को सर्वोपरी मानती है। जो सीता ने अतीत में चुप्पी से सब सही, समाज ने रावण की बुराई की जगह सीता की शुद्धता पर प्रश्न उठाया। कवयित्री कहती है कि दोष रावण की दृष्टियों में था, फिर भी सीता को कठघरे में खड़ा किया गया। यह आज की सच्चाई है, जब कोई अपराध होता है तो दोषी की बजाय पीड़िता से सवाल किए जाते हैं। यह मानसिकता नारी को बार-बार अपमानित करती है। यहाँ कवयित्री राम से सवाल करती है कि जब सीता पर अन्याय हुआ, तब राम मौन क्यों रहे? यह मौन पुरुष प्रधान समाज का प्रतीक है, जो नारी पर होते अन्याय को देखता तो है, पर आवाज़ नहीं उठाता। राम जैसे आदर्श पुरुष भी स्त्री को उसका अधिकार दिलाने में असमर्थ रहे, यही कारण है कि समय के साथ स्त्रियों ने अपने अधिकार खुद हासिल करने का बीड़ा उठाया है।

समय के प्रवाह ने नारी को नया रूप दिया है। अब वह सिर्फ सहनशील की मूर्ति नहीं, बल्कि शक्ति और प्रतिकार का रूप भी है। कल की सीता अब दुर्गा बन चुकी है जो अत्याचार को सहन नहीं करती, बल्कि उसका अंत करती है। यह परिवर्तन समाज में स्त्रियों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जहाँ वे अब न्याय, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की माँग करती हैं और इसे प्राप्त भी करती हैं।

“ए राम मुझे पूजकर भी मेरी/बोली लगा दी

गर्भ में मरने से दहेज जाती है, तब की पीड़ा मुझे दी जाती है”

यहाँ कवयित्री ने एक कटु और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। एक समय स्त्री का सीता, दुर्गा, लक्ष्मी आदि के रूप में पूजनिय मानते थे, उस समाज ने वास्तविक जीवनस में उसी स्त्री को गर्भ में मारा जाता है, दहेज की आग में झोंका जाता है। यह दोहरे सामाजिक मापदंडों पर तीखा व्यंग्य है। एक ओर स्त्री को आदर्श माना गया और दूसरी ओर उसी पर अत्याचार किया गया। आज की सीता चुप नहीं रहेगी। वह अब समर्पण नहीं, संघर्ष का मार्ग अपनाएगी। अपने सम्मान और अधिकार को याचना से नहीं, बल्कि दृढ़ता से प्राप्त करेगी। यह आधुनिक नारी की दृढ़प्रतिज्ञा चेतना है- जो अब संवेदनशील होकर भी निर्बल नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़नेवाली है। नारी कभी घर की लक्ष्मी, वंश की जननी मानी जाती थी, पर अब वही नारी जब सवाल पछती है, विरोध करती है, तब समाज उसे अभिशाप की तरह देखता है। सीता बार-बार कहती रहती है कि वह केवल अतीत की पीड़ा नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे हुए अत्याचार का हिसाब करने आई है। आज की सीता नारी मुक्ति की प्रतीक है, जो सामाजिक मर्यादाओं की बेडियों को तोड़ चुकी हैं। उनका विरोध तो सामाजिक व्यवस्था पर है, जहाँ नारी से हठ बार अपनी शुद्धता का प्रमाण माँगा जाता है, जबकि पुरुष मौन और मुक्त रहता है। यह आज की सच्चाई है- जब कोई अपराध होता है तो पीड़िता से सवाल पछता है। राम जैसे आदर्श पुरुष भी स्त्री को उसका अधिकार दिलाने में असमर्थ रहे, यह परिवर्तन समाज में स्त्रियों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जहाँ वे अब न्याय, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की माँग करती हैं और इसे प्राप्त भी करती हैं।

सीता यहाँ पौराणिक नारी का प्रतीक है, राम उस पुरुष समाज का जो न्यायप्रिय होते हुए भी स्त्री की रक्षा में असफल रहता है। अग्निपरीक्षा और चरित्र प्रमाण आज भी स्त्रियों की सामाजिक परीक्षा की मानसिकता को इंगित करते हैं। कविता यह बताती है कि सीता अब जंगल नहीं जाएगी, अब वह समाज से लड़कर अपने सम्मान को बचाएगी। शिखा कुमारी उपाध्याय की यह रचना आज के समाज को यह आइना दिखाने में पूर्णतः सफल होती है कि स्त्री अब चुप नहीं, वह दुर्गा बनकर अपने अस्तित्व की रक्षा करेगी।

कृषि उपार्जन एवं नवाचारी जनसंचार साधनों का पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में सशक्तीकरण (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. महानन्द द्विवेदी

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र)

शास. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगांज (म.प्र.)

श्रद्धा शुक्ला

शोधार्थी समाजशास्त्र,

शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश:-

नये युग की मांग है कि समाज और परिवार का सर्वांगीण संतुलित विकास किसी भी परिवार या समाज का संतुलन तभी सम्भव है जब समाज या परिवार की रचना करने वाले दो महत्वपूर्ण मानव इकाई जो महिला एवं पुरुष के रूप में रेखांकित होते हैं के विकास के मार्ग सम्यक हों। महिला और पुरुषों का विकास एकपक्षीय होने पर विकास लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं हो पाती। विगत सदियों पर गौर करें तो महिलाएं मूलतः घर की चाहरदीवारी में कैद हो गई थीं। विकास के सभी आयाम पुरुषों के पास संरक्षित हो गये थे। महिलाओं को भोजन, वस्त्र तक पुरुषों द्वारा देय होने लगा। जिस कारण महिलाओं के आत्मशक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती गई और वे सीमित दायरे में रहना ही अपना नियति मान बैठी। इस शोध पत्र में उक्त बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द:- कृषि, उपार्जन, नवाचारी, जनसंचार, साधनों, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, सशक्तीकरण आदि।

प्रस्तावना:- आजादी मिलने के साथ ही महिलाओं के जीवन चक्र में बदलाव आना शुरू हुआ। उन्हें शिक्षा के अवसर मिले और देश की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल अपने मत-अभिमत देने के अधिकार भी मिले। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान एक ऐसा पहलू सामने आया जिसके माध्यम से महिलाओं को पहलीबार अपने विचारधारा को सामने रखने का अवसर मिला। कुछ समय बाद जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को विचार प्रकट करने अपने शक्ति सामर्थ्य अनुकूल कार्य करने के अवसर मिलने लगे। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए महिलाओं के सक्षमता के लिए नये-नये मानक बने जिन्हें महिला सशक्तीकरण के मानदण्ड के रूप में रेखांकित किया जाने लगा।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो मानक निर्धारित किये गये उनमें से इस बात का चिन्तन किया गया कि सशक्तीकरण का मुख्य आधार आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की किसी न किसी रूप में भूमिका होनी चाहिए। महिलाओं की आर्थिक सक्षमता ही उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का समर्थ और सार्थक माध्यम बन सकती है। इस स्थिति में भी समाज और परिवार में महिलाओं की भूमिका प्रभावी बनेगी। वर्तमान में देखा जाये तो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और अर्थमूलक कार्य मिलने के अलग-अलग मानक हैं। प्रस्तुत अध्ययन के राजस्व क्षेत्र में मूलतः कृषि परिक्षेत्र प्रचुरता में है। इस क्षेत्र से लगभग 70 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग महिलाएं संलग्न हैं। इस संलग्नता में उनमें नवक्रांति के अवसर उपलब्ध कराये हैं। कृषि को पारम्परिक पद्धति से हटकर नये परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए इस क्षेत्र में भी नवाचारी कृषि का सूत्रपात होने लगा है। जिसमें महिलाओं की भूमिका भी प्रभावित दिख रही है। जो उनके सशक्तीकरण का परिचायक बनने का मार्ग प्रशस्त कर

सकेगी। महिलाओं को पुरुष के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वयतता से है। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रारंभिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन पहलुओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जिनका सीधा संबंध स्वावलम्बन और उत्थान से है। शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र इनमें से प्रमुख हैं। महिला की प्रगति पूरे घर परिवार समाज एवं राष्ट्र की प्रगति मानी जाती है। महिलाओं के प्रति होते तमाम अत्याचारों, शोषण की समाप्ति तथा दुराग्रही प्रकृतियों की समाप्ति को लेकर कृत संकल्पना दोहराने हेतु महिला सशक्तिकरण की रूप रेखा रखी गयी। ताकि नई सदी में हम एक ऐसे समाज और राष्ट्र के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें जहाँ महिलाओं को अपनी अभिव्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता हो। इस संकल्पना के साथ ही महात्मा गाँधी के कथन भी पूर्णतः साकार हों कि “जब तक भारत की महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं लेंगी, देश तरक्की नहीं कर सकता।”

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा मूलतः महिलाओं की कमजोर स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। महिलाएँ जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, करीब-करीब सम्पूर्ण विश्व में भेद-भाव, अन्याय एवं असमानता के चक्रव्यूह में से सदियों से ग्रसित रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति में कुछ भी नया नहीं है। बल्कि इसमें नई चीज यह है कि महिलाएँ अपनी कमजोर, भेदभाव एवं असमानता की स्थिति के विरुद्ध अब आवाज उठाने लगी हैं। आज यह स्वीकार किया जाने लगा है कि मानव राष्ट्र एवं विश्व का वास्तविक विकास महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अमर्त्यसेन ने इस बात पर जोर दिया है कि आज विश्व के विभिन्न देशों का विकास प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण शब्द का समाजशास्त्रीय अध्ययन में अपना एक विशेष अर्थ है। ‘सशक्तिकरण’ एवं महिला सशक्तिकरण शब्द आज सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों, विभिन्न विकास एजेंसियों, यूनाइटेड नेशन्स एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, महिला समस्याओं के अध्ययनों आदि के सन्दर्भ में सशक्तिकरण शब्द वृहत रूप से व्यवहार हो रहा है।

महिला सशक्तिकरण के अभिप्राय का मुख्य केन्द्र, राजनैतिक सत्ता की भागीदारी, वितरण एवं पुनर्वितरण की गतिशीलता में अवस्थित है, जिसके पास एक वैधता का आधार होता है। सत्ता दूसरों पर नियंत्रण रखने हेतु व्यक्ति की क्षमता है और इस प्रकार जब नियंत्रण की यह क्षमता वैधता प्राप्त कर लेती है, तो वह प्राधिकार बन जाती है। दरअसल सशक्तिकरण की तर्कसंगति में प्राधिकार की गत्यात्मकता शामिल है।

जब हम प्राधिकार अथवा उस अर्थ में वैधता प्राप्त सत्ता के वितरण अथवा पुनर्वितरण प्रक्रिया की बातें करते हैं तो स्वभाविक रूप से न केवल उस प्राधिकार हेतु वैधता के आधार पर बल्कि उन सामाजिक श्रेणी-विभाजनों पर भी सवाल करते हैं, जिनके माध्यम से सत्ता संबंध कार्यरूप में व्यवहृत होते हैं। इसी तर्क के आधार पर सत्ताहीनता को भी प्रदत्त सामाजिक व्यवस्था में वैधता प्रदान कर दी गई है, ताकि सत्ता-वितरण की सशक्त प्रक्रिया बनी रहे। सशक्तिकरण न तो औपचारिक ज्ञान मात्र है और न काल्पनिक जादुई छड़ी, बल्कि यह किसी विशिष्ट स्थान तथा कालखंड में घटित होने वाली मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, जहाँ किसी शक्तिहीन, पीड़ित या शोषित को भिन्न-भिन्न तरीके से शक्ति-सम्पन्न किया जाता है, जिससे वह मानव जीवन के चरमोत्कर्ष को वैधिक और नैतिक रूप में प्राप्त कर सके।

अतएव सशक्तिकरण एक बहु-आयामी एवं बहुस्तरीय अवधारणा

यह कोई अकेली चीज नहीं है। बल्कि यह कई कारकों जैसे-भौतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि की क्रिया और अंतरू क्रिया है। इसी संदर्भ में चिंतक महिला-सशक्तिकरण को भी देखते हैं। महिला सशक्तिकरण को सामान्यतया एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिनमें महिलाएँ भौतिक, मानवीय एवं बोद्धिक-जैसे ज्ञान, सूचना, विचार और वित्तीय स्रोतों जैसे धन अथवा धन तक पहुँच एवं घर, परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र आदि के संदर्भ में निर्णय लेने के सम्बन्ध में अधिक सहभागिता कर सकती हैं।

‘महिला- सशक्तिकरण’ शब्द सामाजिक न्याय एवं समानता प्राप्ति हेतु महिलाओं के संघर्ष से जुड़ी हुई है। महिला-सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं है कि उन्हें दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की शक्ति प्रदान करना तथा अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने हेतु शक्ति सम्पन्न बनाना। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मतलब यह है कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो, जिससे उसके महत्व को स्वीकार किया जा सके तथा उसे समान नागरिक एवं समान अधिकार की स्थिति तक ला सके। उनके लिए शक्ति का मतलब यह है कि न केवल घर के अन्तर्गत बल्कि समाज के प्रत्येक स्तर एवं पक्ष में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उनकी शक्ति के मूल्य एवं भागीदारी को समाज द्वारा उचित मान्यता भी प्राप्त हो सके।

महिलाओं की सशक्तिकरण होने से उनमें अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचानने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ताकि वे एक पूर्ण नागरिक के रूप में अपने देश एवं मानवता की सेवा में सहायता पहुँचा सकें। अपनी क्षमताओं के अनुरूप वे अपने परिवार, समुदाय एवं समाज के प्रत्येक स्तर पर अपनी एक सकारात्मक छवि का निर्माण कर सकें और अपने अंदर आत्मविश्वास को भी उत्पन्न करें। उनमें क्षमताओं का इतना विकास हो सके कि वे किसी भी समस्या का स्वयं समाधान कर सकें।

जब महिलाएँ अपने प्रति होने वाले सामाजिक-मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक अन्याय, लिंग-भेद, असमानता, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध जागरूक हो जाए तो यह समझा जा सकता है कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है। वास्तव में, इसकी शुरुआत तब होती है, जब वे अपनी सकारात्मक स्वच्छ छवि, अधिकार, कर्तव्य और अपनी क्षमताओं के प्रति पूरी जागरूक हो जाती है।

महिला सशक्तिकरण की सार्थकता यह है कि, उन्हें इतना योग्य बनाया जाए कि वे अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचान सकें और इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकें। वे अपने जीवन में विचारों, उसकी अभिव्यक्ति एवं कार्यों की स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें। इतना ही नहीं, उन्हें केवल अपनी योग्यता को ही नहीं पहचानना है, बल्कि इसके लिए उन्हें अवसर, सुविधा, बाहरी और आंतरिक वातावरण पर भी ध्यान देना है, ताकि वे अपनी क्षमताओं एवं आत्मसम्मान की समृद्धि भी कर सकें। अपने प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता भी विकसित हो सके।

लैंगिक-न्याय, लैंगिक-समानता, महिला-अधिकार एवं महिला-सशक्तिकरण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इनमें आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया होते रहते हैं। जब लैंगिक न्याय एवं समानता तथा महिला-अधिकार को मानवाधिकार के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है तभी यह कहा जा सकता है कि महिला-सशक्तिकरण के अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई है तथा लैंगिक-समानता एवं न्याय को तभी प्राप्त किया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण को लिंग-समानता से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। महिला-सशक्तिकरण से लिंग समानता की स्थिति उत्पन्न होती है एवं लिंग-समानता की स्थिति से महिला-सशक्तिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। समान एवं स्थायी मानवीय विकास तभी संभव हो सकता है, जब समाज के हर स्तर पर स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच समानता की स्थिति आ जाए। लिंग-समानता का मतलब संसाधनों तक पहुँच के समान अवसरों, समानता से विश्वास के साथ मूल्य-व्यवस्था का निर्माण, निर्णय निर्धारण करने में पुरुष के समान सहभागिता तथा संसाधनों पर समान नियंत्रण से तात्पर्य लगाया जाता है।

सशक्तिकरण का अर्थ है 'शक्तिसम्पन्न' करना अर्थात् जो पहले से शक्तिहीन है, या शक्तिहीन बनाया गया है या शक्तिहीन माना गया है या जिसे शक्तिहीन रूप में देखा जाता है उसे ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जाएँ जो उसके बहु-आयामी व्यक्तित्व के सम्मान हेतु, पुष्पित-पल्लवित और समृद्ध करने हेतु आवश्यक है। इस सम्मान और समृद्धि की कोई सीमा नहीं है और विभिन्न समाज में यह भिन्न-भिन्न स्वरूप व्यापकता, गहराई या अन्तर्वस्तु में परिभाषित हो सकती है। किन्तु एक मापदण्ड यह तो हो ही सकता है कि यह सम्मान एवं समृद्धि पुरुषों से किसी भी अर्थ में कम न हो। सशक्तिकरण किसी भी प्रकार के भेदभाव विषमता, स्तरण, अधीनता, हिंसा, अशुभ्यता, वंचना तथा किसी भी आभाव को मिटाने वाली वह प्रक्रिया है जो अन्ततः सकारात्मक शक्ति का उपयोग करने की क्षमता पैदा करती है। महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण का अर्थ है संसाधनों पर उनका नियंत्रण तथा निर्णय का अधिकार।

विभिन्न मत और विचारों को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि सशक्तिकरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक यह है कि महिलाओं की सैद्धान्तिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उनकी दयनीय स्थिति को समझना महिलाओं के दायम दर्जे के लिए सैद्धान्तिक और सांस्कृतिक विचारधारा जिम्मेदार है। इन विचारधारों के कारण शक्ति संतुलन पुरुषों के पक्ष में रहा है। इसलिए सशक्तिकरण का तात्पर्य सिर्फ संसाधनों पर महिलाओं के अधिकार स्थापित होने से नहीं है इसका मूल तात्पर्य है समाज में मौजूद पुरुषों के अधिकार को निरापद बनाने वाली विचारधारा को चुनौती देना और समाप्त करना। इसके अतिरिक्त संसाधनों पर अधिकार, निर्णय की स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी, स्वयं में विश्वास, इच्छा की अभिव्यक्ति अवसर की समता, आदि तत्व भी सशक्तिकरण की अवधारणा के परिधि में आता है।

महिला-सशक्तिकरण' शब्द सामाजिक न्याय और समानता प्राप्ति हेतु महिलाओं के संघर्ष से जुड़ी हुई है। वास्तविक सशक्तिकरण विचारों जो व्यक्ति की सोच, उम्मीद, विश्वास, मूल्य एवं मनोवृत्तियों में विद्यमान है को नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण महिलाओं के शक्ति को निर्धारित कर स्रोतों पर उनकी पकड़ को मजबूत बनाता है, अर्थात् सशक्तिकरण का अर्थ शक्तिहीनता से शक्ति समानता की ओर जाना है। यह महिलाओं में शक्ति की वृद्धि करता है तथा उनमें एक सकारात्मक सोच का निर्माण करता है।

अध्ययन क्षेत्र - शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को साक्षात्कार के लिए निदर्शन विधि के माध्यम से चयन करते समय सर्वप्रथम गाँवों का चयन किया गया। रीवा में कुल 2817 गाँव हैं, जो 9 विकासखण्डों में सम्मिलित है। दैव निदर्शन के लाटरी प्रणाली द्वारा 4 विकासखण्डों, सिरमौर, त्योंथर, जवा, हजूर का चयन किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक चयनित विकास खण्ड में से एक-एक कुल 4 गाँवों, पहाड़ी, बन्ना-पांती, घोपी, पिपरवार का चयन भी दैव निदर्शन की लाटरी पद्धति से किया गया है।

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम-

महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य इस प्रकार है-

(1) परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध करके, महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है।

(2) इसके लिए उन्हें उपयुक्त समूहों में संगठित किया जाता है, विपणन सम्बन्धी सम्पर्क कायम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। सेवाओं में मदद दी जाती है और ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(3) इस योजना में रोजगार के आठ परम्परागत क्षेत्र शामिल हैं जो इस प्रकार हैं- कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्राम उद्योग और रेशम कीट पालन आदि।

(4) यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, राज्य निगमों, जिला ग्राम्य विकास अधिकरणों, सहकारिताओं, परिसंघों और ऐसी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लागू की जा रही है जो कम-से-कम तीन साल से अस्तित्व में हैं।

स्वयं सिद्धा-महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इस योजना की दीर्घकालीन उद्देश्य महिलाओं का चहुँमुखी विकास, विशेष तोर पर उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। इसके लिए सभी वर्तमान क्षेत्रीय कार्यक्रमों में समन्वय और लगातार चलने वाली प्रक्रिया के जरिये संसाधनों तक उनकी सीधी पहुँच तथा नियंत्रण सुनिश्चित करना है। योजना का उद्देश्य इस प्रकार है। लघु ऋण योजनाओं तक महिलाओं की पहुँच बनाना। ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना और आर्थिक मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना। महिला और बाल-विकास मंत्रालय और अन्य विभागों की सेवाओं की तरफ अभिमुख करना।

महिला सामाख्या कार्यक्रम-महिला सामाख्या भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, जिसकी अवधारणा 1986 की नयी शिक्षा प्रणाली से उभरी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कमजोर, वंचित, निर्धन वर्गों की महिलाओं व बालिकाओं की, शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा को व्यापक अर्थों में देखते हुए व्यावहारिक शिक्षा का समावेश किया गया है। इसमें नारीवादी सोच का विकास, स्वयं के मुद्दों तथा सामाजिक- आर्थिक मुद्दों पर समझ विकसित करना तथा सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी व हस्तक्षेप को प्रमुखता से शामिल किया गया है।

महिला सामाख्या शैक्षिक पहुँच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अन्तराल का निराकरण करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ी एवं वंचित महिलाओं को इस योग्य बनाना है कि वे अलग-अलग पड़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ सकें और दमनकारी सामाजिक रीति-रिवाज के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकें। वर्तमान में महिला सामाख्या कार्यक्रम देश के ग्यारह राज्यों में संचालित किया जा रहा है।

स्वावलम्बन-इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परम्परागत तथा गैर-परम्परागत व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें स्थायी आधार पर रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता देना है। इस योजना के अधीन लक्ष्य-समूहों में निर्धन तथा जरूरतमन्द तथा समाज के दुर्बल वर्गों की महिलाएँ शामिल की जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्वायत्त संगठनों, न्यासों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय

सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण दिये जाने वाले व्यवसायों में शामिल हैं-कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रानिक्स, घड़ीसाज, रेडियो ओर टेलिविजन की मरम्मत, वस्त्रों की सिलाई, हैंडलूम का कपड़ा बुनना, सामुदायिक स्वास्थ्य-कार्य तथा कशीदाकारी।

महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों कार्यक्रमों ओर स्कीमों के बेहतर अभिसरण के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की इस पहल को प्रचलन में लाया गया। इसके तहत देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई पहलों को सुर्वाही बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य मिशन प्राधिकरणों ओर महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों सहित राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचे स्थापित किये गए हैं।

वर्तमान में कृषि के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाएँ भारत के मानव संसाधनों का लगभग आधा (48 प्रतिशत) हिस्सा हैं। महिलाएँ कृषि उत्पादन में औसतन 60 से 70 फीसदी श्रम का योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे बूवाई से लेकर फसल प्रसंस्करण तक के कृषि उत्पादन में कई प्रकार के कार्य करती हैं। पशुधन, मुर्गी पालन और सभी कृषि उद्यमों की देखरेख भी करती हैं। उनके काम के घंटे प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक होते हैं। वे कृषि के लिए भूमि की तैयारी से फसल की उपज तक की गतिविधियों की एक सरगम में अदृश्य कार्य बलों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

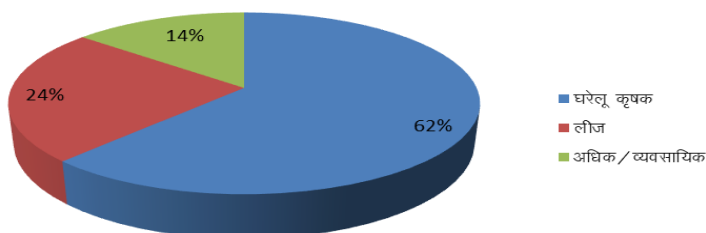
कृषि प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकास के साथ महिलाओं को तकनीकी सम्पन्न करने और उनके तकनीकी कौशल का सम्मान करने के लिए महिलाओं का सामूहिक मीडिया उपयोग व्यवहार मुख्यतः केंद्र में है जो उनके खेती और घर में उत्पादकता में वृद्धि की ओर दर्शित होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में कृषक महिलाओं द्वारा कृषि नवाचार के उपयोग व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश के अन्तर्गत रीवा जिले शोध अध्ययन का क्षेत्र चुना है जिसमें पिछड़ी जाति की महिला कृषकों के न्यादर्श को तैयार कर अध्ययन किया गया है। निष्कर्षों से पता चला कि अधिकांश (70 प्रतिशत) प्राथमिक स्तर पर शिक्षित थी, संचार माध्यमों की उपलब्धता में टेलीविजन माध्यम का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से अधिक रहा व कृषि सूचनाओं की प्राप्ति के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों पर ज्यादातर महिलाएँ निर्भर पायी गयीं, जिसमें संचार प्रारूप अंतर्व्यक्तिक के रूप में सामने आया।

तालिका क्रमांक 1

कृषि व्यवसाय का प्रकार

क्रमांक	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1.	घरेलू कृषक	31	62.00
2.	लीज	12	24.00
3.	अधिक/व्यवसायिक	7	14.00
	योग	50	100.00

आरेख क्रमांक 1



उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि व्यवसाय का प्रकार से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के विचारों का साक्षात्कार में शामिल किया गया है जिसमें 62.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाता घरेलू कृषकों के रूप में है, 24.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की लीज है जबकि 14.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की अधिक/व्यवसायिक है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 62.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की घरेलू कृषक के रूप में है। जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ घर के कार्यों के साथ-साथ कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों में संलग्न रहती हैं।

तालिका क्रमांक 2

कृषि उत्पादन से आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	0-05 हजार	26	52.00
2.	10-15 हजार	13	13.00
3.	15-25 हजार	8	16.00
4.	25 हजार से अधिक	3	6.00
	योग	50	100.00

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि उत्पादन से आय के आधार पर उत्तरदाताओं को साक्षात्कार में शामिल किया गया है जिसमें 52.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 0-05 हजार रुपये तक है, 13.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 05-15 हजार रुपये तक है, 16.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 15-25 हजार रुपये तक है जबकि 6.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 25 हजार रुपये से अधिक है।

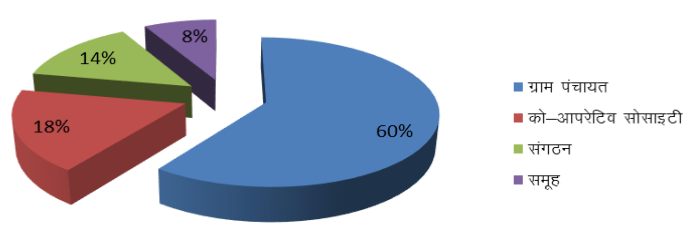
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 52.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 0-05 हजार रुपये तक है, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ घर के कार्यों के साथ-साथ कृषि से आय अर्जित कर रही हैं।

तालिका क्रमांक 3

सामाजिक सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	ग्राम पंचायत	30	60.00
2.	को-आपरेटिव सोसाइटी	9	18.00
3.	संगठन	7	14.00
4.	समूह	4	8.00
	योग	50	100.00

आरेख क्रमांक 2



उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सामाजिक सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं को साक्षात्कार में शामिल किया गया है जिसमें 60.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 0-05 हजार रुपये तक है, 18.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 05-15 हजार रुपये तक है, 14.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 15-25 हजार रुपये तक है जबकि 8.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 25 हजार रुपये से अधिक है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 0-05 हजार रुपये तक है, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर के कार्यों के साथ-साथ कृषि से आय अर्जित कर रही हैं।

तालिका क्रमांक 4
सूचना प्राप्ति के माध्यम के उपयोग का विवरण

क्रमांक	विवरण	कुल संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	टेलीविजन	50	30	60.00
2.	रेडियो	50	12	24.00
3.	समाचार पत्र	50	7	14.00
4.	मोबाइल	50	3	6.00

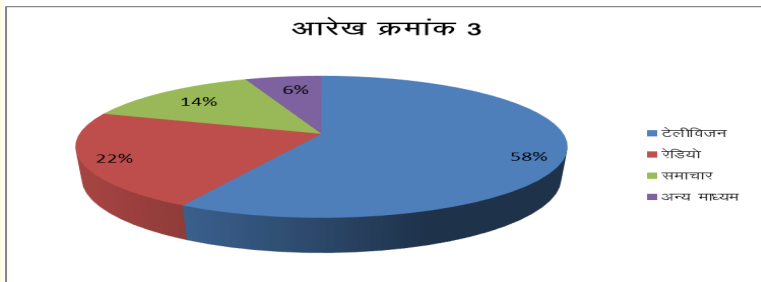
उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सूचना प्राप्ति के माध्यम के उपयोग का वर्गीकरण करके उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात होता है कि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता टेलीविजन को उपयोगी बताया है, 24.00 प्रतिशत उत्तरदाता रेडियो को उपयोगी बताया है, 14.00 प्रतिशत उत्तरदाता समाचार पत्र को उपयोगी बताया है जबकि 6.00 प्रतिशत उत्तरदाता मोबाइल को उपयोगी बताया है।

इस प्रकार से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत सूचना प्राप्ति के माध्यम टेलीविजन को उपयोगी बताया है जिससे लोगों तक सूचना की जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं।

तालिका क्रमांक 5
कृषि संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त उपयोग का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	टेलीविजन	29	60.00
2.	रेडियो	11	22.00
3.	समाचार	7	14.00
4.	अन्य माध्यम	3	6.00
	योग	50	100.00

आरेख क्रमांक 3



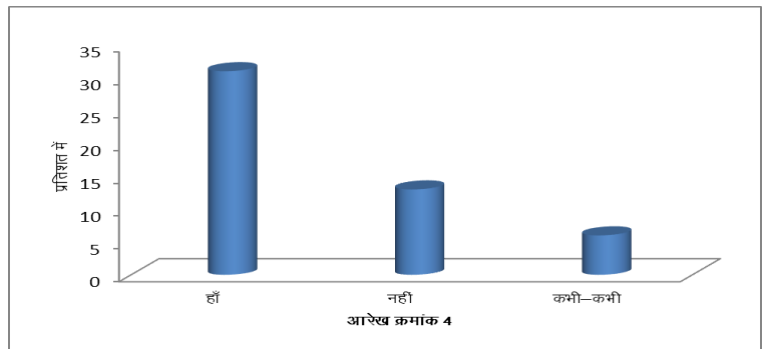
उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त उपयोग का वर्गीकरण करके उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात होता है कि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता प्रयुक्त टेलीविजन को उपयोगी बताया है, 22.50 प्रतिशत उत्तरदाता प्रयुक्त रेडियो को उपयोगी बताया है, 22.00 प्रतिशत उत्तरदाता प्रयुक्त समाचार को उपयोगी बताया है जबकि 6.00 प्रतिशत उत्तरदाता ने प्रयुक्त अन्य माध्यमों को उपयोगी बताया है।

इस प्रकार से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत सूचना

प्राप्ति के प्रयुक्त टेलीविजन को उपयोगी बताया है जिससे लोगों तक सूचना की जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं।

तालिका क्रमांक 6
नवाचारों का कृषि कार्य में प्रयोग का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	31	62.00
2.	नहीं	13	26.00
3.	कभी-कभी	6	12.00
	योग	50	100.00



उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि नवाचारों का कृषि कार्य में प्रयोग का वर्गीकरण करके उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात होता है कि 62.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में प्रयोग को हाँ में सहमति दी है, 26.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में प्रयोग को नहीं में सहमति दी है, जबकि 12.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में प्रयोग को कभी-कभी में सहमति दी है।

इस प्रकार से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 62.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में प्रयोग को हाँ में सहमति दी है, जिससे लोगों तक नवाचारों का कृषि कार्य में प्रयोग देखने को मिल रहा है। जिससे कृषि कार्य में फसलों के उत्पादन में नवाचार से वृद्धि हुई है।

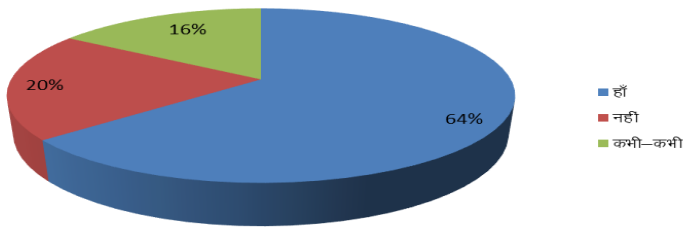
तालिका क्रमांक 7
कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	32	62.00
2.	नहीं	10	20.00
3.	कभी-कभी	8	16.00
	योग	50	100.00

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा का वर्गीकरण करके उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात होता है कि 62.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा किया हाँ में सहमति दी है, 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा नहीं किया जबकि 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा कभी-कभी किया है।

इस प्रकार से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 62.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा किया हाँ में सहमति दी है, जिससे लोगों तक जिससे लोगों को कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा करने से एक दूसरे को लाभ हुआ।

आरेख क्रमांक 5



नवाचारी कृषि एवं महिला सशक्तिकरण:- भारत की कुल आबादी में से लगभग 70 प्रतिशत आबादी खेती-किसानी का काम करते हैं। इस देश के किसानों को भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है लेकिन जब देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति की बात आती है तो आंदोलन और समझौतों के आगे बात नहीं बढ़ पाती। यही कारण है कि केंद्र सरकार बदलते समय के साथ ही कृषि विभाग में विकास के लिए अलग अलग तरह के योजनाओं का ऐलान करते रहते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर कई प्रयास भी किए गए हैं। कृषि के लिए अब आधुनिक उपकरणों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सहारा लिया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों में से एक है मंडियों को डिजिटल किया जाना।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है, जो वर्तमान में पूरे देश में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ता है। साल 2016 में ई-नाम योजना के तहत मंडियों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की गई थी। इस पोर्टल का मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है, जिससे किसानों को उत्पादों का उन्हें ज्यादा और उचित दाम मिल सके। इस पोर्टल की मदद से किसान घर बैठे ई-मंडियों में अपना भी सामान बेच सकते हैं। दरअसल भारत में किसी भी कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने की प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल हैं। इस जटिल प्रक्रिया से बेचने के लिए अक्सर ही किसान अपनी उपज को कम कीमत पर बेच देते हैं। कृषि का बुनियादी ढांचा उत्पादकों के आस-पास घूमता है, जिसमें उत्पादक यानी किसान अपने द्वारा उपजाए अनाजों को बाजार लेकर जाते हैं। यह एपीएमसी के अंतर्गत आता है। इस बाजार प्रणाली में सबसे ज्यादा समस्या किसानों या उत्पादकों को ही होती है। पहले तो उन्हें लंबी यात्रा करके अपने अनाजों को बाजार ले जाना पड़ता है। कई बार इस दौरान ही किसानों की कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं। किसान स्थानीय मंडी पहुंचकर अपने उत्पाद को बेचते हैं, जहां पर उनके उत्पाद की ग्रेडिंग छंटाई और पैकेजिंग होती है इसके बाद स्थानीय एजेंट के जरिए खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेताओं के लिए माल खरीदा जाता है। यह एजेंट हमेशा ही किसानों को कम कीमत पर सामान बेचने को कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कत ये है कि यहां किसान सीधे विक्रेताओं से संपर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसे में किसान एजेंट को ही अपने उत्पाद बेच देते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। इस तरह के बाजार में जहां किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जबकि बिचौलियों की चांदी होती है। कहीं ना कहीं इस तरह के बाजार में बिचौलियों का एक अधिकारी रहता है।

कोई भी किसान ई-नाम पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम रजिस्टर करवाने के बाद कोई भी किसान किसी भी ई-नाम मंडियों में व्यापारियों को ऑनलाइन बिक्री के लिए अपनी उपज अपलोड कर सकते हैं और व्यापारी भी किसी भी स्थान से ई-नाम के तहत बिक्री के

लिए उपलब्ध लाट के लिए बोली लगा सकते हैं। गांवों का देश भारत ग्रामीण से शहरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों के पेशे और उम्मीदों में भी बदलाव महसूस किया जा रहा है। दरअसल साल 2021 की तुलना में साल 2022 में कृषि की लागत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका कारण खेती के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजल, खाद, उर्वरक और कीटनाशकों की कीमतों में बढ़ोतरी है। पिछले एक साल में ही इसमें 10 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ ऐसा ही हाल खाद और कीटनाशकों का भी है। साल 2022 में 50 किलो की एनपीके उर्वरक की एक बोरी अब 275 में आती है, जबकि यही साल 2021 में 265 की थी। बीते साल 2021-22 के खरीद विपणन सीजन में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 72 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और साल 2022-23 के लिए गेहूं के एमएसपी केवल 40 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी हुई है। वहाँ कीट नाशकों की बात करें तो इसकी कीमत में भी 10 से 20 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई। खेती के दौरान लगने वाले सामानों की बढ़ती लागत के साथ किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमतों में फसलों की बिक्री से चिंतित है। हालत इतनी खराब है कि किसान एक क्विंटल धान बेचकर भी 50 किलो डीएपी खाद तक नहीं खरीद पाते, डीएपी के सरकारी दाम 1206 रुपये हैं, लेकिन वो 1400-1600 में मिलती है।

कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहे अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र कृषक महिलाओं की भागीदारी के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय योगदान और पहल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भुवनेश्वर में स्थापित केंद्रीय महिला संस्थान, जिसे पहले राष्ट्रीय केंद्र के रूप में गठित किया गया था, लेकिन हाल में इस विषय के महत्व को देखते हुए इसे संस्थान का दर्जा दिया गया है।

मुख्य रूप से अनुसंधान और कृषि प्रसार पर आधारित इस संस्थान ने केवल ओडिशा में ही नहीं, बल्कि देश भर में कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहद खास काम किया है और सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। कृषक सामाजिक-आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती उपयोगिता की देखते हुए इस संस्थान ने जेंडर नॉलेज सिस्टम पोर्टल का विकास किया है, जो कृषक महिलाओं से संबंधित उपयोगी सूचनाओं की एकल खिड़की की तरह काम करता है और योजनाओं की जानकारी दी गई है, जो कृषक महिलाओं के साथ नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए यहां महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, सूचनाओं, प्रकाशना भी उपयोगी हैं।

संस्थान द्वारा कृषक महिलाओं को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और कुशल बनाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बीज-उपचार, समेकित कीट प्रबंध, बीज उत्पादन, मुर्गी पालन जैसे विषयों पर व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। महिला मछुआरों के लिए सूखी मछलियों के उत्पादन और स्वच्छ सार-संभाल पर चार क्षेत्रीय भाषाओं में मैनुअल तैयार किया गया है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में यह काम ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कृषक महिलाओं की पोषण और आजीविका सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को केंद्र में रखकर समेकित कृषि के मॉडल तैयार किए गए हैं, आमदनी बढ़ाने वाला और उपयोगी पाया गया है।

कृषक महिला सशक्तिकरण की योजनाओं और कार्यक्रमों ने देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और उन्हें स्वाभिमान से जीने की राह दिखाई है। अनेक महिलाएं अपने गांव-कस्बे में कामयाबी की

मिसाल बन गई हैं। कृषक महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा मोटे अनाजों से उत्पाद तैयार करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाई गई हैं। इस संबंध में यह जानना भी आवश्यक है कि भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशिष्ट स्वयंसहायता समूह गठित किए जाते हैं, जिनमें कौशल विकास, दस्तकारी, हथकरघा उद्योग जैसे अनेक आमदनी बढ़ाने वाले व्यवसायों के लिए सहायता दी जाती है। इन समूहों में कृषक महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल होकर आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ रही हैं।

दरअसल कृषक महिलाओं को खेती के काम के दौरान चारा, ईंधन, खाद, बीज, फसल, सब्जियाँ जैसे अनेक सामानों या बोझ को इधर-उधर ले जाना पड़ता महिलाएं इसे सिर पर रखकर ढोती हैं, जिससे उन्हें अकसर सेहत संबंधी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष युक्ति का विकास किया, जिसे कंधों के सहारे सिर पर पहना जाता है। इससे सारा बोझ केवल सिर पर नहीं पड़ता, बल्कि कंधों पर भी बंट जाता है। उपयोग में आसानी और हलका होने के कारण इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह यह भी देखा गया कि धान की बुआई, फसलों की गहाई, फलों और सब्जियों की तुड़ाई या चुनाई के दौरान महिलाओं को संक्रमण, चोट, खुजली आदि का खतरा होता है, क्योंकि वे पहनती।

कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण को वर्तमान सरकार ने गंभीरता से लिया है और माना है कि कृषि विकास की हर योजना में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके लिए योजनाओं में आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आवंटित बजट की 30 प्रतिशत राशि कृषक महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसका लाभ कृषक महिलाओं को उन्नत कृषि प्रणालियों का प्रशिक्षण देने में भी मिल रहा है। देश के 28 राज्यों में इस मिशन को राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। इस क्रम में राष्ट्रीय तिलहन और तेल ताड़ मिशन में भी आवंटित बजट की 30 प्रतिशत राशि को महिला लाभार्थियों तथा कृषक महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करके उन्हें कृषि के लिए आवश्यक सामान, तकनीकी और प्रसार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन के अंतर्गत कृषक महिलाओं को बीज-गांव कार्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम में भागीदारी का समान रूप से अवसर दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे इसमें कृषक महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें और इसके लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराएं। इसी तरह राज्य सरकारों को कृषि प्रसार कार्यक्रमों में कृषक महिलाओं और कृषि प्रसार महिला कर्मियों को शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत कम से कम 30 प्रतिशत साधनों को महिलाओं के सशक्तिकरण पर खर्च करने का निर्देश दिया गया है।

कृषि संबंधी योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कृषक महिलाओं की भागीदारी ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सुनिश्चित की गई है। अब कृषक महिलाओं को कृषक सलाहकार समिति में अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। विशिष्ट रूप से कृषक महिलाओं के लिए विकसित तकनीकों को खेत में ले जाने से पहले कृषक महिलाओं द्वारा जांचने-परखने का प्रावधान भी किया गया है।

पारम्परिक सोच और चिंतन को नकारती हुई समकालीन महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध करते हुए दिख

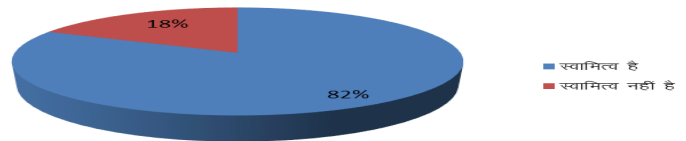
रही हैं। पिछड़ा वर्ग समुदाय जो मूलतः कृषि क्षेत्र से जुड़ा रहा है, के आर्थिक विकास का आधार कृषि उत्पादन रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका धीरे-धीरे प्रभावी होने लगी है। पूर्व में महिलाओं के सामने कृषि संबंधी जो कठिनाई थी वह कृषि कार्य में पारम्परिक संसाधनों की उपस्थिति, कृषि उत्पादन के विपणन की समस्या तथा उन्नत किस्म के बीजों को अभाव के साथ-साथ यांत्रिक उपकरणों की कमी रही है। समय के साथ इन नवीन चीजों के आ जाने से महिलाओं को कृषि कार्य में सहायता मिलने लगी है। जिसके माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होने लगी है। अध्ययन के दौरान अध्ययन क्षेत्र की कृषक महिलाओं से कृषि उत्पादन के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न प्रकार के आय और कृषि लाभ के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है-

तालिका क्रमांक 8

कृषि भूमि स्वामित्व पर उत्तरदाताओं के विचार

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वामित्व है	41	82.00
2.	स्वामित्व नहीं है	9	18.00
	योग	50	100.00

आरेख क्रमांक 6



उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि स्वामित्व पर उत्तरदाताओं के विचार का साक्षात्कार में महिलाओं को शामिल किया गया है जिसमें 82.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की स्वामित्व है जबकि 18.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की स्वामित्व नहीं है। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 18.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की स्वामित्व है। यह स्वामित्व मूलतः महिलाओं के पति के होने के कारण व्यावहारिक रूप से महिलाएं उस पर अपना स्वामित्व मानती हैं। क्योंकि पति और पत्नी में संवेत रूप से एक इकाई मानी जाती है।

तालिका क्रमांक 9

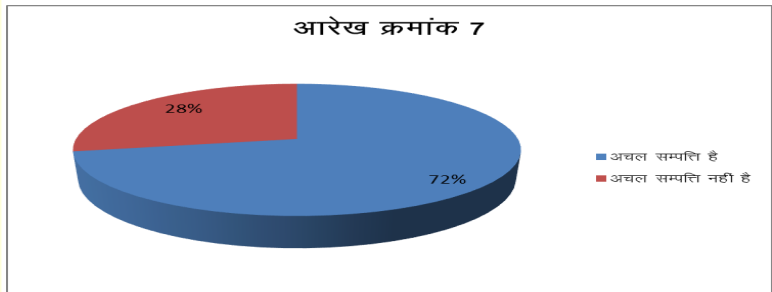
कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन का विवरण

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	साधन है	38	76.00
2.	साधन नहीं है	12	24.00
	योग	50	100.00

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन का विवरण के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 76 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन है जबकि 24 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन नहीं है। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 76 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की परिवार में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध है।

तालिका क्रमांक 10
अचल सम्पत्ति के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार

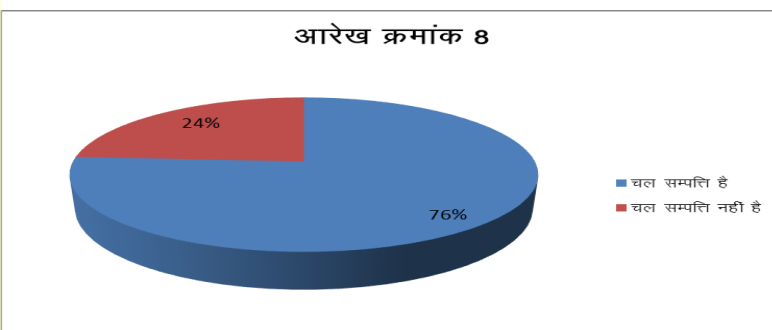
क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	अचल सम्पत्ति है	36	72.00
2.	अचल सम्पत्ति नहीं है	14	28.00
	योग	50	100.00



उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन का विवरण के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 72.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन है जबकि 28.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन नहीं है। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 72.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की परिवार में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध है।

तालिका क्रमांक 11
चल सम्पत्ति में उत्तरदाताओं के विचार

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	चल सम्पत्ति है	38	76
2.	चल सम्पत्ति नहीं है	12	24
	योग	50	100.00



उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि चल सम्पत्ति में उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 76.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन है जबकि 24.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन नहीं है। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 76.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की परिवार में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कृषि संबंधी योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कृषक महिलाओं की भागीदारी ब्लॉक, जिला

और राज्य स्तर पर सुनिश्चित की गई है। अब कृषक महिलाओं को कृषक सलाहकार समिति में अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। विशिष्ट रूप से कृषक महिलाओं के लिए विकसित तकनीकों को खेत में ले जाने से पहले कृषक महिलाओं द्वारा जांचने-परखने का प्रावधान भी किया गया है।

पारम्परिक सोच और चिंतन को नकारती हुई समकालीन महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध करते हुए दिखा रही हैं। पिछड़ा वर्ग समुदाय जो मूलतः कृषि क्षेत्र से जुड़ा रहा है, के आर्थिक विकास का आधार कृषि उत्पादन रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका धीरे-धीरे प्रभावी होने लगी है। पूर्व में महिलाओं के सामने कृषि संबंधी जो कठिनाई थी वह कृषि कार्य में पारम्परिक संसाधनों की उपस्थिति, कृषि उत्पादन के विपणन की समस्या तथा उन्नत किस्म के बीजों को अभाव के साथ-साथ यांत्रिक उपकरणों की कमी रही है। समय के साथ इन नवीन चीजों के आ जाने से महिलाओं को कृषि कार्य में सहायता मिलने लगी है। जिसके माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होने लगी है। अध्ययन के दौरान अध्ययन क्षेत्र की कृषक महिलाओं से कृषि उत्पादन के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न प्रकार के आय और कृषि लाभ पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को मिल रहा है। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में सशक्तिकरण में सार्थक लाभ हो रहा है महिलाएं अपने पैरों पर स्वतः खड़ी होकर घर की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने में सशक्त हुई हैं।

संदर्भ स्रोत:-

1. सिंधी, पी.एम. एण्ड मोदी, बेला (1974), फारमर्स इग्लोरेन्स एण्ड द रोल ऑफ टेलीविजन इन एग्रीकल्चर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद।
2. सिंह, राजेन्द्र कुमार, (1966), ग्रामीण राजनीतिक अभिजन, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
3. सकसेना, गोपाल, (2000), फोरटी इयर्स ऑफ टेलीविजन इन इण्डिया, विन्पुरा, जनवरी-मार्च, वाल्युम 37, इशू, पृ. 32
4. सिंह, योगेन्द्र, (2002), कल्चर चेन्ज इन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. सिसोदिया, मतीन्द्र सिंह, (2005), तृण मूल स्तर पर विकेन्द्रकृत अभिशासन का ग्रामीण सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव-मध्यप्रदेश के गाँवों का अध्ययन, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन।
6. सिंह, योगेन्द्र, (2002), कल्चर चेन्ज इन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. श्रीनिवास, एम.एन., (1955) सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैसूर विलेज इन इण्डिया
8. श्रीवास्तव, एस.एल. (1973), कल्चरल चेन्ज एण्ड सोशल चेन्ज एमंग द रामगाँस मेन इन इण्डिया, वाल्युम 53, नं. 1 जनवरी-मार्च
9. श्रीनिवास, एम.एन., (1962), कास्ट इन मॉडर्न इण्डिया एण्ड अदर एसे, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे।

अति यथार्थवादी कहानी: एक सामाजिक दृष्टिकोण

डॉ. श्रीमाया सी

सह प्राध्यापक, हिन्दी विभाग

पय्यन्नूर कॉलेज, पय्यन्नूर, केरला - 670327

Mob : 9495868174 Email : sreemaya2012@gmail.com

स्वतंत्रता हमारे एवं देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। जो जीवन के बीच में है, कहानीकार ने अनुभव किया कि आज़ादी के बाद हमारे जीवन के आदर्श और मूल्य कितनी तेजी से बदलते हैं, और उनमें एक ज़बरदस्त संघर्ष आया है। इस संघर्ष को, उसकी सारी गहनता, संवेद और नियति के साथ पहली बार इतनी यथार्थता और निर्भीकता से हिंदी के नये कहानीकार की चेतना ने ग्रहण किया। उसने इस युग के संघर्ष को उसके युगबोध के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान इंसान की चेतना को आत्मसात् किया। इसने पहली बार इंसान को परंपरा पुराण, संस्कृति और धर्म से अलग कर उसे इंसान के रूप में देखने का प्रयत्न किया। यही है 'अतिथार्थवादी' कहानी का निजत्व और उसका अपना व्यक्तित्व। इन जीवनगत, मूल्यगत संघर्षों, उसकी आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की चुनौतियों से, रचना के प्राणों से लड़ने का सत्य - यही है स्वतंत्रता के बाद की 'अतिथार्थवादी कहानी' - यही है उसका अपना अपूर्व व्यक्तित्व और निजत्व।

कहानीकार अपनी लंबी कहानियों में व्यक्ति और परिवार के यथार्थ संघर्ष को समाज के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की और बढ़ रहा है और उसकी वे कहानियाँ जिन का विषय व्यक्ति का अकेलापन, हताश और फ्रस्ट्रेशन है। 'सुहागनें' 'आर्द्रा' 'एक और जिन्दगी' तथा 'मित्रों मरजानी' कहानियाँ अपने क्षेत्र की परम मानवीय और सार्थक रचनाएँ हैं।

भारतीय समाज के आधुनिक परिवेश का प्रारंभ ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के आने के बाद से होता है। अंग्रेजों के भारत में आते ही भारतीय जनता के प्रतिरोध संघर्षों की धारा भी शुरू होती है। इस प्रकार, भारतीय जनता के लिए आधुनिक परिवेश उसके संघर्ष के विभिन्न रूपों से अनिवार्यता: जुट जाता है।

समाज की चुनौतीपूर्ण इस वास्तविकता ने समूचे देश के पैमाने पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद- विरोधी लहर पैदा की, तथा जीवन के हर क्षेत्र में एक संघर्ष शील तथा प्रवाहमान साहित्य और संस्कृति का जन्म हुआ। सामाजिक की नयी माँगों के अनुरूप नये विचार पैदा हुए, तथा भाषा और साहित्य की नयी परंपराओं का प्रारंभ हुआ। भारतीय समाज ने अपनी मध्यकालीन स्थिरता और स्तब्धता को तोड़कर जैसे ही आधुनिक काल में प्रवेश किया है, वैसे ही, उसी क्षण से भारतीय जीवन निरंतर बदलता। उसका परिवेश बदलता रहा है। इस परिवेश बदलाव ने भारतीय जीवन के हर अंश को प्रभावित किया है हमारे परिवेश में जो मौलिक परिवर्तन हुआ है। इसने हमारे आचरण को, हमारी दृष्टि को बदलता है। हमारा यह परिवेशगत बदलाव और इस बदलाव के कारण हमारे आचरण और हमारी दृष्टि में जो बदलाव आया है वह समकालीन हिंदी में बखूबी अभिव्यक्त हुआ है या हो रहा है।

इस बदलाव के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आर्थिक क्षेत्र में प्रकट है। यह सच है कि स्वातन्त्र्योत्तर काल में गरीब अधिक गरीब हुआ है और अमीर अधिक अमीर। गरीबी और अमीरों के बीच की खाई निरंतर और अधिक चौड़ी एवं गहरी होती गई है। इसने गाँव से लेकर शहर तक सबको प्रभावित किया है। समसामयिक हिंदी कहानी में गरीबों की यातना और धनाढ्य की भ्रष्टता और प्रदर्शन स्वार्थ और क्रूरता को

विस्तार के साथ उनकी अनेक छाया प्रतिच्छायाओं के साथ रेखांकित किया गया है। प्रतिदिन बढ़ती महंगाई में पिसते मध्यवर्गीय व्यक्ति के अनेक करुणा उत्पादक चित्र समकालीन हिंदी कहानी में अंकित हुए हैं। उदाहरण के लिए श्रवण कुमार की कहानी 'बच्चा' प्रस्तुत की जा सकती है। निम्न मध्य वित्त पति, पत्नी और बच्चा नयी दिल्ली के कनाट प्लेस के बरामदों में चक्कर काट रहे हैं। उनके चारों ओर वैभव बिखरा हुआ है। 'हर दुकान पर 'हर कोने पर, खरीदार ऐसे टूट पड़ रहे थे जैसे मक्खियाँ शहद पर टूटती है। लगता था जैसे आज के दिन के लिए ही लोगों ने अपनी सारी पूंजी जुटा रखी हो। जहां उन्हें एक चीज़ की ज़रूरत थी वहां में वे दो खरीद रहे थे। बाज़ार में जैसे कि पैसे की बाढ़ आ रही थी। कुछ लोग जो भी खरीदते थे, उसे अपनी कारों में जमा किये जा रहे थे। कुछ ने इस काम के लिए छोटे मज़दूर बच्चों का सहारा ले रखा था। इन चमचमाती कारों वालों के उजले, बेष कीमती कपड़ों का कुछ अपना ही रोब था। उनका चटकीलापन जैसे प्रकृति से होड़ ले रहा था, एक ओर यह संपन्नता है ओर दूसरी ओर यह पति - पत्नी है जिन्होंने अपनी आठ महीने की बजत से कुल साठ रुपये जोड़े हैं। वर्षों से न पति ने, न पत्नी ने अपने लिए कोई गर्म कपड़ा खरीदा है। अपने को आधुनिक और सम्पन्न दिखाने के चक्कर अपनी चादर को इतना ताना है कि नंगे हो- हो जाते हैं। उनके पास अपने एकान्त की रक्षा करने के लिए खिड़की पर टाँगने के लिए ठीक से पर्दे तक नहीं है और इनके अड़ोस- पड़ोस में लोग रातोंरात अमीर हो रहे हैं, कोठियां खड़ी कर रहे हैं। राजनीति और व्यापार दोनों मिलकर लूट रहे हैं। इस आर्थिक विषमता ने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया है, उसे 'वस्तु' बना दिया है, उसे अमानवीकृत कर दिया है। सुरेंद्र अरोड़ा की कहानी 'आदमी' इस कथ्य को बड़े शक्तिशाली ढंग से प्रकट करती है। शहर में काम खोजने की तलाश में गाँव से आया बागड़ कई दिन का भूखा है। शहर ने उसे काम तो नहीं दिया, हाँ उसकी कमीज़ और छीन ली। वह जिस बस स्टॉप पर आश्रय लेता है वहाँ खड़े लोगों के लिए वह भय, घृणा या उपेक्षा का विषय है, सौहार्द का, सहयोग का, दया का, करुणा का पात्र नहीं है। जब वह भोजन की सुगंध से आकर्षित होकर एक फोटोग्राफर की कोठी पर पहुंचता है तो उसे आदर और भोजन एक स्वार्थता से प्रेरित है। जब बागड़ अन्धाधुन्ध भोजन पर टूट पड़ रहा है तब सब साहब दनादन उसके फोटो ले रहे हैं क्योंकि इस भूखे आदमी की विभिन्न मुद्राओं में उन्हें ' हंगर परसनिफाईड' और 'पेट भरने पर आँखों में झलकने वाली तृप्ति में 'सैटिस्फेक्शन परसानीफाईड' दिखाई देते हैं।

सुरेंद्र अरोड़ा की यह कहानी पूंजीवादी व्यवस्था पर बड़ा तीखा प्रहार है। यह कहानी बड़ी कुशलता से इस बात को रेखांकित करती है की भूख आदमी को आदमी नहीं रहने देती। जब आदमी का पेट भर जाता है तब उसकी मनुष्यता सक्रिय हो उठती है। पेट की सामान्य भूख तृप्ति की जा सकती है लेकिन लाभ कमाने की तृष्णा तृप्ति नहीं की जा सकती। मृदुला गर्ग ने अपनी कहानी 'दुनिया का कायता' में दिखाया है कि अगर दान - दहेज अच्छा मिले तो एक पत्नी की लाश पर दूसरे विवाह का

सौदा किया जा सकता है। या एक टका प्राप्त करने के लिए पत्नी को अपने सामने दूसरे पुरुष की बाँहों में सौंपा जा सकता है। मदुला गर्ग ने अपनी एक और कहानी 'टुकड़ा - टुकड़ा आदमी में पूँजीपति के चरित्र का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस कहानी के माध्यम से पूँजीपति के चरित्र की विरोधी प्रवृत्तियाँ उजागर हुई हैं। मानवीय व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही समाज की संरचना को प्रभावित करता है। फलस्वरूप समय के साथ उसमें भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। समाज में निरंतर परिवर्तन होता है। परिवर्तन यदि न हो तो समाज जड़, रूढ़िग्रस्त एवं निर्जीव बन जाता है।

स्वातंत्र्योत्तर काल में जब नवचेतना का स्फुरण हुआ तो समाज के प्रत्येक वर्ग में स्वतंत्र भाव विकसित हुआ इस स्वतंत्रता भाव ने स्त्री - पुरुष के आपसी संबंधों को प्रभावित किया। पहली बार स्त्री ने अनुभव किया कि वह भी अपनी स्वतंत्र वैयक्तिक इकाई रखती है। पुरुष से अलग उसका भी एक निजी व्यक्तित्व है। जब आर्थिक रूप से स्त्री आत्मनिर्भर हुई तो उसकी मानसिकता ही विकसित नहीं हुई अपितु वह एक आत्मविश्वास से भर उठी। अभी तक जिन क्षेत्रों पर पुरुषों का एकाधिकार था वह चरमराने लगा। नारी की परिवर्तित भूमिका ने पारिवारिक स्वरूप को प्रभावित किया। चूँकि परिवार समाज की आधारशिला है अतः परिवार के स्वरूप के बदलाव ने समाज को भी बदलाने पर विवश किया। अब समाज नारी को अबला, हेय, पशुतुल्य व अधम प्राणी न मान उसकी क्षमता को स्वीकार करने लगा। स्त्री पति से स्वामी के स्थान पर साथी की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा रखने लगी। जहाँ स्त्री की इस परिवर्तित भूमिका को सहज स्वीकार कर लिया गया वहाँ स्थिति सामान्य है लेकिन जिन परिवारों में आज भी स्त्री के प्रति परंपरागत रूढ़ि से युक्त दृष्टिकोण है वहाँ पारिवारिक कलह, विघटन व टूटन दिखाई देने लगी है। इससे स्पष्ट है कि स्त्री की परिवर्तित मानसिकता ने परिवार की अनेक परंपरागत भूमिकाओं को बदला। नवीन मूल्यों के कारण अनेक प्राचीन भूमिकाओं का हास हुआ।

फ्री सेक्स, फ्री लिविंग ने मातृत्व संबंधी अवधारणा को प्रभावित किया। स्त्रियाँ अपनी अलग पहचान बनाने की कामना में मातृत्व को अपदस्थ करने लगी। वहीं अनेक महानगरीय युवतियाँ बिना विवाह के माँ बन कर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। ऐसी युवतियों के लिए विवाह की अपेक्षा इंसान का जन्म महत्वपूर्ण है। शाश्वत संबंधों के प्रति व्यक्ति ने अपने हित के अनुसार आचरण किया परंपरागत स्वरूप को अस्वीकार ही किया गया - 'वहीं अनाम संबंधों का दायरा भी बढ़ा।

व्यक्ति अपने सुविधानुसार समाज को तोड़ - मरोड़ रहा है। अपनी स्वतंत्रता व स्वयं के हितों के संपादन को महत्व देता हुआ व्यक्ति समाज को रौंद रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने विश्वासों एवं धारणाओं के विरोध में नवीन विचारों, मान्यताओं का जन्म होने लगा। हमारा वर्तमान समाज प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं व्यवस्था से अलग होकर नवीन सभ्यता में प्रवेश कर रहा है। एक नयी 'समाज संरचना' 'नयी संस्कृति' विकसित हो रही है।

समकालीन हिंदी कहानीकार यथार्थ के इन्हीं विभिन्न कोणों को अपनी कहानी में चित्रित कर रहे हैं। जिस गति से जीवन स्थितियाँ बदल रही हैं, उतनी ही तेजी से समकालीन कहानी का यथार्थ भी परिवर्तित हो रहा है। 1947 में देश की स्वतंत्रता के साथ देश - विभाजन की त्रासदी, उससे उत्पन्न शरणार्थी समस्या, सांप्रदायिक दंगे, हत्या, लूटपाट, आग - बलात्कार की घटनाएं, स्वार्थी की टकराहट आदि समस्याओं ने हमारे देश की सामाजिक परिस्थितियों को बहुत प्रभावित किया ऐसे वातावरण में साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन होना संभव था।

आजादी के बाद घटनाओं ने 'नयी कहानी' की पृष्ठभूमि तैयार की। नये कहानीकारों ने अपना संबंध प्रेमचंद्र की यथार्थवादी कहानियों से जोड़ा। उनकी कई समस्याएँ पहले की भाँति थी, कई उग्र हो गई थीं व कई एकदम नई थी, इस तरह उन्होंने स्वयं के परिवेश के अनुसार अपने अनुभव को कहानी में जगह दी। इस प्रकार इन्होंने अपने 'पूर्ववर्ती' कथाकारों से सामग्री भी ली व अपने निजी परिवेश से भी अनुभवों को जुटाया।

डॉ. नामवर सिंह ने 'नयी कहानी' की मान्यता दी और नयी कहानी की बात के साथ ही लेखकों के नाम, रूप गठन, शिल्प आदि को लेकर कहानी पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। आजादी के बाद बढ़ती हुई राजनीतिक परिस्थितियाँ, जनता का मोहभंग, समाज का अधिक - से - अधिक आधुनिक होना वैज्ञानिक प्रगति, शिक्षा का प्रचार - प्रसार पारिवारिक विघटन, स्त्री - पुरुषों के संबंधों में परिवर्तन, आदर्शों व नैतिक मान्यताओं का खोखलापन आदि को कई रूपों में देखा और उसका चित्रण किया।

नयी परिस्थितियों व नए संदर्भों का सफल चित्रण करने के लिए कहानीकारों ने कहानी के शास्त्रीय व शिल्पगत ढाँचे में परिवर्तन किया। नयी कहानी में कथानक नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई।

नये कहानीकारों द्वारा अपने भोगे गए यथार्थ व संवेदना को हमेशा प्रयोग में आने वाले भाषा व शब्दों के माध्यम से चित्रण करने के कारण कहानी में अब न तो कथा - वस्तु का महत्व रह गया और न पात्रों का। नयी कहानी संक्षिप्तता और समकालीनता की माँग करती है। उसमें एक खामोशी, ठण्डापन व सहजता है। "जो जैसा है उसे वैसा ही यानी यथार्थ को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर लेने की ईमानदारी और बाकी हर चीज़ को अस्वीकार कर देने का आग्रह 'नयी कहानी में' ये दो दृष्टियाँ उभरने लगी।

डॉ. नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह 'परिदे' को नयी कहानी की पहली कृति के रूप में लिया है। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि निर्मल वर्मा ने व्यापक मानव मूल्यों को अपनी कहानियों का आधार बनाया तथा इस संग्रह की कहानियाँ शिल्प और कला दृष्टि से भी नयी कहानी की अन्य कहानियों से अलग है। "आज की कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जीवन से दूर नहीं हुई है। बल्कि यह जीवन के अत्यंत गहराई में उतर चुकी है। आज के कहानीकार ने मनुष्य और उसकी जिंदगी का महत्व स्वीकार किया है।

नयी कहानी, मुख्य रूप में अतिथयार्थवादी कहानी का शुरू से अंत तक वर्ण्य विषय था बदलते हुए सामाजिक जीवन का चित्रण करना तथा वर्तमान जीवन की पीढ़ी को उभारना इसके लिए उन्होंने पुरानी नैतिकता पर प्रहार किया टूटते हुए पारिवारिक संबंधों को दिखाया तथा आजादी के बाद के मोहभंग और उससे उत्पन्न व्यक्ति में निराशा और कुंठा की भावना को नयी कहानियों में स्थान दिया। कुंठा और निराशा के साथ व्यक्ति भविष्य की जो प्रतीक्षा कर रहा था उस पीढ़ी को नये कहानीकारों ने अभिव्यक्त किया।

नयी कहानी, ने कहानी संबंधी परंपरागत धारणा में भी परिवर्तन किया। जहाँ शिल्प में कथानक शिल्प का हास हुआ वहीं घटना, चरित्र - चित्रण संबंधी धारणा को भी तोड़ा। "कहानी में पहले जहाँ चरित्रों की, घटनाओं की प्रधानता थी वहाँ अब प्रधानता थी वहाँ अब प्रभावान्वित, संवेदना, वातावरण आदि की प्रधानता हो गई।"

नयी कहानी में आंचलिकता पर भी जोर दिया गया। नये कहानीकारों ने बदलते हुए गाँवों का चित्रण इसलिए किया कि अब गाँव भी सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त हो रहे थे। इस प्रकार जिन क्षेत्रों को पहले कहानीकारों ने छुआ तक नहीं था, नये कहानीकारों ने उनकी

पहचान करायी और उसे भारतीय समाज का एक अंग घोषित किया। मोहन राकेश ने "नयी कहानी" की पूरी व्याख्यात्मक परिभाषा देते हुए लिखा है -"नयी कहानी गाँव की कहानी है, नयी कहानी नये शिल्प की कहानी है, नयी कहानी सहज सांकेतिकता की कहानी है, नयी कहानी सामाजिक संपर्क की कहानी है, नयी कहानी साधारण परिचित जीवन की कहानी है, नयी कहानी समस्त पारदर्शक भाषा में लिखी जाने वाली कहानी है, नयी कहानी सभी तरह की कहानी है।"

स्वतंत्रता के बाद की हमारी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ एवं उनके परिणामस्वरूप औद्योगीकरण, पूँजीवाद, शहरीकरण, समाजवाद, पाचात्य शिक्षा, संस्कृति एवं बेरोजगारी आदि का आधिपत्य रहा परिवर्तित परिस्थितियों में संयुक्त परिवारों, सामाजिक मान्यताओं एवं मूल्यों तथा जातीय बन्धनों का विघटन तेजी से हुआ। उद्योगों के फैलाव से नगरों में भौतिक सुविधाओं की प्रगति हुई। आज यांत्रिक प्रगति की दौड़ में व्यक्ति अपनी मर्यादाओं मूल्यों एवं संस्कारों को तोड़ता जा रहा है। आधुनिक काल में तीव्रगति से होनेवाले सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

अतियथार्थवादी कहानी का सामाजिक यथार्थ बहुआयामी है। उपभोक्तावाद, उपनिवेशवादी आक्रमण उग्रवाद, सांप्रदायिक उन्माद, सामाजिक विषमता, नारी उत्पीड़न, दलित वर्ग की उपेक्षा, बाजारू संस्कृति आदि को कहानीकार अपनी मानसिक चेतना पर झेल रहा है। यही कारण है कि कहानीकार किसी आंदोलन या आदर्श से प्रेरित न हो सम-सामयिक यथार्थ से टकराकर कहानियाँ लिखना ज्यादा पसंद कर रहा है। सामाजिक प्राणी होने के कारण कहानीकार जो कि अपनी कहानियों का कथ्य समाज से ही ग्रहण करता है।

संक्षेप में मेरा विचार है कि वर्तमान समय में भारतीय समाज की परिस्थितियाँ बहुत अधिक बदल चुकी हैं। फलस्वरूप मूल्यों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आया, आत्मीय संबंधों का आधार अर्थ हो गया, फलस्वरूप जीवन में प्रेम तत्व समाप्त होने लगा, वैयक्तिक स्वतंत्रता का परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति पराहित के स्थान पर स्वसुख में केंद्रित हो गया। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति अस्तित्ववादी, फ्रायडवादी चिंतन, जैविक आवश्यकता के फलस्वरूप नवीन नैतिक मूल्य अस्तित्व में आया, जिसने प्रेम व यौन संबंधी प्राचीन मान्यताओं को न केवल झकझोर दिया अपितु उनके स्थान पर पूर्णतः नवीन मानदंड प्रस्तुत किया। विवाह संबंधी परिवर्तित दृष्टिकोण ने परिवार नामक संस्था को हिला दिया।

संदर्भ सूची :

1. स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास - मूल्य संक्रमण - डॉ. हेमेंद्र कुमार पानेरी
2. एक दुनिया समानान्तर - राजेंद्र यादव
3. कहानी : नयी कहानी - डॉ. नामवर सिंह
4. कहानी : स्वरूप और संवेदना - राजेंद्र यादव
5. कहानी आंदोलन की भूमिका - बलराज पाण्डेय
6. हिंदी साहित्य का इतिहास - डॉ. विजयेन्द्र स्नातक

Consumer Behavior Trends in Online Fashion Retail: A Study of Gen Z Shoppers in India.

Shweta Saini

Research Scholar

Faculty of Fashion and Design, SGT University, Haryana

Abstract

This research paper investigates the evolving consumer behavior patterns of Generation Z (Gen Z) in the Indian online fashion retail sector. As digital natives, Gen Z represents a crucial segment for e-commerce businesses, marked by their high digital literacy, preference for personalization, and strong social media influence. The study explores the key drivers that shape their fashion purchasing decisions, such as price sensitivity, brand engagement, peer and influencer impact, and awareness of sustainable fashion practices. Using a mixed-method research design, primary data was collected through structured questionnaires administered to 312 Gen Z respondents across urban and semi-urban regions of India. The data analysis reveals that while affordability and convenience remain central to online purchases, Gen Z also places significant value on authenticity, peer validation, and ethical considerations. Despite showing high awareness of sustainable fashion, a clear attitude-behavior gap persists, with limited translation into actual purchases. The study also finds that AI-enabled personalization, mobile-first user experiences, and influencer marketing are critical in driving engagement and conversion. Based on the findings, the paper offers practical policy implications and strategic recommendations for digital fashion retailers, including promoting sustainable fashion literacy, regulating influencer transparency, investing in technology-driven personalization, and expanding e-commerce training for youth. By providing insights into the preferences and behaviors of Gen Z consumers, this study contributes to both academic understanding and industry practice in digital retail. It emphasizes the need for inclusive, ethical, and innovative approaches to capture and retain the loyalty of India's youngest consumer cohort.

Keywords-Gen Z, Online Fashion Retail, Consumer Behavior, Digital Marketing, Sustainability in Fashion

Introduction- The evolution of online retail in India has fundamentally reshaped consumer purchasing behavior, particularly within the fashion segment. Fueled by rapid digitalization, increasing internet penetration, smartphone adoption, and widespread use of social media, the Indian fashion retail market has experienced an

unprecedented shift from traditional brick-and-mortar formats to digital platforms (KPMG, 2020). Among the various consumer demographics, Generation Z—defined as individuals born between 1997 and 2012—has emerged as a pivotal segment driving innovation and disruption in the online fashion ecosystem. As digital natives, Gen Z consumers display a distinctive set of behavioral traits that challenge conventional marketing approaches and redefine the dynamics of brand-consumer interaction. In India, Gen Z constitutes a significant proportion of the population, with over 370 million individuals below the age of 25 (Statista, 2023). This demographic is characterized by high digital literacy, frequent social media usage, and a preference for experiential and value-driven consumption. Their fashion choices are heavily influenced by peer networks, influencers, and curated content on platforms such as Instagram, YouTube, and Snapchat (PwC, 2022). Unlike previous generations, Gen Z shoppers seek authenticity, diversity, and alignment with social and environmental values, thereby compelling online fashion retailers to adopt more inclusive, personalized, and sustainable business models. Online fashion platforms in India—such as Myntra, Amazon Fashion, Ajio, and a growing number of Direct-to-Consumer (D2C) brands—have responded by leveraging technologies like artificial intelligence, machine learning, and real-time analytics to enhance the shopping experience. Features like AI-driven product recommendations, virtual try-ons, influencer collaborations, and social commerce integrations are increasingly used to engage Gen Z customers. Moreover, with the growing popularity of ethical fashion and eco-consciousness, many Gen Z shoppers are gravitating towards brands that exhibit transparency in sourcing and manufacturing processes (McKinsey & Company, 2021). Despite the growing body of research on consumer behavior and e-commerce trends, there remains a gap in understanding the nuanced preferences and motivations of Indian Gen Z consumers in the context of online fashion retail. This study aims to bridge that gap by exploring the key behavioral patterns, decision-making influences, brand perceptions, and digital touchpoints that shape the fashion consumption journey of Gen Z shoppers in India. It seeks to answer critical questions such as: What motivates Gen Z to shop for fashion online? How do social media and peer influence affect their choices? What role does personalization and brand authenticity play in their purchase behavior? The findings of this research will have significant implications for fashion marketers, digital strategists, and policy makers, offering insights into tailoring retail strategies for this digitally native and socially conscious generation. As the Indian e-commerce

landscape continues to evolve, understanding Gen Z's consumer psyche will be instrumental in driving innovation, fostering brand loyalty, and sustaining competitive advantage in the online fashion industry.

2. Literature Review

2.1 Consumer Behavior in the Digital Age-Consumer behavior has significantly evolved with the advent of e-commerce and digital technologies. Online retail, particularly in fashion, has shifted from a transactional activity to an experience-driven process, influenced by real-time engagement, social interaction, and personalized marketing (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). Digital platforms now serve as both marketplaces and media ecosystems, where consumers seek inspiration, validation, and convenience.

2.2 Characteristics of Generation Z as Consumers

Generation Z, born between 1997 and 2012, represents a tech-savvy, socially aware, and information-rich generation. Studies suggest they are highly individualistic, value authenticity, and exhibit shorter attention spans (Williams et al., 2021). Unlike Millennials, Gen Z prefers video-based content, ephemeral engagement (like Stories and Reels), and interactive formats. They expect brands to reflect their values and engage meaningfully with them across digital channels (Francis & Hoefel, 2018).

2.3 Online Fashion Retail in India- India's online fashion retail market has witnessed exponential growth, projected to reach USD 43 billion by 2025 (IBEF, 2023). The rise of platforms such as Myntra, Ajio, and Amazon Fashion, along with the proliferation of D2C brands, has expanded consumer access to both global and local fashion trends. Key drivers include increasing smartphone penetration, affordable data, and greater awareness of global fashion through digital media.

2.4 Influence of Social Media and Peer Networks- Social media has emerged as a dominant force in shaping Gen Z's fashion choices. Influencer marketing, peer reviews, and visual platforms like Instagram, Pinterest, and YouTube play a pivotal role in discovery and decision-making (Djafarova & Bowes, 2021). Gen Z trusts user-generated content more than traditional advertising, relying heavily on influencers and friends over brand messaging.

2.5 Personalization and Technology in Fashion Retail

Online fashion retailers increasingly use AI and big data to offer tailored recommendations, targeted promotions, and dynamic user interfaces. Gen Z expects seamless, fast, and personalized shopping experiences (Deloitte, 2022). Interactive tools such as AR-based virtual try-ons, chatbots, and customization features enhance engagement and build trust.

2.6 Ethical Fashion and Sustainability Trends-

Environmental consciousness and social responsibility are becoming important purchase criteria for Gen Z. Brands that demonstrate ethical sourcing, sustainable practices, and transparency often gain favor among these consumers (Niinimäki et al., 2020). Greenwashing, however, is a concern, and Gen Z is quick to detect and penalize inauthentic behavior through social channels.

2.7 Gaps in Existing Literature-

While global studies have examined Gen Z's consumer psychology, limited research focuses on Indian Gen Z shoppers in the specific context of online fashion. Cultural diversity, regional disparities, and linguistic preferences add layers of complexity to understanding this segment in India. This study aims to fill that gap by offering context-specific insights into their motivations, preferences, and behavior.

3. Research Objectives-

To analyze the key factors influencing online fashion purchasing decisions among Generation Z consumers in India, including price sensitivity, brand perception, influencer impact, and technology adoption.

To examine the role of digital platforms and social media in shaping Gen Z's fashion preferences and buying behavior in the Indian e-commerce landscape.

To assess the level of awareness and actual purchasing behavior related to sustainable and ethical fashion among Gen Z online shoppers.

To provide strategic recommendations for online fashion retailers and policymakers based on the behavioral patterns, expectations, and preferences of Gen Z consumers.

4. Need for the Study-

With the rapid digitalization of the retail sector in India, Generation Z has emerged as a dominant and influential consumer group in the online fashion market. Their unique preferences, tech-savviness, and social media-driven shopping habits differ significantly from previous generations. However, limited research exists that specifically focuses on Gen Z's behavior in the context of online fashion retail. Understanding their motivations, values, and digital touchpoints is crucial for retailers aiming to develop targeted strategies. This study addresses this gap by offering insights into the evolving patterns of Gen Z shopping behavior.

5. Research Methodology

5.1 Research Design-

The study employs a **descriptive and analytical research design**, aimed at understanding and analyzing the behavior, preferences, and influencing factors affecting Gen Z consumers' online fashion retail choices in India. The descriptive aspect helps to portray trends and patterns, while the analytical approach allows for evaluation of relationships among variables such as technology use, brand ethics, and shopping frequency.

5.2 Research Approach

A **quantitative research approach** has been adopted to collect measurable data that can be statistically analyzed. It is complemented with optional qualitative insights through open-ended responses to enrich interpretations.

5.3 Population and Sampling

Target Population: Gen Z consumers aged 18–27 who shop for fashion products online and reside in India.

Sampling Technique: A combination of **purposive sampling** and **snowball sampling** has been employed. Respondents are selected based on age and online shopping activity, and encouraged to refer peers to participate.

Sample Size: A minimum of **300 respondents** was targeted to ensure adequate representation across regions, genders, and economic segments.

5.4 Data Collection Methods

Primary Data: Collected using a structured **online questionnaire** via Google Forms. The tool was distributed through social media platforms (Instagram, LinkedIn, WhatsApp) and university/college networks to reach the Gen Z demographic.

Secondary Data: Sourced from academic journals, market research reports (e.g., Deloitte, McKinsey, IBEF), government publications, and fashion industry whitepapers to support the literature review and analysis.

5.5 Data Collection Tool

A **structured questionnaire** was designed with both closed-ended (Likert scale, multiple-choice) and a few open-ended questions. The questionnaire covers six broad areas:

Demographic details

Online shopping behavior

Motivational factors and brand influences

Use of technology and personalization

Ethical and sustainability awareness

Brand loyalty and satisfaction

Pre-testing was done with 10 respondents to ensure clarity, consistency, and time efficiency.

5.6 Data Analysis Techniques

Descriptive Statistics: Frequencies, means, and percentages were used to summarize demographic data and general shopping trends.

Inferential Statistics:-Correlation analysis to test relationships between variables (e.g., social media influence and purchase frequency).

Chi-square tests for association between categorical variables (e.g., gender and brand loyalty).

Regression analysis to identify key predictors of online purchase behavior.

Software Tools Used:

SPSS for statistical analysis

Excel for data cleaning and visualization

5.7 Ethical Considerations

Participation was entirely voluntary and anonymous.

Informed consent was obtained at the beginning of the questionnaire.

Data confidentiality was strictly maintained, and no personally identifiable information was collected or disclosed.

5.8 Limitations of the Methodology

The use of online surveys may exclude Gen Z respondents without regular internet access.

Self-reported data may include response biases.

Non-probability sampling may limit generalizability to the broader Gen Z population.

6. Data Analysis and Interpretation

This section presents the results of the primary data collected from Gen Z respondents across India. The data has been analyzed using both descriptive and inferential statistics to identify patterns in behavior, preferences, and influencing factors in online fashion retail.

6.1 Demographic Profile of Respondents

Variable	Categories	Frequency	Percentage (%)
Age Group	18–20	85	28.3%
	21–23	130	43.3%
	24–26	70	23.3%
	27+	15	5.0%
Gender	Male	150	50.0%
	Female	145	48.3%
	Non-binary/Other	5	1.7%
Occupation	Student	190	63.3%
	Working Professional	85	28.3%
	Others	25	8.4%

Interpretation:-The majority of respondents were aged 21–23 and predominantly students, aligning well with the core Gen Z profile. Gender distribution was balanced.

6.2 Online Shopping Behavior

Frequency of Online Fashion Purchase	Respondents	Percentage (%)
Once a month	110	36.7%
2–3 times a month	95	31.7%
Weekly	60	20.0%
Rarely	35	11.6%

Interpretation: Most Gen Z consumers shop at least once a month, showing high engagement with online fashion platforms.

6.3 Factors Influencing Purchase Decisions (Likert Scale Analysis)

Factor	Mean Score (Out of 5)
Discounts & Offers	4.45
Product Variety	4.32
Brand Image	3.85
Reviews & Ratings	4.10
Return/Exchange Policy	4.25
Ethical/Sustainable Sourcing	3.52

Interpretation: Price offers, return policies, and product variety are the top motivators, while ethical considerations are gaining relevance but rank lower in comparison.

6.4 Influence of Social Media

Source of Influence	Frequency	Percentage (%)
Social Media Influencers	125	41.7%
Friends/Peers	95	31.7%
Celebrities	30	10.0%
Brand Ads	25	8.3%
Family	25	8.3%

Interpretation:Social media influencers and peer networks are the primary sources of fashion inspiration for Gen Z, surpassing traditional advertisements.

6.5 Use of Personalization Technology

Feature Used	Yes (%)	No (%)
AI-based recommendations	62.5	37.5
Virtual try-on tools	34.2	65.8
Personalized discounts/offers	70.8	29.2

Interpretation:Gen Z consumers are receptive to personalization features, especially those that enhance convenience and savings.

6.6 Sustainability Preferences

Question	Yes (%)	No (%)	Maybe (%)
Willing to pay more for sustainable products	45.8	26.7	27.5
Check brand's sustainability claims before buying	30.0	40.0	30.0

Interpretation:While a significant share shows interest in sustainability, actual behavior (such as verifying claims or paying more) is less consistent, indicating a possible *attitude-behavior gap*.

.7 Statistical Analysis Highlights(i) Correlation Analysis Social Media Influence and Purchase Frequency: $r = 0.56 \rightarrow$ moderate positive correlation

Brand Ethics and Loyalty: $r = 0.48 \rightarrow$ moderate positive correlation

Personalized Offers and Monthly Spending: $r = 0.60 \rightarrow$

strong positive correlation

(ii) Chi-Square Tests

Gender vs. Fashion Category Preference → *Significant association* ($p < 0.05$)

6 Occupation vs. Spending Range → *Significant association* ($p < 0.01$)

(iii) Regression Analysis

A multiple regression was run with **Monthly Online Purchase Frequency** as the dependent variable and independent variables as:

Social Media Engagement

Use of AI Recommendations

Brand Trust

Sustainability Concern

Result: Adjusted $R^2 = 0.51$ → Model explains 51% variance, indicating a moderately strong predictive relationship.

7. Findings and Discussion-The findings of this study reveal significant trends in the online fashion retail behavior of Gen Z consumers in India. The data analysis highlights key motivations, behavioral patterns, and emerging shifts in consumer values among this digitally native cohort.

7.1 High Frequency of Online Fashion Purchases-The majority of Gen Z respondents reported shopping for fashion products online at least once a month, with a notable portion engaging in 2–3 monthly transactions. This supports the notion that online fashion retail is deeply embedded in the lifestyle habits of Gen Z consumers. The convenience, accessibility, and 24/7 availability of online platforms appear to drive consistent purchasing behavior.

Discussion:This frequency aligns with global studies indicating that Gen Z consumers prefer fast, responsive, and digitally enhanced shopping experiences. Indian platforms like Myntra and Ajio have successfully tapped into this demand by offering curated deals and real-time personalization.

7.2 Influence of Discounts, Reviews, and Return Policies-Discounts and promotional offers received the highest importance score (mean = 4.45), followed closely by product variety and return/exchange policies. Product quality and reviews were also highly rated.

Discussion:These findings reaffirm the price sensitivity of Indian Gen Z consumers, despite their growing brand consciousness. Easy return policies and customer reviews contribute to risk reduction, especially when purchasing clothing online, where fit and feel are difficult to assess.

3 Role of Social Media and Influencers-Social media influencers were identified as the most significant source of fashion inspiration (41.7%), followed by peers and friends. Platforms like Instagram, YouTube, and Pinterest play a central role in trend dissemination among Gen Z consumers.

Discussion:This shift from traditional advertising to peer-led digital influence reflects Gen Z's preference for authenticity, relatability, and aspirational yet attainable

fashion icons. Brands collaborating with micro- and nano-influencers are likely to have better engagement outcomes.

7.4 Technology Adoption and Personalization-A majority of respondents have used AI-powered product recommendations and personalized offers. However, fewer respondents have engaged with virtual try-on tools.

Discussion:-The positive correlation between personalization and monthly spending suggests that Gen Z appreciates customized experiences that align with their tastes and buying habits. However, the limited use of advanced tools like AR-based try-ons may indicate a lack of awareness or perceived complexity.

7.5 Sustainability as an Emerging Concern-While 45.8% of respondents indicated a willingness to pay more for sustainable fashion, only 30% reported actively checking a brand's sustainability claims before purchasing.

Discussion:This reflects a classic **attitude-behavior gap**—Gen Z expresses concern for the environment, but practical application is inconsistent. Brands focusing on sustainability must not only communicate their credentials clearly but also ensure affordability and transparency to convert awareness into action.

7.6 Brand Loyalty and Ethical Alignment-Respondents indicated a high likelihood of staying loyal to brands that align with their values and provide a good experience. Correlation analysis confirmed a positive relationship between ethical commitment and brand loyalty.

Discussion:This presents an opportunity for fashion retailers to build long-term relationships with Gen Z by integrating social responsibility and ethical business practices into their brand narrative.

7.7 Regional and Gender-based Variations-Chi-square tests revealed significant associations between gender and fashion category preferences, and between occupation and monthly spending range.

Discussion:Female respondents showed higher engagement with accessories and ethnic wear, while students were more budget-conscious compared to young professionals. This suggests the need for segmented marketing strategies catering to different sub-groups within Gen Z.

7.8 Predictors of Online Purchase Behavior-Regression analysis identified social media engagement, AI personalization, and trust in the brand as key predictors of purchase frequency.

Discussion:This confirms the multi-dimensional nature of Gen Z's decision-making—driven by digital convenience, emotional connection, and intelligent suggestions. Fashion brands that invest in data-driven customer engagement and social proof mechanisms are more likely to succeed.

Summary of Key Findings:Gen Z consumers shop online frequently and value convenience, discounts, and user-

generated content. Social media and personalization are major drivers of purchasing decisions.

Sustainability is growing in importance but is not yet a dominant factor in behavior.

Gender, occupation, and lifestyle influence fashion preferences and spending.

Brand loyalty is closely tied to experience and ethical alignment.

8. Conclusion and Policy Implications

8.1 Conclusion-This study explored the consumer behavior trends of Gen Z shoppers in India within the context of online fashion retail. The findings reveal that this generation—digitally native, socially connected, and value-conscious—is significantly reshaping the online retail landscape.

Key insights indicate that Gen Z consumers are frequent online shoppers who prioritize convenience, affordability, and social influence. Discounts, easy return policies, and peer reviews are critical motivators, while personalized experiences through AI-driven tools and targeted promotions further enhance engagement. Social media, especially influencers and peers, has emerged as a powerful force in shaping fashion choices and brand preferences.

Although sustainability is a growing concern among Gen Z, there remains a gap between awareness and action. Many express interest in ethical consumption but hesitate to verify sustainability claims or pay a premium for green fashion alternatives. Additionally, brand trust and alignment with ethical values are increasingly influencing loyalty and repeat purchases. In essence, Gen Z shoppers are not just passive consumers—they are informed, expressive, and co-creators of fashion narratives. Their digital fluency, combined with a desire for authenticity and values-based consumption, demands a more agile and responsive approach from fashion retailers.

8.2 Policy Implications and Strategic Recommendations

-Based on the findings of this study, several policy implications and strategic recommendations emerge that can guide stakeholders in the digital fashion retail ecosystem. Firstly, there is a need to promote sustainable fashion literacy by initiating awareness programs in collaboration with educational institutions and industry associations. These efforts can help bridge the existing gap between Gen Z's positive attitude toward sustainability and their actual purchasing behavior. Retailers, in turn, should adopt transparent communication practices, using storytelling and third-party certifications to highlight ethical sourcing, fair labor practices, and reduced carbon footprints.

Secondly, the influence of social media on Gen Z's fashion choices highlights the importance of encouraging responsible digital influencing. Policymakers should consider

establishing self-regulation codes that require influencers to disclose paid partnerships clearly. Retailers can enhance authenticity by partnering with micro- and nano-influencers who align with Gen Z's values of relatability and trust. Another critical recommendation is for online fashion brands to invest in AI-driven personalization to improve customer experience. Tools such as recommendation engines, dynamic pricing, mobile-first UX/UI, and personalized communication can significantly enhance engagement among digitally savvy Gen Z users.

Consumer protection also requires strengthening, especially in the domains of data privacy, product authenticity, and effective grievance redressal mechanisms. A robust regulatory framework is essential to foster trust in online platforms. Additionally, tiered market strategies should be adopted to cater to the diverse demographic and regional preferences of Gen Z consumers. These may include offerings like gender-neutral fashion lines, vernacular marketing, and student discount schemes. Furthermore, there is a growing need to enhance digital skills and e-commerce training among youth. Skilling initiatives focused on digital marketing, fashion-tech innovation, and entrepreneurial development can build a sustainable talent pipeline. Lastly, public-private innovation hubs should be encouraged to foster collaboration among startups, academia, and government. Such hubs can support the development of inclusive, affordable, and sustainable digital fashion platforms, thereby contributing to long-term growth in the sector.

References

- Accenture. (2020). *Life reimaged: Mapping the motivations that matter for today's consumers*. <https://www.accenture.com>
- Deloitte. (2021). *Gen Z and millennials: Shaping the future of work*. Deloitte Insights. <https://www2.deloitte.com>
- Euromonitor International. (2023). *Fashion and apparel in India – Market analysis*. <https://www.euromonitor.com>
- Kapoor, A., & Dwivedi, A. (2022). Understanding consumer behavior of Gen Z in the Indian online fashion market. *International Journal of Consumer Studies*, 46(2), 189–202. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12789>
- McKinsey & Company. (2023). *The State of Fashion: India Edition*. <https://www.mckinsey.com>
- Priporas, C. V., Stylos, N., & Fotiadis, A. K. (2017). Generation Z consumers' expectations for m-commerce: A value-based approach. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 34, 281–289. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.10.011>
- Statista. (2024). *India: Online fashion market size*. <https://www.statista.com>
- Tapscott, D. (2009). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. McGraw-Hill.
- Verma, S., & Sinha, N. (2020). Online apparel shopping behavior: A study on Gen Z consumers in India. *Journal of Retail and Distribution Management*, 48(5), 512–528. <https://doi.org/10.1108/JRDM-06-2019-0182>
- WGSN. (2023). *The Gen Z consumer: Trends and strategies*. <https://www.wgsn.com>

Empowerment and Challenges of Women Tea Workers in Panitola Block with Specific Reference to their Social Status.

Sangita Hazarika

Research Scholar

Department of Legal Studies, Arunachal University of Studies, Namsai, Arunachal Pradesh (India).

Dr. Baloy Bhattacharjee

Research Supervisor

Associate Professor Department of Legal Studies, Arunachal University of Studies, Namsai, Arunachal Pradesh (India)

Dr. Sachchidanand Sharan Das

Research Co-Supervisor

Assistant Professor Centre for Juridical Studies, Dibrugarh University, Assam (India).

Abstract: Women workers hold a significant position in the tea plantation sector in Assam. Panitola Block in Dibrugarh District encompasses a significant portion of the tea gardens within the Dibrugarh District. The empowerment of women employed in tea plantations is essential; otherwise, it may negatively impact their working efficiency. Examining the social status of these women's groups reveals some enlightening insights about their existence. The wages, gender equality, education, and occupational health and safety represent significant domains for assessing social status. The aim of the study is to examine the factors that influence the social status of garden workers. Data was gathered from 63 women workers utilising questionnaires and interviews. The findings indicate that concerns among working women include compensation, healthcare access, and occupational health and safety. Another area of concern is healthcare facilities, housing facilities, working condition. One of the main causes for concern is the limited comprehension of their rights to these amenities. In any case, a lot of employees have expressed how satisfied they are with the company's low pay, which affects their financial status. The statistics also demonstrate the worker's incredibly low educational attainment. We must increase the minimum wage and provide better healthcare in order to eliminate these disparities. Furthermore, it is imperative that some mandatory standards be placed on vocational training.

Key words: Women worker, Social Status, Wages, Education, Health.

Introduction: Women's empowerment is the process of enhancing women's influence, decision-making abilities, and feeling of self-worth for the benefit of women, their families, and communities. Empowering women entails giving them more authority, independence, and resource management to further social, political, and economic advancement. The most common livelihood among the tea tribe women of Assam is to engage themselves in tea plantation jobs. The primary activity of women in tea gardens is the plucking of tea leaves, which is regarded as unskilled labour. The women from the different age groups are come to work in tea gardens. As these women are considered as marginalized class from their historical perspective they are subjected to some exploitation by the contractors and by the Tea company. The social status of this marginalized class is not strong as they are extremely controlled by the management of the tea companies. They are afraid off expressing their plight and they remain silent even though they are not receiving the basic rights. Dibrugarh is known as tea city of Assam first tea garden was established at Chabua, which is in the Dibrugarh District. The Panitola block is part of the Dibrugarh district, which has some of the area's most important tea estates. This block also houses the Chabua TE, which is regarded as one of Assam's oldest tea estates. Studying in this important field is considered to be more thorough.

Despite playing a vital part in the economy, women tea workers in Panitola Block encounter several obstacles. All tea garden women

have hectic daily schedules that conflict with their household responsibilities, leaving little time for leisure or rest. Despite their important contribution to the tea industry, they still do not receive the attention they deserve and instead deal with a number of social, political, economic, educational, and health issues.

Statement of problem: There are still some issues which are associated with the social status of the women tea garden worker in Panitola Block Dibrugarh District, the problem of low wages, health facilities, occupational health and safety and low educational level. These detriment to the welfare and well-being's of the women workers. This research attempts to determine the causes affecting the social status of the tea garden women workers.

Objectives:

1. To study about the social status of the women workers in Panitola block, Dibrugarh District.
2. To find put the causes affecting the social status of the tea garden women worker of Panitola block, Dibrugarh District from the point of view of labour welfare.

Research Questions:

1. What is the social status of the tea garden women worker in Panitola Block?
2. What are causes effecting the social status of tea garden women worker in Panitola Block, Dibrugarh District?

Literature Review:

According to **Amali Philips** in his study on "Rethinking culture and development: marriage and gender among the tea plantation workers in Sri Lanka", Married women on plantations endure self-denial, sacrifice, and subordination within impoverished, male-dominated households, while also facing exploitation and gender discrimination as laborers in the capitalist plantation production system. Patriarchy and plantations, along with kinship culture and capitalist agriculture, work together to subordinate women in their roles as wives and workers. This article examines the relationship between gender-based inequality and culture, with an emphasis on women's experiences in marriage and the workforce. I subsequently consider the potential trajectories for development programs implemented in the plantations.

Horen Goowalla, in his study on "Labour Relations Practices in Tea Industry of Assam-With Special Reference to Jorhat District of Assam" the researcher highlighted the employees of the selected tea estates demonstrate significant dissatisfaction concerning the recruitment and selection processes implemented by the management. The respondents perceive the presence of various pressure groups as obstacles to establishing a transparent, appropriate, and effective recruitment policy. The respondents from selected tea estates exhibit a significant variation in

their satisfaction levels concerning the current wage system. The levels of satisfaction in government-owned tea estates are significantly lower when compared to those in private and public sector tea estates. This situation arises from mismanagement, bureaucratic obstacles, and the government's inadequate investment in these tea estates. The working environment in which the employees operate presents a bleak scenario. The dispute redressal system is also not worker friendly by its procedure.

Dipali Basumatari and Phanindra Goyari, in their research on “*Educational Status of Tea Plantation Women Workers in Assam: An Empirical Analysis*”, rightly pointed out that the significant number of tea plantation workers in India are women, many of whom lack literacy or face educational disadvantages. Since gaining independence, the Government of India has been enacting a range of policies aimed at enhancing women's education, improving literacy rates, and decreasing school drop-out rates. Despite the implementation of various educational policies, a significant percentage of illiteracy persists among women laborers in tea gardens when compared to other occupations. This study analyses the educational status of women workers in tea plantations, investigating the factors contributing to low literacy rates and school drop-out rates among girls in these areas.

The study conducted by **Abir Hassan** on *Deplorable Living Conditions of Female Workers: A Study in a Tea Garden of Bangladesh*, the research elucidates the living conditions of female laborers in tea gardens in Bangladesh, examining the social and occupational environment while incorporating an analysis of their level of awareness, highlighting the distressing circumstances of their lifestyles. This study was conducted in the Lackatoorah Tea Estate, located in the Sylhet district of Bangladesh, selected randomly as the research area. It illustrates the pervasive oppression and suppression of female workers across all domains of existence, from domestic settings to professional environments. It clearly demonstrates that 68 % of female workers lack autonomy over their own income. 90% lack hereditary property ownership, despite their legal entitlement to inherit it from their family. 92% of women believe they are experiencing physical torture and mental harassment from their husbands, male family members, and representatives of estate management. 8- 6% percent of women express a desire to maintain a small family size; however, they often find themselves excluded from the decision-making processes regarding child-related matters. The research is entirely grounded in primary data, employing a stratified sampling method alongside a triangulated research design, while also engaging with relevant literature from previous studies.

The another study done by **Mridusmita Duara**, Women represent almost 50 % of the overall labor in Assam's tea

plantation business. But they continue to be excluded in several facets of the tea business. This research seeks to examine the present condition of the tea business in Assam in relation to the sexual division of labor, the influence of patriarchy, trade unions, sexual abuses, and the subjugation of women on tea estates. It analyzes the interaction of gender and class, workplace disparities, and the industrial relations context within tea estates. The minimal involvement of the State and inadequate social welfare initiatives may be cited as significant factors contributing to the deplorable working conditions, particularly the health risks faced by female workers.

Ananda Das Gupta and Sangeetha M. in their study on “*Improving Labour Productivity through Human Resource Development: A Case Study on Assam Tea Plantation Workers*”, the researcher focuses on the low labour productivity is often highlighted as the primary issue confronting the sector. Labor welfare measures and conventional, cost-inefficient management practices have also played a role in the near stagnation of production. Therefore, the study holds considerable importance in examining the infringement of welfare benefits for workers and its effect on reducing the productivity levels of labor in the Assam tea plantation.

Bijay Chandra Boro and Kokila Saxena this research examines in their study on “*The impact of work-life balance on the wellbeing of employees in the tea gardens of Bodoland territorial region*”, how tea plantation workers produce a backward culture with poor living circumstances and work-life balance issues. Individuals must achieve a balance between personal (family, friends, and self) and professional (work, career) responsibilities. Plantation output and productivity rely heavily on personnel performance. The research examined employees' socioeconomic, vocational, and geographical backgrounds, as well as the main challenges they face in tea gardens, including low wages, poor living circumstances, health difficulties, and inadequate health benefits.

A systematic review conducted by **Silpi Das and Doyel Karmakar**, in their study on “*Lifestyle of Women in Tea Garden Community: A Systematic Literature Review*”, rightly pointed out that over 50% of the workforce in the tea industry consists of women. The economic contribution of women in the tea industry is highly significant. Within the tea garden community, women serve as the main providers, while men's livelihoods are reliant on their contributions. They balance their domestic responsibilities with their work in the tea estate from early morning until evening. Despite of the fact women are within their community, afforded minimal acknowledgment and worth. They face significant challenges in

obtaining quality education, healthcare, adequate living conditions, and safety. A systematic review was conducted to gain a comprehensive understanding of the lifestyle of the female tea garden community. According to these studies, educational and financial conditions are the primary factors that influence their lifestyle. Research indicates that women in the tea community occupy a highly vulnerable position. Every facet of their lifestyle is laden with challenges, from the onset of their marriage to inconsistencies in earnings. There is a necessity for evidence-based, comprehensive intervention strategies to enhance the lifestyle of women in the tea community.

Pronab Jyoti Powrel and Snehal Mishra this research aims to analyze the socio-economic conditions and current satisfaction levels of tea garden laborers in the Biswanath region of Assam. The research investigates seven distinct characteristics of job satisfaction: Compensation Amount, Compensation Regularity, Working Hours, Working Conditions, Occupational Safety, Training Resources, and Supervisor Conduct. The study was conducted in Biswanath District, Assam, India, over the 2023-2024 period. A total of 138 respondents, confirmed to be employed in tea gardens or factories, were surveyed using a semi-structured questionnaire. The socio-economic profile revealed a diverse age distribution and a notable gender disparity among respondents, with males outnumbering girls across all age groups. The research indicated significant dissatisfaction with pay, as more than 50% of respondents expressed their discontent. The study identifies critical areas for improvement in labor conditions within tea estates and businesses in the Biswanath district. Widespread dissatisfaction with remuneration, occupational safety, and managerial behavior underscores the urgent need for targeted interventions. Enhancing compensation frameworks, ensuring prompt remuneration, improving working conditions and safety measures, and fostering positive relationships between employees and management are essential initiatives.

Nura Afrin Kuasha et al., in their study on “*An Investigation on Livelihood Status of Tea Workers at Doldoli Tea Garden*”, the researcher highlighted about the livelihood conditions of tea workers in Doldoli. A field survey was performed, and 60 tea workers were selected randomly. The survey indicated that nearly half of the workers lacked of formal education (48.3%). Concerning monthly earnings, 55% of employees receive just 4500-5500 Taka. The majority of the workers had favorable sentiments regarding the provision of living facilities such as power, sanitation, medical treatment, and hygiene upkeep. While the majority of employees possess job stability, 80% lack bank balances. Only 40% of workers are aware of human rights. Seventy percent of workers said that the trade union is not fulfilling

its responsibilities adequately. Approximately 86.7% of the workforce is excluded from political participation. Homestead operations and animal husbandry are conducted by workers for both familial and commercial interests, but to a lower degree. The survey indicated that low wages was the primary issue for workers, with 30% in agreement, while the predominant proposed remedy, endorsed by 36% of workers, was an increase in pay.

Research Methodology:

Study Design: This research used both qualitative and quantitative approach to provide thorough insights on the empowerment and challenges of the women tea garden workers in Panitola Block, Dibrugarh.

Population and Sampling:

The study focused on tea garden women workers in Panitola Block, Dibrugarh. A total of 63 participants were selected using random sampling to ensure representation from tea plantation sector.

Data Collection Instruments: A structured questionnaire was designed using a 5-point Likert scale i.e, (SD-Strongly Disagree, D-Disagree, N-Neutral, A-Agree, SA-Strongly Agree). The questionnaire included items related to demographic information, wages, working condition, housing facilities health protections medical facilities.

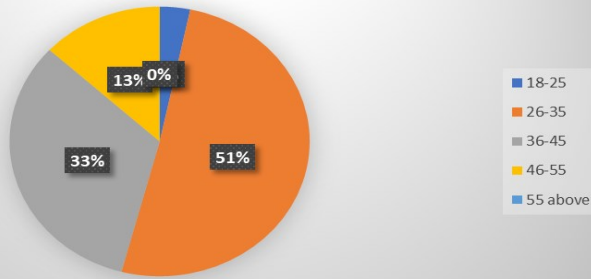
Data Analysis Statistical analysis, including descriptive statistics using SPSS. Qualitative Data Analysis Thematic analysis was employed through questioner data to extract themes related to participant experiences and perception.

Analysis and Discussion: This study basically covers 63 women workers in the Panitola Block Dibrugarh District. The table 1.1 indicates that 49% of the total respondents were in the age group category of 26-35 years. 32 % of the total respondents were in 36-45 years age group. In the below 25 years age group there were 4% respondents. The 46-55 and above age group is representing 13 % and above 55 is 3% The majority of the respondents were in the age group of 25-35 and 35- 45 years which are the most productive years in a person’s life.

Table 1.1: Age of the respondent

Age (in years)	Frequency	Percent
18-25	2	3.174603
26-35	31	49.20635
36-45	20	31.74603
46-55	8	12.69841
55 above	2	3.174603
	63	100

Age of the women worker

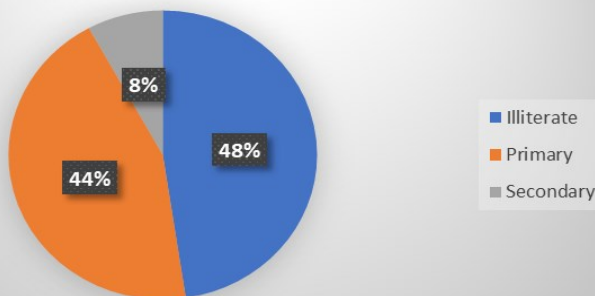


Educational Status -Education is the one of the major factors to shape one’s life. The table indicate the educational level of the women workers in the tea plantation sector in Panitola Block of Dibrugarh district. The respondent group majorly belongs to negligently from illiterate group which covers 48% of the selected population. Primary educational level which covers 44%. Secondary level of education is perused by 8 % of the sample population. Due to the low level of literacy among the tea garden women worker they are facing different type of problem and they even not able to identify if their rights get violate.

Table 1.2 Educational Status of the women workers

Educational Status	Frequency	Percent
Illiterate	30	47.619
Primary	28	44.44444
Secondary	5	7.936508
Total	63	100

Educational Status



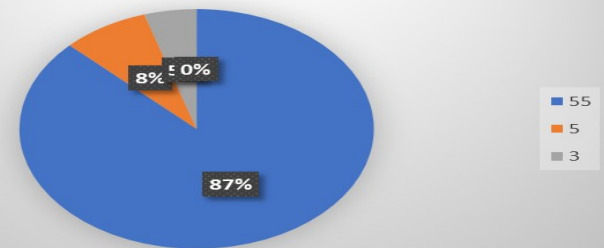
Marital Status-While study about the empowerment and challenges of the women worker in tea plantation sector of Panitola block the marital status of women worker is very important aspect which contribute towards the to determine challenges related to freedom of work. The table 1.3 represents the marital status of these women workers. Some of the women are married and maximum of the sample population are married rest of the population are widow and unmarried. Among these tea garden

women workers they are work even after marriage. The study reveals that 87 % of the women worker are married and they are getting full support from their family to work in tea gardens. The married women covered 8 %, they are expressing their willing to work even after marriage and rest of the 5 % are window they engage themselves as they have some financial constraints and engage themselves for survival.

Table 1.3 Marital Status of the tea garden women worker

	Frequency	Percent
Married	55	87.30159
Unmarried	5	7.936508
Widow	3	4.761905
	63	100

Marital Status of the tea garden women worker



Type of Employment -As the majority of the worker in the tea garden are the women and they majorly engage is tea leaf plucking 86% of the sample population engaged in tea leaf plucking work. The rest 6% of the worker engaged in manufacture activities other 6% are engaged in health care activities of the garden and 2% of the women workers engaged in other miscellaneous activities.

Table 1.4 Type of employment of the tea garden women worker

Type of Employment	Frequency	Percent
Tea Leaf plucking	54	85.71429
Health Care	4	6.349206
Manufacture	4	6.349206
Others	1	1.587302
	63	100

Type of employment of the tea garden women worker

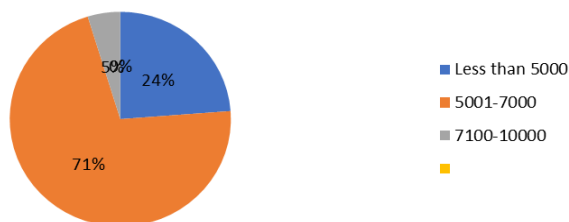


Income: Financial stability is always depended on the income and the salary received by a person. The salary of the tea garden women worker is not satisfying. They only received a minimum scale for their work. 71 % of the sample population are receiving 5001-7000 rupees per month. The rest 24% of the sample population are receiving less than 5000 rupees as their monthly salary and only 5 % of the women worker are receiving 7100-10000.

Table 1.5 Monthly income of the tea garden women worker

Salary	Frequency	Percent
Less than 5000	15	23.80952
5001-7000	45	71.42857
7100-10000	3	4.761905
	63	100

Monthly income of the tea garden women workerles



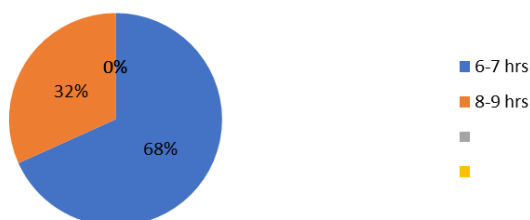
Working Condition

Working Hours: A decent working hour is very important to maintain good health and a balance professional life without effecting the personal life. From the study it has been find out that the working hours of the workers are not uniform. The table 1.6 represents 68% working for 6-7 hours where 32% of the women workers are working for more than 8 hours.

Table 1.6 represent the working hour of the tea garden women worker

Working hour	Frequency	Percent
6-7 hrs	43	68.25397
8-9 hrs	20	31.74603
	63	100

Working hours of the tea garden women workers



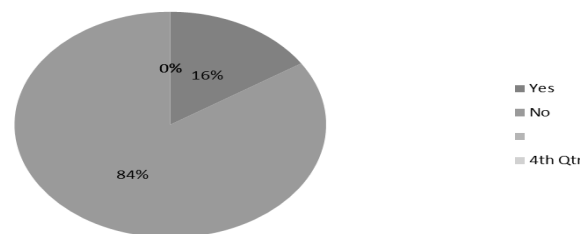
Medical Accessibility

Availability of Medical officer: Medical facilities are always a very important matter of concern in tea garden and medical officer pays a very pivotal role in imparting health care awareness among the garden workers. He is the person who is responsible for primary health check-up for the workers and their family members. But this study revels that the condition in the tea gardens of the Dibrugarh district in regards to medical officer is very poor, only 16% of the respondent acknowledge that they have their medical officer in the tea garden but rest of the 84% are responding negatively as the post of the medical officer is vacant. Therefore, they difficulty in accessing the proper medical assistance during their necessity. Most of the garden hospitals are run by the nurses only without and qualified doctor.

Table 1.7 represent Availability of Medical officer in tea garden

Response	Frequency	Percent
Yes	10	15.87302
No	53	84.12698
	63	100

Availability of Medical officer in tea garden



Women Participation in labour Union

While studying on the socio- legal status of the women worker and talking about the equal right and equal participation of the women worker it is a major factor to see the participation of the women worker in labour union of the tea gardens. But the finding shows that in table 1.8 which represents that the participation of the women worker in labour union is very less which covers the 8% of the total respondent are response positively rest 92% of the sample population is not part of the labour union of the garden neither they get the opportunity to took part in the labour union of the tea garden. It shows that the women worker are not get equal opportunity in participation as a member of the tea garden labour union.

Table 1.8 represents the participation of the women worker in labour union

	Frequency	Percent
Yes	5	7.936508
No	58	92.06349
	63	100

Women worker Participation in labour Union



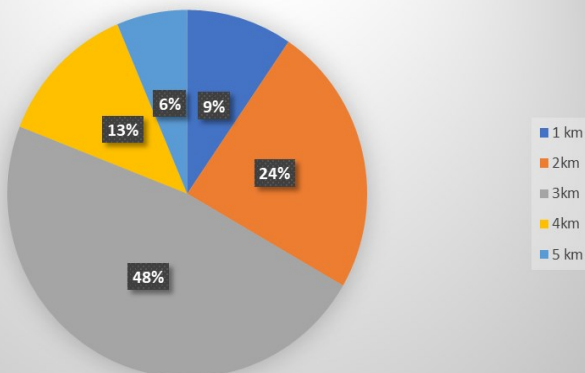
Road and Transport Facility:The road and connectivity to these gardens of the Dibrugarh District is good enough but gardens are situated in some remote and out squared places from the town. In this part of the study the mode of transportation and distance to the work place of the women worker is represented.

Distance from house:The table represents that 24% of the sample population covered 2 km of distance to reach their workplace, where 48 % of the sample population have to cover 3km of distance. The rest 10% covers 1km and 13% of the worker covers 4 km. Rest 6% of the sample population have to cover 5 km.

Table 1.9 represent distance of the work place from their resident tea garden

Distance	Frequency	Percent
1 km	6	9.52381
2km	15	23.80952
3km	30	47.61905
4km	8	12.69841
5 km	4	6.349206
	63	100

Distance of the work place from their resident tea garden

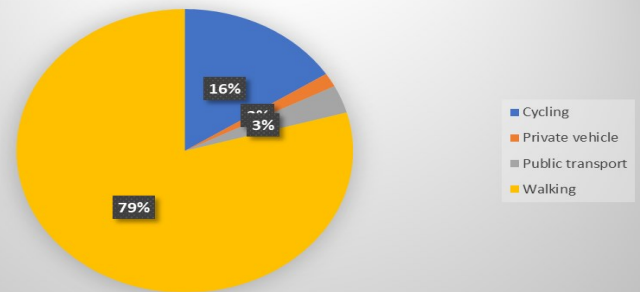


Mode of Transportation: The table 1.10 is representing the mode of transportation of the women worker to reach their work place shows that 79% of the sample population come to the tea garden by walking. Rest 16% come by cycling and rest 3% and 2% of the women respondent come by public transport and private vehicle.

Table 1.10 mode of transportation of the tea garden worker to reach workplace.

	Frequency	Percent
Cycling	10	15.87301587
Private vehicle	1	1.587301587
Public transport	2	3.174603175
Walking	50	79.36507937
	63	100

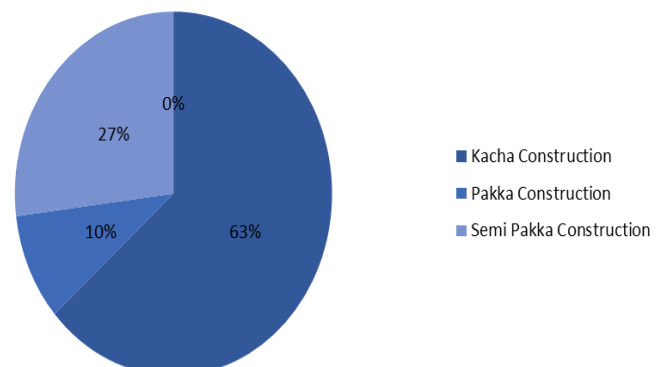
Mode of transportation of the tea garden worker to reach workplace



Housing facilities :Housing is the most important and basic facilities for the workers working in the tea garden. Maximum workers are residing in the quarter provided by the garden authority. Table 1.11 represents the structure of the garden quarters. It shows that 49% of the respondent population resides in semi pakka construction other 32% resides in pakka construction and rest 19% resides in kacha constructed house.

Table 1.11 represent the housing facilities tea garden

Housing facilities tea garden



Findings

- In this study respondent women workers of the tea garden in Panitola block Dibrugarh district are maximum from the age group 25-45 years and married with some widow's women also working in the plantations.
- It is observed that the illiteracy rate of the sample respondents is 48%, the respondent population of 44% are having the educational qualification up to primary level and 5% women are secondary level educational qualification.
- The 86 % of respondent population of the tea garden engaged in tea leaf plucking activities and rest are engaged in manufacture and health care related task.
- The wages paid to the comparatively low they, 71% of the sample population received their monthly salary 5001-7000 which is not sufficient for their basic amenities. This low payment influence on their economic condition and social life.
- During the course of the research, it was discovered that the working hours of the employees are not consistent with one another. A total of 68% of workers are employed for a duration of 6-7 hours, whereas 32% of female workers are employed for times that exceed 8 hours.
- Health and medical accessibility are not satisfactory. This study reveals that the maximum tea gardens in Panitola Block of Dibrugarh District are having their hospital or the primary health care centre for their workers and their family there is the scarcity for medical officer, only 16% of the respondent acknowledge that they have their medical officer in the tea garden but rest of the 84% are responding negatively as the post of the medical officer is vacant.
- While studying on the socio- legal status of the women worker and talking about the equal right and equal participation of the women worker it is a major factor to see the participation of the women worker in labour union of the tea gardens. But the finding shows that in table 1.8 which represents that the participation of the women worker in labour union is very less which covers the 8% of the total respondent are response positively rest 92% of the sample population is not part of the labour union of the garden neither they get the opportunity to took part in the labour union of the tea garden. It shows that the women worker is not get equal opportunity in participation as a member of the tea garden labour union.
- Housing is the most important and basic facilities for the workers working in the tea garden. Maximum workers are residing in the quarter provided by the garden authority. Table 1.12 represents the structure of the garden quarters. It shows that 27% of the respondent population resides in semi pakka construction other 10% resides in pakka construction and rest 63% resides in kacha constructed house. But the quates condition are not good they are not well

maintained.

- The worker has to manage a long distance from their residence to their work place and maximum women workers come by walking with all their heavy belongings.

Conclusion: The study conducted in Panitola Block, Dibrugarh District reveals significant challenges in the social status of the women tea garden worker they are facing some problems related to their wages as the wages paid to them is very nominal, they showed dissatisfaction in this aspect. The findings also highlight substantial deficiencies in health care services in garden due to lack of medical officer. The educational level of the women worker is notably low this also hamper the social status as they are not aware about rights and protection. The findings underscore the urgent need for consistent enforcement and comprehensive support that effectively protect women employees along with their basic amenities and housing facilities with proper maintenance.

Recommendation:

- Enhance Awareness and Training Programs by implementing comprehensive education and training initiatives to increase awareness among women workers about their legal rights and the protections under law.
- Strengthen Enforcement Mechanisms with improvement in the wage structure according to the rules and regulations for the tea garden workers.
- Working hours should be uniform and it must be accompanied by a balance structure of work because constant tea leaf plucking for the women worker create adverse effect to their health.
- Improve Health Support by enhancing proper basic medical facilities with appoint of medical officer and nurses or related health care employees.

References:

1. Amali Philips, *Rethinking culture and development: marriage and gender among the tea plantation workers in Sri Lanka*, Gender and Development. 11(2). (2003) Tailor and Francis Ltd. Pp- 20-29.
2. Ananda Das Gupta and Sangeetha M, *Improving Labour Productivity through Human Resource Development: A Case Study on Assam Tea Plantation Workers*, 6(1), *Journal of Supply Chain Management Systems*, (2017). Available at <http://www.publishingindia.com/GetBrochure.aspx?query=UERGQnJvY2h1cmVzfC8zODgxLnBkZnvwMzg4MS5wZGY=>
3. Abir Hassan, *Deplorable Living Conditions of Female Workers: A Study in a Tea Garden of Bangladesh*, 2(20), *American Journal of Humanities and Social Sciences*, pp 121-132, (2014). Available at https://www.researchgate.net/publication/307789002_Deplorable_Living_Conditions_of_Female_Workers_A_Study_in_a_Tea_Garden_of_Bangladesh

4. Bijay Chandra Boro and Kokila Saxena, *The impact of work-life balance on the wellbeing of employees in the tea gardens of Bodoland territorial region*, 6(S3), International Journal of Health Sciences, pp- 11972-11982, (2022). Available at https://www.researchgate.net/publication/362087073_impact_of_work-life_balance_on_the_wellbeing_of_employees_in_the_tea_gardens_of_Bodoland_territorial_region

5. Bidisha Mahanta, *Gender Gap among the BPL Households of Tea Gardens and Villages of Dibrugarh District of Assam*, 12(1), Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, (2020)

6. Dipali Basumatari and Phanindra Goyeri, *Educational Status of Tea Plantation Women Workers in Assam: An Empirical Analysis*, 1(3), Asian journal of multidisciplinary studies, pp.17-26, (2013).

7. Dr. Bharat Dhiman and J.C. Bose, *Role of Education in Empowering Women: A Systematic Review* (September 9, 2023). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4568381>

8. Horen Goowalla, *Labour Relations Practices in Tea Industry of Assam- With Special Reference to Jorhat District of Assam*, 1(2), IOSR Journal of Humanities and Social Science, pp 35-41, (2012). Available at <https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/vol1-issue2/G0123541.pdf>

9. Himakshi Bhuyan, *Status of the Tea Garden Women Workers of Assam: An Analysis*, 6(5), International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), pp 1-5, (2024), available at <https://www.ijfmr.com/papers/2024/5/27004.pdf>

10. Pronab Jyoti Powreland Snehal Mishra, *Job Satisfaction Level Among the Tea Garden Workers in Biswanath District of Assam, India*. 46(8). Journal of Experimental Agriculture International, pp-570-76. (2024). available at <https://journaljeai.com/index.php/JEAI/article/view/2737>

11. Mridusmita Duara and Sambit Mallick, *Women Workers and Industrial Relations in Tea Estates of Assam*, 55(1), Indian Journal of Industrial Relation. Pp 15-26, (2019). Available at https://www.researchgate.net/publication/333892562_Women_Workers_and_Industrial_Relations_in_Tea_Estates_of_Assam

12. Nura Afrin Kuasha et al, *An Investigation on Livelihood Status of Tea Workers at Doldoli Tea Garden*, 17(1), Journal of Agro Forestry and Environment, pp- 13-19. (2024), available at https://www.researchgate.net/publication/380712554_An_Investigation_on_Livelihood_Status_of_Tea_Workers_at_Doldoli_Tea_Garden_Sylhet

13. Samir Kr. Sen et al, *Empowerment and Women's Empowerment – A Theoretical Basis*, 5(3), International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), (2023).

14. Shilpi Das and Doyel Karmakar, *Lifestyle of Women In Tea Garden Community: A Systematic Literature Review*, 6(6), International Journal for Multidisciplinary Research, pp 1-11, (2024) available at https://www.researchgate.net/publication/388448860_Lifestyle_of_Women_in_Tea_Garden_Community_A_Systematic_Literature_Review

15. Shilpi Das and Doyel Karmakar, *Lifestyle of Women In Tea Garden Community: A Systematic Literature Review*, 6(6), International Journal for Multidisciplinary Research, pp 1-11, (2024) available at https://www.researchgate.net/publication/388448860_Lifestyle_of_Women_in_Tea_Garden_Community_A_Systematic_Literature_Review

शब्दों का खाकरोब कहानी में आर्थिक समस्याएँ

उमा बणिचुल

शोधार्थी

हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय-हैदराबाद

समस्या कहने का तात्पर्य कठिन प्रसंग, कठिन विषय, जटिल स्थिति, उलझा हुआ मामला, मुसीबत आदि को माना जाता है। आर्थिक समस्या कहने से आर्थिक क्षेत्र में परेशानी के अनेकी स्थिति को समझा जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होती हैं। विभिन्न कारणों से आर्थिक समस्या आती रहती है। यह है- अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता एवं दारिद्र्यता, भूमि संबंधी विषमताएँ, ऋणग्रस्तता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, व्यसनाधीनता, दहेज प्रथा, यांत्रिकीकरण, प्राकृतिक कारक, शोषण, जमींदार एवं साहूकार वर्ग अथवा उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण आदि।

अशिक्षा और बेरोजगारी:-आधुनिक युग में भी भारत जैसे देश में लगभग तीस प्रतिशत आबादी अशिक्षित है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अशिक्षा संख्या कहीं अधिक है। इतनी बड़ी आबादी के अशिक्षित होने से देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। अशिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं- निर्धनता, निर्धनता और अशिक्षा के बीच में परम्पर संबंध है। यह भी कहा जा सकता है कि अशिक्षा से गरीबी बढ़ती है एवं गरीबी बढ़ने से लोग शिक्षित नहीं हो पाते। एक दूसरे के लिए दोनों दोषी हैं।

भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी अस्सी प्रतिशत आबादी गाँव में निवास करती है। आधुनिक युग में शहरी चकचौंधता से प्रभावित होने के कारण गाँवों की आबादी में कुछ कमी आई। गाँव में अशिक्षित लोग शिक्षा का महत्व समझ नहीं पाते जिसके कारण वह अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। फलतः वे अशिक्षित रह जाते हैं। अशिक्षा के कारण अच्छे रोजगार नहीं मिल पाते जिससे गरीबी बढ़ती जाती है, मेहनत-मजदूरी करनी पड़ती है, नहीं तो सेठ-साहूकारों तथा जमींदारों के कर्ज के चंगुल में फँस जाते हैं।

'शब्दों का खाकरोब' कहानी संग्रह में 'मुकदमा' प्रमुख कहानी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र पूरन गाँव में रहने वाला एक सरल एवं मेहनती आदमी था। वह कृषि एवं मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उसका एक चचेरा भाई था मूलू जो शहर में रहता था। वह पूरन के पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार का जमाना चाहता था। जिसके लिए वह गलत तरीके से अपनाकर पूरन की जमीन हड़प कर अपने मित्र राम प्रसाद को बेचना चाहता था। अतः उसने पूरन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। चपरासी ने मुकदमे का नोटिस पूरन को देते हुए अँगूठा लगाने को कहा जिसका वर्णन कहानी में इस प्रकार किया गया है-

“चपरासी के कहने पर पूरन ने जहाँ बताया अँगूठा लगा दिया। बेचारा समझ नहीं पाया, आज तक केवल लगान की रसीद पर ही अँगूठा लगाया था।” इससे स्पष्ट होता है कि पूरन यदि पढ़ा-लिखा अर्थात् शिक्षित होता तो उस मुकदमे के नोटिस को अच्छी तरह पढ़कर समझ पाता। इस प्रकार चपरासी के कहने पर तुरंत बिना सोचे समझे अँगूठा नहीं लगाता। अशिक्षा के कारण उसे शिक्षित व्यक्ति की हाँ में हाँ न मिलाना पड़ता। अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़ता है।

भ्रष्टाचार-भारत देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा तथा व्यापक रूप ले चुका है। कुछ लोग कानूनी नीति नियमों को उल्लंघन कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा

देते हैं। जिसके कारण लोगों ने नैतिकता एवं चारित्रिक निम्नता दिखाई देती है। भ्रष्टाचार आज के समय में आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार के द्वारा गलत मार्ग अपना कर अधिक से अधिक मुनाफा व धन कमाया जाता है। भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं यथा- मुनाफाखोरी, पद का दुरुपयोग, घुसखोरी, मिलावट, कर्तव्यपरायणता में आलस्य, सामाजिक दायित्व के विरुद्ध आचरण आदि। देश के सरकारी कार्यालयों, पुलिस विभाग, न्यायालय, प्रशासन, राजनीति और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसारे हैं।

'शब्दों का खाकरोब' में 'मुकदमा' कहानी का मुख्य पात्र पून है जो कि अनपढ़ था। वे कृषि एवं मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। उसका एक चचेरा भाई था मूलू जो कि शहर में नौकरी करता था। जमीन बँटवारे को लेकर मूलू ने मुकदमा तहसील कार्यालय में दायर कर दी थी उस समय पुलिस ने आकर जो कार्य किया उसका वर्णन निम्न में है

“जमीन भी सरकार ने कुर्क कर दी। पुलिस का सिपाही आया और गहूँ की सुपर्दगी मुच्छल बाँकेलाल को दे गया। बाँकेलाल निहायत पियेक्कड़ है और यह तयशुदा था कि वह सारी फसल बेचकर थाने में कुछ हिस्सा पहुँचाकर बाकी हड़प कर जाएगा।” इससे स्पष्ट विदित है कि पुलिस आकर दोनों के कार्य को आसान करने की बजाय जीवन शैली को और अधिक क्लिष्ट बना गई। पुलिस द्वारा फसल को जोर जबरदस्ती बेचना एवं लूट कर ले जाना, उनके पद के दुरुपयोग के साथ-साथ भ्रष्टाचार का एक अन्य उदाहरण है।

जब पून की ज़मीन को कुर्क कर दिया गया तो वह चिन्तित हो गया। घटना को सुलझाने के लिए तथा अपने अधिकार को पाने के लिए रिश्तत द्वारा जेब गरम करने का विचार कहानी में वर्णित है-

“पून ने हाथ जोड़ लिए बोला” माई-बाप, ज़मीन हमारी। गरीब आदमी है, आप ही मालिक है।” थानेदार ने थोड़ी दया दिखाकर दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पंचायत की दोनों तरफ के कागज देखे। दोनों तरफ से दाम वसूली की।” गरीब कृषक पून का नाम पर खेत संबंधि मुकदमा होने से इन्स्पेक्टर धमकाने लगा। पून हाथ जोड़कर सच्चाई बताने की कोशिश किया। थानेदार ने बात को सुलझाने के लिए पून और मुकदमा करने वाला चचेरा भाई मूलू को थाने पे बुलाया था। इससे प्रतीत होता है कि मुनाफाखोरी करना भी भ्रष्टाचार है।

संदर्भ:-

1. राजू शर्मा- हलफनामे, पृ. - 103.
2. राजू शर्मा- शब्दों का खाकरोब (मुकदमा), पृ.-13.
3. राजू शर्मा- शब्दों का खाकरोब (मुकदमा), पृ.-13.
4. राजू शर्मा- शब्दों का खाकरोब (मुकदमा), पृ.-13.
5. राजू शर्मा- शब्दों का खाकरोब (मुकदमा), पृ.-13.

समकालीन स्त्री के बदलते मायने

डॉ. सीमा चन्द्रन

सहायक प्राध्यापक

हिन्दी व तुलनात्मक साहित्य विभाग,

केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय,

पेरिया पोस्ट, तेजस्विनी हिल्स, कासरगोड- 67132

ई-मेल-seemachandran@cukerala.ac.in

प्रस्तावना: समकालीन स्त्री परंपरा के घेरे में न होकर भी धकेल दी जाती है। समकालीन स्त्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर भी रंगीन चुभते तानों या व्याख्या के परे अपनी पहचान पा नहीं पाती। पारिवारिक जिम्मेदारी वर्तमान समय में भी स्त्री के ही कंधों पर है। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ बहु-टास्किंग का कार्य स्त्री को ही करना है। यदि कहीं पर भी कोई चूक हो गई तो नाकाब्रिल हालात को नहीं स्त्री को ही समझा जाता है। इस बीच यही दोनों कार्य शारीरिक बल से संपूर्ण पुरुष को भी करना हो तो उन्हें भी समान दिक्कत होगी। शायद स्त्री से ज़्यादा। परंतु स्त्री को कमजोर की श्रेणी में रखकर कई कार्य थोपे जाते रहे हैं। समकालीन लेखन किस हद तक बदलाव ला सकती है, इसे जानना होगा। बदलाव हमेशा मानसिकता बदलने से ही संभव है। ताकतवर को कमजोर कहने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु सदियों से दबाए हुए को कमजोर कहने से काफी फरक पड़ता है।

बीज शब्द: समकालीन, स्त्री, पुरुष, मानसिकता, साहित्य में स्त्री, स्त्री लेखिकाएँ, शोषण, कारण, बदलाव की माँग।

सदियों से साहित्य और समाज की परंपरा स्त्री के केन्द्र में दैहिक संरचना रखती आई है। इसी कारण उसे कोमल, बलिदानी, करुण हृदय और ममता के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। भारतीय संस्कृति जहाँ स्त्री को महान बनाती है, वहीं स्त्री विमर्श स्त्री को समान बनाने प्रयासरत है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, हिन्दू धर्म में स्त्री को देवी का स्थान प्राप्त है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ विदुषी और दार्शनिक थीं। वे ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययन हेतु स्वतंत्र थीं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को आश्रमों में शिक्षा व यज्ञों में भाग लेने का अधिकार था। धर्म और दर्शन में भी वह निपुण थीं। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि कर्तव्य निर्वाह में स्त्री-पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। उपनिषद् काल तक आते-आते स्त्रियाँ दर्शन के क्षेत्र में अग्रणी रहीं। पुराणों में स्त्रियों को भी, पुरुषों के समान ही शिक्षा का पूर्ण अधिकार था।

हिन्दी व्याकरण में आए शब्द के अंत में 'ई' स्त्रीलिंगवाची शब्द-स्त्री, प्रकृति, शक्ति और बुद्धि, चारों ही स्त्रियों को व्याख्यायित करने में अद्भुत सिद्ध हुए हैं। अर्थात् स्त्री करुणा की प्रतिमूर्ति, प्रकृति जैसी अभेद प्रवृत्ति, निर्माण की शक्ति और विवेकशील बुद्धि का अर्द्धभाग है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना असंभव है।

स्त्री विमर्श, दो शब्दों स्त्री और विमर्श से बना है। विमर्श का अर्थ है -विचार, विवेचन, परीक्षण, समीक्षा, तर्क¹। (हिन्दी शब्दकोश में) वहीं रोहिणी अग्रवाल इसे 'जीवन्त बहस'² मानती हैं। उनका मानना है कि स्त्री को केन्द्र में रखकर समाज, संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास का पुनरीक्षण करते हुए स्त्री की स्थिति पर मानवीय दृष्टि से विचार करने की अनवरत प्रक्रिया। अतः स्त्री विमर्श से तात्पर्य- स्त्री विमर्श एक विचारधारा है, जिसे स्त्री के किसी एक दृष्टिकोण या मानसिकता का अध्ययन न कर समग्र विचारों का अध्ययन करना है। यह एक माध्यम है, जिसमें स्त्री के हितों पर विचार कर अपनी बात को रखा जाता है। इस तरह स्त्री विमर्श एक नवीन विचारधारा को समाज के समक्ष प्रस्तुत

करता है जो स्त्री के हितों को ध्यान में रखकर उसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अपने अस्तित्व को समाज के समक्ष उजागर करने की प्रेरणा देता है। स्त्री विमर्श में एहम मुद्दा स्त्री अस्मिता का है, जिसमें स्त्री को पुरुष के समकक्ष खड़ा करने की बात रखी गई है। स्त्री अस्मिता पर महादेवी वर्मा अपनी रचना, 'श्रृंखला की कड़ियाँ' में कहती हैं, "युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े-बड़े साम्राज्य बह गये, संस्कृतियाँ लुप्त हो गई, जातियाँ मिट गई, संसार में अनेक असम्भव परिवर्तन सम्भव हो गए, परन्तु स्त्रियों के ललाट में विधे की वज्रलेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी।"³

शिक्षा ने स्त्री को संस्कारों के कलेवर पर ढाल दिया। उसे एक आदर्श छवि मिली, पर पुरुष उसका प्रतिद्वन्द्वी बन गया। इस होड़ में समाज सँवरने की जगह बिखरने लगा। जिस अस्तित्व के लिए वह जंग लड़ रही थी, उसी अस्तित्व पर कुलटा, कलंकिनी, चरित्रहीन कहकर उँगली उठाई गई। उसमें भय पैदा किया गया कि, यदि अस्तित्व के लिए आवाज़ उठाई तो बलात्कार, देह-हत्या, कन्या-भ्रूण हत्या, पीड़ा, शोषण, घरेलू-हिंसा, बाल-विवाह, सती-प्रथा, तेजाब में झूलसाकर मार दी जाएगी। स्त्री मुक्ति का तात्पर्य पुरुष को दरकिनार कर अपना वर्चस्व पाना नहीं है, बल्कि उन परंपराओं से मुक्ति है जो मात्र स्त्री के लिए गढ़ी गई है। मृणाल पाण्डे स्त्री मुक्ति के प्रश्न के यथार्थ को यँ प्रकट करती हैं, "नारीवाद पुरुषों का नहीं उनकी मानवीयता घटाने वाले उस छद्म मुखौटे का प्रतिकार करता रहा है। जो मर्दानगी के नाम पर गढ़ा गया है और जिसके पीछे झूठी अहमन्यता और उत्पीड़क प्रवृत्ति के अलावा कुछ नहीं है।"⁴ स्पष्ट है कि स्त्री केवल पुरुष की संकीर्ण विचारधारा से मुक्ति चाहती है। स्त्री चेतना को स्वतंत्रता के पश्चात् से ही पहचाना जाने लगा था। स्त्री सशक्तिकरण के कई प्रयास किए गए हैं। स्त्री चेतना का अर्थ ही अधिकारों के प्रति जागरूक होने की शक्ति से है। डॉ. के. एम. मालती 'स्त्री विमर्श-भारतीय परिप्रेक्ष्य' नामक किताब में स्पष्ट कहती हैं, - "अपने स्वत्व से जुड़ी तमाम समस्याओं के प्रति आज की स्त्री सचेत है। स्त्री से जुड़े बिंदुओं की बारीकी के साथ तीव्र पहचान स्त्री ही कर सकती है। स्त्री विमर्श का मतलब स्त्री पुरुष की स्वार्थ की दौड़ नहीं है, स्त्री की स्वयं की आलोचना भी है।"⁵ स्त्री जागरूक होकर, लेखन क्षेत्र के माध्यम से अपनी अस्मिता के लिए कई स्त्री आगे आईं। परम्परागत मूल्यों और पुरुष प्रधान समाज की कुत्सित मान्यताओं के खिलाफ संघर्ष करने लगीं। मैत्रेयी पुष्पा कहती हैं, "नारीवाद ही स्त्री विमर्श है। नारी की यथार्थ स्थिति के बारे में चर्चा करना ही स्त्री विमर्श है।"⁶ यहाँ मात्र उद्देश्य समकक्षता का है। आगे बढ़ने की होड़ कतई नहीं है। स्त्रीवाद का अर्थ है ऐसा विश्वास या सिद्धांत जो स्त्रियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त कराएँ।

महादेवी वर्मा स्त्री की वास्तविक लड़ाई की ओर इशारा करती हैं और बताती हैं कि यदि स्त्री केवल स्त्री, पुरुष से तर्क करने में लगी रहे, जरा भी समझौता न करे तो तो व्यवस्था निश्चल हो जाएगी। आज की शिक्षित नारी इस बेड़े को उठा सकती है। शिक्षित नारी के संबंध में महादेवी वर्मा कहती हैं, "...भविष्य में भारतीय समाज की क्या रूपरेखा हो? उसमें नारी की कैसी स्थिति हो? उसके अधिकारों की क्या सीमा हो? आदि समस्याओं का समाधान आज की जाग्रत और शिक्षित नारी पर निर्भर है... वह विरोध को ही चरम लक्ष्य मान लें और पुरुष से समझौते के प्रश्न को ही पराजय का पर्याय समझ लें तो जीवन की व्यवस्था अनिश्चित और विकास का क्रम शिथिल होता जाएगा।"⁷ वहीं रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि पुरुष, अपने झूठे पौरुष को स्थापित करने के लिए स्त्री पर हावी होता है। उसका पुरुषार्थ मात्र स्त्री पर अधिकार कर उसे परतंत्र बनाने तक निर्भर है। "पुरुष अपने अहम् के वशीभूत ही स्त्री

के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहा है, और आज तक यदि पुरुष नारी को समझ लेगा तो समाज का सारी विषमताओं का स्वतः ही निराकरण हो जाएगा, आवश्यकता उसे समझने और महसूस करने की है।"⁸ मैत्रेयी पुष्पा जी मानती हैं कि स्त्री के यथार्थ स्थिति के बारे में चर्चा करना ही स्त्री विमर्श है। प्रभा खेतान के शब्दों में, "नारीवाद न मार्क्सवाद है और न पूंजीवाद। स्त्री हर जगह है, हर वाद में है, फैलाव में है, मगर संस्कृति के विस्तृत फलक पर आज भी वह वस्तुकरण की शिकार है, वस्तुकरण की इस पारंपरिक प्रक्रिया को पुरुष दृष्टि से नहीं बल्कि स्त्री-दृष्टि से देखने और समझने की जरूरत है।"⁹ प्रभा खेतान स्त्री की वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार स्वयं स्त्री को मानती हैं। भारतीय स्त्री चिंतक स्त्री और पुरुष के बीच की गहराई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्री को अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। देह को त्याग कर मस्तिष्क से बनानी होगी अपनी पहचान। क्योंकि देह ने स्त्री को हमेशा वस्तुकरण की प्रताड़ना के साथ प्रदर्शनी और भोग्या ही बनाया है। बौद्ध थेरी गाथाओं में 522 गाथाएँ हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा उनके अनुभवों और मनःस्थिति को अभिव्यक्त किया गया है।

विज्ञान ने सिद्ध किया है कि स्त्रियाँ पुरुषों से किसी भी अर्थ में कम नहीं हैं। बल्कि उन्हें मातृत्व का विशेषाधिकार प्राप्त है। समाज ने पक्षपातपूर्ण अनेक अधिकारों से वंचित कर रखा है। वैदिक काल में उसकी स्थिति सम्मानजनक थी, परन्तु उत्तर वैदिक काल में उसका पतन होना आरंभ हो गया। समकालीन दौर में स्त्री अपनी अस्मिता की तलाश समाज, साहित्य और संस्कृति के भीतर लगातार कर रही हैं। एक ओर उसे नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहकर उसे आध्यात्मिक में माया, बाधिनी, सर्पिणी आदि विशेषण दिए गए हैं। इन्हीं रूढ़ियों के बीच सामान्य होने को व्याकुल उसकी छटपटाहट और संघर्ष उसे विमर्श के केन्द्र में खड़ा करता है। पितृसत्तात्मक मूल्य स्त्री को दायम दर्जे का मानते हुए उसके मानवीय मूल्य एवं अधिकारों का हनन करते हैं। स्त्री विमर्श इन्हीं पितृसत्तावादी मूल्यों को तोड़कर समाज में न्याय, समता और स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार करना चाहती है।

स्त्री विमर्श का तात्पर्य पुरुष का विरोध नहीं है बल्कि पितृसत्तावादी मानसिकता का विरोध है, जिसने स्त्री को उसके अधिकारों से वंचित ही नहीं रखा बल्कि उसे संपत्ति समझा। सुधा सिंह अपनी किताब 'ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ' में लिखती हैं, "स्त्री अस्मिता का प्रमुख आधार है स्त्री को पुरुष संदर्भ से बाहर लाना और स्त्री संदर्भ में रखकर देखा।....स्त्री और पुरुष दो अलग अस्मिताएँ हैं। भाषा और विचार के जन्म से पहले स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ। स्त्री और पुरुष का प्रकृति से संस्कृति में रूपांतरण वैसे ही है, जैसे लड़का धीरे-धीरे मर्द और लड़की धीरे-धीरे औरत बनती है। इसी क्रम में दोनों की भूमिकाएँ तय होती हैं। इस संदर्भ में लिंग के संबंध और पहचान का जन्म होता है। भाषा के जरिये लैंगिक चिंतन अभिव्यक्त होते हैं।"¹⁰ प्रस्तुत वक्तव्य से ज्ञात होता है कि सुधा सिंह स्त्री विमर्श का आधार स्त्री अस्मिता को मानती हैं। स्त्री का निर्माण मात्र शारीरिक संरचना के कारण ही नहीं बल्कि समाज के परिवेश, पारिवारिक परिस्थितियाँ, संस्कार, मूल्य आदि सभी मिलकर नारी मानसिकता का निर्माण करते हैं। फ्रैंच लेखिका सीमोन द बोउवार ने लिखा है "स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है।"¹¹

सर्वप्रथम अमरीका के मैसाच्युसेट राज्य में 1611 ई. में वोट देने के अधिकार की माँग से स्त्रियों की आजादी की शुरुआत हुई। इस घोर संघर्ष के दौरान स्त्री विरोधी लोगों ने इस प्रयास को 1980 विफल कर यह अधिकार वापस लिवा लिया। परन्तु इसका प्रयास पूरे विश्व पर पड़ा। क्योंकि पूरे विश्व में तब दो तरह के लोग थे। एक स्त्री विरोधी और दूसरे

शिक्षा ज़रूरी है। फ्रांस के राजनीतिज्ञ कांडसैंड ने स्त्रियों को शिक्षा देने नौकरी देने तथा राजनीति में भाग लेने की बात कही थी, तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी दिखाई पड़ा। अतः सन् 1840 में अमरीका ने दक्षिणशिया के नेतृत्व में समान अधिकार संघर्ष की स्थापना की और श्वेत महिलाओं की तरह अश्वेत महिलाओं के समान अधिकार की मांग की। बीसवीं सदी के मध्य में सीमोन द बोउवार ने स्त्री मुक्ति की आवाज़ अपनी पुस्तक 'द सेकेण्ड सेक्स' स्त्री मुक्ति की आवाज़ लेकर सामने आई। इसका हिन्दी रूपांतर 'स्त्री उपेक्षिता' प्रभा खेतान ने किया। इस पुस्तक का प्रभाव शिक्षित, चेतनायुक्त स्त्रियों पर पड़ा। सीमोन द बोउवार ने विभिन्न जाति के स्त्रियों के संबंध में कहा है, "स्त्री अधीनस्थ जाति है। जाति का अर्थ है कि कोई उस जाति में उत्पन्न हुआ है और वह उससे बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन आप औरत हैं, तो कभी पुरुष नहीं न बन सकती हैं। औरत विशुद्ध रूप से एक जाति है, वर्ग नहीं। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से औरतों के साथ होने वाला व्यवहार उन्हें एक अधीनस्थ जाति के रूप में निर्मित करता है।"¹² प्रस्तुत गद्यांश से ज्ञात होता है कि पूरे विश्व में विभिन्न तबके की स्त्रियाँ हैं। जिनमें निम्न, मध्य, उच्च आदि खेमें आते हैं। इनकी आवश्यकताएँ भी भिन्न होती हैं। सभी स्त्रियों को पहले शिक्षित होना होगा। फिर मिलकर अपने अधिकारों को पाना होगा।

भारत के मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में कवयित्री अनामिका जी लिखती हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी में पंडिता रमाबाई ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि ने स्त्री शिक्षा और स्वावलम्बन की मुहिम का मार्ग प्रशस्त किया। कई ऐसी रूढ़ियाँ तोड़ते हुए जो स्त्री जीवन खासकर विधवाओं और अन्य एकाकी स्त्रियों का अंतरंग जीवन क्षत-विक्षत रखती थी। सन् 1884 ई. में सीमोनतनी उपदेश की अज्ञात हिन्दी लेखिका ने हिंदू स्त्रियों की लड़ाई लड़ी। उन्हें अपना नाम छिपाना पड़ा था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारत के सभी वर्गों की स्त्रियों की मुक्ति की कानूनी लड़ाई हिन्दू कोड बिल देकर लड़ी। इसमें समान अधिकार चाहा गया है। पिता की संपत्ति में पुत्री को भी समान अधिकार की मांग की गई है। तत्कालीन संसद ने यह बिल प्राप्त नहीं होने दिया। इस निराशा में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से 10 अक्टूबर सन् 1951 को इस्तीफा दे दिया। यह बिल बाद में टुकड़ों में प्राप्त हुआ। सही मायने में आज भी स्त्रियों को अपना वाजिब हक नहीं मिलता है। मन्नु भंडारी मानती है कि हर स्त्री की अपनी अलग समस्याएँ हैं, इन्हें सिर्फ एक खाँचे में रखकर नहीं देखा जा सकता। वे लिखती हैं, "कौन सी भारतीय स्त्री ? किस भारतीय स्त्री की बात करते हैं हम वह जो उत्तरप्रदेश, राजस्थान व बिहार के गाँवों में रहती है। एक औरत जो गाँव में रहती है और जो दक्षिण दिल्ली में रहती है, क्या इन सबको एक ही गज से नापा जा सकता है ? इनके लिये क्या एक विमर्श तैयार किया जा सकता है। कि यह होना चाहिए या नहीं जब हमारे देश में इतनी विविधताएँ हैं, तो आप किस स्त्री के विमर्श की बात करते हैं सबकी अपनी अलग-अलग समस्याएँ हैं।"¹³

सीमा ओझा अपने समय की किन्हीं तेजस्वी स्त्रियों का जिक्र करते हुए कहती हैं, "नारी विमर्श पर चर्चा करते समय जिस तेजस्वी व्यक्तित्व का नाम ध्यान आता है वह है-मीरा, जिन्होंने मध्यकाल में सामंती समाज पितृसत्तात्मक समाज के विद्रोह का झंडा बुलंद किया और अपने समय को झकझोर कर रख दिया। मीरा ने समाज द्वारा "

उपर्युक्त समकालीन लेखिकाओं के कथन व उक्ति प्रामाणित करती है कि महिलाएँ वास्तव में सशक्त हैं, भले ही बल से नहीं मगर इरादों और आत्मविश्वास से। उनकी हिम्मत को खत्म करना आसान नहीं है। वे गिर कर भी उठ खड़ी हो लेती हैं। यही कारण है कि आत्मा की शक्ति

से और तटस्थ इरादों में स्त्री से जीतना मुश्किल है। पितृसत्ता यह जानती है कि स्त्री यदि स्वयं रक्षिता हो गई तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं। वास्तव में पहचान की ज़रूरत स्त्री को नहीं पुरुष को है। तभी परिवार में पहचान और आदर प्राप्त होगा। बगैर किसी पहचान के भी स्त्री माँ है। तभी सिंदूर, मंगलसूत्र व रीति-रिवाजों को ज़िन्दा स्त्रियों के माध्यम से रखा गया जिसे बेड़ियाँ बना दी गई। अतः कह सकते हैं कि यदि जिस घर या देश में स्त्री का सम्मान होगा, वह घर या देश समृद्ध और काफी हद तक क्राइम मुक्त होगी।

संदर्भ ग्रंथ-सूची :-

1. डॉ. हरदेव बाहरी, हिन्दी शब्दकोश, राजपाल एंड सन्स, नई दिल्ली, 2015, पृ. 751
2. रोहिणी अग्रवाल, साहित्य की ज़मीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 11
3. महादेवी वर्मा- श्रृंखला की कड़ियाँ- लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2001, पृ. 22
4. मृगाल पाण्डे, परिधि पर स्त्री, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ.
5. डॉ. के. एम. मालती- स्त्री विमर्श-भारतीय परिप्रेक्ष्य - वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, अक्टूबर 2012, पृ.84
6. हंस पत्रिका, संपादक राजेन्द्र यादव, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, अक्टूबर, 1996 पृ. 75
7. महादेवी वर्मा- आधुनिक नारी उसकी स्थिति पर एक दृष्टि-श्रृंखला की कड़ियाँ, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995, पृ.45
8. मधुमति पत्रिका, सं-रोहित गुप्ता, दिनकर की नारी विषयक अवधारणाएँ-डॉ. सुनिता निमावत (आलेख), राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर, फरवरी-मार्च, 2016-पृ.-45.
9. प्रभा खेतान, हंस पत्रिका, संपादक राजेन्द्र यादव, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, अक्टूबर 1996 पृ. 76
10. सुधा सिंह - ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ, शिल्पी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2008
11. सीमोन द बोउवार- स्त्री उपेक्षिता (अनुवाद प्रभा खेतान) - हिन्दी पॉकेट बुक्स प्रकाशन, संस्करण, 1992
12. सीमोन द बोउवार- स्त्री उपेक्षिता (अनुवाद प्रभा खेतान) - हिन्दी पॉकेट बुक्स प्रकाशन, संस्करण, 1992
13. मन्नु भंडारी- आजकल- नई दिल्ली, मार्च 2008 पृ. 15

Physico-Chemical Study of Water in Singrauli District, Madhya Pradesh

Dr. Vishwanath Singh Kushram

Assistant Professor Botany

PMCOE Govt Rajnarayan Smriti P.G. College Waidhan Singrauli(M.P.)

Mail-id-drsvskushram123@gmail.com

Abstract

Singrauli district, located in the northeastern part of Madhya Pradesh, India, is a major hub for coal mining and thermal power generation, leading to significant anthropogenic pressures on its water resources. This study investigates the physico-chemical characteristics of surface and groundwater in the district to assess their suitability for drinking, irrigation, and industrial uses. A total of 50 water samples (30 groundwater and 20 surface water) were collected from 25 locations across key blocks such as Deosar, Chitrangi, and Waidhan during pre-monsoon and post-monsoon seasons in 2024. Parameters analyzed include pH, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), total hardness (TH), calcium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), chloride (Cl^-), sulfate (SO_4^{2-}), nitrate (NO_3^-), fluoride (F^-), dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD), and heavy metals like iron (Fe), manganese (Mn), and chromium (Cr). Results indicate that pH ranged from 6.4 to 8.7, classifying water as slightly alkaline; TDS varied from 131 to 1,845 mg/L, exceeding the BIS desirable limit of 500 mg/L in 60% of samples; TH was 28-921 mg/L, indicating soft to hard water; and heavy metals like Fe (up to 2.273 mg/L) and Cr (exceeding 0.05 mg/L in several sites) posed contamination risks. The Water Quality Index (WQI) averaged 72.5, categorizing most sources as poor to marginal for drinking. Spatial mapping using ArcGIS revealed higher contamination near coal fields and ash ponds, attributed to leaching from industrial effluents and mining runoff. Statistical correlations (Pearson's r) showed strong positive links between TDS and Cl^- ($r=0.85$) and TH and Mg^{2+} ($r=0.92$). The study underscores the urgent need for remediation strategies, including effluent treatment and regular monitoring, to mitigate health risks such as fluorosis and gastrointestinal disorders. Recommendations include rainwater harvesting and policy enforcement for sustainable water management in this industrial hotspot.

Keywords-Physico-chemical parameters; Groundwater quality; Surface water; Singrauli district; Water pollution; Heavy metals; Water Quality Index (WQI)

Introduction-Water is the elixir of life, constituting about 71% of Earth's surface and essential for all

biological processes. However, rapid industrialization and urbanization have exacerbated water pollution, particularly in regions like Singrauli district, which is often dubbed India's "energy capital" due to its vast coal reserves and thermal power plants. Spanning 5,672 km² in Madhya Pradesh, Singrauli lies on the border with Uttar Pradesh, encompassing the Son and Rihand river basins. The district's economy thrives on coal mining (e.g., Northern Coalfields Limited operations) and power generation (e.g., NTPC Vindhyachal and Rihand Super Thermal Power Stations), contributing over 10% to India's electricity production. Yet, this development comes at an environmental cost: acid mine drainage, fly ash disposal, and untreated effluents contaminate local water bodies, threatening aquatic ecosystems and human health. Historically, Singrauli's water resources supported agriculture and tribal communities, but post-1970s industrialization has altered hydrogeology. Groundwater, sourced from Gondwana aquifers, is overexploited for irrigation, while surface water from rivers like Rihand and Kanhar receives industrial discharges. Studies report elevated levels of sulfates, chlorides, and heavy metals, linked to coal combustion byproducts and geological leaching. For instance, fluoride concentrations exceeding 1.5 mg/L in Deosar block pose risks of dental fluorosis, while high TDS (>500 mg/L) affects palatability and boiler scaling in industries.

The significance of physico-chemical studies lies in their ability to quantify pollution and guide policy. Parameters like pH influence solubility of metals; EC and TDS reflect ionic load; hardness ($\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$) impacts scaling; anions (Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^-) indicate salinity and eutrophication; and DO/BOD assess organic pollution. Heavy metals bioaccumulate, causing neurotoxicity and carcinogenicity. Previous research highlights seasonal variations: monsoon dilution lowers TDS, while post-monsoon evaporation concentrates ions.

This study aims to: (1) evaluate spatial and temporal variations in physico-chemical parameters of water in Singrauli; (2) compute WQI for potability assessment; (3) map contamination hotspots using GIS; and (4) correlate parameters statistically. By integrating field data with secondary sources from Central Ground Water

Board (CGWB), the research addresses gaps in comprehensive district-wide analysis, informing sustainable management amid climate change and population growth (district population: ~1.2 million, 2011 Census).

Materials and Methods

Study Area- Singrauli district (24°12'-24°48'N, 82°10'-83°15'E) features undulating terrain with Vindhyan sandstone and shale formations. Major rivers include Rihand (reservoir capacity: 10.6 BCM) and Son tributaries. Sampling covered three blocks: Waidhan (urban-industrial), Chitrangi (agricultural), and Deosar (mining-prone), selected for diverse land use (forests: 32%, mining: 15%, agriculture: 25%).

Sampling and Collection-Fifty samples (25 groundwater from handpumps/dug wells, 25 surface from rivers/ponds) were collected in May (pre-monsoon) and October (post-monsoon) 2024, following APHA guidelines. Sites were geo-referenced using GPS (e.g., Rihand Dam: 24.25°N, 82.75°E; Jayant Mine: 24.15°N, 82.60°E). Samples were stored in 1L polyethylene bottles (acid-washed for metals), preserved at 4°C, and transported to the laboratory within 6 hours.

Analysis of Physico-Chemical Parameters

Parameters were measured per standard methods:

Physical: Temperature (mercury thermometer), Turbidity (nephelometer, NTU), EC (conductivity meter, μS/cm).

Chemical: pH (pH meter), TDS (gravimetric, mg/L), TH (EDTA titration, mg/L as CaCO₃), Ca²⁺/Mg²⁺ (titration), Cl⁻ (argentometric), SO₄²⁻ (turbidimetric), NO₃⁻ (UV spectrophotometry), F⁻ (ion-selective electrode).

Biological: DO (Winkler titration, mg/L), BOD (incubation at 20°C for 5 days).

Metals: Fe, Mn, Cr (Atomic Absorption Spectrophotometry, AAS).

Triplicates ensured precision (SD <5%). BIS 10500:2012 and WHO standards were benchmarks.

Water Quality Index (WQI)-WQI was calculated using the weighted arithmetic index: $WQI = \sum_{i=1}^n q_i w_i / \sum_{i=1}^n w_i$
 $WQI = \frac{\sum_{i=1}^n q_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$ Where $q_i = (C_i/S_i) \times 100$ $q_i = (C_i / S_i) \times 100$ (C_i : observed, S_i : standard), $w_i = k/S_i$ $w_i = k / S_i$ ($w_i = k/S_i$ ($k=1$)). Categories: Excellent (<50), Good (50-100), Poor (100-200), etc.

Statistical and Spatial Analysis-Pearson's correlation analyzed inter-parameter relationships (SPSS v26). Spatial interpolation used ArcGIS 10.8 with IDW method (power=2) for thematic maps of TDS, F⁻, and WQI.

Results— Physico-Chemical Characteristics

Table 1 summarizes pre- and post-monsoon averages. pH ranged 6.4-8.7 (mean: 7.45 ± 0.65), slightly alkaline,

suitable per BIS (6.5-8.5). EC: 375-1,200 μS/cm (mean: 620 ± 210), correlating with mineralization. TDS: 131-1,845 mg/L (mean: 512 ± 285), exceeding 500 mg/L in 65% post-monsoon samples, highest near ash ponds (e.g., 1,845 mg/L at NTPC site).

TH: 28-921 mg/L (mean: 312 ± 156), soft (<150 mg/L) in 40%, moderately hard (150-300) in 35%, hard (>300) in 25%, driven by Ca²⁺ (9.6-156 mg/L, mean: 68 ± 42) and Mg²⁺ (1.95-105.8 mg/L, mean: 42 ± 28). Cl⁻: 82-2,186 mg/L (mean: 312 ± 450), above 250 mg/L in 55% samples, linked to mining leachates. SO₄²⁻: 13-418 mg/L (mean: 145 ± 112), within 200 mg/L except in Deosar (max 418 mg/L). NO₃⁻: 0.09-46 mg/L (mean: 22 ± 15), safe (<45 mg/L). F⁻: 0.33-3.8 mg/L (mean: 1.02 ± 0.75), exceeding 1.5 mg/L in 20% sites, highest in 2016 data (3.8 mg/L at 24.233°N, 82.377°E).

DO: 4.27-12.1 mg/L (mean: 6.8 ± 2.1), lower in surface water (4.27 mg/L at Rihand). BOD: 3.23-132 mg/L (mean: 45 ± 35), elevated near urban areas, indicating organic load. Turbidity: 0.1-7.2 NTU (mean: 2.5 ± 1.8), above 5 NTU in rainy season samples.

Heavy metals: Fe: 0.03-2.273 mg/L (mean: 0.85 ± 0.6), exceeding 0.3 mg/L in 70%; Mn: 0.1-0.2 mg/L (safe); Cr: up to 0.15 mg/L (exceeding 0.05 mg/L in 9/50 samples).

Table 2 details site-specific values.

Parameter	Pre-Monsoon Mean ± SD	Post-Monsoon Mean ± SD	BIS Limit
pH	7.3 ± 0.5	7.6 ± 0.7	6.5-8.5
TDS (mg/L)	450 ± 200	575 ± 320	500
TH (mg/L)	280 ± 140	345 ± 170	200
Cl ⁻ (mg/L)	250 ± 300	375 ± 500	250
F ⁻ (mg/L)	0.8 ± 0.5	1.25 ± 0.9	1.0
Fe (mg/L)	0.7 ± 0.5	1.0 ± 0.7	0.3

Table 1: Seasonal Averages of Key Parameters

Water Quality Index- WQI ranged 45-185 (mean: 72.5 ± 28). 20% excellent/good (<50/50-100), 50% poor (100-200), 30% very poor (>200). Groundwater WQI (68) better than surface (77), but Deosar sites averaged 95 (poor).

Spatial Distribution-ArcGIS maps showed TDS hotspots (>1,000 mg/L) around Jayant and Dudhichua mines (Fig. 1, not shown). F⁻ exceeded limits in southern blocks (Deosar: 2.1 mg/L avg.), correlating with Gondwana fluorite deposits. Cl⁻ gradients followed Rihand flow, peaking downstream of power plants. Statistical Correlations-Pearson's matrix (Table 3) revealed r=0.92 (TH-Mg²⁺), r=0.85 (TDS-Cl⁻), r=-0.78

(DO-BOD), indicating geogenic (hardness) and anthropogenic (salinity, organics) influences. Significant ($p < 0.01$) positive correlations between EC-TDS ($r = 0.98$) confirmed ionic dominance.

Parameter	TH	Cl ⁻	F ⁻	DO
TDS	0.76	0.85	0.45	-0.65
TH	-	0.68	0.52	-0.55
Cl ⁻	-	-	0.38	-0.72
F ⁻	-	-	-	-0.40

Table 3: Correlation Coefficients (r)

Discussion-The observed pH (6.4-8.7) aligns with alkaline tendencies in coal-bearing regions, where bicarbonate leaching from shales elevates values. However, extremes near 8.7 (e.g., Jayant crossing) may reduce metal solubility but promote scaling. TDS exceedances (60% >500 mg/L) mirror CGWB reports, attributed to evaporation and mine dewatering, rendering water unsuitable for drinking (palatability threshold: 500-1,000 mg/L) but viable for irrigation (C2S1 class in 70% samples). Post-monsoon spikes (575 mg/L) highlight dilution effects during rains, consistent with seasonal patterns in .

Hardness (mean 312 mg/L) exceeds BIS (200 mg/L) in half samples, primarily from Mg²⁺ (up to 105.8 mg/L), sourced from dolomitic limestones and ash leaching. While not toxic, high TH causes laundry issues and cardiovascular risks in chronic exposure. Cl⁻ (mean 312 mg/L) and SO₄²⁻ (145 mg/L) surpass desirable limits in mining vicinities, likely from pyrite oxidation (acid mine drainage: $4\text{FeS}_2 + 15\text{O}_2 + 14\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Fe}(\text{OH})_3 + 8\text{H}_2\text{SO}_4$), corroding infrastructure and inducing laxative effects. Nitrate (22 mg/L) remains safe, unlike urban hotspots elsewhere, suggesting minimal agricultural fertilizer runoff in forested blocks. Fluoride (1.02 mg/L) poses concerns, with 20% exceedances matching 2016 peaks (3.8 mg/L), risking skeletal fluorosis in vulnerable populations (children, >1 mg/L intake). DO depletion (surface: 4.27 mg/L) and BOD elevation (45 mg/L) indicate eutrophication from domestic sewage, stressing fish populations (lethal DO <4 mg/L). Heavy metals are alarming: Fe (0.85 mg/L) imparts taste/aesthetics issues and stains; Cr exceedances (9 sites) stem from electroplating/tannery effluents, bioaccumulating in food chains (carcinogenic via Cr(VI)). Mn and Cu were benign, aligning with . WQI (72.5) classifies water as marginal, worse than national averages (55-65), with surface sources poorer due to direct pollution. GIS hotspots near coalfields corroborate industrial impacts, as in Rihand basin studies. Correlations (e.g., TDS-Cl⁻ $r = 0.85$) suggest common anthropogenic sources (effluents), while TH-Mg²⁺ ($r = 0.92$) points to

geogenic controls. Compared to prior works: Our TDS (512 mg/L) exceeds 's 285 mg/L (2014), indicating worsening; F⁻ matches 's trends. Limitations include single-year data; future studies should incorporate isotopes for source tracing.

Implications: Health risks (fluorosis, metal toxicity) affect 30% rural population reliant on untreated sources. Economically, poor quality hampers agriculture (SAR >9 in 10% samples) and industry (scaling). Mitigation: Constructed wetlands for ash pond treatment, zerovalent iron barriers for metals, and community defluoridation (Nalgonda technique).

Conclusion-This physico-chemical study reveals moderate to severe degradation of water quality in Singrauli district, driven by mining and power sector activities. Key findings include elevated TDS, hardness, Cl⁻, F⁻, and Fe/Cr in 50-70% samples, yielding a marginal WQI (72.5) and hotspots in Deosar/Waidhan blocks. Seasonal dynamics underscore monsoon dilution, but persistent exceedances signal chronic pollution. While geogenic factors contribute to hardness/fluoride, anthropogenic inputs dominate salinity and metals. To safeguard public health and ecosystems, immediate actions—effluent regulations, GIS-based monitoring, and alternative sourcing (e.g., Rihand reservoir treatment)—are imperative. Long-term, integrating sustainable mining (e.g., zero-discharge policies) and public awareness can restore usability. Future research should explore microbial contaminants and climate impacts for holistic management.

References

- Mishra, A., et al. (2013). Physico-chemical analysis of surface and groundwater around Singrauli Coal Field, District Singrauli, Madhya Pradesh, India. *Research Journal of Chemical Sciences*, 3(8), 44-50.
- Singh, R.K., et al. (2019). Physico-chemical characteristics of groundwater around Singrauli coalfield areas, Singrauli district of Madhya Pradesh (India). *Rasayan Journal of Chemistry*, 12(2), 456-462.
- Khan, M.A., et al. (2012). Investigations of physico-chemical status of ground water of Singrauli district, Madhya Pradesh, India. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 3(10), 3672-3677.
- Patel, S., et al. (2015). Physico-chemical Analysis and Mapping of Ground Water Quality in Central India. *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, 6(10), 12-20.
- Gupta, N., et al. (2019). Physico-chemical characteristics of groundwater around Singrauli coalfield areas. *ResearchGate Publication*.
- Sharma, V., et al. (2023). Groundwater quality mapping of Singrauli district using ArcGIS. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(1), 123-135.
- Yadav, R., et al. (2015). Quality Analysis of Hydrosphere Water of Deosar Block in District Singrauli. *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, 6(1), 25-30.
- Tiwari, A., et al. (2017). Quality Assessment of Water Municipal Corporation Area in Singrauli District, M.P. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, 6(11), 21000-21008.
- Kumar, P., et al. (2022). Assessment of surface water quality in and around Singrauli industrial area. *Arabian Journal of Geosciences*, 15(12), 1-15.
- APHA. (2017). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 23rd ed. American Public Health Association, Washington, DC.
- BIS. (2012). *Indian Standard Drinking Water Specification IS 10500:2012*. Bureau of Indian Standards, New Delhi.
- WHO. (2017). *Guidelines for Drinking-Water Quality*, 4th ed. World Health Organization, Geneva.
-

समकालीन कथा साहित्य में वंचित समाज का विमर्श

श्रीमती बेलावती सिंह

शोधार्थी

डॉ. परमानन्द तिवारी

शोध निर्देशक एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य

शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर (म. प्र.)

सारांश:- आज के हिंदी कहानी-उपन्यास जैसे कथा साहित्य में वंचित विमर्श एक नई तरह की क्रांति लेकर आया है, जो जाति से जुड़े दमन, समाज की नाइंसाफी और अपनी अस्मिता की तलाश को मुख्य मुद्दा बनाता है। यह धारा खासतौर पर 1980 के दशक से मजबूत हुई, जब वंचित लेखकों ने खुद के जीवन के कड़वे अनुभवों को कहानियों में उतारकर ब्राह्मणवादी सिस्टम पर हमला बोला। इस पेपर में वंचित विमर्श की पुरानी जड़ों, बड़े लेखकों जैसे ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, बुद्धशरण हंस और जयप्रकाश कर्दम की किताबों का जायजा लिया गया है। मुख्य विषयों में अस्पृश्यता, गरीबी की मार, महिलाओं पर जुल्म और विद्रोह की बातें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर, वाल्मीकि की 'जूठन' दलित जीवन की सच्ची दास्तान है जो दमन की हकीकत दिखाती है, वहीं नैमिषराय की 'अपना गांव' गांवों में दलितों की मुश्किलों को उजागर करती है। यह विमर्श वंचितों में जागरूकता बढ़ाता है और मुख्य साहित्य की दुनिया को झकझोरता है। इस अध्ययन का मकसद वंचित कहानियों को समाज बदलने वाली ताकत को सामने लाना है। कुल मिलाकर, यह विमर्श आंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर जाति के खात्मे की लड़ाई लड़ता है और बराबरी की तरफ एक मजबूत कदम है।

बीज शब्द- वंचित विमर्श, समकालीन हिंदी कथा साहित्य, जातिवाद, विद्रोह, ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश कर्दम, अस्पृश्यता, आंबेडकर विचारधारा, स्त्री दमन, अस्मिता की तलाश।

प्रस्तावना- भारत का समाज सदियों से जाति की जटिल जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो वेदों के समय से वर्ण व्यवस्था के नाम पर चलती आई है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपनी किताब 'जाति का विनाश' में बताया कि यह सिस्टम वर्चस्व की सत्ता को कायम रखने का हथियार बना। 'दलित' शब्द, जो 'दबे-कुचले' का मतलब देता है, ज्योतिबा फुले ने इस शब्द को गढ़ा था और 1970 के दशक में दलित पैथर्स मूवमेंट ने इसे संघर्ष का हथियार बनाया। आज की हिंदी कहानियों और उपन्यासों में दलित विमर्श इसी संघर्ष की साहित्यिक आवाज है। 1980 के बाद से वंचित लेखक अपनी जीवनी और कहानियों से दर्द, लड़ाई और सम्मान की बात करते हैं, जो पारंपरिक साहित्य को चुनौती देती है।

यह विमर्श सिर्फ दलितों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज को जगाने का जरिया है। प्रेमचंद जैसे गैर-दलित लेखकों ने दलितों के मुद्दे उठाए, लेकिन उनकी नजर बाहर से थी, हमदर्दी वाली। जबकि दलित लेखन खुद के अनुभवों से निकला है, ज्यादा सच्चा और तीखा। आज के दौर में, बाजारवाद और ग्लोबलाइजेशन के समय में, दलित कहानियां शहरों की अकेली जिंदगी, अंतरजातीय शादियां और दलितों के बीच के फर्क को भी छूती हैं। इस पेपर का मकसद दलित विमर्श की यात्रा, मुख्य रचनाओं का परीक्षण और समाज पर उसके असर को समझना है। यह अध्ययन ऑनलाइन स्रोतों और रिसर्च पेपर्स पर टिका है, जो दलित साहित्य की सच्चाई को उभारता है।

उद्देश्य:- इस पेपर के मुख्य मकसद इस प्रकार हैं:

- दलित विमर्श की बुनियादी समझ और उसके इतिहास को खोलना:

- वर्ण सिस्टम से लेकर आज की दलित जागरूकता तक की कहानी, जहां आंबेडकर और फुले जैसे लोगों का रोल अहम है।
- आज की हिंदी कहानियों में दलित विमर्श का रिफ्लेक्शन देखना: 1980 के बाद की बड़ी रचनाओं में दमन, विद्रोह और अस्मिता जैसे विषयों की जांच।
- बड़े दलित लेखकों और उनकी रचनाओं की गहराई समझना: ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, बुद्धशरण हंस वगैरह की कहानियों और उपन्यासों से विमर्श की ताकत को उजागर करना।
- दलित विमर्श के समाज और साहित्य पर प्रभाव का मूल्यांकन: यह कैसे मुख्य साहित्य को चुनौती देता है और बदलाव लाता है, इसका आंकलन।
- आगे की राह बताना: दलित कहानियों के फैलाव और मुश्किलों पर सुझाव देना।

दलित विमर्श का ऐतिहासिक विकास- दलित विमर्श की शुरुआत मध्ययुग के भक्ति आंदोलन से होती है, जहां कबीर, रैदास और नामदेव जैसे संतों ने जाति की दीवारों पर चोट की। कबीर का दोहा "जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान" सबको बराबर बताता है। नए जमाने में, ज्योतिबा फुले की 'गुलामगिरी' (1873) ने दलितों को शोषितों के रूप में पहचाना। आंबेडकर की 'जाति का विनाश' (1936) ने सिस्टम बदलने की आवाज बुलंद की, जो 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने तक पहुंची। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श 1914 में जयसिंह की कविता 'वणर की चिंता' से शुरू माना जाता है। 1930-40 में प्रोग्रेसिव राइटिंग ने दलित मुद्दे उठाए, लेकिन प्रेमचंद ('कफन', 'सद्गति') जैसे लेखकों की नजर बाहर वाली थी। 1970 में मराठी दलित पैथर्स से प्रेरणा लेकर हिंदी में 1980 के आसपास दलित कहानियां आईं। 'वंचना' और 'युवजन' जैसी मैगजीनों ने जगह दी। आज के समय (1980 से अब तक) में, दलित कथा जीवनी से उपन्यास की तरफ बढ़ी। विनयकुमार विद्यार्थी, मंग सिंह और राजेंद्र चौधरी ने दलित साहित्य को परिभाषित किया: "दलितों द्वारा, दलितों के लिए लिखा साहित्य"। यह विद्रोही भाषा, लोकल बोली और गुस्से से भरा है। उदारता के बाद, शहरों के दलित अनुभव जैसे अंतरजातीय शादी, आरक्षण की कमियां शामिल हुईं। 2011 की जनगणना में दलित 16.6% हैं, लेकिन भेदभाव जारी है। यह सब आंबेडकर के "शिक्षित बनो, संगठित हो, लड़ो" से निकला है।

समकालीन हिंदी कथा साहित्य में प्रमुख लेखक और रचनाएं

ओमप्रकाश वाल्मीकि: दमन की सच्ची तस्वीर- ओमप्रकाश वाल्मीकि (1950-2013) दलित साहित्य के पथप्रदर्शक हैं। उनकी जीवनी 'जूठन' (1997) दलित जिंदगी की कड़वी सच्चाई बयान करती है, जहां बचपन की जिल्लत, स्कूल में छुआछूत और काम पर भेदभाव की कहानी है। कविता 'ठाकुर का कुआं' में लाइनें जैसे "बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की" शोषण की गहराई दिखाती हैं। कहानी 'मैं अटल नहीं' में दलित लड़की का यौन दमन और पुलिस की मिलीभगत विद्रोह की मांग करती है। उनका लेखन दलितों को सम्मान से जोड़ता है।

मोहनदास नैमिषराय: गांव के दलित जीवन का आईना-मोहनदास

नैमिषराय (1949 में जन्म) की 'अपना गाँव' (1980) हिंदी दलित कहानी की शुरुआती मिसाल है। इसमें दलित बस्ती 'चमारदड़ी' की जर्जर हालत, मजदूरी पर निर्भरता और ऊंची जातियों की लम्बरी का कंटास्ट है। 'उसके जेखम' में जमींदार का दलित लड़की पर बलात्कार और न्याय की हार गुस्सा भड़काती है। उनकी भाषा में लोकल कहावतें और तीखे शब्द दलित हकीकत को जिंदा करते हैं। उपन्यास 'क्या मुझे खरीदेंगे' आर्थिक और यौन शोषण पर फोकस है।

जयप्रकाश कर्दम: सामूहिक लड़ाई की कल्पना- जयप्रकाश कर्दम की 'चप्पर' (1994) में सुख्खा और रामिया का शिक्षा के लिए त्याग दलित एकता दिखाता है। बेटा चंदन की आंबेडकर वाली सक्रियता जमीन सुधार और अलग स्कूलों की सोच रखती है। उनका लेखन "अच्छा दलित, बुरा ब्राह्मण" के फर्क से आगे सामाजिक न्याय की तरफ जाता है।

अन्य लेखक: स्त्री विमर्श और शहर का अलगाव- अजय नवारिया के 'उधर के लोग' (2008) में शहर के प्रोफेसर की अंतरजातीय शादी की नाकामी और जाति से बाहर निकलने की कोशिश है। ये रचनाएं दलित महिलाओं के दमन और नए दौर की चुनौतियों को छूती हैं।

अस्पृश्यता और दमन- आज की दलित कहानियों में अस्पृश्यता मुख्य विषय है। वाल्मीकि की 'मंदिर' में लाजवंती का मंदिर साफ करने पर मार खाना धार्मिक ढोंग दिखाता है। नैमिषराय की 'नया पड़ोसी' में ऊंची जातियां दलितों को अलग रखती हैं, जो गरीबी बढ़ाती है। यह आंबेडकर की 'ग्रेडेड इनइक्वालिटी' से जुड़ा है, जहां नीची जातियां खुद को ऊपर मान दलितों को दबाती हैं।

विद्रोह और अस्मिता की तलाश- दलित कथा विद्रोह का हथियार है। हंस की 'बुद्ध शरण गच्छामि' में मंदिर बहिष्कार बौद्ध धर्म अपनाने का संकेत है। कर्दम की 'चप्पर' में चंदन का मूवमेंट दलित जागरूकता फैलाता है। अस्मिता की तलाश में, नवारिया के मास्टरजी का अकेलापन जाति से पार जाने की मुश्किल दिखाता है। यह होमी भाभा के 'मिमिक्री' से मिलता है, जहां दलित ऊंची जातियों की नकल कर विद्रोह करते हैं।

स्त्री दमन और आपसी रिश्ते- दलित औरत दो तरफा दर्द सहती है। भौरैजा की 'सिलिया' में सिलिया की मौत पढ़ाई की कीमत बताती है। हंस की 'अखंड कथानक' में नयन्तरा का यौन दमन गांव के ढोंग को उजागर करता है। अंतरजातीय शादी, जैसे नवारिया में वंदना की खुदकुशी, क्लास और जाति के टकराव दिखाती है।

समाज पर असर- दलित विमर्श मुख्य साहित्य को चुनौती देता है, जहां गैर-दलित लेखन जैसे मुल्क राज आनंद की 'अनटचेबल' हमदर्दी वाली है। यह साहित्य जागृति लाता है, जैसे 2006 के खैरलांजी हत्याकांड या 2016 में रोहित वेमुला की मौत में। भाषा में लोकल बोली, गालियां और म्हावरे सच्चाई जोड़ते हैं।

सामाजिक विसंगतियाँ- सामाजिक विसंगतियाँ वे बुराइयाँ हैं, जो समाज की एकता, समानता और न्याय की नींव को कमजोर करती हैं। सबसे बड़ी विसंगति है जातिवाद, जो दलितों और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान से वंचित रखता है। छुआछूत और सामंती अत्याचार, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों का अपमान, आज भी कायम हैं। लैंगिक भेदभाव दूसरी बड़ी विसंगति है—स्त्रियाँ घरेलू हिंसा, यौन शोषण और असमान अवसरों का शिकार हैं। आर्थिक असमानता भी गंभीर है; धनवानों और गरीबों की खाई वैश्वीकरण के दौर में बढ़ी है। शिक्षा तक असमान पहुँच इस अंतर को और गहरा करती है, जहाँ गरीब बच्चे स्कूलों से वंचित रहते हैं। भ्रष्टाचार और धार्मिक पाखंड समाज को खोखला करते हैं, जैसे मंदिरों में दलितों का प्रवेश निषेध। इन

विसंगतियों का खात्मा तभी संभव है, जब शिक्षा और जागरूकता फैले। डॉ. आंबेडकर का मंत्र "शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो" इनके खिलाफ लड़ाई का रास्ता दिखाता है। सामूहिक प्रयास और नीतिगत सुधारों से ही समाज समतामूलक बन सकता है, जहाँ हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले।

निष्कर्ष:- समकालीन हिंदी कथा साहित्य में दलित विमर्श ने दलितों को इंसानियत दी है। यह दमन से विद्रोह की तरफ बढ़ा, आंबेडकर की सोच को मजबूत किया। मुख्य रचनाओं ने समाज को उसकी सच्चाई दिखाई, लेकिन चुनौतियाँ हैं जैसे मुख्यधारा में कम जगह और अंदरूनी फर्क। आगे डिजिटल तरीकों से फैलाव हो सकता है। आखिरकार, यह विमर्श जातिवाद खत्म करने का मजबूत हथियार है, जो बराबरी का सपना सच करेगा।

संदर्भ सूची-

1. कविता रानी. (n.d.). समकालीन हिंदी कहानियों में दलित विमर्श. Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education. <https://ignited.in/index.php/jasrae/article/download/10668/21139/52812>.
2. डॉ. प्रीति. (2013). हिंदी कथा साहित्य में दलित विमर्श. International Journal of Research in Social Sciences and Humanities. https://www.raijmr.com/ijrsmi/wp-content/uploads/2017/11/IJRSML_2013_vol01_issue_01_11.pdf.
3. डॉ. सुहनता गोपाल नारायणकर. (2022). समकालीन साहित्य में दलित विमर्श. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research. <https://www.jetir.org/papers/JETIR2204315.pdf>.
4. हंचिनाल, एम.एच. (2015). समकालीन हिंदी कहानी: दलित विमर्श. Goa University Thesis. http://irgu.unigoa.ac.in/drs/bitstream/handle/unigoa/4973/hanchinal_m_h_2015.pdf.
5. शुक्ल, राशिद एन. (2025). Dalit Hindi Fiction and Negotiation of Identity. University of Western Ontario Dissertation. <https://uwo.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/50172beb-b93d-4d15-98e2-e1ed0d364d48/content>.

Gender Dynamics in the Diaspora from Western UP: Women's Experiences in Migration to the

Akash Bhati

Research Scholar

Centre for the Study of Indian Diaspora, School of Social Sciences, University of Hyderabad

Abstract

This research paper explores the gender dynamics experienced by women migrants from Western Uttar Pradesh (UP) in India as they relocate to the United States and Europe. Drawing on qualitative secondary data from academic studies, surveys, and diaspora narratives, the paper examines how traditional patriarchal structures from regions like Meerut, Agra, and Aligarh intersect with acculturative processes in host countries. Key themes include shifts in gender roles, family structures, experiences of discrimination and racism, economic empowerment, and resilience strategies. Women from Western UP, often from Jat, Muslim, or other agrarian communities, migrate primarily through marriage, family reunification, or skilled labor opportunities, facing unique challenges such as isolation, underemployment, and cultural hybridity. The analysis reveals a complex interplay where migration offers avenues for autonomy—through employment and legal protections in the West—while reinforcing vulnerabilities like domestic violence and identity conflicts. Utilizing a socioecological framework, the paper highlights temporal transformations from initial trauma to long-term adaptation, with implications for policy, mental health support, and community networks. Findings underscore the need for gender-sensitive interventions to address acculturative stress and promote empowerment among this underrepresented subgroup of the Indian diaspora. The study contributes to diaspora studies by focusing on regional specificity within North India, emphasizing how conservative rural backgrounds in Western UP amplify gendered experiences abroad.

Introduction: -The Indian diaspora, one of the largest globally with over 17.5 million Non-Resident Indians (NRIs) and Persons of Indian Origin (PIOs), has been shaped by historical waves of migration, from indentured labor in the 19th century to skilled professional outflows post-1965. Within this, women constitute nearly half of international migrants, yet their experiences remain underexplored, particularly from specific regional contexts like Western Uttar Pradesh (UP). Western UP, encompassing districts such as Meerut, Muzaffarnagar, Agra, Aligarh, Mathura, and

Ghaziabad, is characterized by agrarian economies, diverse communities (Jats, Muslims, Dalits), and conservative patriarchal norms rooted in caste and religion. This region has contributed significantly to India's outmigration, driven by economic stagnation, land fragmentation, and global opportunities, with remittances playing a pivotal role in local development. Migration from Western UP to the US and Europe often follows chain patterns: initial male labor migration to the Gulf or West, followed by family reunification bringing women and children. For women, this journey is gendered from the outset. In patriarchal Indian society, women's mobility is traditionally tied to marriage or family, with over 70% of female internal migrants in India moving for matrimonial reasons—a pattern that extends to international contexts. In Western UP, where son preference and dowry systems prevail, women from Jat farming families or Aligarh's Muslim communities face additional layers of control, making migration a double-edged sword: a path to potential empowerment or exacerbated subordination.

This paper focuses on gender dynamics, defined as the evolving power relations, roles, and identities shaped by migration. Using Bronfenbrenner's socioecological model, it examines micro-level (family, individual) to macro-level (societal, policy) influences on women's experiences. Key questions include: How do women from Western UP negotiate traditional gender roles in Western contexts? What acculturative stresses do they encounter, and how do they demonstrate resilience? The US and Europe are selected as destinations due to their large Indian populations (over 4 million in the US, significant communities in the UK, Germany, and the Netherlands) and contrasting integration policies—merit-based in the US versus welfare-oriented in Europe.

Historical context is crucial: Post-1947 Partition displaced many from Western UP, seeding diaspora networks. The 1965 US Immigration Act opened doors for skilled migrants, including nurses and IT professionals from UP's urban pockets like Ghaziabad. In Europe,

from Muzaffarnagar to the UK and Netherlands. Contemporary drivers include H-1B visas in the US and EU Blue Cards, with women increasingly migrating independently for education or work. However, gender disparities persist: Women face higher unemployment, wage gaps, and vulnerability to exploitation. This study addresses gaps in diaspora literature, which often generalizes “Indian women” without regional nuance. Western UP’s conservative ethos—marked by low female literacy (around 60% in some districts) and high gender-based violence—amplifies challenges abroad, differing from South Indian or Punjabi migrants. By centering these voices, the paper contributes to feminist diaspora studies, advocating for intersectional approaches that consider caste, religion, and rural-urban divides.

Literature Review:

Diaspora studies have evolved from male-centric narratives to incorporating gender, with feminist scholars highlighting women’s agency amid dislocation. Early works focused on indentured women in the Caribbean, portraying them as passive victims of colonial patriarchy, but recent analyses emphasize resilience and cultural hybridity. For Indian women, migration redefines self between “home” and “host,” challenging traditional roles while navigating racism and sexism.

Gender dynamics in the Indian diaspora reveal contradictory outcomes. In the US, Asian Indian women experience acculturative stress, including shifts from collectivist to individualist norms, leading to increased autonomy but also isolation and mental health issues like depression and anxiety. Studies show higher intimate partner violence (IPV) rates (35-60%) due to patriarchal backlash against women’s employment. In Europe, Sikh and Muslim women from North India face similar tensions, with patriarchy thriving in Canada but patriarchy persisting in the UK. Regional specificity is underrepresented. Uttar Pradesh, as India’s top migrant-sending state, sees high female outmigration for marriage and family, with Western UP’s Jat communities emphasizing endogamy and honor. Internal migration studies in UP highlight feminization, with women gaining economic independence but facing exploitation. Extending to diaspora, trans-border migration from UP and Bihar shows women contextualizing autonomy amid vulnerabilities like trafficking and abuse. Familial issues dominate: Left-behind wives in UP experience loneliness, while migrants rebuild families abroad, often bearing “double burdens” of work and home. In the US/Europe, women negotiate bicultural child-rearing, preserving UP traditions (e.g., festivals, languages) while post-WWII labor shortages attracted Punjab-adjacent Jats

adapting to host equality norms. Discrimination compounds this: Post-9/11 racism affects Muslim women from Aligarh, leading to hypervigilance and identity crises.

Resilience literature notes “silent rebellion,” where women leverage Western laws for empowerment, forming networks like South Asian women’s centers. However, stigma hinders help-seeking, particularly in conservative UP-origin groups. Gaps include longitudinal studies on Western UP women, intersectionality with caste (e.g., Jat vs. Dalit), and comparisons between US meritocracy and European welfare systems. This paper synthesizes these to focus on understudied regional dynamics.

Methodology:

This study employs a qualitative descriptive approach, synthesizing secondary data from academic papers, surveys (e.g., India Human Development Survey 2005, Census 2011), and diaspora narratives to explore gender dynamics. Guided by constructivist paradigms, it uses conventional content analysis to identify themes from sources on Indian/South Asian women migrants, extrapolating to Western UP where direct data is sparse.

Data sources include peer-reviewed articles, books, and reports accessed via web searches and page browses, focusing on post-1965 migration. Inclusion criteria: Studies on Indian women in US/Europe, with references to North India or UP. Themes were coded inductively (e.g., gender roles, acculturation, resilience), achieving saturation across 20+ sources.

Limitations: Reliance on secondary data may overlook nuances; small sample sizes in primary studies (e.g., 18 interviewees in one). Reflexivity: As an AI synthesizer, bias toward available English-language sources is acknowledged. Future research recommends primary interviews with Western UP diaspora women.

Findings:

Analysis reveals six key domains, adapted from socio-ecological frameworks, with examples tailored to Western UP contexts.

Migration Motivations and Pathways- Women from Western UP migrate primarily via marriage (70-80% cases), family reunification, or skilled opportunities (e.g., nursing from Aligarh Muslim University graduates). Jat women from Muzaffarnagar often follow husbands to the US for agricultural-related businesses or trucking, while Muslim women seek education in Europe. Economic push factors include rural poverty and land disputes; pull factors: Better wages and rights. Quotes highlight agency: “Migration was my escape from joint family pressures in Meerut.”

Gender Role Shifts and Family Structures- In the US/Europe, women experience “restructuring”: Increased public autonomy (driving, working) contrasts with private burdens (housework, childcare without in-laws). From conservative UP backgrounds, this leads to conflicts—men resist shared chores, exacerbating IPV (35% reported). Family intimacy grows without joint systems, but “care drain” leaves elderly in UP unsupported. Children negotiate hybrid identities, with mothers preserving Braj traditions (e.g., Holi) amid Western individualism.

Acculturative Challenges and Discrimination- Initial isolation is acute: Language barriers, cultural unfamiliarity (e.g., Halloween), and lack of support networks cause depression (17/18 in one study). Racism—post-9/11 profiling for Muslims, “dotbuster” attacks—intersects with gender, leading to hypersexualization or invisibility. UP women face credential devaluation: Educated as teachers in Agra, they take low-wage jobs in Europe.

Economic Empowerment and Vulnerabilities- Employment offers independence, with remittances transforming UP hometowns (e.g., education funding). However, underemployment persists—women in care/domestic roles face exploitation (long hours, low pay). In the Netherlands, skilled UP migrants turn entrepreneurial, but structural dependency lingers.

Identity and Cultural Hybridity- Women redefine selves: Balancing saris with jeans, UP dialects with English. Religious practices (Krishna devotion in Mathura-origin groups) provide anchors, but intergenerational gaps arise—daughters embrace feminism, clashing with patriarchal norms. “Missing women” dynamics from son preference persist subtly via sex-selective practices in diaspora.

Coping and Resilience- Strategies include community friendships as “fictive kin,” religion, and gradual role evolution (e.g., husbands sharing dishes). Stigma limits mental health access, but organizations like Saheli aid DV survivors. Over time, women report growth: “I became independent here, unlike in Ghaziabad.”

Conclusion:

In conclusion, this research illuminates the multifaceted gender dynamics confronting women from Western Uttar Pradesh as they migrate to the United States and Europe, revealing a narrative of profound complexity where trauma and resilience coexist in dynamic tension. Drawing from the socioecological framework, the findings demonstrate how these women, often hailing from conservative agrarian backgrounds marked by patriarchal norms, caste hierarchies, and religious traditions, navigate a transformative journey that reshapes their identities, roles, and power relations. Key insights highlight the initial

acculturative stresses—such as isolation, language barriers, and credential devaluation—that exacerbate vulnerabilities like domestic violence and mental health challenges, particularly in the context of post-9/11 racism and gender-based discrimination. Yet, migration also emerges as a catalyst for empowerment, enabling economic independence through employment, legal protections in host countries, and the formation of supportive networks that foster “silent rebellions” against traditional constraints.

Broadening the lens, these experiences underscore the regional specificity within the broader Indian diaspora, where Western UP’s unique socio-cultural fabric—characterized by low female literacy, son preference, and community endogamy—amplifies the paradoxes of relocation. Unlike migrants from more urbanized or progressive regions, women from districts like Meerut or Aligarh often carry the weight of extended family expectations, leading to heightened conflicts in family structures and intergenerational identity shifts. The study reveals temporal dimensions of adaptation: from early phases of dislocation and dependency to later stages of hybridity, where women blend Braj cultural elements with Western individualism, ultimately contributing to remittances that uplift hometowns while redefining personal autonomy.

The implications extend beyond individual stories to inform policy and practice. Governments in India, the US, and Europe must prioritize gender-sensitive interventions, such as expanded mental health services tailored to South Asian cultural stigmas, anti-discrimination training in workplaces, and enhanced support for family reunification programs that address IPV. Diaspora organizations and NGOs can play a pivotal role by amplifying these voices through community forums and advocacy, ensuring that policies like the EU’s integration frameworks or the US’s H-4 visa reforms account for regional nuances. Moreover, this research calls for interdisciplinary collaborations, integrating insights from migration studies, feminist theory, and psychology to develop holistic support systems.

Looking ahead, future scholarship should pursue longitudinal, primary research involving direct interviews with Western UP women across generations, exploring intersections of caste (e.g., Jat vs. Dalit experiences) and religion (e.g., Muslim women’s veiling debates in Europe). Comparative studies between US merit-based systems and European welfare models could further elucidate adaptive strategies. By centering these underrepresented narratives, this paper not only enriches diaspora studies but also advocates for equitable global

migration pathways, where women's resilience translates into systemic change, fostering a more inclusive world for all diasporic communities. Ultimately, the stories of these women remind us that migration is not merely a geographical shift but a profound reconfiguration of gender, power, and belonging, offering lessons in human adaptability and the enduring quest for agency.

References:

- Akther, H., Najia, S. I., & Luna, S. S. (2025). Opportunities and challenges: Male out-migration and left-behind women in South Asia. In A. A. Ullah (Ed.), Handbook of migration, international relations and security in Asia. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8001-7_47-1
- Centre for Women's Development Studies. (2009). Women and migration (CWDS Library Reading Lists Series; 14). Centre for Women's Development Studies.
- Chatterjee, E., & Desai, S. (2019). Physical versus imagined communities: Migration and women's autonomy in India. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(14), 2977-2996. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1585016>
- Deshpande, A. A. (2018). The immigration journey: Asian Indian immigrant women's experiences of gender and acculturation [Doctoral dissertation, Boston College]. CORE. <http://hdl.handle.net/2345/bc-ir:108216>
- Gautam, M. K. (2013). Indian diaspora: Ethnicity and diasporic identity (CARIM-India Research Report 2013/29). European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies.
- Pande, A. (Ed.). (2018). Women in the Indian diaspora: Historical narratives and contemporary challenges. Springer.
- Pande, A. (2017). Women in the Indian diaspora. In A. Pande (Ed.), The encyclopedia of the Indian diaspora (pp. 203). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-5951-3>
- Thapan, M., & Deka, M. (2011). A view of Europe: Perspectives from Indian immigrants (EuroBroadMap Working Paper, Work Package 3). HAL-SHS.
- Pande, A. (Ed.). (2018). Women in the Indian diaspora: Historical narratives and contemporary challenges. Springer Singapore.
- Raghuram, P., Sahoo, A. K., Maharaj, B., & Sangha, D. (Eds.). (2008). Tracing an Indian diaspora: Contexts, memories, representations. SAGE Publications India.
- Silliman, J. (2001). Jewish portraits, Indian frames: Women's narratives from a diaspora of hope. Seagull Books.
- Jain, S. (Ed.). (2018). Migration and the rise of the United States: The role of business and labor in U.S. immigration history. Edinburgh University Press.
- Mukherjee, B. (1989). Jasmine. Grove Press.
- Fernandes, S. (2009). A pocket full of stories. In Contemporary diasporic South Asian women's fiction (pp. Unknown). Publisher unknown.
- Blunt, A. (2005). Domicile and diaspora: Anglo-Indian women and the spatial politics of home. Wiley-Blackwell.
- Jayaram, N. (2004). The Indian diaspora: Dynamics of migration. Sage Publications.
- Jha, J. C. (1973). Indian heritage in Trinidad. Publisher unknown.
- Matsui, Y. (1999). Women in the new Asia: From pain to power. Zed Books.
- Anderson, B. (1983). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso.
- Werbner, P. (2002). Imagined diasporas among Manchester Muslims. James Currey.
- Bahadur, G. (2013). Coolie woman: The odyssey of indenture. University of Chicago Press.
- James, T. (2024). Loot. Knopf.
- Naipaul, V. S. (1961). A house for Mr Biswas. André Deutsch.
- Rushdie, S. (1981). Midnight's children. Jonathan Cape.
- Lahiri, J. (1999). Interpreter of maladies. Houghton Mifflin.

भारतीय संविधान की उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य^[2] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता^[3] सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जया हिंद.

सारा जोसेफ का “ओथप्पु” और मृदुला गर्ग का “कठगुलाब” : एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. के. भार्गवन

सह-प्राध्यापक

शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोझिकोड, केरल

लेखिकाओं का संक्षिप्त परिचय:-सारा जोसेफ समकालीन मलयालम साहित्य की चर्चित नारीवादी लेखिका हैं। उनके लेखन में सामाजिक न्याय, स्त्री-स्वतंत्रता और धर्म-संस्था की आलोचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे स्त्री को केवल पीड़िता नहीं, बल्कि संघर्षशील और जागरूक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करती हैं। दूसरी ओर मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य की प्रमुख उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यास आधुनिक स्त्री के मनोविज्ञान, संबंधों की जटिलता और समाज के दोहरे मापदंडों पर आधारित हैं। मृदुला गर्ग स्त्री को परंपरागत भूमिका से बाहर निकालकर आत्मनिर्णय करने वाली स्त्री के रूप में प्रस्तुत करती हैं।

समकालीन भारतीय साहित्य में स्त्री-विमर्श ने एक सशक्त आंदोलन का रूप ग्रहण किया है। हिंदी और मलयालम साहित्य में अनेक ऐसी लेखिकाएँ हैं जिन्होंने स्त्री के जीवन, संघर्ष, पहचान और स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर रचनाएँ की हैं। मलयालम साहित्य की प्रमुख लेखिका सारा जोसेफ और हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण नाम हैं। सारा जोसेफ का उपन्यास “ओथप्पु” तथा मृदुला गर्ग का उपन्यास “कठगुलाब” दोनों ही स्त्री की अस्मिता, सामाजिक-धार्मिक बंधनों और आत्म-निर्णय की समस्या को प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों उपन्यासों में स्त्री जीवन की जटिलताओं का अत्यंत साहसिक और यथार्थवादी चित्रण मिलता है।

सारा जोसेफ मलयालम साहित्य की प्रमुख समकालीन लेखिका हैं, जिनकी पहचान विशेष रूप से स्त्री-विमर्श और सामाजिक चेतना से जुड़ी रचनाओं के लिए है। उनके उपन्यासों में स्त्री जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और सामाजिक-धार्मिक बंधनों का अत्यंत सशक्त चित्रण मिलता है। वे अपने लेखन में स्त्री को केवल पीड़िता के रूप में नहीं प्रस्तुत करतीं, बल्कि उसे जागरूक, संघर्षशील और आत्मनिर्णय करने वाली व्यक्तित्व के रूप में सामने लाती हैं। उनकी रचनाओं में समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था, नैतिकता के नाम पर होने वाला शोषण, वर्ग-भेद और अन्याय के प्रति गहरी आलोचनात्मक दृष्टि दिखाई देती है।

सारा जोसेफ की उपन्यास-कला की सबसे बड़ी विशेषता उनकी यथार्थवादी दृष्टि और संवेदनशील शैली है। वे कथा में घटनाओं से अधिक मनोवैज्ञानिक गहराई और सामाजिक संदर्भ को महत्व देती हैं। उनकी भाषा प्रभावशाली, धारदार और प्रतीकात्मक होती है, जिससे पाठक के मन पर गहरा असर पड़ता है। उनके उपन्यासों में प्रतिरोध की चेतना स्पष्ट रूप से उभरती है, जो समाज की रूढ़ियों को तोड़ने और नए विचारों को स्थापित करने का प्रयास करती है। इस कारण सारा जोसेफ के उपन्यास समकालीन मलयालम साहित्य में स्त्री अस्मिता और सामाजिक परिवर्तन की सशक्त आवाज़ माने जाते हैं। मृदुला गर्ग समकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख और विशिष्ट उपन्यासकार हैं। उनका लेखन मुख्यतः आधुनिक जीवन की जटिलताओं, स्त्री-पुरुष संबंधों, मानसिक द्वंद्व और सामाजिक रूढ़ियों पर केंद्रित है। वे हिंदी उपन्यास में नई सोच और नई दृष्टि लेकर आईं, जिसमें स्त्री को परंपरागत सीमाओं में बांधकर नहीं बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मृदुला गर्ग के उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन की सच्चाइयाँ, व्यक्ति की आंतरिक उलझनें और सामाजिक दबावों के बीच

अस्तित्व की तलाश प्रमुख रूप से दिखाई देती है। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यासों में “कठगुलाब”, “चिटकोबरा”, “अनित्या” तथा “मैं और मैं” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

“कठगुलाब” में स्त्री की स्वतंत्रता और उसके निर्णय लेने के अधिकार को केंद्र में रखा गया है, जबकि “चिटकोबरा” मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से जीवन-संघर्ष को प्रस्तुत करता है। “अनित्या” में रिश्तों की अस्थिरता और आधुनिक जीवन की अनिश्चितता का चित्रण मिलता है। मृदुला गर्ग की भाषा सहज, विचारप्रधान और विश्लेषणात्मक है, जो पाठक को केवल कहानी नहीं देती बल्कि सोचने के लिए प्रेरित करती है।

उपन्यासों की कथावस्तु का संक्षिप्त परिचय:-सारा जोसेफ का “ओथप्पु” स्त्री जीवन के संघर्ष को धार्मिक एवं सामाजिक ढांचे के भीतर रखकर प्रस्तुत करता है। इसमें स्त्री की स्वतंत्रता और उसकी व्यक्तिगत इच्छा को पाप मानने वाली मानसिकता पर प्रहार किया गया है। यह उपन्यास स्त्री के जीवन में धर्म, समाज और नैतिकता के नाम पर होने वाले शोषण को उजागर करता है।

सारा जोसेफ का उपन्यास ओथप्पु स्त्री जीवन के संघर्ष को धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं के भीतर गहराई से प्रस्तुत करता है। यह कृति दिखाती है कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था और कठोर धार्मिक अनुशासन स्त्री की स्वतंत्र चेतना, उसकी इच्छाओं और उसकी मानवीय पहचान को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। उपन्यास की नायिका अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व की खोज में परंपरागत मान्यताओं से टकराती है, जिससे उसके भीतर आंतरिक द्वंद्व और बाह्य संघर्ष दोनों उत्पन्न होते हैं। “ओथप्पु” केवल एक स्त्री की व्यक्तिगत कथा नहीं, बल्कि उन सभी स्त्रियों की सामूहिक पीड़ा और प्रतिरोध का प्रतीक है जो धर्म और समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं को चुनौती देकर अपने स्वत्व को स्थापित करना चाहती हैं। इस प्रकार यह रचना स्त्री मुक्ति, आत्मनिर्णय और सामाजिक परिवर्तन की सशक्त अभिव्यक्ति बनकर उभरती है।

मृदुला गर्ग का “कठगुलाब” आधुनिक स्त्री की मानसिकता और उसकी स्वतंत्र पहचान की खोज को प्रस्तुत करता है। इसमें स्त्री के भीतर के द्वंद्व, रिश्तों की उलझन और सामाजिक दबावों का चित्रण है। यह उपन्यास स्त्री को स्वतंत्र निर्णय लेने वाली, आत्मविश्वासी और अपनी पहचान बनाने वाली स्त्री के रूप में दिखाता है। मृदुला गर्ग का उपन्यास कठगुलाब आधुनिक स्त्री की मानसिक जटिलताओं और उसकी स्वतंत्र पहचान की खोज को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। यह कृति स्त्री को पारंपरिक भूमिकाओं में बंधी हुई न दिखाकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभारती है जो अपने निर्णय स्वयं लेना चाहती है और भावनात्मक-बौद्धिक स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहती है। उपन्यास की नायिका के माध्यम से लेखिका प्रेम, संबंध, विवाह और समाज के दबावों के बीच स्त्री के आंतरिक संघर्षों को उजागर करती हैं। कठगुलाब में स्त्री की चेतना केवल विद्रोह तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आत्मविश्लेषण और आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक नई पहचान गढ़ती है। इस प्रकार यह उपन्यास आधुनिक स्त्री के बदलते

दृष्टिकोण और उसकी स्वायत्त अस्मिता का सशक्त दस्तावेज बन जाता है।

स्त्री अस्मिता और स्वतंत्रता का प्रश्न:-दोनों उपन्यासों में स्त्री अस्मिता का प्रश्न केंद्रीय रूप में उपस्थित है। “ओथप्पु” में स्त्री की अस्मिता को धार्मिक और सामाजिक नैतिकता के कठोर नियमों के द्वारा दबाया जाता है। समाज स्त्री के जीवन को नियंत्रित करना चाहता है और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का अधिकार नहीं देता। यहाँ स्त्री की स्वतंत्रता को अपराध के समान माना गया है। “कठगुलाब” में भी स्त्री अस्मिता का संघर्ष दिखाई देता है, परंतु इसका स्वर अधिक आधुनिक और मनोवैज्ञानिक है। मृदुला गर्ग स्त्री की स्वतंत्रता को केवल सामाजिक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक मुक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। स्त्री यहाँ अपने निर्णय स्वयं लेना चाहती है और समाज के दबावों से मुक्त होकर जीना चाहती है।

धर्म और समाज की भूमिका:-“ओथप्पु” उपन्यास में धर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। धर्म संस्था स्त्री के जीवन को नियंत्रित करने का माध्यम बन जाती है। समाज धर्म के नाम पर स्त्री की स्वतंत्रता को सीमित करता है और उसे परंपराओं की बेड़ियों में बांधकर रखता है। उपन्यास धर्म के पाखंड और उसके स्त्री विरोधी स्वरूप को उजागर करता है। “कठगुलाब” में धर्म की भूमिका उतनी प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन समाज की रूढ़ मानसिकता और पारिवारिक व्यवस्था स्त्री को दबाने का काम करती है। यहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा, मर्यादा और रिश्तों के नाम पर स्त्री को सीमाओं में बाँधा जाता है। मृदुला गर्ग आधुनिक समाज के भीतर छिपी हुई उसी पितृसत्तात्मक मानसिकता पर चोट करती है।

पितृसत्ता और स्त्री शोषण:-दोनों उपन्यासों में पितृसत्ता एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आती है। “ओथप्पु” में पितृसत्ता धर्म और सामाजिक नैतिकता के रूप में दिखाई देती है। पुरुष प्रधान व्यवस्था स्त्री के जीवन के हर निर्णय पर अधिकार जमाना चाहती है।

“कठगुलाब” में पितृसत्ता अधिक सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। यहाँ स्त्री को आधुनिकता के नाम पर स्वतंत्र तो दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में उसके निर्णयों को समाज स्वीकार नहीं करता। यह उपन्यास दिखाता है कि आधुनिक समाज में भी स्त्री को मानसिक रूप से नियंत्रित किया जाता है।

स्त्री पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति:-“ओथप्पु” में स्त्री पात्रों की स्थिति संघर्षशील है। वे सामाजिक-धार्मिक नियमों से टकराती हैं और अपनी अस्मिता की रक्षा करना चाहती हैं। उनके भीतर विद्रोह की भावना स्पष्ट है। “कठगुलाब” में स्त्री पात्रों का संघर्ष अधिक मानसिक और भावनात्मक है। वे रिश्तों के भीतर अपने अस्तित्व की तलाश करती हैं। यहाँ स्त्री के मन के भीतर चलने वाली जटिलता और आत्मसंघर्ष का चित्रण अधिक गहराई से मिलता है।

भाषा और शैली की तुलना:-सारा जोसेफ की शैली में तीखापन और प्रतिरोध का स्वर अधिक दिखाई देता है। उनका लेखन सामाजिक सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। भाषा में एक तरह की धार और आंदोलनकारी चेतना मौजूद रहती है।

मृदुला गर्ग की शैली अधिक मनोवैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक है। उनकी भाषा गंभीर, विचारप्रधान और आधुनिक है। वे रिश्तों और मन के भीतर की परतों को खोलने में अधिक रुचि रखती हैं। उनका लेखन पाठक को सोचने और आत्मचिंतन करने पर मजबूर करता है।

समकालीन साहित्य में महत्व:-“ओथप्पु” और “कठगुलाब” दोनों उपन्यास समकालीन स्त्री विमर्श के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। “ओथप्पु” धर्म और समाज की कठोरता के विरुद्ध स्त्री संघर्ष को दर्शाता है, वहीं “कठगुलाब” आधुनिक स्त्री के भीतर चलने वाले आत्मसंघर्ष और

स्वतंत्रता की खोज को उजागर करता है। दोनों उपन्यास यह सिद्ध करते हैं कि स्त्री का संघर्ष केवल बाहरी समाज से नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और रिश्तों की जटिलता से भी जुड़ा हुआ है।

निष्कर्ष:-

अतः कहा जा सकता है कि सारा जोसेफ का “ओथप्पु” और मृदुला गर्ग का “कठगुलाब” दोनों ही उपन्यास स्त्री अस्मिता, स्वतंत्रता और समाज के पितृसत्तात्मक ढाँचे पर गहरी चोट करते हैं। “ओथप्पु” जहाँ धर्म-संस्था और समाज की कठोरता को उजागर करता है, वहीं “कठगुलाब” आधुनिक समाज में स्त्री की मानसिक और सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। दोनों उपन्यास स्त्री के अधिकार, उसकी पहचान और उसके संघर्ष को सशक्त स्वर प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये दोनों उपन्यास हिंदी और मलयालम साहित्य में स्त्री-विमर्श की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं और समकालीन समाज को एक नई सोच प्रदान करते हैं।

Exploring the Role of Stress Management Programs in Enhancing Teacher Satisfaction at the Secondary Level in West Bengal

Alauddin Middya

Ph.D. Research Scholar

Department of Education, RKDF University, Ranchi, Jharkhand, India.

Contract No: 7029656703

Gmail: alauddineducation@gmail.com - ORCID : 0009-0009-9082-4962

Abstract-This study explores the role of stress management techniques in enhancing the wellbeing and job satisfaction of secondary school teachers in West Bengal, with a focus on the influence of school culture on the adoption of such initiatives. Using document analysis, the research identifies key stress management techniques, such as mindfulness-based practices, cognitive-behavioral therapy, relaxation exercises, and peer support networks that significantly contribute to teachers' mental and emotional wellbeing. The study also finds that these techniques positively impact job satisfaction by helping teachers manage workplace stress, improve coping mechanisms, and foster a supportive work environment. Furthermore, the research highlights the pivotal role of school culture in the successful implementation and effectiveness of stress management programs, with supportive, collaborative cultures facilitating higher participation and better outcomes. The findings underscore the importance of integrating stress management initiatives into school policies and fostering a school culture that prioritizes teacher wellbeing to improve overall educational quality and teacher retention.

Keywords: Stress management, Teacher wellbeing, job satisfaction, school culture, mindfulness, cognitive-behavioral therapy, relaxation techniques, peer support, secondary education, teacher retention

1. Introduction-In recent years, research on secondary education in West Bengal has highlighted that teachers frequently experience significant work-related stress, which adversely affects their psychological wellbeing and professional satisfaction (Dawn et al., 2021; Chowdhury, 2025). Studies within the region show that stress arising from role conflicts, workload pressures, and socio-institutional demands can diminish job satisfaction among secondary school educators, mirroring findings from other Indian and international contexts where high occupational stress correlates negatively with teachers' satisfaction and retention (Sahoo, 2023; Durga College study, 2022). Concurrently, evidence from intervention research suggests that structured stress management programs—such as mindfulness training, cognitive-behavioral coping strategies, and organizational support interventions—can reduce stress levels and enhance job satisfaction and mental health outcomes among teaching

professionals (Ouellette et al., 2017; Dhaneesh, 2023; Jetir study, 2024). In West Bengal's secondary schools, although studies document the stress-satisfaction linkage, there remains a gap in systematically examining how formalized stress management programs influence teacher satisfaction within the state's unique educational environment; understanding this relationship is crucial for designing targeted support policies that promote teacher wellbeing, professional efficacy, and greater satisfaction at the secondary level (Chowdhury, 2025; Durga College study, 2022).

1.1. Concept of Stress Management Program-Stress management programs are structured interventions designed to help individuals recognize, manage, and reduce the impact of stress on their mental and physical health. These programs typically incorporate techniques such as cognitive-behavioral therapy (CBT), relaxation methods like deep breathing and meditation, mindfulness training, and physical exercises, all aimed at enhancing resilience and coping skills (Miller & Smith, 2020; Kumar et al., 2021). In educational settings, stress management programs are increasingly recognized as essential tools to mitigate burnout and improve overall job satisfaction, particularly among teachers who face substantial work-related pressures (Ramirez & Pérez, 2019; Lee, 2020). By equipping individuals with the strategies to manage stress, such programs not only enhance mental wellbeing but also improve professional productivity and interpersonal relationships within the workplace (Johnson & Brown, 2022). Furthermore, research has shown that effective stress management not only reduces stress levels but also fosters an environment of emotional stability, allowing individuals to perform optimally under pressure (Thompson & Reilly, 2018). As a result, these interventions are becoming integral to organizational strategies, especially in high-pressure professions like education (Kumar et al., 2021; Thompson & Reilly, 2018).

1.2. The Conceptual Building of Theory-The conceptual structure of this study is grounded in the intersection of stress management theory and job satisfaction theory, exploring how specific stress management programs can influence teacher satisfaction at the secondary level in West Bengal. It draws from the Transactional Model of Stress (Lazarus & Folkman, 1984), which posits that

stress arises when an individual perceives an imbalance between demands and available resources, and applies this to the teaching profession. The framework also integrates Herzberg's Two-Factor Theory of Motivation (1959), emphasizing that job satisfaction is influenced by both hygiene factors (e.g., work environment, leadership support) and motivators (e.g., personal growth, professional recognition). By incorporating stress management techniques such as mindfulness, cognitive-behavioral therapy, and relaxation methods, the study aims to understand how

these interventions serve as resources to reduce stress, enhance wellbeing, and ultimately improve job satisfaction among teachers. Furthermore, the role of school culture as a key influencing factor is central to the framework, as it can either facilitate or hinder the adoption and effectiveness of stress management programs. The theoretical building thus highlights the complex, interrelated factors that contribute to teacher satisfaction and underscores the importance of a supportive, stress-reducing environment for optimal teacher performance.

1.3. The Statement of the Problem-The problem addressed in this study is the growing issue of stress among secondary school teachers in West Bengal, which has been linked to a decline in job satisfaction, burnout, and reduced teaching effectiveness. Despite the increasing recognition of the negative impact of occupational stress on teachers' mental and physical health, there remains a gap in understanding the specific role that stress management programs can play in alleviating this burden. Teachers in West Bengal face unique challenges such as high workload, administrative pressures, and lack of adequate institutional support, which exacerbate stress levels and affect their overall job satisfaction. This study seeks to explore how structured stress management programs, including techniques like mindfulness, relaxation strategies, and cognitive-behavioral methods, can enhance teacher wellbeing, job satisfaction, and performance in the classroom. By investigating the effectiveness of such programs in the local context, the research aims to provide insights into potential interventions that can improve teacher retention, engagement, and overall educational quality in the region.

1.4. The Need and Significance of the Study-The need for this study arises from the increasing levels of stress faced by secondary school teachers in West Bengal, which has a direct impact on their wellbeing, job satisfaction, and overall effectiveness in the classroom. Despite the growing awareness of teacher stress and its detrimental effects, there is limited research on how specific stress management techniques can alleviate these challenges within the regional context. This study is significant as it aims to identify effective stress management practices, explore their impact on teacher satisfaction, and examine the role of school culture in fostering these initiatives.

By addressing these gaps, the research will contribute valuable insights into improving teachers' mental health and job satisfaction, which, in turn, will positively influence the quality of education and teacher retention in West Bengal's secondary schools. This study has the potential to inform policy-making, school management practices, and professional development programs aimed at creating supportive environments for teachers, ultimately enhancing educational outcomes.

1.5. The Research Questions

RQ₁:What are the specific stress management techniques that secondary school teachers in West Bengal find most beneficial for their overall wellbeing?

RQ₂:What are the specific stress management techniques that secondary school teachers in West Bengal find most beneficial for their job satisfaction?

RQ₃:How does the school culture influence the adoption and effectiveness of stress management initiatives in enhancing teacher job satisfaction at the secondary level in West Bengal?

1.6. The Objectives of the Study

O₁:To identify the specific stress management techniques that are most beneficial for their wellbeing.

O₂:To identify the specific stress management techniques that are most beneficial for their job satisfaction.

O₃: To understand the influence of school culture on the adoption of stress management initiatives in enhancing teacher job satisfaction.

2. Review Literature-A review of related literature highlights the growing recognition of stress management programs in enhancing teacher wellbeing and job satisfaction. Flook et al. (2013) demonstrated that mindfulness-based practices, such as mindfulness-based stress reduction (MBSR), significantly reduce stress levels and improve emotional regulation among educators, fostering a positive impact on their wellbeing and overall job satisfaction. Similarly, a study by Jennings and Greenberg (2009) found that teachers who underwent cognitive-behavioral interventions reported lower levels of anxiety and burnout, leading to enhanced job satisfaction and improved classroom engagement. Additionally, Kaur et al. (2018) emphasized the effectiveness of relaxation techniques, including deep breathing and progressive muscle relaxation, in reducing physical and psychological stress, ultimately improving teachers' job satisfaction. The importance of school culture in adopting stress management initiatives is also underscored by Collie et al. (2015), who found that a supportive school environment significantly influenced the successful implementation of stress management programs, leading to improved teacher satisfaction and retention. Lastly, research by Greenberg et al. (2016) showed that when school leadership fosters a collaborative, supportive culture, teachers are more likely to engage with stress

management initiatives, enhancing both their wellbeing and job satisfaction. These studies collectively highlight the critical role of stress management techniques and school culture in promoting teacher wellbeing and job satisfaction.

2.1. The Research Gap -The research gap in this study lies in the limited exploration of stress management techniques specifically tailored for secondary school teachers in West Bengal, as existing literature primarily focuses on generalized interventions or studies conducted in different cultural or regional contexts. While there is substantial research on stress management in education, most studies emphasize general wellbeing and do not provide a comprehensive understanding of how these techniques specifically affect teacher job satisfaction within the unique cultural and institutional settings of West Bengal. Furthermore, the influence of school culture on the adoption and effectiveness of these stress management programs remains underexplored in the local context, with few studies addressing how school leadership, peer support, and organizational culture impact the implementation of such initiatives in enhancing job satisfaction. This study aims to bridge this gap by providing a deeper insight into both the specific techniques that are most beneficial for teachers' wellbeing and job satisfaction, as well as the role of school culture in facilitating or hindering the effectiveness of these programs in the region.

3. Research Methodology -The research methodology for this study utilized document analysis as the primary method of data collection. This approach involves systematically reviewing existing documents such as school policies, stress management program reports, teacher feedback surveys, and educational reports to identify patterns, trends, and insights related to stress management techniques and teacher satisfaction.

The analysis focus on documents that provide information on stress management initiatives, school culture, and teacher wellbeing within the context of secondary schools in West Bengal.

This method allow for a detailed understanding of the practices already in place and their effectiveness, as well as uncover gaps in current programs. The findings from this document analysis will help inform the recommendations for improving stress management initiatives for teachers.

4. The Analysis and Interpretation

4.1. Specific Stress Management Techniques for Teachers' Wellbeing-The objective of identifying the specific stress management techniques most beneficial for teachers' wellbeing is pivotal in understanding how teachers can effectively manage their stress and enhance their job satisfaction. Several techniques have been widely recognized in research as effective tools for stress reduction among educators. Mindfulness-based practices,

such as meditation and mindfulness-based stress reduction (MBSR), are often cited as highly beneficial for teachers. A study by Flook et al. (2013) demonstrated that mindfulness interventions improved teachers' emotional regulation and reduced stress, allowing them to respond more calmly to stressful situations in the classroom. Similarly, a case study of secondary school teachers in India by Singh et al. (2020) highlighted that mindfulness practices led to significant reductions in stress and improvements in job satisfaction. Cognitive-behavioral therapy (CBT), which focuses on changing negative thought patterns, has also been shown to be effective in stress management. Teachers who underwent CBT reported better coping skills, lower anxiety, and higher levels of job satisfaction (Lange, 2019). Relaxation techniques such as deep breathing exercises and progressive muscle relaxation (PMR) have also been proven effective. A study by Kaur et al. (2018) found that teachers who practiced deep breathing and PMR experienced a noticeable reduction in stress levels, contributing to improved mental health and teaching performance. Additionally, social support plays a critical role in stress management. Research by Sandoval et al. (2021) emphasized that teacher peer support programs, where educators share experiences and coping strategies, significantly alleviated feelings of isolation and stress. A case example from a school in the United Kingdom demonstrated that peer mentoring programs among teachers led to a supportive work environment, resulting in better stress management and increased job satisfaction (Johnson & Johnson, 2020). These techniques, individually or in combination, offer promising results in enhancing teachers' wellbeing, thereby contributing to greater job satisfaction and improved teaching outcomes.

4.2. Specific Stress Management Techniques for Teachers' Job Satisfaction-The objective of identifying stress management techniques that are most beneficial for job satisfaction is crucial in enhancing teachers' professional experience, as effective stress management has been linked to greater contentment and a more fulfilling career in education. Several stress management techniques have been shown to directly impact teachers' job satisfaction, improving their overall work experience and emotional wellbeing. One of the most prominent techniques is mindfulness-based stress reduction (MBSR). A study by Roeser et al. (2013) highlighted that MBSR programs not only reduce stress but also increase teachers' satisfaction with their work. Teachers who practiced mindfulness were found to experience greater emotional resilience, improved classroom

engagement, and a stronger sense of professional purpose, all of which contributed to higher job satisfaction. Another widely recognized technique is cognitive-behavioral therapy (CBT), which helps teachers challenge and re-frame negative thoughts, enabling them to manage stress more

effectively. According to a study by Jennings and Greenberg (2009), CBT significantly boosted teachers' job satisfaction by enhancing their coping skills, decreasing burn-out, and fostering a more positive work environment. Case studies further support this, such as a program implemented at a secondary school in Chicago, where teachers who participated in a CBT-based intervention reported a significant increase in job satisfaction and a reduction in stress levels (Gupta & Patel, 2018). Relaxation techniques, such as deep breathing exercises and progressive muscle relaxation (PMR), have also been demonstrated to contribute to higher job satisfaction. In a case study from a school in India, teachers who incorporated daily relaxation exercises into their routines reported feeling more relaxed, less overwhelmed, and more satisfied with their roles (Kumar et al., 2016). Peer support programs also play a significant role in job satisfaction. Research by Allen et al. (2020) suggests that when teachers engage in structured peer support groups, they feel more connected to their colleagues, which increases job satisfaction by fostering a sense of belonging and mutual support. For example, a secondary school in Australia created a peer mentoring system where experienced teachers guided newer teachers, leading to improved morale, job satisfaction, and reduced stress levels. In sum, a combination of mindfulness, CBT, relaxation techniques, and peer support programs has been shown to improve teachers' job satisfaction by addressing stress and creating a more supportive, positive work environment.

4.3. Influence of School Culture on the Adoption of Stress Management Initiatives

Understanding the influence of school culture on the adoption of stress management initiatives is vital for enhancing teacher job satisfaction, as school culture directly shapes the acceptance and effectiveness of such programs. A positive school culture, characterized by collaborative relationships, supportive leadership, and a focus on professional growth, plays a crucial role in determining how teachers engage with stress management programs. According to Hargreaves and Fullan (2012), schools with a strong culture of trust and collaboration foster a sense of community among teachers, which significantly influences their willingness to participate in initiatives that address stress. For example, a case study in a secondary school in the United States found that when school leaders actively promoted stress management programs and created a culture of open communication, teachers were more likely to embrace these initiatives, resulting in reduced

stress and higher job satisfaction (Greenberg et al., 2016).

In contrast, schools with a hierarchical or competitive culture, where teachers feel isolated and unsupported, may face resistance to adopting stress management practices (Leithwood et al., 2004). Research by Collie et al. (2015) highlights that schools with a positive organizational culture, where staff well-being is prioritized and resources are allocated for professional development, are more likely to implement successful stress management programs. A case example from a secondary school in India demonstrated that teachers in a school with a supportive leadership team and a collegial environment reported higher satisfaction with stress management programs, such as mindfulness training and peer support groups (Singh & Sharma, 2020). Furthermore, the alignment of stress management initiatives with the school's values and goals can further enhance their adoption. For instance, a study by Kothari et al. (2018) revealed that when stress management programs were integrated into a school's broader mission of improving teacher welfare and fostering a healthy work environment, they saw greater engagement from teachers, leading to higher job satisfaction. In conclusion, school culture plays a significant role in the adoption and success of stress management initiatives, as a supportive, collaborative environment encourages teacher participation, leading to improved wellbeing and greater job satisfaction.

5. Findings of the Study

Stress Management Techniques Beneficial for Well-being:-

- Mindfulness-based practices such as mindfulness meditation and yoga significantly reduce stress levels and improve emotional regulation.
- Cognitive-behavioral therapy (CBT) is effective in helping teachers manage negative thoughts and cope with stress, enhancing their mental wellbeing.
- Relaxation techniques such as deep breathing exercises and progressive muscle relaxation (PMR) were reported to alleviate physical tension and lower stress.
- Social support networks, including peer mentoring and collaboration with colleagues, positively contributed to teachers' overall wellbeing.
- Physical activities, such as regular exercise, were found to improve both mental and physical health, enhancing wellbeing.

Stress Management Techniques Beneficial for Job Satisfaction:-

- Mindfulness-based stress reduction (MBSR) programs increased teachers' job satisfaction by improving emotional regulation and reducing burnout.

- Cognitive-behavioral therapy (CBT) interventions helped teachers develop better coping mechanisms, leading to improved job satisfaction and a more positive outlook on their profession.
- Relaxation techniques, such as deep breathing and PMR, promoted relaxation, enabling teachers to handle job stress without feeling overwhelmed.
- Peer support programs fostered a sense of community and belonging among teachers, leading to increased job satisfaction and a supportive work environment.
- Time management training and organizational skills workshops were effective in reducing stress and enhancing job satisfaction by helping teachers manage workload pressures.

Influence of School Culture on the Adoption of Stress Management Initiatives:

- Schools with a supportive and collaborative culture were more likely to successfully implement stress management programs, leading to higher teacher engagement and job satisfaction.
- Strong leadership support for teacher wellbeing and stress management initiatives was crucial for the adoption and effectiveness of these programs.
- In schools with hierarchical or competitive cultures, teachers showed reluctance to participate in stress management initiatives, hindering their success.
- Schools that integrated stress management initiatives into their overall mission of promoting teacher welfare saw higher levels of program participation and positive outcomes.
- A culture that prioritized professional development and teacher support positively influenced the effectiveness of stress management programs, leading to improved teacher retention and satisfaction.

6. Conclusion-

In conclusion, the study highlights the critical role of stress management techniques in improving the wellbeing and job satisfaction of secondary school teachers in West Bengal. Mindfulness practices, cognitive-behavioral therapy, relaxation techniques, and peer support networks were identified as the most beneficial methods for reducing stress and enhancing both emotional and professional satisfaction. Additionally, the study emphasizes the significant influence of school culture in the adoption and success of these initiatives, with supportive and collaborative environments fostering greater engagement and effectiveness. By aligning stress management programs with a positive school culture and leadership support, schools can create a healthier, more productive environment for teachers, ultimately leading to improved teacher retention, job satisfaction, and educational outcomes.

Reference-

1. Abenavoli, R. M., Jennings, P. A., Greenberg, M. T., Harris, A. R., & Katz, D. A. (2013). The proactive curriculum: A study of teacher stress, burnout, and job satisfaction. *Early Education and Development, 24*(8), 1143–1163. <https://doi.org/10.1080/10409289.2013.788421>
2. Agai-Szabó, K., et al. (2024). The impact of mindfulness-based stress reduction on secondary school teachers' professional well-being. *European Journal of Psychology of Education. https://doi.org/10.1007/s10212-024-00812-w*
3. Aloe, A. M., Amo, L. C., & Shanahan, M. E. (2014). Classroom management self-efficacy and burnout: A multivariate meta-analysis. *Educational Psychology Review, 26*(1), 101–126. <https://doi.org/10.1007/s10648-013-9244-0>
4. Ansley, B. M., Houchins, D. E., & Varjas, K. (2016). Optimizing teacher health and well-being: A review of internal and external factors. *Education and Treatment of Children, 39*(4), 545–577. <https://doi.org/10.1353/etc.2016.0024>
5. S., Ploumpi, A., & Ntalla, M. (2013). Occupational stress and professional burnout in teachers of primary and secondary education: The role of coping strategies. *Psychology, 4*(3), 349–355. <https://doi.org/10.4236/psych.2013.43A051>
6. Awa, W. L., Plaumann, M., & Walter, U. (2010). Burnout prevention programs: Any stages of change? *Prevention Medicine, 51*(3), 184–189. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2010.07.009>
7. Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2017). Job demands-resources theory: Taking stock and looking forward. *Journal of Occupational Health Psychology, 22*(3), 273. <https://doi.org/10.1037/ocp0000056>
8. Barata-Gonçalves, M., et al. (2025). Mindfulness in teaching and teachers' job satisfaction: A comparative study. *Social Sciences, 14*(3), 148. <https://doi.org/10.3390/socsci14030148>
9. Beltman, S., Mansfield, C., & Price, A. (2011). Thriving not just surviving: A review of research on teacher resilience. *Educational Research Review, 6*(3), 185–207. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.09.001>
10. Benevene, P., et al. (2020). Effect of teachers' happiness on health: The mediating role of occupational stress. *Frontiers in Psychology, 11*, 1239. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01239>
11. Beshlideh, K., et al. (2023). Effectiveness of cognitive-behavioral stress management on job satisfaction and burnout in high school teachers. *Journal of Education and Health Promotion. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_120_23*
12. Blase, J. J. (1986). A qualitative analysis of sources of teacher stress: Consequences for performance. *American Educational Research Journal, 23*(1), 13–40. <https://doi.org/10.3102/00028312023001013>
13. Bottiani, J. H., et al. (2019). The Role of School Climate and Teacher Self-Efficacy in Secondary School Teachers' Job Satisfaction and Burnout. *Journal of School Psychology, 72*, 46–61. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2018.12.002>
14. Brackett, M. A., Reyes, M. R., Rivers, S. E., Elbertson, N. A., & Salovey, P. (2012). Classroom emotional climate, teacher affiliation, and student conduct. *Journal of Classroom Interaction, 27*-36.
15. Buric, I., Šlišković, A., & Penezić, Z. (2019). Understanding teacher burnout: The role of emotional labor and emotional intelligence. *International Journal of School & Educational Psychology, 7*(2), 114–130. <https://doi.org/10.1080/21683603.2018.1438287>
16. Cano-García, F. J., Padilla-Muñoz, E. M., & Carrasco-Ortiz, M. A. (2005). Personality and contextual variables in teacher burnout. *Personality and Individual Differences, 38*(4), 929–940. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.06.018>
17. Chan, D. W. (2006). Emotional intelligence and components of burnout among Chinese secondary school teachers in Hong Kong. *Teaching and Teacher Education, 22*(8), 1042–1054. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.04.005>
18. Chang, M. L. (2009). An appraisal perspective of teacher burnout: Examining the emotional work of teachers. *Educational Psychology Review, 21*(3), 193–218. <https://doi.org/10.1007/s10648-009-9106-y>
19. Collie, R. J., Shapka, J. D., & Perry, N. E. (2012). School climate and social-emotional learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. *Journal of Educational Psychology, 104*(4), 1189–1204. <https://doi.org/10.1037/a0029356>
20. Convertino, C. (2023). Secondary teacher burnout and interventions in the post-pandemic era. *Educational Review. https://doi.org/10.1080/00131911.2023.2172011*

मालती जोशी की कहानियों में सामाजिक यथार्थ

अनीता कुमारी

शोधार्थी

हिन्दी विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

प्रस्तावना-समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी एक-दूसरे के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें सभी तरह के मानवीय क्रिया-कलाप शामिल होते हैं। समाज में तरह-तरह की घटनाएँ घटते रहती हैं। समाज से संबंधित घटनाओं का यथार्थ चित्रण ही सामाजिक यथार्थ कहलाता है। युग के अनुरूप सामाजिक यथार्थ की अवधारणा बदलती रहती है। हमारे समाज में घटित होनेवाली घटनाएँ साहित्य के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। चूँकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। अतः समाज के अंदर होनेवाले उतार-चढ़ाव का यथार्थ रूप रचनाकार अपनी रचनाओं के द्वारा समाज के सामने लाने का प्रयास करता है। नारी और पुरुष दोनों ही समाज के परस्पर पूरक अंग हैं, क्योंकि समाज निर्माण में नारी तथा पुरुष दोनों का ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुरुष अपने घर तथा समाज का सिर्फ अकेले निर्माण नहीं कर सकता, उसमें नारी का भी प्रमुख स्थान है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैदिक काल में नारियों का स्थान पुरुष के समान ही था, किन्तु कालान्तर में नारी की स्थिति दयनीय होती चली गयी।

मालती जोशी जी, हिन्दी कहानीकारों में एक प्रमुख कहानीकार हैं, जिन्होंने समाज की वास्तविकता को अधिक महत्त्व दिया है। समाज में रहते हुए उन्हें जो अनुभूति मिली उसे ही उन्होंने अपनी कहानियों का आधार बनाया। समाज में व्याप्त कुशीतियों के कारण अपमान का दंश झेलती हुई स्त्रियों की यथार्थ स्थिति का चित्रण मालती जोशी जी ने किया है। उन्होंने नारी के विविध पहलुओं को अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। उन्होंने नारी उत्पीड़न के प्रति विद्रोह के भाव को तो व्यक्त किया ही है साथ ही साथ बदलते मानवीय जीवन मूल्यों के कारण नारी समस्याओं को भी चित्रित किया है। उन्होंने नारी के आधुनिक स्वरूप को उभारकर समाज में नारी-पुरुष की समानता पर भरपूर बल दिया है। मालती जोशी जी ने आधुनिक नारी की वास्तविक स्थिति से परिचय कराया है तथा नारी हृदय की आशा-आकांक्षाओं, मानसिक प्रथियों एवं समस्याओं का मार्मिक चित्र अपनी कहानियों में खींचा है। उन्होंने दहेज-प्रथा, अनमेल-विवाह, विधवा-विवाह, आदि जैसी सामाजिक समस्याओं को बड़े ही गहनता के साथ चित्रित किया है।

मालती जोशी जी ने समाज में फैली कुरीतियों में से एक दहेज-प्रथा जैसी कुरीति को उद्धृत किया है। जिससे समाज में चली आ रही इस प्रथा के कारण नारी को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है। "कन्यादान" कहानी की नायिका सुम्मी के घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण परिवार वालों को उसके विवाह की चिन्ता लगी रहती है। दहेज के लिए रकम जुटाना मध्यवर्गीय परिवारवालों के लिए बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि सुम्मी की माँ परेशान सी लगती है। अपने छोटे भाई से सुम्मी के दूद कहते हैं— "तुम यदि सोचते हो कि कोई नारियल-सुपारी के साथ तुम्हारी बेटी ब्याह कर ले जाएगा, तो भइये, हिन्दुस्तान में अभी पचास साल तक वह दिन नहीं आएगा।" कथानायिका सुम्मी इस प्रथा के कारण हीन भावना से ग्रस्त दिखती है। "बकुल फिर आना" कहानी में दहेज के कारण बकुल को ससुरालवालों द्वारा जलाकर मार दिया जाता है परन्तु सबकुछ जानते हुए भी आर्थिक तंगी के कारण चार बेटियों वाला पिता अपनी बड़ी बेटी का विवाह उसी

घर में कर देता है, क्योंकि उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं होते। समाज में फैली कुप्रथा की वजह से मोरी "रंग दी चुनरिया" की नायिका जया को घर से बाहर आने-जाने में प्रतिबंध लगा दिया जाता है तथा घर में उसे कैद करके रखा जाता है। अपनी इस पीड़ा को जया अपनी सखी से कहती है— सच कह रही हूँ दीदी! मुझे कमरे में कैद करके रखा गया है, कॉलेज नहीं जाने देते, टी०वी० नहीं देखने देते, पानी भी मांगकर पीना पड़ता है। मुझे कोई घड़ा नहीं छूने देता।² इस तरह उसे अपने ही लोगों द्वारा बार-बार अपमानित किया जाता है। उसका कुसर सिर्फ इतना रहता है कि उसके पति जिसे न उसने देखा और न कभी उसके घर गई, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके ऊपर विधवा होने का ठप्पा लग जाता है। भारतीय समाज आज भी पुरानी प्रथाओं तथा मान्यताओं से ग्रस्त दिखता है। भारतीय समाज में विधवा का शोषण होता है एवं उसे अनेक विषमताओं से गुजरना पड़ता है। विधवा नारी अपने ही लोगों द्वारा आश्रय पाने के लिए विवश हो जाती है तथा समाज द्वारा अनेक प्रतिबंध उस पर लगा दिए जाते हैं। उनकी उसकी सभी प्रतिक्रियाओं पर बार-बार टोककर और ताने देकर उनका जीवन दुखमय बना दिया जाता है। समाज की यह विडंबना है कि विधवा स्त्री को हमेशा उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता रहा है, उसे हर शुभ कार्यों से दूर रखा जाता है खास कर जब कोई शादी ब्याह का मौका हो। समाज में फैली इस कुप्रथा के कारण कई महिलाएँ मानसिक रोग का शिकार हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियाँ अपने सभी कार्यों के लिए दूसरे पर आश्रित हो जाती हैं। विधवा स्त्री को दूसरों के घर में विवाह के रस्मों में शामिल तो नहीं ही किया जाता लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, यहाँ तक कि उसे अपने संतान के विवाह के शुभ अवसर पर भी रस्मों में भाग लेने पर प्रतिबंध होता है। जो माँ अपने संतान की रक्षा के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती है उसी माँ के हाथों अमंगल की कामना से उसे अपने बेटे से दूर रखा जाता है। "कवच" कहानी में इसी सामाजिक कुप्रथा से संबंधित है। इसमें विनय की माँ जो खुद नौकरी करके अपने बेटे को पढ़ा-लिखा कर इस योग्य बनाती है कि वह भी नौकरी करने लगता है। उसी बेटे के विवाह के अवसर पर हरेक रस्म में वह अलग-थलग रहती है। अकेले में होकर वह अपने आँसू बहाती है, ताकि बेटे को उसकी पीड़ा का आभास तक न हो। परन्तु विनय अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता है और वह सारे नियमों को तोड़कर बारात जाते समय अपनी माँ से तिलक लगवाता है तथा अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा समाज आज बहुत आगे बढ़ गया है। परन्तु सिर्फ कहने के लिए हम आगे बढ़े हैं, हमारी सोच आज भी वहीं की वहीं है। हमारे भारतीय समाज में जाति प्रथा की रीढ़ सजातीय विवाह को माना जाता है। हालाँकि अंतर्जातीय विवाह भी होने लगा है, फिर भी सजातीय विवाह को ज्यादा महत्त्व दिया जाता है। अन्तर्जातीय विवाह को आसानी से मान्यता नहीं मिल पाती उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसी प्रसंग से संबंधित कहानी "प्रत्यावर्तन" है, जिसमें मालती जोशी जी ने अन्तर्जातीय विवाह के कारण उत्पन्न समस्या पर प्रकाश डाला है। अनुराधा और अशोक पेशे से डॉक्टर रहते हैं और दोनों का अन्तर्जातीय विवाह होता है। परन्तु अशोक के घरवाले इस विवाह के खिलाफ रहते हैं। जब अशोक अनुराधा को लेकर अपने घर जाता

अशोक की माँ उसे अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और उसकी तरफ इशारा करके बोलती है— "इस चुड़ैल के साथ यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?"³ इस तरह अनुराधा अपनी सास के द्वारा अपमानित होकर वापस लौट जाती है लेकिन कुछ दिनों के बाद अशोक के पिता को कैंसर हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। अशोक जिद्द करके अनुराधा को भी साथ ले जाता है, जहाँ उसकी सास अशोक को कमरे में ले जाकर दरवाजा को सटा देती है। अनुराधा बाहर ही प्रतीक्षा करते रह जाती है। लेकिन अशोक भी अनुराधा को न तो लिवा ले जाता है और न घर जाने के लिए कहने आता है। अंत में अनुराधा घर आकर अपना सामान समेटती है और अपने पिता के घर आ जाती है। अशोक भी उसे मनाने की कोई किसी प्रकार से कोई पहल नहीं करता। इस प्रकार अनुराधा और अशोक एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। समाज की सबसे ज्वलंत समस्या तलाक की समस्या है। दर्व्यवहार, छलकपट, धोखा, अहंकार, विवाहेतर संबंध आदि के कारणों से तलाक जैसी समस्या उत्पन्न होती है। "पिता" कहानी में नमिता के पिता का अपनी पत्नी के प्रति दर्व्यवहार का कारण उनकी बेटे की चाह थी। जब उनकी दूसरी संतान भी बेटे ही होती है तो वे अपनी पत्नी को अनेकों तरह से प्रताड़ित करते हैं। जिसके कारण अपनी दोनों बेटियों को लेकर वह अपनी माँ के घर आ जाती है। इस तरह पति के अत्याचार से पीड़ित होने के कारण पति-पत्नी दोनों के बीच वैवाहिक संबंध का पतन हो जाता है। दोनों अलग हो जाते हैं।

उनकी एक कहानी अक्षम्य है जिसमें पति-पत्नी के बीच संदेह के कारण तलाक जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। श्याम एवं उसकी माँ बिन्दु के कम पढ़े-लिखे होने के कारण उसे हमेशा अपमानित करते हैं। श्याम भी उससे तलाक लेने के लिए कोई न कोई बहाना ढूँढता रहता है। जब श्याम की माँ, बिन्दु को 'रज्जू' हलवाहे के साथ गलत लाक्षण लगाती है तो श्याम भी उसे संदेह की नेजर से देखने लगता है। इस संदेह के कारण वह बिन्दु से तलाक ले लेता है।

आज बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं। हर एक क्षेत्र में आज वह अपने माता-पिता का नाम रौशन कर रही हैं। फिर भी सामाजिक परंपरा को निभाने का जिम्मा अधिकतर लड़कों के हिस्से में ही आता है। इसी कुंठित मानसिकता से ग्रस्त लोग बेटे पैदा हो जाने के कारण अवसादग्रस्त हो जाते हैं। बेटियों को बचपन से ही कभी पिता के अधीन तो कभी बड़े होने पर भाई के अधीन और विवाह हो जाने पर पति के अधीन रहना पड़ता है। वे अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तड़प कर रह जाती हैं। इसी विषय से संबंधित कहानी है "पिया पीर न जानी" जिसमें यह दृश्य देखने को मिलता है कि बार-बार बेटियों को जन्म देने कारण एक स्त्री को किस प्रकार पीड़ित होना पड़ता है। इस कहानी की रमा जब-जब लड़की को जन्म देती है तब-तब सास-बहू के सम्बन्ध में कड़वाहट उत्पन्न होती है। रमा कहती है— "कन्या के होने पर अम्मा जी का कहना था कि दुःख ने उन्हें पत्थर बना दिया था। पर सच तो यह है कि पत्थर तो वह शुरू से ही थी, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान के लिए अपनी कन्याओं का गर्भ में ही गला घोट दिया था। अतएव सास के खौफ से रमा अपनी दोनों कन्याओं को जन्म से पहले ही मार डालती है। अभिप्राय यह कि आधुनिक युग में शिक्षित पत्नी को भी इस यातना का शिकार होना पड़ता है। समाज में बेटे को महत्व दिया जाता है जिसकी वजह से नारी को इस पीड़ा को भोगना पड़ता है।

निष्कर्षतः भारतीय समाज में जिस प्रकार कुरीतियों के कारण नारियों का शोषण किया जाता रहा है उसका दुष्परिणाम यह होता है कि या तो स्त्री खुद की जीवनलीला समाप्त कर लेना चाहती है या फिर घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर होती है।

आज के दौर में भी यह एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसी विषय पर मालती जोशी जी ने अपनी कहानियों में जहाँ विचारों से जकड़े व्यक्तियों का चित्रण किया है वहीं के समाज में स्त्रियों की विभिन्न स्थितियों को भी दर्शाया है। उन्होंने समाज में व्याप्त पुरानी परंपराएँ, मान्यताएँ तथा रूढ़ियों को समाप्त कर नयी परंपराओं और मान्यताओं का निर्माण करना चाहती हैं। जिससे कि नारी को भी पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हो सके और उसका जीवन सुखमय बन सके। इनकी कहानी पाठकों को समाज में व्याप्त कुरीतियों, पुरानी मान्यताओं और रूढ़ियों को तोड़कर एक नये समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

संदर्भ सूची-

1. जोशी, मालती - कन्यादान, 'मन न भये दस बीस' (कहानी-संग्रह) साक्षी प्रकाशन, दिल्ली - 2010 पृ० 50
2. जोशी, मालती - मोरी रंग दी चुनरिया (कहानी-संग्रह) किताबघर प्रकाशन, दिल्ली - 1992 पृ० 34
3. जोशी, मालती - प्रत्यावर्तन, ना जमीं अपनी ना फलक अपना (कहानी-संग्रह) साक्षी प्रकाशन दिल्ली - 2014 पृ० 81
4. जोशी, मालती - पिया पीर न जानी (कहानी-संग्रह) किताबघर प्रकाशन, दिल्ली - 1999 पृ० 22-23

हिन्दी कथा साहित्य में भारतीय ग्यान परंपरा

डा. सुधामणि.एस.

सह प्राध्यापक, हिन्दी विभाग

सरकारी रामनारायण चेल्लाराम वाणिज्य तथा प्रबंध महाविद्यालय,
रेस कोर्स रोड, बेंगळूरु. 560001

प्रस्तावना: हिन्दी कथा साहित्य में भारतीय ग्यान परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और दर्शन से प्रेरित होकर नैतिकता, आध्यात्मिकता, दार्शनिकता और सामाजिक मूल्यों की रक्षा करती है। यह परंपरा ईश्वर भक्ति, सूफि प्रेम और नैतिक बोध के माध्यम से जीवन को संतुष्ट बना दिया है। हिन्दी कथा साहित्य, भारतीय परंपरा (वेद, पुराण, दर्शन, लोकग्यान) का आधुनिक रूप है। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ वेद, उपनिषद, पुराण, और रामायण-महाभारत के दर्शन, नीति, आध्यात्मिक मूल्यों तथा सामाजिक नैतिकता को कथा के माध्यम से जनसामान्य तक पहुँचाना है। यह परंपरा कबीर के संत साहित्य से लेकर प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों और आधुनिक साहित्य तक, नैतिक मूल्यों, समाज सुधार, और भारतीय अस्मिता के रूप में निरंतर प्रवाहमान है।

बीजक शब्द : साहित्य, नैतिकता, आध्यात्मिकता, दर्शन शास्त्र, आधुनिक साहित्य

हिन्दी कथा साहित्य- हिन्दी कथा साहित्य आधुनिक काल (19वीं सदी के अंत) में पाश्चात्य और लोक कथा परंपरा के प्रभाव से विकसित हुआ। इसमें उपन्यास और कहानी प्रमुख विधाएँ हैं, जो सामाजिक, यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक विषयों को दर्शाती हैं। प्रेमचंद ने इसे यथार्थ से जोड़कर उन्नत शिखर तक पहुँचाया, प्रसाद ने उसे भावनात्मक गहराई दी। यह विधा, मानव जीवन की विविधता को प्रस्तुत करती है। हिन्दी कथा साहित्य के अंतर्गत गद्य की दो विधाओं का अध्ययन किया जाता है, उपन्यास और कहानी। इसके अंतर्गत छात्रों को उपन्यासों और कहानियों के संदर्भ के अनुसार जोड़कर पढ़ने का प्रयास किया जाता है तथा कुछ प्रमुख रचनाकारों तथा रचनाओं से अवगत करने का प्रयास किया जाता है।

हिन्दी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों में यथार्थवाद, मनोविश्लेषण, प्रगतिवाद और समकालीन का बोध प्रमुख हैं, जो प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से लेकर आज के महानगरीय जीवन की जटिलताओं, अस्तित्व-बोध, स्त्री विमर्श और दलित चेतना को दर्शाती हैं। ये कहानियाँ समाज के बदलते हुए मूल्यों, मध्यमवर्गीय जीवन, और मानवीय संवेदनाओं को यथार्थ के धरातल पर चित्रित करती हैं।

हिन्दी साहित्य क्षेत्र में कथा साहित्य जो ऐसी दो विधाएँ हैं जिसके द्वारा साधारण मानव भी अपनी मन की भावनाओं एवं चेतनाओं को

व्यक्त कर सकता है। कथा साहित्य, मानव जीवन की साधारण अभिव्यक्ति है। कथा साहित्य, मानव जीवन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। हिन्दी कहानी और उपन्यास का विकास आधुनिक काल में ही हुआ। हिन्दी कहानी की विकास-यात्रा लगभग सौ वर्षों की यात्रा माना गया है जिसमें बहुत तेज गति से नये परिवर्तन होते रहे हैं। उसकी विकास-गति तीव्र और अपने समय-संदर्भों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि हिन्दी कहानी ने बहुत कम समय में एक श्रेष्ठ साहित्यिक विधा का रूप प्राप्त कर लिया। इसका प्रमुख कारण यह है कि आरंभ में ही कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों ने अपनी प्रतिभा से उसे (हिन्दी कहानी) प्रारंभिक दौर की लड़खड़ाहट और अनगढ़पन से मुक्त कर दिया। हिन्दी कहानी के उदयकाल में ही श्रेष्ठ रचना का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण विषय है। इसने आगे के कहानीकारों के लिए उत्कृष्ट कहानी की रचना के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर दी। हिन्दी साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ उसके 1000 वर्षों के क्रमिक विकास (आदिकाल से आधुनिक काल) को दर्शाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से भक्ति-भावना, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, प्रकृति चित्रण, और समन्वय की प्रवृत्ति प्रमुख है। यह भाषा (ब्रज, अवधी, खड़ीबोली), श्रृंगार और वीर रस के मिश्रण के साथ मानवीय संवेदनाओं को उजागर करता है।

हिन्दी साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ : समन्वय और भक्ति भावना: भारतीय साहित्य के मूल भावना है, जो ज्ञान, भक्ति और कर्म को जोड़ती है। भक्तिकाल में सगुण और निर्गुण ईश्वर की उपासना के साथ गुरु का महत्व दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार: आधुनिक काल में राष्ट्रप्रेम, स्वाधीनता आंदोलन, और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन-जागरण का स्वर का मुखरित हुआ। वीर और श्रृंगार रस (आदिकालीन विशेषता): आदिकाल में राजाओं की प्रशंसा (रासो काव्य) में वीर रस और श्रृंगार रस का सजीव चित्रण प्रमुख था।

प्रकृति चित्रण: साहित्य में प्रकृति का स्वतंत्र और मानवीय रूप में (छायावाद) सुंदर वर्णन मिलता है।

भाषाई विकास (ब्रज से खड़ीबोली): मध्यकाल में ब्रज और अवधी की प्रधानता थी, जबकि आधुनिक काल में खड़ीबोली हिन्दी प्रमुख साहित्य भाषा बनी।

विविधता और यथार्थवाद: छायावाद में वैयक्तिकता और प्रेम, प्रगतिवाद में शोषितों की आवाज, और प्रयोगवाद में नवीन प्रयोगों के साथ समकालीन साहित्य में यथार्थवाद (वास्तविक जीवन) को प्रमुखता मिली है।

भारतीय ज्ञान परंपरा: भारतीय ज्ञान परंपराहजारों वर्षों पुरानी एक समृद्ध, निरंतर प्रणाली है, जो वेदों, उपनिषदों, पुराणों, और योग-आयुर्वेद, गणित शास्त्र, खगोल विज्ञान, जैसे विभिन्न शास्त्रों पर आधारित है। यह ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्म, नैतिकता, दर्शन और कला का मिश्रण है, जिसका मुख्य उद्देश्य समग्र मानव कल्याण और सतत विकास करना है।

भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य स्तंभ: वैदिक साहित्य (वेदों का ज्ञान): वेदों (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद) को भारतीय ज्ञान का मूल आधार माना जाता है।

विज्ञान और तकनीक: प्राचीन काल में आयुर्वेद, खगोलशास्त्र (ज्योतिष), गणित, वास्तुकला (शिल्पशास्त्र), और धातु विज्ञान का उद्भव तथा विकास हुआ।

साहित्य और कला: रामायण, महाभारत, पुराण, और कालिदास जैसे महान कवियों की रचनाएँ, जो जीवन के मूल्य और सांस्कृतिक चेतना को दर्शाती हैं।

योग और साधना: महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग परंपरा, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

गुरु-शिष्य परंपरा: ज्ञान के हस्तांतरण की अनूठी प्रणाली, जहाँ ज्ञान मौखिक और व्यावहारिक रूप से पीढ़ियों तक पहुँचाया गया।

भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमुख विशेषताएँ:

सर्वसमावेशी : यह लौकिक (भौतिक) और पारलौकिक (आध्यात्मिक) ज्ञान में समन्वय की स्थापना की है।

कल्याणकारी दृष्टिकोण: 'वसुधैव कुटुंबकम्' (पूरी दुनिया एक परिवार है) के दर्शन पर आधारित है।

अनुभव और अन्वेषण: यह परंपरा केवल पुस्तकीय नहीं, बल्कि अनुभव, अवलोकन, और प्रयोग या अन्वेषण पर आधारित है।

वैज्ञानिकता: इसमें प्राकृतिक विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा प्राचीन काल से ही मौजूद है।

हिंदी कथा साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा : हिंदी कथा साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ है वेदों, उपनिषदों, पुराणों और दर्शन से निकले शाश्वत मूल्यों का आधुनिक कहानियों में समावेशन। यह परंपरा त्याग, नैतिकता, सत्य और मानवीय संवेदनाओं को लोकभाषा में प्रस्तुत करती है, जो प्रेमचंद, प्रसाद से लेकर समकालीन कथाकारों तक पात्रों के माध्यम से भारतीय जीवन-दर्शन को दर्शाती है।

हिंदी कथा साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएँ

मूल्य-आधारित चिंतन: प्रेमचंद की कहानियों में 'पंच परमेश्वर' जैसी रचनाओं में धर्म, न्याय, और नैतिकता की भारतीय परंपरा स्पष्ट चित्रण हुआ है।

दार्शनिक और सांस्कृतिक गहराई: जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों में भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति का समन्वय किया है।

त्याग और आत्मिक विकास: भारतीय ज्ञान परंपरा त्याग भावन पर ध्यान दिया है, जो कथाओं में पात्रों के संघर्ष और आत्म-शुद्धि के रूप में व्यक्त हुआ है।

मानवतावाद: रामकाव्य और अन्य साहित्य के माध्यम से मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने और समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश कथाओं में प्रमुख रूप से प्रचलित हैं।

लोक-चेतना: मध्यकालीन संत परंपरा से लेकर आधुनिक कथाओं तक, ज्ञान को जनभाषा में लाकर उसे समाज के जन समुदाय तक पहुँचाया गया है।

निष्कर्ष : हिंदी कथा साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा, सदियों से सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकता, योग, और दर्शन का संरक्षक रही है। कथा साहित्य ने वेद-पुराणों के जटिल ज्ञान को जनसाधारण भाषा में सुलभ बनाकर सामाजिक समरसता, कर्तव्यबोध और आध्यात्मिक चेतना का संचार किया है। यह साहित्य केवल अतीत का गौरव नहीं, बल्कि प्रेमचंद से लेकर आधुनिक लेखकों तक, सामाजिक यथार्थ और नैतिक पुनर्स्थापना का जीवंत माध्यम बना हुआ है।

संदर्भ सूची :

- 1) https://www.google.com/search?q=hindi+kataa+saahitya+&sca_esv=eb9bc99a534cb7d&rlz=C1G1GM_enI N973IN973&biw=1366&bih=580&sxsrf=ANbL-n4xmZnCo5FlyaWyMsKGILHhXuU
- 2) https://www.google.com/search?q=hindi+kataa+saahitya+&sca_esv=3eb9bc99a534cb7d&rlz=1C1G1GM_enI N973IN973&biw=1366&bih=580&sxsrf=ANbL-n4xmZnCo5FlyaWyMsKGILHhXu
- 3) https://www.google.com/search?q=hindi+kathaa+saahitya+ki+visheshataae++in+hindi&sca_esv=97954111f5c3aa31&rlz=1C1G1GM_enI N973IN973&sxsrf=ANbL-n7gJOBA4pr_itR0
- 4) https://www.google.com/search?q=bhartiya+gyan+parampara+in+hindi&sca_esv=97954111f5c3aa31&rlz=1C1G1GM_enI N973IN973&biw=1366&bih=580&sxsrf=ANbL-n7wRaa9hgE
- 5) https://www.google.com/search?q=hindi+kataa+saahitya+me+bhaaratya+gyaan+parampara+in+hindi&rlz=1C1G1GM_enI N973IN973&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362i8.1547148j0j15&sourceid=chr

अप्रैल - जून -2025



<https://shodhutkarsh.com>

त्रैमासिक ऑनलाइन पत्रिका - 'शोध उत्कर्ष'



शोध उत्कर्ष (RESEARCH ARETE JOURNAL)

Shodh Utkarsh

